भाजपा का घोषणा पत्र बनाम संकल्प पत्र

भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में तीसरी बार सत्ता में वापसी होने पर भारत में न्याय संहिता लागू की जाएगी। वन नेशन और वन इलेक्शन पर काम किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र के बारे में अपने संकल्पों को दोहराया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों,युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए घोषणा पत्र में जो कहा है, उसके बारे में विस्तार से समझाया। मछुआरों के लिए बीमा की सुविधा, आदिवासियों के लिए मोटे अनाज को सुपरफुड के तौर पर दुनिया भर में पहचान बनाने, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने, एसटी-एससी वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम, एकलव्य स्कूल खोलने, रामायण उत्सव मनाने,अयोध्या का विकास और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे कई संकल्पों की घोषणा की। ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट को समाप्त करने और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का बिना किसी भेदभाव के इलाज करने के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब, गांव और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी।भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जिन विषयों को संकल्प रूप में दर्शाया गया है। वह कब और किस रूप में पूरे होंगे। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। 2024 में 2047 का खाका जरूर खींचा गया है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में जो वायदे और संकल्प किए गए थे। समय-समय पर जो सपने और घोषणाएं भाजपा ने की थी। मतदाता अब 10 साल बाद उसे विश्वसनीयता की कसौटी पर कसने की मुद्रा में आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है। वह ज्यादा स्पष्ट,और मतदाताओं को लुभा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासी, एससी-एसटी वर्ग प्रत्येक परिवार को न्यूनतम आर्थिक गारंटी, बेरोजगार युवाओं को नौकरी पढ़ाई के बाद स्टाई फंड इत्यादि विषयों को शामिल किया गया है।

स्वस्थ भारत की जननी है आंगनबाड़ी केंद्र

आरती कुमारी

एक अप्रैल से राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. इससे आंगनबाड़ी से जुड़े सदस्यों को काफी लाभ पहुंचेगा. इस वक़्त पूरे राज्य में 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं. जिसके माध्यम से लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त बनाया जा रहा है. इन आंगनबाड़ी केंद्रों का सफलतापूर्वक संचालन इन्हीं कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं के माधयम से मुमकिन होता है. कई बार कम वेतन और विषम परिस्थितियों के बावजूद इन कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं ने देश के नौनिहालों के शारीरिक और मानसिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है. अक्सर समाचारपत्रों में कई महीनों तक इनके वेतन रुके होने की ख़बरें आती रहती हैं. जिससे इनकी आर्थिक परेशानियों को समझा जा सकता है. इसके बावजूद यह समर्पण और सेवा भाव से बच्चों के विकास के लिए तत्पर नज़र आती हैं.

दरअसल सभी आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार की आईसीडीएस योजना के तहत संचालित होती है. यह दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है. जिसके माध्यम से लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाना है. 02 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई इस योजना ने अब तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त बनाया है. यही कारण है कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकारों ने समय समय पर न केवल इस योजना को प्रोत्साहित किया है बल्कि अन्य कई योजनाओं को इससे जोड़ा भी है. जिसका परिणाम है कि ज़मीनी स्तर पर इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिलते रहे हैं. हालांकि कई बार इन्हें बच्चों के पंजीकरण और उनकी उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं का इन्हें सामना भी करनी पड़ती है.

इसका एक उदाहरण राज्य के बीकानेर स्थित कालू गांव है. जिला मुख्यालय से 92 किमी और लूणकरणसर ब्लॉक से 20 किमी की दूरी पर स्थित इस गांव में पिछले कई वर्षों से संचालित 6 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुचारु रूप से लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है. पंचायत से उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस गांव की जनसंख्या करीब 10334 है. इतनी बड़ी आबादी वाला यह गाँव 9 वार्डों में विभाजित है. यहां अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 14.5 प्रतिशत है. इन सभी 6 आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 6 साल की उम्र के लगभग 400 बच्चे पंजीकृत हैं. जिन्हें पूरक आहार के तहत

प्रतिदिन दलिया और खिचड़ी दी जाती है ताकि बच्चों को कुपोषण मुक्त बना कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके. लेकिन अक्सर इन पंजीकृत बच्चों और उनकी नियमित उपस्थिति से संबंधित कमियां रह जाती हैं. कई बार पंजीकरण से काफी कम बच्चे केंद्र पर आते हैं. इस संबंध में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 6 की कार्यकर्ता पार्वती देवी का कहना है कि "यहां कुल 55 बच्चों का पंजीकरण है. जिसमें 0 से 3 साल के 29 बच्चे और 3 से 6 साल के 26 बच्चे पंजीकृत हैं. लेकिन केंद्र पर नियमित रूप से केवल 6 बच्चे ही आते हैं." पंजीकरण के बावजूद बच्चों की कम संख्या के सवाल पर पार्वती देवी बताती हैं कि 'दरअसल इस गाँव का अधिकतर परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है. ज्यादातर माता पिता दैनिक मजदूरी करने शहर जाते हैं. जहां से उन्हें लौटने में अक्सर शाम और कभी कभी देर रात हो जाती है. इतनी देर तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला नहीं रह सकता है. इसलिए वह अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़ने की जगह अपने साथ कार्य स्थल पर ले जाते हैं. हालांकि जो बच्चे केंद्र पर आते हैं उन्हें हम खुद घर से लाते और फिर वापस छोड़ कर आते हैं. केंद्र पर बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है. यहां पर बच्चों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध है. उनके लिए पीने के साफ पानी और शौचालय की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है. लेकिन कम बच्चों की उपस्थिति सभी के लिए चिंता का विषय है." वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 3 की कार्यकर्ता सुशीला देवी कहती हैं कि "इस केंद्र में कुल 87 बच्चों का पंजीकरण हुआ है. जिसमें 0 से 3 साल के 60 बच्चे और 3 से 6 साल के 27 बच्चे पंजीकृत हैं. लेकिन नियमित रूप से केवल 13 बच्चे ही केंद्र पर आते हैं. इसका कारण भी केंद्र संख्या 6 की तरह है." वह बताती हैं कि केंद्र में बच्चों को पूरक पोषित आहार के रूप में 540 ग्राम दलिया, 480 ग्राम खिचड़ी और 540 ग्राम सादा दलिया दिया जाता है. इसके अतिरिक्त यहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें भी दी जाती हैं. वहीं छोटे बच्चों के लिए खिलौने उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त कर सकें." वह बताती हैं कि केंद्र की सहायिका और सेविका प्रतिदिन बच्चों को उनके घर से लेकर आती हैं और फिर वापस छोड़ कर भी आती हैं. सुशीला देवी कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र किसी सौगात से कम नहीं है. अक्सर कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता अपने बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं. जिससे बच्चों में कुपोषण के लक्षण नज़र आने लगते हैं. लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के माधयम से न केवल लाखों गरीब बच्चे बल्कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं भी कुपोषण से मुक्त हुई हैं. आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 5 की सहायिका किरण देवी कहती हैं कि समय समय पर विभिन्न योजनाओं को आईसीडीएस से जोड़कर आंगनबाड़ी केंद्र का दायरा बढ़ाया गया है. अब केंद्र के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को सेनेटरी पैड भी उपलब्ध कराये जाते हैं. इसके अतिरिक्त यहां पर हर बुधवार को किशोरियों के बीच आयरन और कैल्शियम की टेबलेट वितरित की जाती है. किशोरियों के साथ माहवारी के दौरान साफ सफाई और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए उनके साथ प्रति माह मीटिंग भी की जाती है. इस प्रकार से देखा जाए तो अब आंगनबाड़ी केंद्र में केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि महिलाओं और किशोरियों की सेहत को भी बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किये जा रहे हैं. हालांकि कई बार केंद्र में सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों के साथ साथ कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. एक ही गांव में 6 आंगनवाड़ी केंद्र होने के बावजूद कुछ ग्रामीण इनमें उपलब्ध सुविधाओं की कमी का जिक्र करते हैं. गांव की एक 28 वर्षीय महिला सरस्वती देवी कहती हैं कि "आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 6 में मेरी 5 साल की बेटी जाती है. मैं खुद अपनी बेटी को आंगनबाड़ी केंद्र छोड़ने और लेने जाती हूं. यहां पढ़ाई भी बहुत कम करवाई जाती है और बच्चों का पोषण आहार भी कम दिया जाता है. इसके अतिरिक्त समय पर हमें पैड भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं. हमें दो महीने से सेनेटरी पैड भी नहीं मिले हैं. वहीं 17 वर्षीय किशोरी अनीता कहती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से पैड और आयरन की गोलियां नहीं मिलती हैं. जिससे हमें काफी परेशानी होती है. बहरहाल कुछ कमियों के बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए थे कालू गाँव में वह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को नाकारा नहीं जा सकता है.

अमेठी और रायबरेली के बारे में गांधी परिवार क्या सोच रहा है ?

अशोक भाटिया

यदि हम पिछले 2019 के चुनाव पर नज़र फेरे तो तब कांग्रेस की 15 उम्मीदवारों की पहली सूची में अमेठी और रायबरेली शामिल थे। इस बार कांग्रेस ने 15 सूची में 244 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए लेकिन इन दोनों सीटों के नाम सामने नहीं आए। रायबरेली से चुनाव लड़ती रही सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन चुकी है। ऐसे में वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम कई बार सामने आया, लेकिन पार्टी ने अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अमेठी में 2019 में राहुल गांधी भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए जबकि वायनाड से जीते थे। वायनाड से राहुल के बतौर उम्मीदवार नाम पहली सूची में आ गया, लेकिन अमेठी की घोषणा रोक दी। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ाने का विकल्प खुला हुआ है। कांग्रेस नेता तर्क देते हैं कि अमेठी-रायबरेली में चुनाव 20 मई को है इसलिए अभी फैसले के लिए काफी समय है। दूसरी ओर कांग्रेस वाराणसी, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है जहां अंतिम चरण में एक जून को मतदान है। ऐसे काफी समय होने का पार्टी का तर्क दमदार नजर नहीं आता।कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह डर भी सता रहा है कि दोनों सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो भाजपा चुनाव में यह मुद्दा बना सकती है वह डर गए हैं। ऐसे में पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और सोच विचार के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ-साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के आला नेता का कहना है कि अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। पहले वायनाड छोड़ तो अमेठी नाराज और अमेठी छोड़ तो वायनाड नाराज के चलते राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हाल में जब राहुल पर हार के डर से भागने की तोहमत बीजेपी ने लगाई, तो कांग्रेस नेता ने भी अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है।कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने कहा, "हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी व्यक्तिगत वजहें थीं, लेकिन डर के भागने जैसी बात की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया। ये संदेश गलत है, इसको नेस्तनाबूत करना होगा। कांग्रेस के भीतर भी नेता अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। भले ही वे मीडिया के सूत्र बनकर कुछ न कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन वे भी हवा में ही कयास लगा रहे हैं - लेकिन अमेठी पर फैसले में वायनाड फैक्टर की एक खास भूमिका जरूर लगती है। रही बात रायबरेली लोकसभा सीट की तो उसे सोनिया गांधी की चिट्ठी से समझने की थोड़ी कोशिश की जा सकती है। राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम बड़ी ही इमोशनल चिट्ठी लिखी थी - और पुराने रिश्तों को कायम रखते हुए आगे भी परिवार के लिए सपोर्ट सिस्टम बने रहने की सोनिया गांधी ने अपील की थी। अपनी चिट्ठी के जरिये रायबरेली को लेकर जो संकेत सोनिया गांधी ने देने की कोशिश की थी, राहुल गांधी ने कभी ऐसे भाव नहीं व्यक्त किये। हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो अमेठी और रायबरेली गये जरूर थे - लेकिन उस दौरे को लेकर वहां के कांग्रेस नेताओं की नाराजगी ही सामने आई थी। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस नेता के स्वागत के लिए जगह जगह जरूरी इंतजाम किये गये थे, लेकिन राहुल गांधी किसी भी जगह अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। राहुल गांधी की नाराजगी स्वाभाविक लगती है। हैं तो वो भी इंसान ही, नेता और राजनेता होने से क्या होता है? वैसे भी अमेठी के लोगों ने जो सलूक राहुल गांधी के साथ किया है, रायबरेली के लोगों ने तो सोनिया गांधी के साथ नहीं किया। 2019 में भी रायबरेली के लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे, लेकिन अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी समझ से अमेठी की ही तरह रायबरेली में भी तो कभी गांधी परिवार के करीबी रहे कांग्रेस नेता को सोनिया गांधी के खिलाफ उतार दिया था। हां, दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी में बड़ा फर्क तो है ही। बहरहाल, सीनियर कांग्रेस नेता एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर जो संकेत दिया है, वो अपनेआप में काफी महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे वक्त जब दोनों सीटों पर आम लोगों के साथ साथ बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हों। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी अमेठी और रायबरेली में से किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है - वैसे भी अमेठी और रायबरेली में वोटिंग वायनाड के बाद ही होनी है। गांधी परिवार के लिए ये भी बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। एक इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों कांग्रेस उम्मीदावार को लेकर सवाल पूछा गया था। एंटनी ने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया लेकिन काफी हद तक तस्वीर साफ भी कर दी - कम से कम ये तो साफ कर ही दिया है कि गांधी परिवार ने यूपी छोड़ देने का फैसला नहीं किया है। वैसे भी यूपी छोड़ देने के मतलब तो उत्तर भारत ही छोड़ देने जैसा समझा जाएगा। एके एंटनी का कहना है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कयास लगाये जाने की जरूरत नहीं है। एके एंटनी कहते हैं, आप अमेठी और रायबरेली लोक सभा सीटों पर फैसले का इंतजार कीजिये। और इंटरव्यू में एके एंटनी ने जो सबसे खास बात कही है, वो है - 'नेहरू परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में होगा। एके एंटनी का ये जवाब एक चीज तो स्पष्ट कर ही रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से नाता तोड़ लिये जाने की बातें पूरी तरह बकवास हैं - लेकिन दायरा बढ़ा कर एके एंटनी ने नये नये कयासों को दावत दे डाली है। कांग्रेस नेता ने सिर्फ गांधी परिवार का नाम न लेकर नेहरू परिवार की बात कही है, यानी गांधी परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार हो सकता है - हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर एके एंटनी ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली सीटों को लेकर तो सवाल पूछा ही गया, अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाये जाने की संभावनाओं पर भी पूछ लिया गया। जवाब तो एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को लेकर भी दिये, लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट रिस्पॉन्स उनका रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ही लगा। असल में हाल ही में एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने एक साथ कई दावे किये थे। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि चाहते तो वो यही हैं कि पहले प्रियंका गांधी ही संसद पहुंचें, और उसके बाद उनका नंबर आये। अमेठी के लोगों का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वे चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ने का फैसला करूं तो अमेठी से ही - और लगे हाथ, रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी दावा कर डाला था कि कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी दलों से भी उनके पास टिकट के ऑफर हैं। कांग्रेस नेता ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम को तो खारिज कर दिया है लेकिन जो बात कही है, उसमें तो राहुल और प्रियंका के साथ साथ वरुण गांधी भी शामिल हो जाते हैं। अभी तक ऐसे कोई संकेत तो नहीं मिले हैं कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस ने नो-एंट्री वाला बोर्ड हटा लिया है, लेकिन पीलीभीत से बीजेपी ने उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट देकर ऐसी संभावनाओं के द्वार तो खोल ही दिये हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना करीब करीब पक्का है। लेकिन जो स्थिति है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में राहुल गांधी की तुलना में बीजेपी की स्मृति ईरानी को ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती हैं - और जिस तरह से राहुल गांधी को वारिस के तौर पर पेश किया जाता रहा है, रायबरेली का मैदान उनका ज्यादा सूट करता है। अमेठी को लेकर राहुल गांधी के अलावा दो नाम चर्चा में हैं। एक नाम है एमएलसी रह चुके कांग्रेस नेता दीपक सिंह का - और दूसरा नाम है, बीजेपी सांसद वरुण गांधी का। दीपक सिंह को सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी से बड़े ही सख्त लहजे में दो-दो हाथ करते देखा जा सकता है - और वरुण गांधी के बारे में यहां तक बातें हो रही हैं कि वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी सीट तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस के ही पास है। वरुण गांधी को लेकर ऐसी चर्चाओं को एक ही बात कमजोर करती है वो है मेनका गांधी का ताज़ा बयान कि 'हम ऐसे लोग नहीं हैं।'

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष : कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सवेरे निपटा लें। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। शुभांक-3-6-8

वृष : व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। बुरी संगति से बचें। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना। मित्रों से सावधानी रखें तो ज्यादा उत्तम है। शुभांक-4-5-6

मिथुन : शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। खान-पान में सावधानी रखें। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। शुभांक-2-4-5

कर्क : रुपये पैसों की सुविधा नहीं मिल पाएगी। कामकाज सीमित तौर पर ही बन पाएंगे। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर बना रहेगा। यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। मेहमानों का आगमन होगा। शुभांक-3-6-9

सिंह : समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम को प्राथमिकता से करें। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़नेके अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। भाई-बहनों का प्रेम बढ़ेगा। शुभांक-2-4-6

कन्या : महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते हैं। कोई प्रिय वस्तु अथवा नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। सभा-गोष्ठियों में मान-सम्मान बढ़ेगा। शुभांक-7-8-9

तुला : धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। निर्मूल शंकाओं के कारण मनस्ताप भी पैदा हो सकते हैं। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। बुद्धितत्व की सक्रियता से अल्प लाभ का हर्ष होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनाने के लिए भाग-दौड़ रहेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होंगी। शुभांक-6-8-9

वृश्चिक : घर के सदस्य मदद करेंगे और साथ ही आर्थिक बदहाली से भी मुक्ति मिलने लगेगी। बढ़ते घाटे से कुछ राहत मिलने लगेगी। दवा-दारू में ज्यादा खर्च होगा। हाथ में आने वाला धन भी किसी अवरोध का शिकार हो जाएगा। व्यापार में स्थिति उत्तम रहेगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग है। शुभांक-5-6-9

धनु : चापलूस मित्रों से सावधानी रखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रुभय, चिंता, संतान को कष्ट, अपव्यय के कारण बनेंगे। संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी। सब्र का फल मीठा होता है। अतः धैर्य रखें व अच्छे समय इन्तजार करें। शुभांक-5-7-8

मकर : थोड़े प्रयास से कार्य सिद्ध होंगे। घर-परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न होने से वातावरण आनन्द देने वाला बना रहेगा। बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा। सुबह-सुबह की महत्वपूर्ण सिद्धि के बाद दिन-भर उत्साह बना रहेगा। किये गए कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। शुभांक-4-6-7

कुंभ : कुछ प्रतिकूल गोचर का क्षोभ दिन-भर रहेगा। दिन-भर का माहौल आडंबरपूर्ण और व्ययकारी होगा। वरिष्ठ लोगों से कहासुनी वातावरण में तनाव पैदा करेंगे। संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। आवेग में आकर किये गए कार्यों का मलाल, अवसाद रहेगा। जरा-सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। शुभांक-3-5-7

मीन : प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य संपन्न होंगे। कई प्रकार के हर्ष उल्लास के बीच अप्रत्याशित लाभ होंगे। आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा रहेगी। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। शुभांक-2-4-6

भूतो न भविष्यति, जब ग्वालियर से अटल जी ने खाई मात

राकेश अचल

भारत की सियासत में अनेक नेता अजेय माने जाते है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ऐसे ही नेताओं में से एक थे ,लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 1985 का लोकसभा चुनाव सिंधिया परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया गया एक बड़ा बलिदान है। अटल जी ने उस चुनाव में अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी पराजय का सामना किया था। अटल जी भारतीय राजनीति के अजातशत्रु थे।

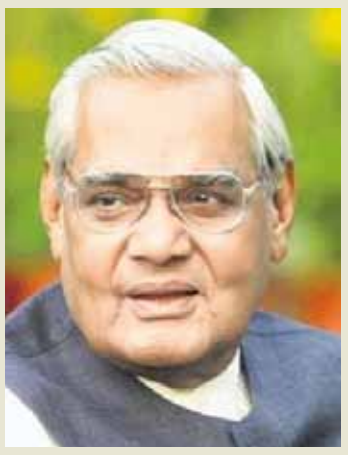

माधवराव सिंधिया ने 1971 ,77 और 1980 का लोकसभा चुनाव गुना-शिवपुरी संसदीय सीट से लड़ा था । माधवराव सिंधिया को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई लेकिन वो कभी चुनाव नहीं हारे। बाद में माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गए और 1985 में कांग्रेस ने भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी बाजपेयी को हारने के लिए माधवराव सिंधिया को तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हुए गवालियर सीट सेअटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ग्वालेऔर सीट से मैदान में खड़ा कर दिया। ये फैसला नामांकन पत्र भरने के अंतिम क्षणों में हुआ बाजपेयी के खिलाफ किसी दूसरी सीट से नामांकन भरने का वक्त ही नहीं बचा था। मुझे याद है कि उस समय राजमाता और माधवराव सिंधिया के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। माधवराव सिंधिया जनसंघ छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। जिस कारण से राजमाता नाराज थीं। ऐसे में राजमाता ने भी 1984 का लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ने की बात कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे ही राजमाता के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की भनक लगी वो सीधे ग्वालियर आकर राजमाता से मिले और कहा कि मैं कोटा की जगह ग्वालियर से चुनाव लड़ूगा।अटल जी ने ये प्रस्ताव भावुकता में किया था ,उन्हें क्या पता था कि उनका ये फैसलना आत्मघाती साबित होगा। माधवराव सिंधिया ने उन्हें करीब पौने दो लाख वोटों से हराया था। भाजपा 1984 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में थी। जिसके लिए पहले कोटा और बाद में ग्वालियर सीट पर विचार किया गया,अंत में ग्वालियर सीट से उनका नाम फाइनल किया था क्योंकि ये सीट राजमाता के प्रभाव वाली सीट थी। मजे की बात ये है

कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर से चुनाव लड़ने से पहले माधवराव सिंधिया से पूछा था कि आप ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ? दोनों के रिश्ते बहुत मधुर थे। माधवराव सिंधिया ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे तो गुना से चुनाव लड़ते हैं। ग्वालियर से क्यों लड़ेंगे ?। लेकिन ऐन मौके पर जब राजीव गांधी ने माधवराव सिंधिया की सीट बदल दी तो खुद माधवराव सिंधिया अवाक रह गए। 1984 -85 में अटल बिहारी वाजपेयी वैसे तो माधवराव सिंधिया की उम्मीदवारी सामने आते ही आधा चुनाव हार गए थे ,लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। पांव में तकलीफ के बाद भी वे प्लास्टर बांधकर चुनाव प्रचार करते rh। भाजपा के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अटल जी कि ऊँट पल पर हुई सभा में बम रखे होने की अफवाह उड़ाई और एक नारियल छिपकर रख दिया लेकिन हवा को नहीं बदलना था ,सो नहीं बदली। अटल जी मन मारकर गलीई-गली चुनाव प्रचार करते रह। खुद राजमाता ने सार्वजनिक रूप से अटल जी का प्रचार किया लेकिन उनका दिल आपने बेटे की जीत के लिए धड़क रहा थ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी राजमाता के मन की बात सुनी और अटल जी का साथ छोड़ दिया। अटल जी को चुनाव है=रना था सो चुनाव हार गए। चुनाव परिणामों की अंतिम घोषणा से पहले ही अटल जी ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत में एक खीज भरी मुस्कराहट बिखेरते हुए कहा कि - ग्वालियर से चुनाव लड़कर मैंने मां -बेटे की लड़ाई को महल तक सीमित रहने दिया। उसे सड़क पर नहीं आने दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अटल जी ने कहा था कि- अगर मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ता तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ राजमाता चुनाव लड़ जाती और मैं यही नहीं चाहता था। आपको याद होगा कि राजमाता में राजहठ बहुत था। इससे पहले वे पार्टी के मना करने के बावजूद रायबरेली से इंदिरा गाँधी के खिलाफ चुनाव लड़कर हार चुकी थी।भाजपा कि सिंधिया परिवार के प्रति भक्ति अटल जी की हार का कारण बनी । कांग्रेस ने जब माधवराव सिंधिया को कांग्रेस से बाहर कर दिया था उस समय भी भाजपा ने सिंधिया को ग्वालियर से वॉक-ओव्हर देते हुए अपने प्रत्याशी को मैदान से हटा लिया था,वो भी केवल राजमाता की वजह से। 1984 -85 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता माधवराव सिंधिया के समर्थन में रैली की थी। ये उनकी पहली रैली थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र मात्र 14 साल थी। उन्होंने अपनी मां के साथ अपने माधवराव सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार किया था। वहीं, राजमाता ने चुनाव प्रचार में केवल एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एक ओर पूत है, दूसरी ओर सपूत।

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, सोमवार 15 अप्रैल 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

दिवास्वप्न जैसा भाजपा का घोषणापत्र

आम चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है और उससे ठीक पांच दिन पहले अंबेडकर जयंती पर सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र पेश किया। यूं तो 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर बैठी भाजपा को अपने 10 साल के काम दिखाकर ही जनता से वोट मांग लेने चाहिए थे। अलग से घोषणाएं करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने अच्छे दिनों का वादा जनता से किया था। अगर अच्छे दिन 2014 से शुरु हो चुके थे, तो उन्हें 2024 में भी जारी रहने दिया जा सकता था। लेकिन हकीकत क्या है, ये भाजपा भी अच्छे से जानती है और अब जनता भी समझने लगी है। इसलिए भाजपा को अपना संकल्प पत्र नाम का घोषणापत्र जारी करना पड़ा। जिसमें महंगाई या बेरोजगारी पर कोई बात नहीं की गई, अलबत्ता मोदी की गारंटी जैसी शब्दावली के साथ नयी घोषणाओं को पेश किया गया है।

कांग्रेस का घोषणापत्र न्यायपत्र के नाम से जारी किया गया है और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ज्ञान का ज़िक्र किया है। जी वाय ए एन का विस्तार हुआ, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। भाजपा की यह ज्ञान वाली कोशिश कांग्रेस के आगे बचकानी ही नजर आई। क्योंकि भाजपा अगर 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए नए वादे कर रही है, इसका मतलब यही हुआ कि 10 सालों में इन वर्गों के उत्थान में भाजपा सफल नहीं हो पाई है।

भाजपा ने 2014 में सत्ता में आने के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार, हर खाते में 15 लाख जैसे वादे किए थे, फिर 2022 तक किसानों की दोगुनी आय की बात कही थी, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी के सपने लोगों को दिखाए थे। और भाजपा की सत्ता के साल गुजरने के साथ ही ये तमाम बातें जुमलेबाजी में बदल गईं। हल्की-फुल्की चर्चा और मस्ती-मजाक में किसी पर जुमलेबाजी करने, ऊंची-ऊंची हांकने, मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाने जैसी बातें स्वीकार्य हो सकती हैं, लेकिन जब इनका असर देश पर होने लगे तो यह हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी है कि वह संभल जाए।

भाजपा के 10 सालों में गंगा नदी साफ नहीं हुई, बल्कि इस दौरान काशी विश्वनाथ से लेकर महाकाल तक कई मंदिरों में कॉरिडोर बनाकर उन्हें आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया। उत्तराखंड में हिमालय में पड़ रही दरारों को अनदेखा कर ऑल वेदर रोड जैसी परियोजनाएं शुरु हो गईं। एक साल तक किसानों को आंदोलन पर बैठना पड़ा, अब भी किसान आंदोलनरत हैं, इस बात को भुलाकर किसानों के उत्थान के नए वादे हो रहे हैं। मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों तक नारी उत्पीड़न के कई गंभीर मामलों को अनदेखा कर नारी शक्ति की बात की जा रही है। बुलेट ट्रेन अब तक नहीं चली, अब नयी वंदे भारत की बात होने लगी है और ओडिशा में हुई बड़ी रेल दुर्घटना के दोषियों को कब सजा मिलेगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती टिकट की व्यवस्था क्या फिर से शुरु होगी, इस पर कोई बात नहीं की जा रही। 45 सालों में बेरोजगारी के आंकड़े क्यों बढ़े, इसका कोई जवाब न देकर पकौड़ा रोजगार का विकल्प मोदी सरकार ने पेश किया था, अब सरकार रोजगार की बात ही नहीं कर रही और युवाओं को लुभाने के लिए पेपरलीक पर कड़े कानून की बात कर रही है। पेपर तो पिछले 10 सालों में कई बार लीक हुए, तो अब तक सरकार ने कोई कानून क्यों नहीं बनाया, ये सवाल भाजपा से पूछा जाना चाहिए।

सरकार का दावा है कि उसने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन ये बात सच है तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज योजना का सच क्या है। क्या लोग इसी तरह 5 किलो अनाज के मोहताज बनकर अपने स्वाभिमान को छोड़कर केवल सांस लेते रहने के लिए जिंदा रहेंगे। क्या श्री मोदी 2047 के विकसित भारत में ऐसे ही जिंदा लोगों का देश बनाना चाहते हैं।

भाजपा के घोषणापत्र में एक नया शिगूफा 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का छोड़ा गया है। ओलंपिक की मेजबानी शायद ही किसी देश में चुनाव का मुद्दा बना हो, श्रीमान नरेन्द्र मोदी ने इस बात को भी मुमकिन कर दिखाया है। ओलंपिक किस देश में होंगे, यह तय करना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों का काम है, और समिति किसी पार्टी नहीं, बल्कि देश के हालात देखकर उसका चयन करती है। अभी 2032 तक की मेजबानी तय हो चुकी है, मगर श्री मोदी ने 2036 की बात अपने घोषणापत्र में कर दी है। मानो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत को नहीं भाजपा को ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुनेगी। भाजपा के घोषणापत्र में ओलंपिक की मेजबानी का ज़िक्र ठीक वैसा ही है जैसे 15-15 लाख हर खाते में डालने की बात थी। तब लोगों को ये आसान गणित समझाया गया था कि स्विस बैंकों में रखा हुआ काला धन मोदीजी देश में ले आएंगे और उसे फिर सारे लोगों में बांट देंगे। अभी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प.बंगाल में पकड़ी गई अवैध धनराशि के भी इसी तरह वितरण की बात श्री मोदी ने कही है। लोगों को यह सुनकर ही अच्छा लगता है कि बैठे-ठाले उन्हें लाखों की रकम मिल जाएगी। मगर 10 सालों में लोगों को नोटबंदी, जीएसटी और बैंकों के दिवालिया होने या बड़े कर्जदारों के देश से भाग जाने पर लाखों का चूना लग चुका है।

भाजपा के घोषणापत्र में इन भगोड़ों को वापस लाने की कोई बात नहीं है, बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने, छोटे और लघु व्यवसायियों को राहत मिलने, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और नए सार्वजनिक निकायों को स्थापित करने की कोई बात नहीं है। केवल सुनहरे ख्वाबों को नए सिरे से दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जनता अब शायद दिन में सपने देखने से मना कर दे।

मुकाबला : कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाम भाजपा का घोषणा पत्र

अभी जो पहली निगाह में दिखा वह है भाजपा के घोषणा पत्र में हर पेज पर मोदी जी का फोटो। कितने होंगे गिनना पड़ेगा। 50 से ऊपर तो होंगे। फोटो के मामले में तो कांग्रेस के घोषणा पत्र से बहुत आगे है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो राहुल के तीन चार फोटो होंगे। और वह भी साथ में। अकेला तो कोई दिखा नहीं। बाकी मोदी जी के फोटो में तो कोई उनके साथ फ्रेम में आ ही नहीं सकता। सारे फोटो एकल होते हैं।

और बाकी क्या तुलना करें! कांग्रेस की 30 लाख सरकारी नौकरियों का जवाब तो भाजपा के घोषणा पत्र में कहीं दिख नहीं रहा। न महंगाई की बात। न शिक्षा फ्री करने की बात। घोषणा पत्र शुरू ही मोदी जी के देश के नाम संदेश से होता है। जिसमें वे 23 साल बाद की बात 2047 की कर रहे हैं। दस साल में लाखों युवा ओवर एज हो गए। और 2047 तक वे भी हो जाएंगे जो अभी टीन एज (किशोरावस्था) में आ रहे हैं या आए ही हैं।

लेकिन जो भी हो यह मुकाबला अच्छा है। घोषणा पत्र बनाम घोषणा पत्र का। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने देश में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी थी। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक करोड़ रोजगार की बात करके उस उम्मीद को और परवान चढ़ा दिया। इससे पहले बिहार में सरकार में रहते हुए तेजस्वी यह कारनाम कर चुके थे। लाखों शिक्षकों को नौकरी देने का। इसलिए उनका केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर नौकरियों को प्राथमिकता देने के वादे का युवाओं और उनके माता-पिताओं पर गहरा असर हुआ। अब लग यह रहा था कि कांग्रेस आरजेडी इन सबका जवाब देने के लिए मोदी जी नौकरियों का खजाना वैसे ही खोल देंगे जैसे उन्होंने अडानी-अंबानी के लिए सरकार के खजाने खोल दिए हैं।

मगर 76 पेज के संकल्प पत्र में, जाहिर है कांग्रेस के 46 पेज के न्याय पत्र से ज्यादा पेज का निकालना था, युवाओं को नौकरी देने की गारंटी ढूंढे नहीं मिल रही है।

एक चेप्टर है युवाओं को अवसर मोदी की गारंटी। मगर उसमें सरकारी नौकरी का कहीं जिक्र नहीं दिख रहा है। एक उप शीर्षक है- पारदर्शी सरकारी भर्तियां। मगर उसमें सरकारी नौकरी कितनी और कब देंगे के बदले पेपर लीक नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाने की की बात है। और पारदर्शी सरकारी परीक्षाओं की।

अभी तक यह दोनों काम क्यों नहीं किए इसका कोई कारण नहीं बताया है। युवाओं से हर वादा ऐसा है कि अभी और जीते होते यही इंतजार होता। 2014 में मोदी जी आए थे। उस समय जो युवा था वह दस साल से इंतजार कर रहा है। अब इस घोषणा पत्र में उससे कहा है 2047। मतलब 2014 के 33 साल बाद का नक्शा। तब तक 2014 का युवा वरिष्ठ नागरिक हो चुका होगा। शायद इसलिए वह वरिष्ठ नागरिकों वाला चेप्टर ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा है।

मोदी जी ने भी युवाओं के ठीक बाद अगले पेज पर ही वरिष्ठ नागरिकों को वरियता मोदी की गारंटी शीर्षक से चेप्टर लगाया है। 2014 से पहले वह पढ़ा-लिखा। 14 के बाद नौकरी का इंतजार करता रहा और फिर 2047 में विकसित भारत बनेगा पढ़कर वह वरिष्ठ नागरिकों के चेप्टर में अपना भविष्य देखने लगा है।

शकील अख्तर

> देखना युवा को ही है कि उसे क्या करना है। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र के शुरू में ही एक सवाल पूछा है। सवाल है कि क्या आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है? भाजपा के घोषणा पत्र आने के बाद युवाओं को इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए। क्या वह 2047 तक इंतजार करेगा? 2014 में जिस की औसत आयु 27 वर्ष थी। वह 2047 में 60 वर्ष का हो जाएगा। परफेक्ट सीनियर सिटीजन।

मजेदार है। देखना युवा को ही है कि उसे क्या करना है। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र के शुरू में ही एक सवाल पूछा है। सवाल है कि क्या आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है? भाजपा के घोषणा पत्र आने के बाद युवाओं को इस सवाल का जवाब खोजना चाहिए। क्या वह 2047 तक इंतजार करेगा? 2014 में जिस की औसत आयु 27 वर्ष थी। वह 2047 में 60 वर्ष का हो जाएगा। परफेक्ट सीनियर सिटीजन। ढूंढे कि उस उम्र के क्या-क्या लाभ मिलते हैं। वैसे बता दें कि सीनियर सिटीजन को मिलने वाले रेल यात्रा कंसेशन को मोदी सरकार बंद कर चुकी है। और न केवल बंद कर चुकी है बल्कि इसका फायदा भी देश को यह कहकर बता चुकी है कि वरिष्ठ नागरिकों के रेल किराए में छूट खत्म करके हमने 5800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए भी।

मतलब वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता उनसे भी पैसे छीने। और इसे गर्वपूर्वक अपनी कमाई बता रहे हैं। यह ऐसा ही है जैसे घर में वृद्ध माता-पिता की दवाइयां बंद करके या उनके खाने-पीने में से दूध, दही, घी, फल, सब्जी निकालकर कहा जाए हमने इतने पैसे कमाए! 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहे युवाओं को यह देख लेना चाहिए उस समय जो वे वरिष्ठ नागरिक हो चुके होंगे तो उनके लिए क्या होगा। युवावस्था में नौकरी नहीं और वृद्धावस्था में उनके खाने-पीने, दवाइयों से कटौती करके कमाई! इसलिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पूछा है कि क्या जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है? दें युवा जवाब। और बाकी सब भी दें।

चुनाव है। मौका है। मुंह से बोलने से डर लगता है तो वोट से दें। जवाब दें कि क्या 2014 से पहले जो पढ़ाई-लिखाई की वह 14 के बाद काम आई? या आगे जैसा बीजेपी बता रही है उसकी 2047 तक की योजना उसमें कोई भविष्य की संभावना दिख रही है?

बहुत बढ़िया है। दो प्रमुख पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र का मुकाबला। जनता देखे। युवा देखें। किस ने कितनी नौकरी, रोजगार का वादा किया है। सरकारी शिक्षा का वादा है। नि:शुल्क। भूमिहीनों को जमीनों का वादा है। किसानों को मजदूरों को महिलाओं को किसके लिए क्या ठोस घोषणा है और किसने क्या शब्द जाल फैलाते हुए सब्ज बाग दिखाए हैं।

मोदी जी ने तो बोल दिया कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। हड़कम्प मचा दिया। क्या देश में क्या विदेश में हर आदमी कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ने लगा। 46 पेज का है। एक-एक पेज पढ़ डाला। एक-एक शब्द। कहीं मुस्लिम लीग नहीं मिला। युवा, किसान, महिला, मजदूर, आम जनता, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी मध्यमवर्ग ही मिलता चला गया। उसी के हितों की बातें मिलती चली गईं। मोदी जी ने यह क्या कर दिया। कांग्रेस के न्याय पत्र को एकदम हिट कर दिया। गरीब कमजोर युवाओं में लोकप्रिय। जो पढ़ना नहीं जानते वे भी वीडियो देख-देख कर सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग कहीं मिलता नहीं। उनके मतलब की सारी बातें मिलती हैं। उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात। उनके लिए मुफ्त सरकारी इलाज की बात। जमीन की बात। कर्ज माफी की बात। रोजगार की बात।

मोदी जी ने यह क्या कह दिया। अब उनका घोषणा पत्र आ गया। वह भी पढ़ते हैं। सुनते हैं। मगर नौकरी की बात तो कहीं मिल नहीं रही। महंगाई कम करने की बात भी नहीं। हां बुलेट ट्रेन के विस्तार की बात है। हैं न चौंकने वाली बात। बुलेट ट्रेन है कहां? जो इसका विस्तार होगा। मजेदार है। चुनाव इसी पर होना चाहिए। टीवी वालों डिबेटें शुरू कर दो। कांग्रेस का न्यायपत्र और भाजपा का संकल्प पत्र!

अगर यह हो गया दोनों के घोषणा पत्रों पर अखबारों और टीवी में बहस हो गई तो बड़ी मजेदार चीजें निकलकर सामने आएंगी। पहली तो यह कि फोटो के मामले में राहुल बुरी तरह हारेंगे। अभी किसी ने गिन कर बताया मोदी जी के 55 फोटो हैं। राहुल के 5 भी नहीं। दूसरे मोदी की गारंटी हैं। कांग्रेस राहुल का न्याय कह ही नहीं पाई। तो मोदी में राहुल कहीं मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बस मीडिया को ध्यान यह रखना है कि नौकरी, बेरोजगारी, मंहगाई की बात न होने पाए। इन पर भाजपा के घोषणा पत्र में कुछ नहीं मिलेगा। यहां एंकरों को एकदम स्पष्टवादी बनना होगा। साफ कह देना होगा नौकरी, युवा, जनता, महंगाई कोई इशु नहीं। इशु है मुस्लिम लीग। और वह कांग्रेस के न्याय पत्र में कहां है। यह हम ढूंढ रहे हैं। और यकीन मानिए ढूंढ कर मानेंगे। मोदी जी ने कहा है तो है। उनकी दूसरी गारंटियों की तरह यह भी गारंटी है। जैसे बाकी गारंटी पूरी होंगी। यह भी होगी। आज नहीं तो कल। कल नहीं तो 2047 में। नहीं तो मोदी जी ने एक हजार साल की बात भी कही है। तब। हम बताएंगे ढूंढ कर कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का जिक्र। हां, मगर हमसे यह उम्मीद मत कीजिए कि हम बीजेपी के घोषणा पत्र में से नौकरी, बेरोजगारी और महंगाई की बात ढूंढ कर बता दें। वह संभव नहीं है। रेत में सुई ढूंढने को कहेंगे तो वह भी ढूंढ सकते हैं। मगर भाजपा के घोषणा पत्र में नौकरी नहीं!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है)

सर्वोच्च न्यायालय चुनाव तक विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर लगाए रोक

■ नित्य चक्रवर्ती

इसमें थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत में केवल छह दिन बचे हैं, लेकिन अब भी समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाकर विपक्ष के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करे। वर्तमान में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित छापे मारे जा रहे हैं।

लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया एक जून तक चलेगी। सात चरणों में मतदान पूरा होने में अभी छह हफ्ते बाकी हैं। अब तक, सत्तारूढ़ भाजपा ने न केवल विपक्षी दलों, विशेषकर मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी कांग्रेस के वित्तीय संसाधनों को कमजोर करने के लिए अपनी तीन केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया है, बल्कि इसने प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं के चुनाव प्रचार अभियान को भी उन्हें ईडी, सीबीआई आदि केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा सम्मन जारी करबाधित किया जा रहा है। विशेषकर ईडी विपक्ष से भाजपा के पक्ष में दलबदल कराने के लिए सत्तारूढ़ दल के मुख्य हथियार के रूप में काम कर रही है।

> किसी भी राजनीतिक दल के साथ अपनी गैर-संबद्धता और 'भारत के संविधान में निहित आदर्शों' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाना शुरू किया। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी गिरफ्तारी तब की जब आदर्श आचार संहिता लागू थी।

यह एक विषैली स्थिति है और किसी भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय को 18वीं लोकसभा चुनावों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी और आदेश देना होगा कि विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी सभी गतिविधियां चुनाव के आखिरी दिन 1 जून तक निलंबित करना होगा ताकि चुनाव मैदान में समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके। एजेंसियां अपने कार्यों की निगरानी करना जारी रख सकती हैं लेकिन विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कुछ विशिष्ट कार्रवाई की है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनाव खत्म होने तक टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी समन नहीं कर सकती है। इसी तरह, कोर्ट के कहने पर आईटी विभाग ने बकाया और जुर्माने की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव के अंत तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। ये विशिष्ट हस्तक्षेप हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब सामान्य हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि ईडी या आईटी विभाग निचली अदालतों की मदद से अपने कार्यों को अंजाम न दे सकें।

11 अप्रैल को, 87 सेवानिवृत्त उच्चाधिकारियों के एक समूह, जिन्होंने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में सेवा की, ने आम चुनाव से पहले समान अवसर की चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा। हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। यद्यपि यह पत्र ईसीआई के लिए है, यह शीर्ष न्यायालय द्वारा विचार किये जाने के लिए अधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह संविधान को प्रभावित करने वाले व्यापक क्षेत्रों से संबंधित है।

किसी भी राजनीतिक दल के साथ अपनी गैर-संबद्धता और 'भारत के संविधान में निहित आदर्शों' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए, हस्ताक्षरकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाना शुरू किया। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी गिरफ्तारी तब की जब आदर्श आचार संहिता लागू थी।

पूर्व उच्चाधिकारियों ने 'आम चुनाव के दौरान विपक्षी दलों और विपक्षी राजनेताओं के उत्पीड़न और उन्हें परेशान करने वाले पैटर्न' पर भी चिंता जताई और कहा कि 'यह एजेंसियों की प्रेरणा पर सवाल उठाता है'।

उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग की पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई और विपक्षी नेताओं को नोटिस के बारे में भी आपत्ति व्यक्त की।

यह हैरान करने वाली बात है कि आयकर विभाग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों के पुराने आकलन को फिर से क्यों खोलना चाहिए, वह भी आम चुनाव की पूर्व संध्या पर। पत्र में कहा गया है कि इस समय लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा से संबंधित परिसरों की तलाशी लेना और अन्य विपक्षी उम्मीदवारों को नोटिस जारी करना भी समझ से परे है।

सूत्रों की मानें तो तीन सदस्यीय ईसीआई ने भारतीय नेताओं द्वारा भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लगाये गये आरोपों की सत्यता पर चर्चा की। चुनाव आयोग का नवीनतम विचार यह है कि आयोग के पास किसी भी चल रही जांच में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों को एडवाइजरी जारी करने की बात हुई थी, लेकिन वह विचार भी छोड़ दिया गया। इसलिए, विपक्षी दल ईसीआई से किसी प्रभावी हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बल्कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों को कोई सलाह जारी कर सकता है।

इससे पहले भी, सर्वोच्च न्यायलय ने मणिपुर में जातीय दंगों के दौरान और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोविड काल के दौरान की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। अप्रैल 2024 में, सर्वोच्च न्यायलय ने तीन केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई से दूर रहने के लिए कड़ी सलाह जारी करने में हस्तक्षेप करके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करने का दावा कर सकता है। इस साल 15 फरवरी को 2017 इलेक्टोरल बॉन्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करके सीजेआई डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय लोकतंत्र में समान अवसर प्रदान करने की बड़ी सेवा की। इसी भावना से, विद्वान सीजेआई तीन केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों में नवीनतम का आकलन कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

पावन प्रसंग

सफलता के सूत्र

सफलता हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन चाहते हुए भी अधिकांश में एक सफल जीवन नहीं जी पाते जिसमें बाहरी उपलब्धियों के साथ जीवन में सार्थकता का बोध भी हो। इसी विषय पर अमेरिकी लेखक स्टीफन कॉवे की पुस्तक सेवेन हेबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, प्रखर मार्गदर्शन करती है। व्यक्तिगत, सामाजिक तथा पेशेवर जीवन में सफलता को सुनिश्चित करने वाली इस पुस्तक में सात आदतों की चर्चा की गई है, जो हर प्रभावशाली व्यक्ति में पाई जाती है। पुस्तक में पूर्वी एवं पश्चिमी चिंतन के ज्ञान सार को समेटते हुए लेखक ने अपने सफल व्यावसायिक जीवन के अनुभवों को साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है।

पहले चरण की आदत है, वो प्रोएक्टिव अर्थात अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें और अपने समय व ऊर्जा को उन क्षेत्र में केंद्रित करें, जो आपके भावक्षेत्र में आती हों। भविष्य में जो चुनौतियां आ सकती हैं जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है,जिस तरह का उज्जवल भविष्य आप देखना चाहते हैं, इनके अनुरूप वर्तमान रणनीति पर विचार प्रोएक्विक्टव की आदत में शामिल है, जिससे कि हम वर्तमान कर्मों को ऐसा स्वरूप देते हैं कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्व से ही तैयार होते हैं, जिससे भविष्य में इच्छानुकूल अपेक्षित परिणाम आ सकें।एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने लिए आवश्यक हो जाता है कि हम अपने व्यक्तित्व व जीवन के हर आयाम से अधिकाधिक परिचित हों तथा उन चीजों के प्रति जागरूक हों, जिन्हें हम अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। बदल सकते हैं, न कि उन चीजों पर, जो हमारे प्रभावक्षेत्र से बाहर हैं व जिन्हें हम बदल नहीं सकते।

दूसरा चरण है, बिगिन विद दि एंड इन माइंड अर्थात अपनी रुचि, क्षमता, संभावना तथा स्थिति को देखते हुए अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। यह अपने जीवनलक्ष्य से जुड़ी आदत है। हमारा जीवनलक्ष्य कितना स्पष्ट है,एक मिशन स्टेटमेंट के रूप में क्या यह परिभाषित है, जिसमें आपका जीवन-दृष्टिकोण परिलक्षित होता हो। यह मायने रखता है और एक प्रभावशाली जीवन का निर्णायक तत्व रहता है। लक्ष्य स्पष्ट न होने पर जीवन के प्रति रवैया भी ढुलमुल रहता है, व्यक्ति के प्रयास आधे-अधूरे व शिथिल रहते हैं तथा जीवन में कहने योग्य सफलता अर्जित नहीं हो पाती, क्योंकि जीवन की शक्तियां इधर-उधर बिखरी रहती है।

इसी आधार पर आप अपने जीवन की नैया के खेवनहार की भूमिका में आ जाते हैं, अपने जीवन की पटकथा के लेखक की भूमिका में स्वयं को खड़ा पाते हैं। आप अपने भाग्य विधाता स्वयं बनते हो। प्रोएक्टिव माइंडसेट या मन:स्थिति के यह जीवन बोध मिलक सुनिश्चित करते हैं कि आप जो भी निर्णय लेंगे, वे आपके अपने जीवन के साथ मेल खा रहे हैं जैसा कि आप बनना चाहते हैं और आप अपने जीवन के लिए स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं।

तीसरे चरण की आदत है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट,, अर्थात यह समय प्रबंधन से जुड़ा पहलू है। यहां निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करना होता है। इस चरण में अपने विजन को वास्तविकता में रूपांतरित किया जाता है और इसके अनुरूप उचित निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए अपने जीवन में महत्वपूर्ण, गैरमहत्वपूर्ण तथा आवश्यक व गैर आवश्यक कारकों की पहचान आवश्यक हो जाती है, साथ ही तात्कालिक चीजों को कैसे निपटाया जाना है, स्टीफन कॉवे के अनुसार, इसका अभ्यास व्यक्ति के इमोशनल बैंक एकाउंट को समृद्ध करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अधिक भावप्रवण बनता है और उसके व्यक्तित्व की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता में इजाफा होता है, जो सामूहिक एवं सामाजिक स्तर पर सफल जीवन का एक निर्णायक आधार रहता है।

युग निमाण योजना

आपके पत्र

भाजपा के मेनिफेस्टो में गरीब और मध्यम वर्ग आम जनता को सीधा फायदा

भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी के नाम का मेनीफेस्टो जारी किया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी है। हर वर्ग और हर व्यक्ति को लाभकारी योजनाओ का फायदा देने के लिए श्री मोदी संकल्पित हैं। हर व्यक्ति को सुखी करने का वादा किया है। मेनिफेस्टो में 70 साल के बुजुर्गों के लिए पांच लाख का मुफ्त इलाज की घोषणा की है। दस साल की कामयाबी और हर व्यक्ति हर गांव और हर तहसील के लोगों को दस साल के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया है। वीडियो जारी कर केंद्र की लाभदायक योजनाओं को हर घर पहुंचाया है। उसको साझा किया है। मुफ्त राशन योजना 2029 तक जारी रखने और हर घर को नल से जल की योजना शुरू करने का वादा किया गया है। भाजपा एवं एनडीए जनता को हर तरह का लाभ देने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार यूसीसी लाने का वादा किया है। तीन करोड़ गरीब लोगों को पक्के मकान देने का वादा मेनिफेस्टो के संकल्प पत्र में किया गया है। नतीजे आने के बाद काम शुरू हो जाएगा और सौ दिन के भीतर नई सरकार कार्य को अंजाम देने की तैयारी कर चुकी होगी। जनता की महत्वाकांक्षा ही मोदी जी का मिशन है। भारत को बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प एनडीए ने लिया है। उस पर तेजगति से काम हो रहा है। 20 लाख रुपए लोन की सीमा का प्राविधान है। सीएए लागू करने एवं यूसीसी की कवायद शुरू की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। फसलों में एमएसपी में वृद्धि की मंशा है। बुलेट ट्रेन पूर्व पश्चिम और उत्तर की तरफ योजना का विस्तार किया जाने वाला है। राममन्दिर धारा 370 तीन तलाक सीएए महिला आरक्षण जैसे बिलो को लागू किया गया है। नारी शक्ति अधिनियम भाजपा की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। भारत उभरते सेक्टर का भागीदार बन रहा है। वंदे भारत ट्रेन का विस्तार और देश के हर कोने में बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान है। कल्चर और टुरिज्म बढ़ाने की योजना है। मेनिफेस्टो में कांग्रेस की चार बड़ी योजनाओं से आम जनता का कोई उचित फायदा दिखाई नहीं दे रहा है।

देश मे केंद्र सरकार की योजनाओं का असर हावी

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल चुका है और अभी योजनाएं लागू हैं उसका फायदा गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाने में भाजपा युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में इन्हीं योजनाओं को आगे रखकर भाजपा मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। देश में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए भाजपा ने कमर कस रखी है। जल जीवन मिशन, नल से जल योजना, गैस सिलेंडर और आवास योजनाओं का लाभ सीधा लोगों के खातों में जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे मूलभूत सुविधाओं पर आधारित है। देश की तरक्की और विकास की बुलंदियों को छूने वाली इन योजनाओं से आम आदमी लाभान्वित हुआ है। जम्मू- कश्मीर से 370 की धारा हटने और सरकार विकास को आगे रखकर चुनाव में अपना पक्ष रख रही है। कश्मीर की जनता अमनपरस्त है। हर घर तक सुविधा मुहैया कराने का प्रयास हो रहा है इस पर काम भी हो रहा है। भाजपा ने विकास का मुद्दा बनाया है तो दस साल में भाजपा ने किए गए कार्यो को भी भुनाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस फिर से जनाधार खो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पांच फेज में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने चाकचौबंद व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने पिछले दिनों दिये अपने भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र नहीं है। यह एक मस्तक है यह कह कर सम्मान दिया। पांच सीटों वाले जम्मू-कश्मीर में भाजपा मैदान मारने की तैयारी में है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना जम्मू-कश्मीर की पहली सबसे अहम योजना है जिसको लेकर जनता आतुर है और 93 प्रतिशत लोगों ने कार्ड बनाया हुआ है।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

भारत-चीन संबंध

सकारात्मक संकेत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार के माध्यम से दिए शांति संकेतों पर चीन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों में स्थायित्व आएगा। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच संबंध बनाने में अक्सर राजनयिक बयानबाजी, रणनीतिक दृष्टिकोण तथा कभी-कभी तनाव घटाने वाले बयानों का विशेष महत्व होता है। हाल ही में दुनिया के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों-भारत और चीन ने यही किया। सीमा की स्थिति पर की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी पर चीन की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। 'न्यूज़वीक' पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा पर वर्तमान स्थिति को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने आशा प्रकट की कि रचनात्मक संवाद के माध्यम से शांति और सद्भाव बहाल किया जा सकता है। इसकी प्रतिक्रिया में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 'गहरे और स्थाई' संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए क्षेत्रीय शांति एवं विकास में परस्पर हितों को रेखांकित किया। इस प्रतिक्रिया से सीमा पर तनाव के बावजूद भारत के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने की चीन की प्रतिबद्धता प्रकट होती है। माओ निंग के बयान में सीमा मुद्दे को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के ढांचे में रखा गया है। सीमा समस्या का महत्व रेखांकित करते हुए सुश्री निंग ने जोर दिया कि यह समग्र रूप से भारत-चीन संबंधों पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। यह दृष्टिकोण चीन द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन के प्रति लक्षित है जिसमें मतभेदों से बाहर निकलने के लिए संवाद, सहयोग तथा रणनीतिक सोच को महत्व दिया गया है।

इन बयानों की पृष्ठभूमि में मई, 2020 में पैगोंग सो के निकट हिंसक झड़प के बाद सीमा पर व्याप्त गतिरोध है। डीजीपी सम्मेलन में साझा किए एक शोधपत्र से खुलासा हुआ है कि 65 निगरानी बिंदुओं में से 26 तक पहुंच विवादास्पद है। इसके साथ ही लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर परस्पर विरोधी दावे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। जून, 2020 में भारत और चीन ने गलवान घाटी के निगरानी बिंदु 14 से अपने सैनिक हटा लिए थे। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पैगांग सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से फरवरी, 2021 तथा इसी साल अगस्त में गोगरा चौकी के निकट निगरानी बिंदु 17ए से तनाव घटाने के प्रयास हुए। लेकिन कार्पर्स कमांडरों की अनेक बैठकों के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विवाद अब भी बना हुआ है। भारत ने कुछ क्षेत्रों जैसे डेपसांग व देमचोक से तनाव समाप्त करने पर जोर दिया है। इससे एक समग्र समाधान की दिशा में आ रही चुनौतियां स्पष्ट हैं। भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध न केवल दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसका सीमावर्ती क्षेत्रों तथा सारी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक महाशक्ति और नाभिकीय शक्ति संपन्न देशों के रूप में वे अपने मतभेद दूर कर स्थाई संबंध विकसित करने में सक्षम हैं जो क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य बनाने का रास्ता संभवत: निरंतर संवाद, विश्वास बहाली उपायों तथा व्यावहारिक समझौतों से निकल सकता है। हालांकि, इस मार्ग में अनेक बाधायें हैं, पर दोनों देशों के साझा हित एक ऐसा आधार बनाते हैं जिस पर स्थाई व रचनात्मक संबंधों की नीव डाली जा सकती है। भारत इसके साथ ही अपनी रक्षा तैयारियां व सीमा पर ढांचागत संरचना मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है।

अंबेडकर: न्याय व समानता के अग्रदूत

भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर ने सभी नागरिकों के लिए मूलाधिकारों तथा संरक्षणों का आधार तैयार किया था।

बंडारू दत्तात्रेय
(लेखक, हरियाणा के राज्यपाल हैं)

भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर ने सभी नागरिकों के लिए मूलाधिकारों तथा संरक्षणों का आधार तैयार किया था। भारत रत्न डा. भीमराव अंबेडकर का जन्त 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। उनको हमेशा एक न्यायोचित व समावेशी भारत निर्माण में योगदान के लिए याद किया जाएगा। वे सामाजिक न्याय के संरक्षक अग्रदूत तथा समावेशन, न्याय व समानता के मसीहा थे। प्रख्यात न्यायविद, अर्थशास्त्री तथा समाज सुधारक के रूप में डा. अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने तथा हमारे देश के हाशियाकृत वर्गों की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने देश के सभी नागरिकों के लिए मूलाधिकारों तथा संरक्षणों को सुनिश्चित किया था। आज भी डा. अंबेडकर की विरासत दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। वे दुनिया भर में गरिमा और समानता के लिए संघर्ष करने वाले वंचित समुदायों के लिए आशा की किरण बने हुए हैं। हम उनके जीवन तथा सामाजिक न्याय के उनके दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख कर स्वयं को अनुप्राणित कर सकते हैं।

बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का आधार समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धान्त हैं। बाबा साहेब ने अपने आसपास के जीवन से भारतीय समाज में गहराई तक व्याप्त असमानताओं की पहचान की और उनको समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने खासकर भारतीय समाज में सैकड़ों सालों से व्याप्त 'जाति व्यवस्था' का गंभीर विश्लेषण किया जो करोड़ों लोगों के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न का कारण बनी हुई थी। जाति व्यवस्था ने कृत्रिम रूप से कुछ लोगों को जन्म से ही श्रेष्ठ व सक्षम तथा बहुत से अन्य लोगों को अक्षम व निचली श्रेणी का घोषित कर दिया था। जाति व्यवस्था के कारण पैदा ऊंचनीच ने भारतीय समाज को अत्यधिक प्रभावित किया बा। इसने करोड़ों लोगों को भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार बनाया था।

डा. अंबेडकर ने 'अशपृश्यता उन्मूलन' के लिए निरंतर संघर्ष किया जो मूल रूप से वैदिक शिक्षाओं के विरोध में थी। अशपृश्यता का कारण बनने वाली अत्याचारी जाति-व्यवस्था ने उनको भीतर तक झकझोर दिया था। डा. अंबेडकर ने अपने लेखों, पुस्तकों और भाषणों से लगातार हिंदू समाज की विकृतियों की ओर संकेत किया जिनका कोई पौराणिक या वैदिक आधार नहीं था। अपने अनेक प्रयासों को समुचित सफलता मिलते न देख कर उन्होंने हिंदू समाज को झटका देने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म गहराई से भारतीय विचार पद्धति तथा मूल्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। अंबेडकर 'हिंदूवाद' या हिंदुत्व के दुश्मन नहीं थे। उन्होंने हिंदूवाद की अनेक विकृतियों का विरोध किया, पर उन्होंने उचित भावना वाले हिंदुत्व का विरोध नहीं किया था। हालांकि, इस्लामी व ईसाई विद्वानों ने उनको प्रभावित करने के बहुत प्रयास किए, पर उन्होंने कोई अन्य विजातीय धर्म स्वीकार नहीं किया।

बहुत गरीब परिवार में जन्मे डा. अंबेडकर को शुरू से ही अनेक सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और इनके खिलाफ संघर्ष करते रहे। वे अपने माता-पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता ने उनको अच्छे संस्कार दिए थे और वे उनको महान संतों की कहानियां सुनाया करते थे। इन संतों में संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर व संत शिरोमणि रविदास आदि शामिल थे। इसके साथ ही पिता ने उनको रामायण और महाभारत की शिक्षाओं से भी प्रेरित किया था। भीमराव अंबेडकर ने 1908 में एल्फिंस्टन हाईस्कूल से मैट्रीकुलेशन पास किया। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कालेज में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। 1912 में उनको बंबई विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि मिली। बड़ौदा के महाराजा से प्राप्त स्कालरशिप के माध्यम से वे कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क सिटी में पढ़ने गए जहां से उन्होंने जून, 1915 में परास्नातक डिग्री प्राप्त की। उनके शोध का विषय 'प्राचीन भारतीय वाणिज्य' था। 1916 में वे अध्ययन करने लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स गए। 1920 में उनको लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी की उपाधि मिली। वे जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन के लिए गए। जून, 1927 में उनको कोलम्बिया विश्वविद्यालय ने डाक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। वे अपने समय के ऐसे विरले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स तथा बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।

डा. बी.आर. अंबेडकर ने हमें 'पढ़ो और संघर्ष करो' का नारा दिया था। उन्होंने बौद्धिक समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। सामाजिक न्याय के उनके सिद्धान्त ने वंचित जातियों के लिए शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व उजागर किया था। वे इनको सशक्तीकरण और उत्थान के आवश्यक उपकरण मानते थे। उन्होंने ज्यादा समावेशी और न्यायोचित समाज की नीव डाली थी। उनका संवाद के विचार और आदर्शों में विश्वास था। वे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बहाल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के विरोधी थे। उनका विश्वास शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में था। वे सत्य, अहिंसा तथा सभी जातियों व धर्मों के लोगों का सम्मान करने की शिक्षा देते थे। डा. अंबेडकर शिक्षा को केवल अकादमिक योग्यता प्राप्त करने का साधन नहीं मानते थे, बल्कि उन्होंने इसे उत्पीड़ित व हाशियाकृत समुदायों की मुक्ति का उत्प्रेरक माना था।

उन्होंने सबको शिक्षा तक पहुंच पर जोर दिया था। वे खासकर ऐसे लोगों को शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे जिनमों ऐतिहासिक रूप से जातीय भेदभाव तथा सामाजिक असमानता के कारण शिक्षा नहीं मिल पाई थी। वे संवेदना, न्याय व समानता जैसे मूल्य पैदा करने के दृढ़ पैरोकार थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास मानव अस्तित्व का चरम लक्ष्य है। वे महिला सशक्तीकरण के भी पक्के समर्थक थे। उनका यह कथन बहुत लोकप्रिय है कि 'मैं किसी समुदाय की प्रगति इस तथ्य से आंकता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।' डा. अंबेडकर उस समय महिलाओं की कठोर पर्दा पृथा तथा उनको घरों की चारदीवारी में कैद करने के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि इससे महिलाओं का न केवल स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में भी बाधा आती है। डा. अंबेडकर ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता प्रकट की थी। वे इनको किसी राष्ट्र की प्रगति और स्थायित्व के लिए मूल स्तंभ मानते थे। डा. अंबेडकर ने ऐसे समाज की पैरवी की थी जहां प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार हों तथा उसे समान अवसर मिलें। उन्होंने सामाजिक सद्भाव तथा परस्पर सम्मान पर जोर दिया था। उन्होंने भारत के श्रम कानून बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने फैक्ट्रीज़ एक्ट, मिनिमम वेजेज़ एक्ट तथा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कानून आज भी देश में श्रमिक अधिकारों तथा औद्योगिग प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डा. भीमराव रामजीराव अंबेडकर ने हमेशा लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता तथा संविधानवाद को सर्वोच्च स्थान देते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता तथा संविधानवाद समाज के कमजोर तबकों को अधिकार देने तथा उनको बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं। उनका यह भी मानना था कि ये सिद्धान्त राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत के लिए डा. अंबेडकर का दृष्टिकोण समावेशन और बहुलतवाद पर आधारित था।

वे बहुलता और विविधता को विभाजन के बजाय शक्ति का स्रोत मानते थे। उन्होंने अश्पृश्यता को न केवल नैतिक रूप से गलत, बल्कि सामाजिक प्रगति तथा भारत की एकता के लिए बड़ी बाधा माना था। उन्होंने अश्पृश्यता के समूल उन्मूलन की पैरवी करते हुए इस दिशा में विधायी उपायों तथा सामाजिक सुधार पर जोर दिया था। जन्म दिवस पर डा. बी.आर. अंबेडकर की याद करते हुए हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष व समावेशी राष्ट्र की उनकी शिक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित करना चाहिए।

नवरात्रों की आध्यात्मिक महिमा

"उपवास या ऐसी कोई भी तकनीक तभी फल देगी जब उसे वैराग्य की भावना के साथ विकास के लिए किया जाए।"

अश्विनी गुरुजी
(लेखक, आध्यात्मिक शिक्षक हैं)

नवरात्र साल में दो बार आते हैं और ऋतुओं के परिवर्तन, सर्दी-गर्मी और गर्मी-सर्दी का प्रतीक हैं। आयुर्वेद के अनुसार, इस दौरान बारिश के दौरान शरीर में एकत्र विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए कम से कम मात्रा में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

नवरात्रि की नौ रातें और दस दिन शक्ति के दस रूपों- शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और पराठा की ऊर्जा को धारण करते हैं, इस प्रकार प्रत्येक नवरात्रि का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। नवरात्रि में मौसम में बदलाव होता है, यानी हमारे शरीर सहित इस सृष्टि की विभिन्न ऊर्जाएं असंतुलन से नई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ती हैं। इन नौ दिनों में, हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति पुन: संरेखण की प्रक्रिया से गुजरती है, यानी असंतुलन से नए मौसम के लिए नए संतुलन की ओर।

इसे री-अलाइन करने के लिए शरीर को हल्का रखना होगा। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन नौ दिनों में व्रत या उपवास का विधान किया है। उपवास का अर्थ उससे कहीं अधिक बड़ा है जिसे आम तौर पर गलत समझा जाता है - केवल कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से रोकना।

ध्यान आश्रम में, साधक अपने प्रामाणिक अर्थ में उपवास का पालन करते हैं, अर्थात, साधना के दौरान तपस्या का आनंद लेना छोड़ देते हैं। यह जश्न मनाने, ऊर्जा के लिए भोजन करने, न कि कामुक सुख के लिए, आपके गुरु द्वारा आपको दी गई साधना के एक नियम का पालन करने से किया जाता है - एक मंत्र, ध्यान या एक तांत्रिक अभ्यास जहां इंद्रियों को सख्त नियंत्रण में रखा जाता है और ध्यान आपके इष्ट देव पर होता है

और उन दिनों के दौरान आपके सभी विचार और कार्य इष्ट-देव को समर्पित होते हैं। दान और सेवा ऐसी साधनाओं का अभिन्न अंग हैं।

उपवास के अलावा, कुछ मंत्र भी हैं जिनका जाप इन दिनों संपूर्ण शरीर को डिटॉक्स करने के लिए किया जाता है। शुरुआती लोगों के लिए, इन नौ दिनों को शरीर के तीन हिस्सों के लिए 3-3 दिनों के 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है - नाभि के नीचे का क्षेत्र, नाभि और कंधों के बीच और ऊपरी सिर का क्षेत्र, जो देवी सरस्वती की ऊर्जा के अनुरूप है।, क्रमश: देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा। 9 देवियों की उत्पत्ति इन 3 देवियों से हुई है जिनकी उत्पत्ति आदिशक्ति से हुई है। इन 3 भागों को आगे 3-3 भागों में विभाजित किया गया है, इस प्रकार शरीर कुल 9 भागों में विभाजित है। पहले 3 दिनों में, साधक मसालेदार भोजन खाना बंद कर देता है और सुबह और शाम की संध्या में माँ दुर्गा का आह्वान करते हुए मंत्रों के साथ हवन करता है। घृत के साथ काला तिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है और देसी गायों को ऊपर उठाकर पलाश की समाधि दी जाती है। अगले तीन दिनों में साधक अन्न का सेवन बंद कर देता है और शरीर को हल्का रखने के लिए केवल हल्का भोजन ही ग्रहण करता है।

दोनों संध्याओं में घृत के साथ मिठाई की आहुति देकर मां लक्ष्मी के लिए हवन किया जाता है। अंतिम तीन दिनों में, साधक केवल पानी और जूस (दूध भी नहीं, क्योंकि इसे पशु उत्पाद माना जाता है) का सेवन करता है और दो संध्याओं में घृत और गुग्गल की आहुति देकर मां सरस्वती के लिए हवन किया जाता है। 10वें दिन पूर्ण व्रत रखा जाता है और एक बार फिर मां दुर्गा या मां काली का आह्वान किया जाता है क्योंकि इस दिन रावण ने मां काली का आह्वान किया था और राम ने मां दुर्गा का आह्वान किया था। यह प्रक्रिया आवश्यक पुन: संरेखण लाती है। इसके बाद, साधक अपनी साधना करता है और अपने गुरु द्वारा बताए गए एक विशिष्ट मंत्र का जाप करता है। योग साधना से आह्वान की गई सभी शक्तियां साधक के पास आ जाती हैं। नवरात्र आपके शरीर को आने वाले मौसम की नई ऊर्जाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करने के दिन हैं। 9 दिनों तक आप अपने शरीर को पुन: व्यवस्थित करें और उसके बाद 10वें दिन नई ऊर्जा को स्वीकार करें।

अधिकांश लोग 9 दिनों तक उपवास करके अपने शरीर को हल्का करते हैं, लेकिन 10वें दिन रेस्तरां और शराब की दुकानों पर भीड़ लगाकर इसे भारी बना लेते हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे आप अपना कमरा साफ करते हैं और उसके बाद सारा कचरा कमरे में वापस ले आते हैं।

उपवास या ऐसी कोई भी तकनीक तभी फल देगी जब उसे वैराग्य की भावना के साथ विकास के लिए किया जाए। इसलिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सनातन क्रिया जैसी यौगिक प्रथाओं के साथ-साथ उपवास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आप की बात

केजरीवाल पर संकट

आम आदमी पार्टी-आप और केजरीवाल सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। समय का चक्र देखिये कि जो इंसान दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सलाखों के पीछे भेजना चाहता था आज वो खुद सलाखों के पीछे है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने साफ़ कर दिया है कि उनकी गिरफ़्तारी किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि मजबूत तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में वह पूरी तरह व मुख्य रूप से शामिल थे और यही उनकी गिरफ़्तारी का मूल बिंदु है। उनकी इस आबकारी नीति के चलते दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ। आबकरी नीति वापस लेने से भ्रष्टाचार की आशंका और गहरी हुई थी। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस डूबती नाव को छोड़ कर भागने का विचार कर रहे हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राज कुमार आनंद का इस्तीफा पहला और आखिरी इस्तीफा नहीं होगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की अन्य राज्यों में गतिविधियां भी ऐन लोकसभा चुनाव के पहले अत्यधिक प्रभावित होंगी। उत्तर प्रदेश में आप नेता संजय सिंह द्वारा चुनाव लड़ने के बजाय सपा को समर्थन की घोषणा इस दिशा में एक कदम है। पंजाब में आप के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी जहां बहुकोणीय मुकाबला होना पूरी तरह निश्चित हो गया है।

- **बाल गोविंद,** नोएडा

विवादित बयान

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के कारण विवाद में घिर जाते हैं। उन्होंने कच्चातीबू द्वीप को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने पूछा, कच्चातीबू पर कौन रहता है। यह सवाल उचित नहीं है क्योंकि इस द्वीप का हमारे देश के लिए काफी रणनीतिक महत्व है। यहां तैनात हमारी सेना सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर सकती है। अनेक भारतीय मछुआरे यहां मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा इसे श्रीलंका को सौंपने के बाद अब उनका यह अधिकार समाप्त हो गया है। देश की संप्रभूता एवं अखंडता के लिए वैसे भी किसी क्षेत्र की उपयोगिता का महत्व नहीं होता है। एक समय हमारी सरकार ने अक्साईचिन को बंजर बता कर चीनी कब्जे का समुचित विरोध नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए जनता से पूछा कि क्या हम प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों को दुश्मन को सौंप देंगे? कच्चातिबू मामले पर कांग्रेस और तमिलनाडु में उसकी सहयोगी द्रमुक फंस गई है और वह अपने पुराने पाप छिपाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस व द्रमुक की छवि सुधरने के बजाय जनता में और खराब होती चली जा रही है।

- **एमएम राजावत,** शाजापुर

मुद्रा का अपमान

भारत में रुपयों-पैसों को हवा में उड़ाने का चलन आम है। बारातों एवं खुशी के मौकों पर या नाच गानों के कार्यक्रमों में नोटों को हवा में उड़ाते या किसी के ऊपर फेंकते देखा जा सकता है। इससे कई बार रूपया-पैसा हमारे पैरों के नीचे आ जाता है। भारतीय संस्कृति में इसकी तुलना देवी लक्ष्मी से कर उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। कई देशो में इस तरह रूपए फेंकने को कानून का उल्लंघन माना जाता है। एक नाइजीरियाई ट्रांसजेंडर महिला को छह महीने की सजा सुनाई क्योंकि एक स्थानीय अदालत ने उसे मुद्रा को हवा में फेंकने का दोषी ठहराया था। भारत में भी मुद्रा के अपमान व उसके दुरुपयोग के लिए इस तरह का सजा का प्रावधान होना जरुरी है ताकि देवी लक्ष्मी स्वरूपा रुपयों-पैसों को पैरों तले रौंदने से बचाया जा सके। देश की मुद्रा, यानी रुपये पैसे तैयार करने में काफी खर्च होता है, लेकिन उनका लोग ठीक से रखरखाव नहीं करते हैं। अक्सर रुपयों को तोड़-मरोड़ कर रखने से उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक को कटे-फटे या सड़े-गले नोट वापस लेकर उनके स्थान पर नई मुद्रा छापनी पड़ती है। वजनदार पैसों की धातु का मूल्य बढ़ने पर उनको गलाने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है जिससे देश को नुकसान होता है।

- **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

मतदाता जागरूकता

लुभावने वादों से मतदाता कतई भ्रमित न हों। गत 15-20 वर्षों से लुभाने और भ्रामक किए जा रहे वादे अनेक पार्टियों द्वारा पूरे नहीं किए गए। आमतौर से ऐसे वादे अधूरे रह जाते हैं या अवधि बढ़ाने के वादे किए जाते हैं या बहानेबाजी की जाती है। इसके परिणामस्वरूप मतदाता गलत व्यक्ति और पार्टी को वोट देने के बाद में पछताता है। अस्तु इस बार बहुत सोच समझकर उसे ही वोट दें जो देश और क्षेत्र के विकास की न केवल बात करता होए बल्कि उसके वादों में सत्यता भी झलकती हो। वोट उन्हें न दें जो सांप्रदायिक जहर घोलता हो या जातिगत द्वेष फैलाता हो या सरकारी धन का दुरुपयोग करता हो अथवा अपराधी और भ्रष्टाचारी हो। मतदाताओं को सरकारों में रह चुकी पार्टियों के कामकाज पर स्वतंत्र स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर ही उनके बारे में राय बनानी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर मिलने वाली भ्रामक जानकारी के बजाय समाचार पत्रों की वेबसाइटों से मिलने वाली तथ्यपरक जानकारी को ही अपनी राय बनाने का माध्यम बनाना चाहिए। वोट अवश्य दें। चाहिए। कोई उम्मीदवार पसंद न होने पर नोटा का प्रयोग करें।

- **बी एल शर्मा,** उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभी वे 400 प्लस की बात कर रहे हैं, मई के अंत तक इंतजार करें, पाएंगे कि संख्या 250 से कम रह जाएगी। जून के पहले हफ्ते तक यह संख्या 175-200 के बीच रहनी चाहिए...मैं आधा दर्जन अल्फांसों आमों के दाम की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि हर संदेश में राजनीति ही जुड़ी हो।
— डॉ. एस.वाई. कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त@DrSYQuraishi

इतिहास के सबक

भारत डोगरा

आधिपत्य नहीं सहयोग के संबंध जरूरी

विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के बावजूद विश्व में जिस तरह कई स्तरों पर लोगों के दुख-दर्द बढ़े हैं, युद्ध और हिंसा का संकट कई तरह से बढ़ा है, पर्यावरण का संकट उग्र हुआ है, उसने इस विषय पर चिंतन बढ़ाया है कि वे कौन-सी बुनियादी विसंगति या विकृतियां हैं जिनके कारण विश्व सही राह पर नहीं चल पा रहा है।

यदि इतिहास के पृष्ठों में इन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजें तो एक बड़ी समझ यह बनती है कि विभिन्न स्तरों पर आधिपत्य के संबंध हावी होने के कारण दुख-दर्द बहुत बढ़ सकता है। दूसरी ओर, आधिपत्य के स्थान पर सहयोग के संबंध आ सकें तो यह दुख-दर्द बहुत कम हो जाता है। बहुत-सी गंभीर, व्यापक समस्याओं की गहराई में हम जाएं तो कहीं न कहीं टूटते, बिखरते मानवीय संबंधों की भूमिका हमें दिखाई देगी। मनुष्यों के आपसी संबंधों की एक प्रमुख कमजोरी और कमी यह है कि एक दूसरे पर आधिपत्य करने, शासन करने, अपना बड़प्पन सिद्ध करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल रही है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस प्रवृत्ति के साथ अधिकतर एक दूसरे का हक छीनने, अधिक संचय करने या अधिक लालच की प्रवृत्ति जुड़ी रही है। पर जहां यह लालच नहीं है, वहां भी अहं के कारण अपनी उच्चता स्थापित करने या अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति प्रायः देखी गई है। कारण अहं हो या लालच, मनुष्य के आपसी संबंधों में आधिपत्य करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त और व्यापक रही है। जहां जनसाधारण के दैनिक जीवन में इस प्रवृत्ति ने तरह-तरह के दुख-दर्द उत्पन्न किए, वहां युद्ध के मैदान में इस कारण भयानक खून-खराबा भी हुआ। इतिहास के पृष्ठ गवाह हैं कि बहुत प्राचीन समय से ही गुलाम और मालिक, गरीब और अमीर, पराजित और विजेता, कमजोर और बलशाली, यहां तक कि स्त्री और पुरुष के संबंध में आधिपत्य करने की प्रवृत्ति ने बहुत से लोगों को अत्यधिक और असहनीय दुख दिए।

बहुत से लोगों पर यह प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है कि उन्होंने अपने आदर्श के रूप में उन्हीं को ग्रहण करना आरंभ किया जो अपना आधिपत्य जमा सकें। सोचने-समझने के ढंग, बातचीत, कथा-कहानियों, यहां तक कि इतिहास में भी उन लोगों को अधिक महत्त्व दिया गया-और प्रायः प्रशंसा की भावना से ही दिया गया-जिन्होंने अपने आधिपत्य को अधिक फैलाने में सफलता प्राप्त की, चाहे इस प्रयास में उन्होंने कितने ही लोगों को नाहक ही अथाह कष्ट पहुंचाए हों। दूसरी ओर, अनेक धर्म-गुरुओं, दार्शनिकों और समाज सुधारकों ने इंसान की इस मूल कमजोरी और इससे जुड़े दुख-दर्द को पहचाना और लोगों को इससे बचाने का प्रयास किया। इनमें से अनेक प्रयासों का असर दूर-दूर तक हुआ और काफी समय तक हुआ। अतः इतिहास में ऐसे दौर भी आए जब आधिपत्य पर आधारित मानव संबंधों को बहुत से लोगों ने एक बुराई के रूप में पहचाना और इसके स्थान पर भाई-चारे, समता, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों की इज्जत करने और समझने का प्रयास करने की प्रवृत्ति को अपनाया। कुछ समयों और स्थानों में इन विचारों का प्रसार विभिन्न धर्मों और पंथों के रूप में हुआ, अन्य मौकों पर इनका प्रसार नई आर्थिक-राजनीतिक विचारधाराओं और उनसे जुड़ी क्रांतियों के रूप में हुआ। अनेक सराहनीय शुरुआतों के बावजूद बाद में इन प्रयासों में भी प्रायः कुछ कमजोरियां आ जाती थीं, और आधिपत्य की प्रवृत्ति को फिर प्रबल होने या पहले से भी अधिक प्रबल होने का मौका प्रायः मिल जाता था। आरंभ में इस प्रवृत्ति को हावी करने का अवसर किसी व्यक्ति को छोटे से समूह के स्तर पर ही मिल सकता था, पर बाद में आधिपत्य की महत्त्वाकांक्षा का बेहद विस्तार कर ऐसे साम्राज्य स्थापित किए गए जो लाखों पराजित लोगों और गुलामों पर आधिपत्य कर सके।

वे कौन-सी बुनियादी विसंगति या विकृतियां हैं जिनके कारण विश्व सही राह पर नहीं चल पा रहा है। यदि इतिहास के पृष्ठों में इन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर खोजें तो एक बड़ी समझ यह बनती है कि विभिन्न स्तरों पर आधिपत्य के संबंध हावी होने के कारण दुख-दर्द बहुत बढ़ सकता है। दूसरी ओर, आधिपत्य के स्थान पर सहयोग के संबंध आ सकें तो यह दुख-दर्द बहुत कम हो जाता है। बहुत-सी गंभीर, व्यापक समस्याओं की गहराई में हम जाएं तो कहीं न कहीं टूटते, बिखरते मानवीय संबंधों की भूमिका हमें दिखाई देगी। मनुष्यों के आपसी संबंधों की एक प्रमुख कमजोरी और कमी यह है कि एक दूसरे पर आधिपत्य करने, शासन करने, अपना बड़प्पन सिद्ध करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल रही है। इस प्रवृत्ति के साथ अधिकतर एक दूसरे का हक छीनने, अधिक संचय करने या अधिक लालच की प्रवृत्ति जुड़ी रही है

विश्व इतिहास के शायद सबसे निर्मम शोषण और तबाही की शुरुआत हुई। यूरोप से दौलत और जमीन के लालच में गए लोगों ने यहां के मूल निवासियों (रेड इंडियन) पर हर तरह के अत्याचार किए, उनसे जबरन मजदूरी करवाई, उनकी जमीन छीनी, अनेक जगह उनका कत्लेआम किया। करोड़ों की संख्या में यहां के मूल निवासी मारे गए। हजारों वर्ग मील के क्षेत्रों में वे खत्म ही कर दिए गए। अमेरिकी महाद्वीपों में कोलंबस के आगमन के समय (वर्ष 1500 के आसपास) लगभग 10 करोड़ लोग रहते थे। यूरोप के लोगों के यहां आने के बाद के डेढ़ सौ वर्षों में ही 90 प्रतिशत मूल निवासियों की मृत्यु हो गई, मात्र 10 प्रतिशत बचे। बाद में आस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों पर भी ऐसा ही अत्याचार हुआ।

उधर, अमेरिका के मूल निवासी बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे, इधर यूरोप के लुटेरों ने अफ्रीका के गुलामों को पकड़ कर अमेरिका के खेतों और खदानों में भेजना आरंभ किया। लगभग 350 वर्षों तक जारी रहे इस व्यापार में लगभग डेढ़ करोड़ अफ्रीकावासियों को गुलाम के रूप में अमेरिकी महाद्वीपों में भेजा गया। भेजने का तरीका इतना निर्दयी था कि लाखों गुलाम तो यात्रा के दौरान ही मर गए और अधिकांश अन्य की मौत कार्यस्थल पर निर्मम शोषण के कारण कुछ वर्षों में हो गई। साथ ही, एशिया के अधिकांश देशों का इतना कठोर शोषण हुआ कि भुखमरी और अकाल से लाखों लोग मरने लगे। इस औपनिवेशिक दौर ने कुछ देशों को बाहरी लूट के आधार पर भौतिक सुख-सुविधाओं और संपत्ति की ऐसी व्यवस्था खड़ी करने दी जिसे बनाए रखने के लिए आज भी अनेक तौर-तरीकों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषमता और आधिपत्य की प्रवृत्ति को दृढ़ किया जा रहा है। विभिन्न समाजों में कदम-कदम पर किसी जाति, नस्ल, वर्ग, गुट, व्यवसाय आदि का बड़प्पन सिद्ध करने और उसका आधिपत्य स्थापित करने के प्रयासों से सामुदायिक मेलजोल की भावना से कार्य आगे बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, नाहक तरह-तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं और सब लोगों की सूझबूझ और सोच-विचार का पर्याप्त लाभ हमें नहीं मिलता है। समाज की जो ऊर्जा सार्थक कार्य में लगनी थी, वह बेवजह उत्पन्न किए गए तनावों में नष्ट हो जाती है।

आधिपत्य के संबंधों में चाहे ऊपरी और फौरी तौर पर क्षति केवल दबाए गए व्यक्ति की होती है, पर गहरे और दीर्घकालीन स्तर पर क्षति दबाने और कुचलने वाले व्यक्ति की भी होती है। जो दूसरों से शोषण और निर्दयता का व्यवहार करते हैं, वे या तो इस कारण ऐसे अपराधबोध से पीड़ित होते हैं, जो उनके जीवन की सुख-शांति छीन लेता है, अथवा (इस अपराधबोध से बचने के लिए) उन्हें अपने जीवन में इतनी संवेदनविहीनता लानी पड़ती है कि वे जीवन के अनेक प्रसन्नता और संतोष देने वाले अनुभवों से वंचित हो जाते हैं। इसका असर उनके जीवन के सबसे नजदीकी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि जहां आधिपत्य के आधार पर बहुत सी भौतिक संपदा अर्जित कर ली जाती हैं, वहां भी तनाव, अवसाद और नैतिक पतन से जीवन तबाह रहता है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

इस तरह आधिपत्य के संबंधों के दोनों ओर दुख-दर्द बढ़ते हैं, आधिपत्य से त्रस्त होने वालों में भी और आधिपत्य जमाने वालों में भी। यह इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण पर उपेक्षित सबक है कि आधिपत्य के संबंधों को दूर कर सहयोग के संबंध विकसित करने के प्रयास निरंतरता से होने चाहिए।

कुछ विज्ञापन कुछ विखंडन

मीडिया

सुधीश पचौरी

खबर चैनलों में आते विज्ञापन ध्यान खींचते हैं: एक निम्न मध्यवर्गीय घर। पत्नी के चेहरे पर नाराजी छाई है। दूधरहित काली चाय बनाकर देती है। उस चाय का घूंट लेकर जैसे ही पति मुंह बना कर कहता है कि ये क्या बना दिया है तो पत्नी कहती है तुमने व्हाट्सऐप सरकार बनाई उसकी महंगाई में यही मिल सकता है। फिर गुस्से से कहने लगती है, 'मेरे विकास का दो हिसाब'। फिर हाथ का चित्र आता है, जो कहता है : 'हाथ बदलेगा हालात'। यह विज्ञापन एनडीए के शासन में बढ़ती महंगाई पर कटाक्ष करता है, और कांग्रेस का 'हाथ' ही 'हालात बदलेगा', ऐसी आश्वस्ति देता है। दूसरा विज्ञापन 'बेरोजगारी' पर चोट करता है। 'वॉयसओवर' कहता है कि इंजीनियरिंग के आखिरी बरस में बता दिया गया था कि बड़ी नौकरी मिलेगी...इंजीनियरिंग पास जब ये नौजवान अपने बाल काढ़कर और टाई लगाकर नौकरी के लिए घर से निकलता है तो किसी बड़ी नौकरी की जगह, घर के सामने खड़ा एक 'ई-रिक्शा' नजर आता है। वह गुस्से में अपनी टाई निकाल कर उस 'ई रिक्शा' को ड्राइवर बन चलाने के लिए बैठ जाता है, और गुस्से से भर कर कहता है 'मेरे विकास का दो हिसाब'। फिर आता है 'हाथ' का वही चिह्न जो कहता है कि 'हाथ बदलेगा हालात'।

इनके बरक्स भाजपा के विज्ञापन कुछ अलग भाषा बोलते नजर आते हैं। एक विज्ञापन काफी लंबा है। इसमें मोदी की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को पहुंच रहे लाभों को आम लोगों द्वारा ही कई भाषाओं में गाकर बताया जाता है, और अंत में कहा जाता है 'ये तो अभी ट्रेलर है' और अंत में सब कहते हैं कि जब मोदी की गारंटी हमारा कल्याण है तो हमारी गारंटी मोदी को जिताना है। अंत में ऊपर 'विकसित भारत' लिखा आता है, और नीचे मोदी के चित्र के साथ लिखा आता है 'अबकी बार मोदी सरकार!' ऐसे ही एक विज्ञापन में तीन युवक मोदी द्वारा किए गए राम मन्दिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत अन्य तीर्थों के विकास के बारे में खुशी-खुशी बताते हुए भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और कहते हैं 'ये तो अभी ट्रेलर है'...फिर कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है तो हमारी भी गारंटी है कि मोदी को जिताएं...। ऐसे ही एक विज्ञापन एक परिवार की तीन पीढ़ी की स्त्रियों के जरिए कहता है कि मोदी जी ने दवाएं सस्ती की, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। अब सब खुश हैं। एक बच्ची कहती है मोदी जी कहते हैं कि 'ये तो अभी ट्रेलर है'... जब मोदी हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारी गारंटी मोदी को जिताने की है...ऐसे ही, एक पिता-पुत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की चरचा करते हैं। फिर कहते हैं मोदी जी के कहते हैं 'ये तो अभी ट्रेलर है'...। फिर पुत्री कहती है कि हमारा सपना पूरा करने की गारंटी मोदी जी की तो मोदी जी का सपना पूरा करने की गारंटी हमारी...।'

'मोदी की गारंटी' के बदले 'जनता की मोदी को जिताने की गारंटी' की बात जनता की 'थैंक्स गिविंग' की तरह दिखती है। जैसे पब्लिक कहती हो कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हमारा भी कर्त्तव्य है कि उनके लिए भी कुछ करें...कहने की जरूरत नहीं कि ये विज्ञापन 'इंटरएक्टिव विज्ञापन' हैं, जो पॉजिटिव संदेश देकर जाते हैं और जो मोदी की नीतियों से बने लाभार्थियों को मोदी के पक्ष में 'एक्टिवेट' भी करते हैं। यहां एक भी चेहरा किसी से नाराज नहीं दिखता।

सब मोदी की गारंटियों के दीवाने दिखते हैं। यह इनका 'फीलगुड फेक्टर' है जबकि कांग्रेसी विज्ञापनों में नाराजी अधिक मुखर है। वे मोदी शासन के विरोध में जनता की नाराजी को हवा देते दिखते हैं। मानो जनता सत्ता से उतनी ही नाराज हो जितनी कि कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का एक तीसरा विज्ञापन अवश्य जरा पॉजिटिव दिखता है। इसमें तीस लाख पक्की नौकरी देने का वादा किया जाता है। फिर एक युवक को नौकरी मिली बताई जाती है। अंत में बड़े अक्षरों में 'जून, 2024' लिखा आता है। साथ ही 'हाथ' के चित्र के साथ 'हाथ बदेलगा हालात' वाली कैचलाइन भी नजर आती है। साफ है कांग्रेसी विज्ञापनों में नाराजी ज्यादा दिखती है, जो विज्ञापन कला के हिसाब से भी उचित नहीं दिखती क्योंकि 'पॉजिटिव' विज्ञापन' ही असर करते हैं। नकारात्मक विज्ञान कारगर नहीं होते। इस मानी में मोदी के विज्ञापन हर बार पॉजिटिव संदेश देते लगते हैं। इस तरह वे अधिक कारगर नजर आते हैं।

सब मोदी की गारंटियों के दीवाने दिखते हैं। यह इनका 'फीलगुड फेक्टर' है जबकि कांग्रेसी विज्ञापनों में नाराजी अधिक मुखर है। वे मोदी शासन के विरोध में जनता की नाराजी को हवा देते दिखते हैं। मानो जनता सत्ता से उतनी ही नाराज हो जितनी कि कांग्रेस नाराज है

पूर्व से पश्चिम तक संकट में एशिया

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान एशिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो को प्रकारांतर से खुला न्यौता दिया गया। किशिदा ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के विश्व स्तर पर कायम वर्चस्व को बनाए रखने की वकालत की। उन्होंने अमेरिका की हिमायत में वे सभी बातें कहीं जो वहां के नेताओं और सांसदों के लिए कर्णप्रिय थीं। किशिदा ने अमेरिका के नेतृत्व और नीतियों की इतनी पुरजोर तारीफ की कि पता लगाना मुश्किल हो गया कि अमेरिका ही वह देश था जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले के लिए अमेरिका ने कभी जापान से माफी नहीं मांगी। किशिदा जैसे जापानी नेताओं ने मानो यह स्वीकार कर लिया कि परमाणु हमले के लिए हम खुद जिम्मेदार थे।

किशिदा का संबोधन भारत और एशिया के अन्य देशों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि उन्होंने चीन के साथ ही रूस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दक्षिण चीन सागर और पूर्व एशिया में चीन की आक्रामक गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि यह क्षेत्र नया यूक्रेन बन सकता है। जाहिर है कि वह अमेरिका के नेताओं से गुहार लगा रहे थे कि वे यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देते समय इंडो पेसेफिक देशों को नजरअंदाज न करें। किशिदा ने कहा कि उनका देश रूसी आक्रमण के खिलाफ संघर्षरत यूक्रेन के साथ खड़ा है। किशिदा ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इंडो पेसिफिक में सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। उनके भाषण का यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक 'एशियाई नाटो' के पक्ष में है।

गौर करने वाली बात होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्षों पहले क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाए थे। क्वाड का कोई सैनिक मंसूबा नहीं था, लेकिन किशिदा जिस एशियाई सुरक्षा ढांचे की बात कर रहे हैं, वह अमेरिका के वर्चस्व वाला सैनिक गठबंधन जैसा है। जाहिर है कि भारत किशिदा के इन विचारों और नीतियों से सहमत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक को दिए गए साक्षात्कार में चीन के साथ संबंधों को पटरी पर लाने के लिए एक पहल की है। मोदी ने कहा है कि सीमा पर लंबे समय से चल रहा तनाव दोनों देशों में से किसी के हित में नहीं है। उनकी यह सोच किशिदा से एकदम अलग है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच किशिदा की यह यात्रा बाइडन को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है। किशिदा ने कहा कि अमेरिका के नेताओं को अपनी ग्लोबल भूमिका को लेकर कोई संदेह और दुविधा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने अपने बलबूते दुनिया में स्थायित्व कायम रखा है। उसे अपनी यह भूमिका जारी रखनी चाहिए तथा इस क्रम में जापान पूरी तरह उसके साथ है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद निशस्त्र कर दिया गया था। तकनीकी रूप से जापान आज भी सेना नहीं रख सकता लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की सैन्य मुहिम को बिना शर्त समर्थन देने का ही नतीजा है कि जापान आज एक सैन्य ताकत बनने की राह पर है। जिस देश से शांति के पैगाम की उम्मीद थी, वह युद्ध का नगाड़ा बजा रहा है। वह भी ऐसे समय जब गाजा में इस्राइल का नरसंहार जारी है तथा फारस की खाड़ी के बीच संभावित संघर्ष जापान के लिए मारक सिद्ध हो सकता है। यह संघर्ष यदि व्यापक रूप लेता है तो दुनिया का कच्चे तेल का आधा कारोबार ठप हो जाएगा। रूस से ऊर्जा आयात कम करने वाला जापान इस नये संकट का सामना कैसे करेगा।

वास्तव में भारत के लिए भी पश्चिम एशिया का संकट नई आर्थिक चुनौती पेश कर सकता है। गनीमत यह है कि रूस एक विश्वसनीय ऊर्जा प्रदाता देश है जो आड़े समय में भारत के काम आएगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कितना ऊपर जाता है, यह विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए निर्णायक होगा। रूस के खिलाफ यदि प्रतिबंध जारी रहा और पश्चिमी एशिया से तेल आपूर्ति बाधित हुई तो जापान और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है।

किशिदा का संबोधन भारत और एशिया के अन्य देशों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि उन्होंने चीन के साथ ही रूस पर भी निशाना साधा

भारतीय संस्कृति का इंद्रधनुषी गुलदस्ता

बैसाखी पर्व

योगेश कु. गोयल

कृषि प्रधान देश भारत में बैसाखी पर्व का संबंध फसल पकने के बाद उनकी कटाई से जोड़कर देखा जाता रहा है। वैसे विशेष तौर पर पंजाब का प्रमुख त्यौहार माना जाने वाला यह त्यौहार पंजाब ही नहीं, बल्कि देश भर में लगभग सभी स्थानों खास तौर से पंजाबी समुदाय द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सिख बैसाखी से ही नये साल की शुरुआत मानते हैं, और इसलिए भी एक-दूसरे को बैसाखी की बधाइयां देते हैं। पंजाब देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है, जब यहां किसान अपने खेतों को फसलों से लहलहाते देखता है, तो खुशी से झूम उठता है। खुशी के इसी आलम में शुरू होता है गिद्दा और भांगड़ा का मनोहारी दौर। यही वजह है कि विशेष रूप से पंजाब में बैसाखी के पर्व पर गिद्दा और भांगड़ा के मनोहारी कार्यक्रम न हों, यह हो ही नहीं सकता। यहां ढ़ोल-नगाड़ों की धुन पर पारंपरिक पोशाक में युवक-युवतियां नाचते-गाते और जश्न मनाते हैं तथा गुरुद्वारों को फूलों तथा रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है।

उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब-हरियाणा में गिद्दा और भांगड़ा की धूम के साथ मनाए जाने वाले बैसाखी पर्व के प्रति भले ही काफी जोश देखने को मिलता है लेकिन वास्तव में यह त्यौहार विभिन्न धर्म एवं मौसम के अनुसार देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे 'नबा वर्ष' के नाम से मनाया जाता है, तो केरल में 'विशू' तथा असम में 'बीहू' नाम से मनाया जाता है। बंगाल में 'पोइला बैसाखी' भी कहा जाता है, और वे इसे अपने नये साल की शुरुआत मानते हैं। हिन्दू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन गंगा आरती करने तथा पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा रही है।

बैसाखी पर्व के साथ भारतीय इतिहास की कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। इसी दिन अर्थात 13 अप्रैल, 1699 को सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोबिन्द सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में 'खालसा पंथ' की स्थापना की थी। इस पंथ की स्थापना करने का उनका प्रमुख उद्देश्य था लोगों को मुगल शासकों के अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाना तथा इन अत्याचारों का सामना करते हुए देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। गुरु गोबिन्द सिंह कलम के साथ-साथ तलवार के भी उपासक थे और उनके पंच प्यारों में सभी जातियों के लोग शामिल थे। उन्होंने अन्याय, विरोध एवं पाखंड के सर्वनाश की प्रेरणा और मानव जाति को एकता का संदेश देते रहने में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था।

बताया जाता है कि लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौटे 'शेरे पंजाब' महाराणा रणजीत सिंह का राजतिलक भी बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी को सूर्य वर्ष का प्रथम दिन माना गया है क्योंकि इसी दिन सूर्य अपनी पहली राशि मेष में प्रविष्ट होता है। इसलिए इस दिन को 'मेष संक्रांति' भी कहा जाता है। देखा जाए तो बैसाखी का पर्व हमारे लिए खुशियों का पर्व तो है ही लेकिन इसके साथ-साथ यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कड़वी यादें भी संजोये हुए है। बैसाखी का पवित्र दिन हमें गुरु गोबिन्द सिंह जैसे महापुरुषों के महान आदर्शों एवं संदेशों को अपनाने तथा उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और हमें संदेश देता है कि हमें देश में शांति, सद्भावना एवं भाईचारे के नये युग का शुभारंभ करने की दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

हाल फिलहाल हम तरस खाते हैं

बतंगड़ बेतुक

विभांशु दिव्याल

झल्लन ने हमें जुहार किया और हमारी बगल में अपना ठीया गह लिया। जब वह आदत के विपरीत बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो हमने ही अपना मुंह खोला, 'क्या हुआ झल्लन, आज चुप्पी काहे मार ली है, काहे चेहरे पर मनहूसियत उतार ली है?' झल्लन बोला, 'सही पकड़े हो ददाजू, हमारे भीतर मनहूसियत भर रही है, वही हमारे चेहरे पर उतर रही है। हम सुखी हों या दुखी हों, हंसे या रोयें, गुस्सा करें या तरस खायें, चिल्लाएं या हमदर्दी दिखाएं, इनमें से क्या करें यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, शायद इसीलिए हमारे चेहरे पर मनहूसियत छा रही है।' हमने कहा, 'आखिर हुआ क्या जिसने तुझे इतनी विकट दुविधा में ले लिया है और तेरे इर्द-गिर्द मनहूसियत ने डेरा डाल दिया है?' वह बोला, 'ददाजू, जब हाई कोर्ट ने ईडी का पूरा साथ दिया था और हमारे केजरी भैया को तगड़ा झटका दिया था तब हम निश्चिंत थे कि केजरी भैया हार नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा देंगे, उनका जो पक्ष हाई कोर्ट की समझ में नहीं आया उसे सुप्रीम कोर्ट को जरूर समझा देंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाएंगे और जिस सरकार को वह जेल के भीतर से चला रहे हैं उसे जल्दी ही बाहर लाकर चलाएंगे।'

हमने कहा, 'ठीक है, तेरे केजरी भैया ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की तारीख लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तू दुविधाग्रस्त क्यों हो रहा है, तू फालतू में क्यों रो रहा है?' वह बोला, 'ददाजू, सुप्रीम कोर्ट जब सुनेगा तब सुनेगा, जो फैसला करेगा सो करेगा पर फिलवक्त तो हमें केजरी भैया की सरकार के दलित मंत्री आनंद कुमार पर गुस्सा आ रहा है जिसने पार्टी और सरकार से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और सच कहें तो हमारे केजरी भैया की पीठ में छुरा घौंप दिया है।' हमने कहा, 'इसमें छुरा घोंपने की बात कहां से आ गयी, मंत्री हैं, जब तक अच्छा लगा काम किया, जब बुरा लगा तो इस्तीफा सौंप दिया। जब केजरी भैया को छोड़कर जाने वाले बड़े-बड़े लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाये तो एक और व्यक्ति पार्टी से निकलकर उनका क्या बिगाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। तेरे भैया जेल में रहेंगे तो जेल से सरकार चलाएंगे, बाहर आ गये तो बाहर से सरकार चलाएंगे, मोदी और मोदी सरकार के विरुद्ध जैसे चिल्लाते रहे हैं वैसे ही आगे भी चिल्लाएंगे।'

झल्लन बोला, 'ददाजू, या तो आप हमें बेवकूफ समझ रहे हो या आप जानबूझकर हमारी बात नहीं पकड़ रहे हो। जब जेलबंद केजरी भैया के जेलबाहर के सारे सिपहसालार चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया गया है, उन्हें ईडी द्वारा फंसाया गया है तब उनका ही एक कद्दावर मंत्री सीधे-सीधे उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगा रहा है, अपने आरोपों के समर्थन में सबको दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला दिखा रहा है। कह रहा है कि केजरी सरकार भ्रष्टाचार के दल-दल में फंसी हुई है इसलिए दुनियाभर में उसकी इतनी हंसी हुई है सो अब उसका जमीर गवारा नहीं करता कि वह इस भ्रष्ट सरकार का मंत्री बना रहे और अपनी अंतरात्मा की आवाज से धोखा करता रहे। अब बताइए, जब आपका अपना आदमी आपको आईना दिखा रहा है, आपको भ्रष्टाचारी बता रहा है तो ऐसे तो केजरी भैया के ईमानदारी के दावे की सारी हवा निकल जाएगी और मोदी सरकार के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान की गाड़ी ही पटरी से फिसल जाएगी। हमें लगता है आनंद कुमार के इस्तीफे ने आप नेताओं के हाथ से नैतिकता का हथियार ले लिया है और इस हथियार को भाजपाइयों के हाथ में दे दिया है।'

हमने कहा, 'देख झल्लन, हम नहीं कहते कि भाजपा दूध की धुली है या भाजपा की हर खिड़की ईमानदारी की तरफ ही खुली है। लेकिन हमें लगता है कि तेरे केजरी भैया की जो दुर्गति हो रही है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं यानी उनकी दुर्गति के कारण उनके अपने वाणी-व्यवहार हैं। यह आदमी भ्रष्टाचार मिटाने आया था, यह समझता था कि यह मंच से भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाता जाएगा, जनता के सामने उन्हें खलनायक बनाता जाएगा, अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाता जाएगा। पहले राज्य में फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा और जैसे ही यह अपनी सरकार बनाएगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। इसे भ्रम था कि नेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता इसकी ईमानदारी का जश्न मनाती रहेगी और इसे सत्ता का ताज पहनाती रहेगी। पर इस अल्पज्ञ को यह पता नहीं था कि भ्रष्ट व्यवस्था खुद इसे ही भ्रष्टाचार करने को विवश कर देगी, इसे और इसकी पूरी सरकार को भ्रष्टाचार में लिथेड़ देगी और अंततः इसकी बखिया उधेड़ देगी। कम से कम अब इसे ठोस वास्तविकता की जमीन पर आ जाना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी गलतियों को समझना और सुधारना चाहिए।' झल्लन सर खुजाते हुए बोला, 'ठीक है ददाजू हम समझ गये, हाल फिलहाल हम केजरी भैया पर तरस खा रहे हैं, अपनी बाकी की भावनाएं आगे के लिए बचा रहे हैं।'

हमने कहा, 'देख झल्लन, हम नहीं कहते कि भाजपा दूध की धुली है या भाजपा की हर खिड़की ईमानदारी की तरफ ही खुली है। लेकिन हमें लगता है कि तेरे केजरी भैया की जो दुर्गति हो रही है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं यानी उनकी दुर्गति के कारण उनके अपने वाणी-व्यवहार हैं। यह आदमी भ्रष्टाचार मिटाने आया था, यह समझता था कि यह मंच से भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाता जाएगा, जनता के सामने उन्हें खलनायक बनाता जाएगा, अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाता जाएगा। पहले राज्य में फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगा और जैसे ही यह अपनी सरकार बनाएगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। इसे भ्रम था कि नेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता इसकी ईमानदारी का जश्न मनाती रहेगी और इसे सत्ता का ताज पहनाती रहेगी। पर इस अल्पज्ञ को यह पता नहीं था कि भ्रष्ट व्यवस्था खुद इसे ही भ्रष्टाचार करने को विवश कर देगी, इसे और इसकी पूरी सरकार को भ्रष्टाचार में लिथेड़ देगी और अंततः इसकी बखिया उधेड़ देगी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा ● राष्ट्रीयता ● कर्तव्य ● समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, **फैक्स :** 2535935,2520760 **विज्ञापन**-3911455/434, **प्रसार**- 3911451/428

वर्ष - 18, अंक 6272 आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

सुभाषित *त्यागके बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेनेके लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है।* ❑ *नीतिशतकम्*

भारतीयोंकी रिहाई जरूरी

ईरान और इजराइलके बीच निरन्तर बढ़ता तनाव अब युद्ध तक पहुंच गया है और दोनों ओरसे हमले भी शुरू हो गये हैं। इस हमलेमें क्षतिके बारेमें परस्पर विरोधी दावे भी किये जा रहे हैं। कितनी क्षति पहुंची है, इसके बारेमें वास्तविकता सामने नहीं आयी है लेकिन एक गंभीर चिंताकी बात यह है कि शनिवारको होरमूजकी खाड़ीके निकट हेलीकाप्टरसे आये ईरानी कमाण्डोंने उस इजराइली पोतको अगवाकर अपने कब्जेमें ले लिया, जिसमें २५ सदस्यीय चालक दलमें १७ भारतीय नागरिक भी सवार हैं। सभी कमाण्डों रस्सीके जरिये जहाजपर उतरे और उन्होंने चालक दलको अपने प्रभावमें ले लिया। इस जहाजका संचालन लन्दनकी कम्पनी जोडैक मेरीटाइम करती है। जोडैक मेरीटाइम इजरायली धन कुबेर एयाल ओफरके जोडैक ग्रुपका हिस्सा है। कमाण्डों काररवाईका वीडियो भी वायरल हुआ है। पोतका अगवा किया जाना निन्दनीय है। इससे समुद्री सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। अब सबसे प्रमुख प्रश्न १७ भारतीयोंकी जीवन रक्षा और उनकी सुरक्षित रिहाईसे सम्बन्धित है। इन भारतीयोंकी सुरक्षित स्वदेश वापसी होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास भी शुरू किये गये हैं। भारत सरकार तेहरान और दिल्ली दोनों स्थानोंपर राजनयिक चैनलों के माध्यमसे सम्पर्क में है। इसके लिए भारत सरकारको कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। ईरान और इजरायलके बीच युद्धके हालात को देखते हुए भारतीय विमान ईरानी हवाई क्षेत्रसे नहीं जा रहे हैं। इन विमानोंके लिए वैकल्पिक मार्गोंका उपयोग शुरू हो गया है। भारतीय विमान यूरोप और मध्य पूर्वके लिए अपना रास्ता बदल रहे हैं। ईरान और इजरायलके बीच हालात और बिगड़ सकते हैं। यदि दोनों देशोंने संयमसे काम नहीं लिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। रूस-यूक्रेन और इजरायल तथा हमासके बीच युद्ध पहले से ही जारी है। अब युद्धका तीसरा मोरचा भी खुल गया है। ईरान ने कहा है कि यदि इजरायल ने जवाबी हमला किया तो हम इसका और मजबूत जवाब देंगे। ईरानी हमलेके बाद इजरायलके प्रधान मंत्री नेतन्याहूका जो पहला बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरानी डोन्स-मिसाइलोंको रोक दिया है। हमलोंको ब्लाक कर दिया है। भारतकी घटनाक्रमोंपर सजग दृष्टि बनी हुई है। परराष्ट्र मंत्रालय ने कहा है कि ईरान-इजरायलके बीच बढ़ता विवाद क्षेत्रकी शांति और सुरक्षाके लिए खतरा है। भारत तुरन्त तनाव समाप्त करने और हिंसा रोकनेके पक्षमें है। जो भी हो, स्थिति चिंताजनक है। इसके समाधानकी दिशामें प्रयास आवश्यक है और अगवा किये गये भारतीय नागरिकोंकी यथाशीघ्र सुरक्षित रिहाई भी होनी चाहिए।

मणिपुरमें फिर हिंसा

मणिपुरमें हिंसक वारदातें थमनेका नाम नहीं ले रही हैं जो राज्य सरकार की विफलताको उजागर करती है। राज्यके थोउबल जिलेके हेइरोक गांवमें बीते शुक्रवारको हथियारोंसे लैस ग्रामीण वालंटियर्स और अज्ञात बन्दूकधारियोंके बीच एक घण्टेतक हुई गोलीबारीकी आंच अभी धीमी भी नहीं पड़ी थी कि अगले ही दिन शनिवारको एक बार फिर हिंसा भड़क उठी जिसमें दो लोगोंकी मौत हो गयी। यह हिंसक झड़प पूर्वी इम्फाल और कांगपोकपी जिलेके बीच सटे मोइरंगपुरेल इलाकेमें हुई। इसमें हथियारबन्द दो समूहोंके बीच गोलीबारी हुई जिसमें दो कुकी समुदायके लोगोंकी मौत हो गयी। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन बीते दो दिनसे मणिपुरमें अलग-अलग इलाकोंमें जिस तरह गोलीबारीकी घटनाएं हुई वह चिन्तित करने वाली है। सोमवारको स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहका मणिपुर दौरा है। ऐसेमें लगातार हिंसा जारी रहनेसे तनावका जो माहौल बन रहा है, वह शासन-प्रशासनके समक्ष बड़ी चुनौती है। चुनावके पहले फेजमें इनर और आउटर मणिपुर लोकसभा सीटके लिए १९ अप्रैलको मतदान होना है। इसके लिए केन्द्र सरकारकी ओर से सुरक्षाबलकी तैनाती की गयी है। साथ ही राज्यमें ३६ हजार सुरक्षाकर्मी और ४० आईपीएस तैनात किये गये हैं। पहाड़ी और घाटी दोनों जिलोंमें १२९ चौकियां स्थापित की गयी हैं, इसके बाद भी लगातार हिंसा जारी है जिसे लोकसभा चुनावको बाधित करनेका कुचक्र माना जा रहा है। केन्द्र सरकारको ताजा हिंसा की घटनाओंको गम्भीरतासे लेने और हस्तक्षेप करनेकी जरूरत है जिससे चुनाव शांतिपूर्ण ढंगसे सम्पन्न कराया जा सके। साथ ही राज्यमें लम्बे समयसे जारी दो समुदायोंके बीच कटुता समाप्त करने और सौहार्दपूर्ण माहौल बनानेका प्रयास होना चाहिए।

लोक संवाद

बढ़ते तापमानका संकट

महोदय,-मनुष्यकी लिप्साओंने वायुमंडलीय पर्यावरणको प्रदूषित करते हुए धरतीको संकटके कगारपर ला छोड़ा है। विगत वर्षोंसे अनवरत बढ़ता वायुमंडलीय तापमान आज एक चिंताजनक मुद्दा बन चुका है। विगत वर्ष ग्रीन हाउस गैसों, भूमि एवं जलीय तापमान तथा ग्लेशियरों एवं समुद्री बर्फके पिघलनेमें हुई रिकार्डतोड़ वृद्धिका उल्लेख करते हुए, हालमें संयुक्त राष्ट्र एजेंसीने ग्लोबल वार्मिंगके संबंधमें रेड अलर्ट जारी किया। इसके तहत वर्ष २०२३ को अबतकका सर्वाधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया। ग्लेशियरोंके स्वास्थ्यपर इसका प्रतिकूल प्रभाव देखनेमें आया, ध्रुवीय बर्फ पिघलनेके समस्त रिकार्ड ध्वस्त होते दिखाई पड़े। विश्व मौसम विज्ञान संघटनने वैश्विक जलवायुकी स्थिति रिपोर्टपर चिंता जताते हुए, बहुप्रतीक्षित जलवायु लक्ष्यको खतरेमें बताया। यूरोपीय संघकी कॉपरनिकस क्लाइमेट सर्विसके अनुसार मार्च २०२३ से फरवरी २०२४ तक, १२ माहकी अवधिमें तापमान १.५ डिग्री सीमासे आगे निकल गया, जो औसतन १.५६ सैल्सियस (२.८१ फॉरेनहाइट) रहा है। २०२३ में वर्षकी रिकॉर्ड गर्म शुरुआतने १२ महीनेके औसत स्तरमें वृद्धि कर दी। तापमानका निरंतर बढ़ना, धरतीपर संकटके संदर्भमें एक स्पष्ट चेतावनी है। जीवाश्म ईंधन जलनेसे कार्बन डाइऑक्साइडका बढ़ता स्तर इसका प्रमुख कारण रहा। २०२३ के मध्य ९० फीसदीसे अधिक महासागरीय जलमें कमसे कम एक बार लू का अनुभव किया गया। गौरतलब है, १९५० के बादसे ग्लेशियरोंमें बर्फ रिकॉर्ड स्तरपर गायब हो रही है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ घुलकर अबतकके सबसे छोटे आकारमें पहुंच गयी है। इस वायुमंडलीय विक्षोभके विषयमें भारतवर्ष भी अपवाद नहीं। १९७० के बादसे ग्लोबल वार्मिंगको लेकर, अमेरिका स्थित क्लाइमेट सेंट्रलके शोधकर्ताओं द्वारा भारतके संदर्भमें किये गये विश्लेषण के मुताबिक भारतमें सर्दियोंका मौसम तेजीसे गर्म हो रहा हैय वसंत ऋतुकी अवधि लगातार सिमट रही है। देशके कई भागोंमें तो वसंत ऋतु जैसे गायब ही हो चुकी है। शोधकर्ताओंके अनुसार सिकुड़ता वसंत भविष्यमें पारिस्थितिकी तंत्रके लिए नयी चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। जैसा कि इस वर्ष उत्तर भारतमें जनवरीकी ठंडके साथ कुछ दिन हल्की गर्मी भी महसूस की गयी, वहीं फरवरीमें बढ़ती गर्मीके साथ मार्चमें रहने वाली गुलाबी ठंड गायब रही। कुछ दिनकी हल्की ठंडकको छोड़कर मौसम सामान्यत: गर्म रहा, जिसका सीधा असर फरवरी-मार्चमें फूल खिलनेकी प्रक्रियापर पड़ा। गेंदा, कनेर, गुड़हल, गुलाबमें तीव्र बदलाव देखनेको मिले। अध्ययनके तहत इस वर्ष राजस्थानमें जनवरी-फरवरीके तापमानमें २.६ डिग्री सेल्सियसका अंतर रहा। केन्द्रशासित प्रदेशों तथा कुल नौ राज्यों राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तराखंडमें जनवरी-फरवरीके दौरान दो डिग्री सेल्सियससे अधिकका अंतर देखा गया। पूर्वोत्तर राज्यों, मणिपुरमें यह २.३ डिग्री एवं सिक्किममें २.४ डिग्री सेल्सियस रहा। मौसमी चक्रमें यह बदलाव वसंत लुप्त होनेकी आशंकाओंका प्रतीक है। अध्ययनके अनुसार समस्त परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंगके कारण ही देखनेको मिल रहे हैं। वर्ष १८५० के बादसे वैश्विक औसत तापमान १.३ डिग्री सेल्सियससे अधिक बढ़ गया है, जिससे जलवायु प्रभावित हुई। तभी वर्ष २०२३ रिकॉर्ड स्तरपर गर्म रहा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसीके महासचिव सेलेस्टे साउलोके अनुसार पेरिस समझौतेमें सभी देशों द्वारा पृथ्वीके तापमानमें वृद्धिको औद्योगीकरणके पूर्वके स्तरसे १.५ डिग्री सेल्सियस (२.७ डिग्री फॉरेनहाइट) से अधिक नहीं होने देनेपर सहमति जतानेके बावजूद आज पृथ्वी १.५ डिग्री सेल्सियसकी निचली (लक्ष्मण रेखा) सीमाके समीप होना, निश्चय ही चिंताजनक है। यानी विनाशकारी प्रवृत्तिको उलटने हेतु किये गये प्रयास अपर्याप्त हैं। निरंतर बढ़ता वायुमंडलीय तापमान पर्यावरणीय संतुलनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। **-दीपिका, वाया ईमेल।**

अपराधियोंको नायक बनानेकी प्रवृत्ति

मुख्तारके घर नेताओंके जानेका सिलसिला जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादवने अंसारीके घर जाकर उसे महान साबित करनेकी कोशिशको आगे बढ़ाया। उन्होंने बांदा जेलमें मुख्तारकी मृत्युपर सरकारको घेरा। बांदा मेडिकल कालेजने पोस्टमार्टम रिपोर्टमें मृत्युका कारण हार्ट अटैक बताया है।

❑ अवधेश कुमार

मुख्तार अंसारीकी मौतको राजनीतिक दलों, कुछ नेताओं द्वारा विवादास्पद बनाया जा चुका है। जेलमें किसी भी कैदीकी मृत्यु हो कानूनके अनुसार उसकी न्यायिक दंडाधिकारीसे जांच आवश्यक है। यह अंसारीके मामलेमें भी है और जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। बांदा मेडिकल कालेजने पोस्टमार्टम रिपोर्टमें मृत्युका कारण हार्ट अटैक बताया है। बांदा जेलसे भी समाचार यही था कि मुख्तार अंसारीको हार्ट अटैक आया और उसे अस्पताल ले जाया गया। मुख्तार अंसारी, पिछले लम्बे समयसे जब भी वीडियोमें आया काफी कमजोर दिखता था। ह्वील चेयरपर ही उसके बाहर निकलने या अन्दर जानेकी तस्वीरें आयी थीं। उसकी मेडिकल रिपोर्टमें अनेक बीमारियां लिखी हुई है। इतनी बीमारीसे ग्रस्त व्यक्तिकी कभी भी किसी कारणसे मृत्यु हो सकती है। स्वयंको बाहुबल और धनबलकी बदौलत बादशाहत कायम करनेकी मानसिकतामें जीनेवाले व्यक्तिको जेलमें आम अपराधीकी तरह व्यवहारसे मानसिक आघात लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। मानसिक तनाव, दबाव, हताशा मनुष्यको अनेक बीमारियोंसे ग्रस्त करती है। योगी आदित्यनाथ सरकारके कारण बांदा जेलमें वह आम सजा प्राप्त कैदीकी तरह ही था। हमारे देशके कुछ बुद्धिजीवी, संघटन, नेता, राजनीतिक पार्टियों आदिके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्टका कोई मायने ही नहीं है। प्रचारित यह किया जा रहा है कि उसे मारा गया है। जिस तरह कुछ दिनोंसे उसके परिवार और वकील यह खबर फैला रहे थे कि उनको धीमा जहर दिया जा रहा है वह रणनीतिका अंग था। ऐसा लगता था जैसे उसे जमानत देने या मन मुताबिक किसी जेलमें शिफ्ट करनेका आधार बनाया जा रहा था। मृत्युसे कुछ दिनों पहले अपने बेटेसे बातचीतका उसका आडियो वायरल हुआ जिसमें उसके काफी कमजोर होनेका आभास मिल रहा था। वह कह रहा था कि काफी दिनोंसे उसे मोशन नहीं हुआ और यह भी कि शरीर चला जायगा लेकिन रुह रहेगा। अंसारीका बेटा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि पापा आपका शरीर रहेगा और आप हज भी करेंगे। हम अदालतसे गुहार कर रहे हैं और अनुमति मिलते ही आपसे मिलने आयंगे। उसके काफी अस्वस्थ एवं कमजोर होनेके साथ गहरी निराशामें डूबे होनेका पता भी आडियोसे चलता है।

जेल नियमके अनुसार किसी भी कैदीकी हर प्रकारसे देखभाल कानूनी तौरपर अपरिहार्य है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे प्रशासन या जेल या सरकार उसे तत्काल अवैध तरीकेसे मारनेका कदम उठाये। इस समय उसकी मृत्युसे किसीको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला था। ठीक इसके उलट लगातार उसे सजा मिल रही थी और अंतिम समयतक वह जेलमें छटपटाते रहता तो इसका सन्देश अन्य माफियाओं, बाहुबलियों, अपराधियोंके बीच जाता कि ऐसे लोगोंके साथ यही होना है। योगी आदित्यनाथ सरकारकी दृष्टिसे यह स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। मुख्तार अंसारी न्यायालय द्वारा सिद्ध माफिया, हत्यारा, अपहरणकर्ता, सांप्रदायिक दंगा करनेवाला बाहुबली था। ६५ से ज्यादा मुकदमे उसके नामपर थे जिनमेंसे आठमें उसे सजा दी जा चुकी थी। इनमें दोमें उम्रकैदकी सजा थी। यानी न्यायालयने उसे अंतिम सांसतक जेलमें रखनेकी सजा दी थी तो न्यायालय द्वारा घोषित सजाप्राप्त अपराधीको मुसलमानोंका नायक, गरीबोंका मसीहा बताया जा रहा है तथा राजनीतिक पार्टियां और नेता उसके पक्षमें बयान दे रहे हैं इससे ज्यादा डरावना किसी देशके लिए कुछ नहीं हो सकता। वे सरकार और पुलिस प्रशासनके साथ न्यायपालिकापर भी प्रश्न उठा रहे हैं। किसी उदारवादी, समाज हितैषी, हिन्दू मुस्लिम एकताके लिए काम करनेवाले मुसलमानकी मृत्युपर न ऐसी प्रतिक्रियाएं आतीं हैं, न इतने लोग इकट्ठे होते हैं और न उनमें किसी तरहकी भावविह्वलता और आक्रामकता देखी जाती है। इसके विपरीत चाहे मुख्तार अंसारी हो, बिहारका बाहुबली सैयद सहाबुद्दीन, अतीक अहमद या मुंबई बम विस्फोटोंका आतंकवादी टाइगर मेनन उनके जनाजेमें इतने बड़े जन-समूहका उभरना मुस्लिम समाजके अन्दर बढ़ती ऐसी प्रवृत्ति है जिससे डरने और जिसको हर हालमें रोके जानेकी आवश्यकता है।

२०१३ में मुंबई बम विस्फोटोंके अपराधी टाइगर मेननके जनाजेमें मुंबईमें उमड़ी भीड़ने पहली बार देशको हैरतमें डाला था। उस समयसे यह एक स्थापित प्रवृत्ति दिख रही है। अतीक अहमद हत्या पुलिसकी सुरक्षा व्यवस्थापर प्रश्न था और उसका उत्तर देना कठिन था। लेकिन उसकी मृत्युपर विशेष नमाज जगह-जगह अदा कर जन्नतकी दुआ करना किस बातका द्योतक था। डां एपीजे अब्दुल कलामकी मृत्युपर इस तरहका दृश्य नहीं था। वस्तुत: उनके जनाजेमें हिन्दुओंकी संख्या सर्वाधिक थी। राजनीतिके अपराधीकरणके भयावह दौरमें ऐसी अपराधी और बाहुबली हमारे नीति-नियंता बने, जिन्हें उस समय भी जेलमें होना चाहिए था। यह राजनीतिक तंत्रकी विफलता थी कि जिन्हें जेलमें होना चाहिए वह हमारे माननीय विधायक और सांसद बनकर नीति-नियंता बन गये। अतीक, अंसारी या शहाबुद्दीन जैसोंकी एकमात्र योग्यता यही थी कि वह अपने अपराधके बलपर साम्राज्य कायम कर चुके थे तथा चुनाव जीतने-जितानेमें सक्षम थे। इसी कारण सपा-बसपा दोनोंने उन्हें महत्व दिया और कांग्रेस पार्टीका भी उन्हें समर्थन था। सैयद शहाबुद्दीनको भी अपराधी होनेके बाद ही राजदने सांसद बना दिया। माना जाता है कि इनके कारण इन पार्टियोंको कुछ क्षेत्रोंमें मुसलमानोंके बड़े वर्गका वोट मिलता था। सांसद और विधायक बननेके बाद इनका अपराध तंत्र ज्यादा फैला और प्रशासनके लिए उनके विरुद्ध काररवाई हमेशा कठिन रही। आप सोचिये, भाजपा विधायक कृष्णानंद रायकी हत्या मुख्तारने जेलमें रहते हुए करायी और उनकी चुटियातक काट डाली। एक हिन्दू प्रतीक काटनेसे ज्यादा सांप्रदायिकता क्या हो सकती है। अतीक भी जेलसे अपना पूरा तंत्र चलता था और पुलिसकी तरह ही उसके पास इंटेरोगेशन जान देनेके ढांचे बने हुए थे। शहाबुद्दीनकी भी ऐसी ही स्थिति थी। मऊ दंगेमें डीएसपी शैलेंद्र सिंहने जब मुख्तारको गिरफ्तार किया तो उनका कहना था कि तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादवने हर तरह उसे छुड़ानेकी कोशिश की और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अपने त्यागपत्रमें उन्होंने इसकी सार्वजनिक चर्चा की। गाजीपुर जेलमें मुख्तारके साथ स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियोंके बैडमिंटन खेलनेतकके प्रमाण हैं। यदि उत्तर प्रदेशमें योगी आदित्यनाथकी सरकार नहीं होती तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बाबू बजरंगी जैसे लोगोंका कानूनकी गिरफ्तमें इस तरह आना, मारा जाना या सजा देना कतई संभव ही नहीं होता। जरा सोचिये, मुख्तार अंसारीने उत्तर प्रदेशके वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अजय रायके बड़े भाई अवधेश रायकी सरेआम हत्या करवायी और आज कांग्रेस पार्टी उसे अपने एक भी वक्तव्यमें अपराधीतक कहनेके लिए तैयार नहीं है। ऐसी पार्टियोंके होते क्या उसे सजा मिल सकती थी। लेकिन ये पार्टियों भूल रही हैं कि देशने राजनीतिके अपराधीकरणके दौरको पीछे छोड़ दिया और जिन पार्टियोंने ऐसा किया उनकी जगह जहां भी दूसरी पार्टीयों और नेताओंने जीतका विश्वास दिलाया उन्हें मत दिया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीके नेतृत्वमें भाजपाकी केन्द्र या फिर राज्योंमें सरकार गठित होनेके पीछे हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, जन-कल्याणके साथ अपराध और भयमुक्त माहौलकी उम्मीद भी बहुत बड़ा कारण रहा है। योगी आदित्यनाथके नेतृत्वमें २०२२ में भाजपा सरकारकी वापसीका सबसे बड़ा कारण यही था कि अपराधी और माफियाके विरुद्ध काररवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देशमें आम लोगोंके बीच अपराधियों एवं माफियाओंके विरुद्ध किसी भी दबावसे परे अडिग रहते हुए कठोरतासे काररवाई करनेवाले नायकके रूपमें खड़े हुए हैं तो इसी कारण। उत्तर प्रदेशमें सभी समुदायोंका आम आदमी कहता है कि हम अब निर्भय होकर सड़कोंपर चल सकते हैं। इसलिए बसपा, सपा या कांग्रेस या अन्य पार्टी यदि मानती है कि ऐसे नेताओंके पक्षमें खड़ा होकर वे मुस्लिम वोटोंसे फिर विजय प्राप्त कर सत्ता पा लेंगे तो यह सपना अब पूरा नहीं होने वाला। इस व्यवहारके कारण सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाया गया खतरनाक झूठ है। देशमें साम्प्रदायिक तनावका वातावरण पैदा कर रहा है। इस तरहकी राजनीति और एक्टिविज्म भयभीत करनेवाली है।

ऐसे अपराधियोंने न जाने कितने परिवार नष्ट किये, कितनोंका जीवन बर्बाद किया और कहां-कहां, कौन-कौन इनसे प्रतिशोध लेनेकी फिराकमें हो कोई नहीं जानता। इनमेंसे कोई यदि जेलमें या जेलके बाहर उनकी हत्या कर दे, हमले कर दे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग समाजके हीरो नहीं खलनायक हैं। खलनायकको नायक बनानेकी साम्प्रदायिक और विभाजनकारी प्रवृत्ति खतरनाक है। माफियाओं और अपराधियोंको सजा देना न्यायिक प्रक्रियाका अंग है।

मुख्तार अंसारी न्यायालय द्वारा सिद्ध माफिया, हत्यारा, अपहरणकर्ता, सांप्रदायिक दंगा करनेवाला बाहुबली था। इस तरहकी राजनीति भयभीत करनेवाली है। ऐसे अपराधियोंने न जाने कितने परिवार नष्ट किये, कितनोंका जीवन बर्बाद किया। ऐसे लोग समाजके हीरो नहीं खलनायक हैं। खलनायकको नायक बनानेकी साम्प्रदायिक और विभाजनकारी प्रवृत्तिके खिलाफ खड़ा होनेकी आवश्यकता है। हमारे देशमें न्यायका शासन है। माफियाओं और अपराधियोंको सजा देना न्यायिक प्रक्रियाका अंग है। यह जितना मुसलमानपर लागू होता है उतने ही हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारस, ईसाई सभीपर।

गठबंधनमें कांग्रेसकी प्रासंगिकता

राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेशको छोड़ कर केरल चले गये हैं। केरलमें भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र वायनाडको उन्होंने अपने लिए चुना है। उन्हें लोकसभामें जानेके लिए कांग्रेसकी विचारधाराके कारण वायनाड ही सुरक्षित लगता है।

❑ कुलदीप चंद अग्निहोत्री

भारतीय जनता पार्टीको हरानेके लिए विपक्षी पार्टियोंमें जो सर्वाधिक व्याकुल प्राणी थे, उनमेंसे चार शिखरपर थे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और कम्युनिस्ट। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैंने अन्य दलोंका नाम न लिखकर, उन दलोंके प्रमुख व्यक्तिका नाम लिखा है, लेकिन कम्युनिस्टोंके मामलेमें व्यक्तिका नाम न लिख कर केवल कम्युनिस्ट शब्दका प्रयोग क्यों किया है। उसका कारण है। हमारे भारतमें कम्युनिस्ट सदा किसी शरीरकी तलाशमें रहते हैं। जब कम्युनिस्ट अपने शरीरमें प्रकट होते हैं तो भारतके लोग उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और नकार देते हैं। इसलिए वे निरंतर किसी दूसरे शरीर, जिंदा या मुर्दाकी तलाशमें रहते हैं और अपनी सुविधानुसार उसे पा भी लेते हैं। उनकी ऐसी पृष्ठभूमिमें उनके किसी शीर्ष पुरुषका नाम पहचान पाना या तलाश करना बहुत मुश्किल है। उनके शीर्ष पुरुष आपसमें इतने मिले-जुले हैं कि किसीको पहचान पाना ही मुश्किल है। इसलिए मैंने किसी व्यक्ति विशेषका नाम न लिखकर नंगा चिट्टा कम्युनिस्ट शब्दका प्रयोग ही किया है। लेकिन नीतीश कुमार इंडी मोहल्ला छोड़कर वापस अपने घर लौट गये हैं। ममता बनर्जी इंडी मोहल्ला उस मोहल्लाके बाकी लोगोंसे उन्होंने बोलचाल बंद कर दी है। उनकी पार्टीने पश्चिम बंगालकी सभी सीटोंपर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिये हैं। लेकिन वैसे वे बराबर कह रही हैं कि वे इंडीके साथ मजबूतीसे खड़ी हैं और बंगालको छोड़कर बाकी सभी जगह उसका समर्थन कर रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी इतना तो जानती हैं कि उनकी पार्टीको यदि ममता बनर्जीकी जरूरत थी तो केवल बंगालमें थी।

शेष भारतमें ममता बनर्जी खुद भी जानती हैं कि उनकी हैसियत ही नहीं है। एक दूसरी पार्टी है जो इंडी गठबंधनमें सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं देती। यह पार्टी अब भारतमें अशरीरी हो गयी है। उसका नाम मुस्लिम लीग है। यह कांग्रेसके पैदा होनेके कुछ साल बाद १९०५ में पैदा हुई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजोंने इस पार्टीको पैदा करनेके लिए ही बंगालका विभाजन किया था। मुस्लिम लीगको पैदा करनेके बाद बंगाल विभाजनको भी खत्म कर दिया था। १९१६ में कांग्रेस और मुस्लिम लीगने अंग्रेजोंसे भारतके मुसलमानोंके लिए अलग निर्वाचन मंडलकी मांग की थी। बादमें संबंध बनते बिगड़ते गये, लेकिन कांग्रेसने १९४७ में अपनी कार्यसमितिकी अंतिम बैठकमें मुस्लिम लीगकी भारत विभाजनकी मांगका समर्थन करनेके लिए भारत विभाजनका प्रस्ताव पारित किया था। भारत विभाजनके बाद जब बचे-खुचे भारतमें मुस्लिम लीगके लिए रहना मुश्किल हो गया तो उसने अपना रूप बदल लिया था। उससे चेहरा तो बदल लिया लेकिन भारतके लोग उनकी आवाज अच्छी तरह पहचानते ही हैं। इसलिए वे चिल्ला रहे हैं। यह वही मुस्लिम लीग है जिसने भारतका विभाजन करवाया था। लेकिन सोनियाका कहना है कि यह पुरानेवाली मुस्लिम लीग नहीं है। यह नयी ताजा मुस्लिम लीग है जिसका पुरानी मुस्लिम लीगसे कोई ताल्लुक नहीं है। पता चला है कि कुछ पुराने कांग्रेसियोंने कानमें बताया भी कि मैडम, आपको पुरानीवालीका पता नहीं है, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि इटलीकी है। यह मुस्लिम लीग शत-प्रतिशत पुरानेवाली मुस्लिम लीग ही है। लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी। वह उसीको सच मानती हैं जो राहुल-प्रियंका-राबर्ट वाड्रा बताते हैं। अब यह नयीवाली मुस्लिम इंडीका हिस्सा है। उसका परिणाम भी सामने आने लगा है। सोनियाकी पार्टीने अपना जो चुनाव घोषणापत्र जारी किया है, यदि उसको ध्यानसे पढ़ा जाय, जिससे अंग्रेजीवाले टू रीड बिटवीन दी लाईन्ज कहते हैं तो वह काफी हदतक १९४७ से पहलेका मुस्लिम लीगके चुनाव घोषणापत्रका नया संस्करण लग रहा है। अब तवलीन सिंहका कहना है कि आधा हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टीका ही है। सोनिया गांधी जीकी एक दूसरी समस्या भी है। वह मुस्लिम लीगका समर्थन तो लेना चाहती हैं, लेकिन यह नहीं चाहती कि लोग इसको जान लें। वैसे पूछा जा सकता है कि गुड़ तो खायें, लेकिन गुलगुलोंसे परहेजकी इस नीतिका कारण क्या है। जब अपने चुनाव घोषणापत्रमें मुस्लिम लीगका घोषणापत्र समेट लिया, अयोध्यामें राम मंदिरमें आनेके निमंत्रणको सार्वजनिक रूपसे ठुकरा दिया और मुस्लिम लीगको मंचपर भी बिठा लिया तो अब बचा क्या है। फिर यह हिचकिचाहट कैसी। यह संकट केरलके वायनाडमें आया। राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेशको छोड़कर केरल चले गये हैं। केरलमें भी मुस्लिमबहुल क्षेत्र वायनाडको उन्होंने अपने लिए चुना है। सारे देशमें उन्हें लोकसभामें जानेके लिए अपनी पार्टीकी विचारधारा और उसके अनुरूप मित्रोंके कारण वायनाड ही सुरक्षित लगता है। यह पांच साल पहले ही स्पष्ट हो गया था जब राहुल गांधीको उत्तर प्रदेशकी जनताने अमेठीमें ठुकरा दिया था और वायनाडने उन्हें संकटके उस कालमें सुरक्षा चक्र प्रदान किया था। तब बहुतसे राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे थे कि राहुल गांधी अब पांच साल मेहनत करके उत्तर प्रदेशके लोगों का विश्वास जीतेंगे। लेकिन शायद सोनिया परिवारने यह लंबा रास्ता अख्तियार करने की बजाय वायनाडका सुरक्षा चक्र लेना ही उचित समझा। लेकिन इस बार एक झंझट हो गया। राहुल गांधी दिल्लीसे वायनाडतककी लंबी दूरी तय करके लोकसभा चुनावके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वायनाड पहुंचे तो स्वाभाविक ही मनमें आया होगा कि शक्ति प्रदर्शनके लिए रोड शो भी कर लिया जाय। कांग्रेस पार्टीके झंडे बड़ी संख्यामें तैयार कर लिये गये। स्वाभाविक है जो मुस्लिम लीग उनको सुरक्षा चक्र प्रदान करती है, उन्होंने शर्त लगा दी कि रोड शोमें उनके झंडे भी बराबर लगेंगे। यह राहुल गांधीको स्वीकार नहीं था।

यदि रोड शो हुआ तो मुस्लिम लीगके झंडोंके साथ ही। तब कांग्रेसने इटलीके मैकियावलीको याद किया होगा। मध्य मार्ग। झंडा न कांग्रेसका लगेगा और न ही मुस्लिम लीगका। देशमें शायद कांग्रेसका पहला रोड शो था जिसमें कांग्रेसके झंडोंको ही मुस्लिम लीगको प्रसन्न करनेके लिए, कांग्रेसके लिए ही हानिकारक मान लिया गया। लेकिन कांग्रेसकी समस्याओंका हल केवल मुस्लिम लीगको प्रसन्न कर ही तो होनेवाला नहीं लगता। मुस्लिम लीग खुश हुई तो कम्युनिस्ट बोले। कम्युनिस्ट दो रूपोंमें हैं। पहला, जो कांग्रेसके शरीरके बीच ही घुसकर बैठा है। दूसरा रूप शरीरसे बाहर विद्यमान है। कई बार बाहर वाला शरीर प्रश्न करता है और अंदरवाला जवाब देता है। यह जवाब वही होता है जो बाहर वाले कम्युनिस्टकी हित साधना करता है। लेकिन वायनाडने सब गड़बड़ कर दिया। कम्युनिस्टोंने राहुल गांधीसे पूछा कि आप तो पिछले दस सालसे चिल्ला रहे हो कि आपकी लड़ाई भाजपावालोंसे है, लेकिन आप केरलमें तो हमसे ही लड़ रहे हो। हम दिल्लीमें आपके साथ एक मंचपर बैठ कर लम्बे भाषण देते हैं। मिलकर भाजपाके साथ लड़नेकी हुंकार लगाते हैं, लेकिन उस सबके बावजूद आप केरलमें हमसे ही लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जी इसका क्या उत्तर दें। फिलहाल कांग्रेसको पुन: अपना धरातल तलाशना चाहिए, अपनी उपयोगिता स्थापित करनी चाहिए। तभी उसका कल्याण होगा।

माता बालासुंदरी

❑ निलेश शास्त्री

पूरे उत्तर भारतमें अपनी पहचान बना चुका जिला सिरमौरका त्रिलोकपुर स्थित माता बालासुंदरी मंदिर लाखों श्रद्धालुओंकी आस्थाका केंद्र है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बालासुंदरी ५१ शक्तिपीठोंमेंसे एक है। सिरमौर जिलाके मुख्यालय नाहनसे २३ किलोमीटरकी दूरीपर स्थित है माता बालासुंदरी मंदिर। उल्लिखित है कि शक्तिपीठ माता बालासुंदरी उत्तर प्रदेशके मुजफ्फर नगरके देवबंदसे नमककी बोरीमें पिंडीके रूपमें त्रिलोकपुर आयी थी। बताया जाता है कि एक व्यापारी लाला रामदास त्रिलोकपुरमें नमकका व्यापार करते थे। उनकी दुकान त्रिलोकपुरमें पीपलके वृक्षके नीचे हुआ करती थी। मंदिरके समीप ही पीपलके वृक्षके नीचे लाला रामदास प्रतिदिन पूजा करते थे, परन्तु उन्हें चिन्ता सता रही थी कि आखिरकार उनकी दुकानमें रखा नमक समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन माता बालासुंदरीने प्रसन्न होकर रात्रिको लाला रामदासको स्वप्नमें दर्शन देकर कहा कि भक्त मैं तुम्हारे भक्ति भावसे अति प्रसन्न हूं। मैं यहांपर पीपलके वृक्षके नीचे पिंडीके रूपमें स्थापित हूं। लाला रामदासने मातासे प्रार्थना की और कहा कि मंदिर निर्माणके लिए उसके पास धनका अभाव है तथा इस बारेमें रियासतके महाराजाको भवन निर्माणका आदेश दें। तब माता बालासुंदरीने भक्तकी पुकार सुन ली और सिरमौर रियासतके शासक राजा दीप प्रकाशको मंदिर बनानेका आदेश दिया। राजाने १५७३ में त्रिलोकपुरमें माता बालासुंदरी मंदिरका निर्माण आरंभ करवाया। इसके लिए विशेष रूपसे महाराजाने जयपुरसे कारीगरोंको बुलाया। १६३० में मंदिरका निर्माण पुर्ण हुआ। यहांपर माता बालासुंदरी तीन रूपमें विराजमान हैं। ललिता देवी, बालासुंदरी एवं त्रिभावनी। ललिता देवीका मंदिर बालासुंदरीसे चार किलोमीटर दूर पहाड़ीपर स्थित है, जबकि मां त्रिभावनीका मंदिर पश्चिम उत्तर दिशामें स्थित है। इन दोनों मंदिरोंके बीच माता बालासुंदरीका भव्य मंदिर है। मंदिर परिसरका द्वार एक भव्य सिंहकी मूर्तिसे बना है। मंदिरके भीतर गणेश, शिव परिवार, हनुमान, मां काली, मां मनसा देवी आदि भी विराजमान हैं। माता बालासुंदरी मंदिरमें वर्षमें दो बार नवरात्रके दौरान मेलेका आयोजन होता है। चैत्र माहमें लगनेवाले मेलेको बड़ा मेला और अश्विन माहमें लगनेवाले मेलेको छोटा मेला कहा जाता है। मेलोंके दौरान श्रद्धालुओंकी सुविधाका पूरा ध्यान रखा जाता है। कहते हैं कि माता बालासुंदरीके दरबारमें जो भी भक्त सच्चे मनसे अरदास करता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। यहांपर दर्शन करनेसे भक्तोंको सुख और समृद्धिकी प्राप्ति होती है।

जलवायु परिवर्तनसे तत्काल निबटनेकी जरूरत

❑ मनिंदर सिंह

जलवायु परिवर्तन अब कोई दूरकी चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान वास्तविकता है जिसपर तत्काल ध्यान देनेकी आवश्यकता है। गर्म मौसमसे लेकर समुद्रके बढ़ते स्तर और संसाधनोंकी कमीतक इसका प्रभाव विश्व स्तरपर महसूस किया जा रहा है। हालांकि इन चुनौतियोंके भीतर पर्यावरणके प्रति जागरूक निर्णय लेनेका अवसर भी छिपा है। शहरी खेती, जिसे कभी विशिष्ट माना जाता था, अब जलवायु परिवर्तनके प्रभावोंको कम करनेके लिए एक व्यावहारिक प्रतिक्रियाके रूपमें पहचानी जाती है। शहरी स्थानोंको टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्रमें परिवर्तित करके, शहरी खेतीमें हमारे पर्यावरणीय प्रबंधनको बदलने और अधिक लचीला भविष्य बनानेकी क्षमता है।

जलवायु परिवर्तनसे निबटनेकी तत्काल आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओका अनुमान है कि २०३० के दशकतक मलेरिया और तटीय बाढ़ जैसी जलवायु संबंधी बीमारियोंके कारण वार्षिक २५०,००० अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। तापमान, पिघलती बर्फकी परतें और अधिक बार होनेवाली गर्म मौसमकी घटनाएं अस्थिर प्रथाओंके परिणामोंमेंसे हैं। अब काररवाई करनेका समय आ गया है और शहरी खेती आगे बढ़नेका एक आशाजनक मार्ग प्रस्तुत करती है। शहरी खेती- शहरी खेतीमें शहरोंके भीतर और आसपास फसलोंकी खेती शामिल है। यह प्रथा न केवल ताजा, स्थानीय रूपसे उगायी गयी उपज प्रदान करती है, बल्कि इसके कई पर्यावरणीय लाभ भी हैं। भोजनकी लंबी दूरीके परिवहनकी आवश्यकताको कम करके, शहरी खेती कार्बन उत्सर्जनको कम करनेमें मदद करती है। इसके अलावा, जैविक कृषि पद्धतियोंके उपयोगसे मिट्टीके स्वास्थ्य और जैव विविधतामें सुधार हो सकता है, जो जलवायु लचीलेपनमें और योगदान दे सकता है।

शहरके स्थानोंको बदलना- शहरी खेतीके प्रमुख लाभोंमेंसे एक कम उपयोगवाले शहरी स्थानोंको जैविक खाद्य उत्पादन केन्द्रोंमें बदलनेकी क्षमता है। खाली जगहों, छतों, बालकनियों और यहांतक कि खड़ी सतहोंको खेतीके लिए पुन: उपयोग किया जा सकता है, जिससे शहरी क्षेत्रोंके बीचों-बीच हरित स्थान तैयार किया जा सकता है। यह न केवल शहरोंकी सौंदर्य अपीलको बढ़ाता है, बल्कि शहरी ताप द्वीप प्रभावको कम करनेमें भी मदद करता है, जो जलवायु परिवर्तनके प्रभावोंको बढ़ा सकता है। सामुदायिक व्यस्तता- शहरी खेती सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक एकजुटताको भी बढ़ावा देती है। भोजन उगाने और सांझा करनेके लिए लोगोंको एक साथ लाकर, शहरी फार्म सामाजिक बंधनको मजबूत कर सकते हैं और अपनेपनकी भावना पैदा कर सकते हैं। यह घनी आबादीवाले शहरी क्षेत्रोंमें विशेष रूपसे महत्वपूर्ण हो सकता है जहां सामाजिक अलगाव एक बढ़ती चिंताका विषय है। इसके अलावा शहरी खेती स्थानीय निवासियों, विशेषकर वंचित समुदायोंके लिए आर्थिक अवसर प्रदान कर सकती है।

नीति समर्थन- शहरी खेतीकी क्षमताको पूरी तरहसे साकार करनेके लिए सहायक नीतियों और प्रोत्साहनोंकी आवश्यकता है, जबकि कुछ राज्य सरकारोंने सब्सिडी प्रदान करके अपना समर्थन बढ़ाया है और इस प्रकार शहरी खेतीके लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया है, नीति निर्माता इस स्थायी अभ्यासको बढ़ाने और इसे अधिक लोगोंके लिए सुलभ बनानेमें मदद कर सकते हैं। जमीनी स्तर- शहरी खेतीमें जलवायु परिवर्तनके खिलाफ लड़ाईमें गेम चेंजर बननेकी क्षमता है। शहरी स्थानोंको टिकाऊ आश्रयोंमें परिवर्तित करके, शहरी खेती कार्बन उत्सर्जनको कम करने, खाद्य सुरक्षामें सुधार करने और शहरी क्षेत्रोंकी लचीलापन बढ़ानेमें मदद कर सकती है। हालांकि इस क्षमताको साकार करनेके लिए नीति-निर्माताओं, समुदायों और व्यक्तियोंके ठोस प्रयासोंकी आवश्यकता होगी। अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तनके समाधानके रूपमें शहरी खेतीको अपनाया जाय और अधिक टिकाऊ भविष्यकी दिशामें काम किया जाय।

देशप्राण स्वतंत्र हिन्दी दैनिक

सोमवार
रांची, 15 अप्रैल, 2024

चर्चा में मंडी का चुनाव

मंडी संसदीय क्षेत्र ने अचानक सारे राष्ट्र की निगाहें हिमाचल की ओर मुखातिब की हैं। मानना पड़ेगा कि यह सब वहां से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की वजह से कहीं ज्यादा हो रहा है। चुनावी फलक के दूसरे छोर पर वीरभद्र सिंह परिवार का पारंपरिक दुर्ग और उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकार खड़ा है। बात कहां से चली और कहां तक पहुंचेगी, लेकिन आरंभिक जोश से ही मालूम पड़ता है कि मंडी चुनाव में जाहिर मंतव्य किसी भी हद तक जहरीला और व्यक्तिगत आक्षेपों में माहिर होना चाहता है। यहां कंगना की पृष्ठभूमि, ग्लैमर और बेबाकी के सामने विक्रमादित्य सिंह की राजनीतिक समझ, वाकपटुता और सत्ता में भागीदारी खड़ी है। कंगना का प्रचारतंत्र देश के लिए और देश के सामने, भाजपा का अभ्यास वर्ग है, इसलिए जरूरी नहीं कि वह हिमाचली मुद्दों की बिसात तक ही रहे। इसलिए वह सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय बहस की पात्र बनी रहना चाहती है और मुकाबले के हर पहलू में मंडी के स्वाभिमान और पहाड़ की बेटी होने का मर्म जाग्रत करती है। इस तरह वह न तो अधकचरी और न ही आसान हस्ती हैं। विवाद उनका गहना और चर्चाएं उनका पोशाक है। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में यह दूसरी बार हो रहा है जब कोई सियासी शख्सियत अपनी गैर मौजूदगी में भी चर्चाओं से दूर नहीं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को जब प्रदेश की राजनीति से दूर केंद्रीय मंत्री के दायित्व में सीमित करने के जोरदार प्रयास हो रहे थे, तब भी वह हिमाचल की हर बहस के प्रमुख पात्र थे। हिमाचल के प्रवेशद्वारों यानी सोलन व ऊना जिलों में वह बयान दाग कर विपक्ष को तब तक चर्चा का मौका देते थे, जब तक वह दिल्ली नहीं लौट जाते। उनकी शब्दावली से निकले रौंदू या मकरझंडू जैसे शब्दों की व्याख्या आज भी विरोधियों के सिर में खुजली करती है, जबकि उनकी हाजिरजवाबी का अंदाज आजकल के नेताओं में ढूंढे नहीं मिलता। ऐसे में कंगना का राजनीतिक अवतार पुनः बहस के कटोरे में कई खड्डों का पानी भर रहा है। सवाल यह है कि हिमाचल की जनता को अब इस स्तर की बहस में मजा आने लगा है। क्या वह नारी होने के कारण विरोधियों पर भारी होने जा रही है। क्या उसे राष्ट्रीय बहस में हिमाचल के मुद्दे गौण करने से लाभ होगा या कांग्रेस की लंका जलाते हुए अपने हाथ जलाने चाहिएं। जो भी हो, मनाली में उसके निशाने अगर बड़े पप्पू बनाम छोटे पप्पू को खोज रहे हैं, तो यह नई राजनीति का पहला संदेश भी है। इस दौर की आक्रामकता की पेशगी में कंगना बता चुकी है कि वह अपनी तरह की बिसात पर कुछ भी फैला सकती है। जो भी हो हिमाचल में अब सवाल कंगना बनाम विक्रमादित्य सिंह तक ही नहीं, बागी कांग्रेसी बनाम कांग्रेस, राजनीतिक गोटियां बनाम हकीकत, दोस्त बनाम कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री बनाम वर्तमान, डबल इंजन बनाम व्यवस्था परिवर्तन और इसी तरह उम्मीदवारों के चयन में कहीं गद्दी बनाम चौधरी, पंडित बनाम राजपूत और दलित बनात कबायली भी होने लगा है।

जब झुंझुनू से चुनाव हार गए थे उद्योगपति कृष्ण कुमार बिड़ला

रमेश सर्राफ धमोरा

हरियाणा सीमा पर स्थित राजस्थान का झुंझुनू जिला एक तरफ जहां पूरे देश में सैनिकों के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश के बहुत से बड़े-बड़े उद्योगपति भी झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। हालांकि सभी बड़े उद्योगपति झुंझुनू जिले से बाहर जाकर अपना व्यवसाय बढ़ा कर उद्योग जगत में अपना नाम कमाया है। मगर कई बार औद्योगिक घरानो के परिवार के सदस्य अक्सर झुंझुनू आते रहते हैं। इसी तरह भारतीय सेना में देश में किसी एक जिले से सबसे अधिक सैनिक झुंझुनू जिले के जवान है। वही देश में सबसे अधिक शहीद भी झुंझुनू जिले के सैनिक हुए हैं।

चुनाव में एक तरफ देश के सबसे धनवान प्रत्याशी थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक साधारण किसान चुनाव लड़ रहा था। उस वक्त के चुनाव में धनवान बनाम किसान का नारा लगा था। स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण कुमार बिड़ला ने अपने कल कारखानों में कार्यरत झुंझुनू जिले के सभी लोगों को चुनाव प्रचार के लिए झुंझुनू भेज दिया था। बिड़ला की ओर से बड़े भव्य तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था तथा जमकर पैसा खर्च किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवनाथ सिंह गिल सामान्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव नतीजे आए तो सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक दंग रह गए। बड़े-बड़े राजनीतिक भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी फेल हो गई। देश के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के कृष्ण कुमार बिड़ला को कांग्रेस के एक किसान परिवार के प्रत्याशी शिवनाथ सिंह गिल ने 98949 वोटो के अंतर से चुनाव हार दिया था।

देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी जगह चुनावी चर्चाएं जोरों से चल रही है। झुंझुनू जिले में 1971 का लोकसभा चुनाव पूरे देश में चर्चित रहा था। उस समय देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार बिड़ला घराने के कृष्ण कुमार बिड़ला स्वतंत्र पार्टी से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक साधारण किसान के घर जन्मे शिवनाथ सिंह गिल को चुनाव मैदान में उतारा था। पिलानी के रहने वाले बड़े उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला के सुपुत्र कृष्ण कुमार बिड़ला का उस समय देश के उद्योग जगत में एक बड़ा नाम होता था। लाखों की संख्या में लोग बिड़ला घराने के औद्योगिक संस्थानों में काम करते थे।

दूसरी तरफ बैंकों के राष्ट्रीयकरण व पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की देशभर में हवा चल रही थी। उस समय देश में इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है नारा बहुत चर्चित हुआ था। उस नारे की बदौलत देश में कांग्रेस की ऐसी हवा चली थी कि विपक्ष के कई बड़े धुरंधर नेता चुनाव हार गए थे। इंदिरा गांधी ने बिड़ला घराने के कृष्ण कुमार बिड़ला को हराने के लिए जिले के धमोरा गांव के शिवनाथ सिंह गिल को चुनाव मैदान में उतार दिया था। उस समय शिवनाथ सिंह गिल गुढ़ा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक थे।

चुनाव में एक तरफ देश के सबसे धनवान प्रत्याशी थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक साधारण किसान चुनाव लड़ रहा था। उस वक्त के चुनाव में धनवान बनाम किसान का नारा लगा था। स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण कुमार बिड़ला ने अपने कल कारखानों में कार्यरत झुंझुनू जिले के सभी लोगों को चुनाव प्रचार के लिए झुंझुनू भेज दिया था। बिड़ला की ओर से बड़े भव्य तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा था तथा जमकर पैसा खर्च किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवनाथ सिंह गिल सामान्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे।

जब चुनाव नतीजे आए तो सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक दंग रह गए। बड़े-बड़े राजनीतिक भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी फेल हो गई। देश के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के कृष्ण कुमार बिड़ला को कांग्रेस के एक किसान परिवार के प्रत्याशी शिवनाथ सिंह गिल ने 98949 वोटो के अंतर से चुनाव हार दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस के शिवनाथ सिंह गिल को 223286 यानी 59.79 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं स्वतंत्र पार्टी के कृष्ण कुमार बिड़ला को 124337 यानी 33.30 प्रतिशत वोट मिले थे। कामरेड घासीराम को 9548 वोट, हणुताराम को 5073 वोट, बलदेव प्रसाद को 3143 वोट, दुलाराम को 3013 वोट, महादेव प्रसाद को 2113 वोट, बृजमोहन को 1801 वोट, तारावती को 1113 वोट मिले थे। उस चुनाव में मुल 9 प्रत्याशी खड़े हुए थे। मगर मुख्य मुकाबला कृष्ण कुमार बिड़ला व शिवनाथ सिंह गिल के बीच ही हुआ था।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद बिड़ला परिवार का झुंझुनू जिले से मोह भंग हो गया और उन्होंने अपनी जन्म भूमि पिलानी में एक शैक्षणिक संस्थान बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स) के अलावा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जिले की जनता के काम आ सके। हालांकि बाद में कृष्ण कुमार बिड़ला कांग्रेस के टिकट पर 1984 से 2002 तक लगातार 18 वर्षों तक राज्यसभा सदस्य रहे। बाद में कृष्ण कुमार बिरला की बेटी व हिंदुस्तान टाईम्स अखबार की अध्यक्ष शोभना भरतीया भी एक बार कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रह चुकी है।

कहते हैं कि उस चुनाव में बिड़ला परिवार ने अपने यहां काम करने वाले लोगों को चुनाव प्रचार के लिए झुंझुनू भेज दिया था और बिड़ला परिवार के बड़े-बड़े मैनेजर अलग-अलग विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे। जब वह अपने समर्थन में आए हुए लोगों से चुनाव के दौरान चुनाव की स्थिति पूछते थे तो सभी लोग कहते थे कि बाबू बारह आना यानी की 12 आने में बाबू है बाकी में शिवनाथ सिंह गिल है। मगर जब बिड़ला परिवार की चुनाव में हार हो गई तो लोगों ने एक जुमला बना लिया कि बाबू बिड़ला तो पहले ही बारह आना थे। यानी कि पहले ही उनके भाव खराब थे। उस समय बाबू बारह आना बहुत चर्चित हुआ था।

पुराने लोग बताते हैं कि चुनाव के दौरान बिड़ला परिवार ने लोगों से वायदा किया था कि यदि कृष्ण कुमार बिड़ला चुनाव जीतते हैं तो जिले में ऐसे बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की जाएगी जिससे आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर बिड़ला परिवार की हार के बाद उन्होंने जिले के विकास में कोई रुचि नहीं ली। 1971 में बिड़ला को भारी मतों से हराने वाले शिवनाथ सिंह गिल भी 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की लहर में कन्हैयालाल महला से सवा लाख से ज्यादा मतों से चुनाव हार गए थे।

बाबा साहेब के तीन सूत्र-संगठित हों, शिक्षित हों और आंदोलन करें

वीरेंद्र कुमार यादव

(सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति, भारत सरकार, सह अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय हिन्दी परिषद)

डॉ अम्बेडकर ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ा। डॉ अम्बेडकर अपनी पार्टी के 14 सहयोगियों के साथ बंबई विधानसभा के लिए चुन लिए गए। फरवरी 1938 में मनमाड़ रेल मजदूरों के विराट सम्मेलन में घोषित किया था कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद श्रमजीवी वर्ग के दुश्मन हैं। उन्होंने अछूत कामगार नहीं रखे जाने की श्रम नीति का विरोध किया था और औद्योगिक विवाद बिल जिसमें हड़ताल का अधिकार अस्वीकार किया था, का विरोध किया। वे जुड़वें खतरों पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए किसी का भी साथ देने के लिए तैयार थे। सैनिक बलों में अधिकारी पद पर दलित वर्गों के लोगों को रखने पर लगी रोक को हटवाने के लिए केन्द्रीय विधान सभा में प्रस्ताव पास कराने में उनका हाथ था। नवंबर 1943 में उन्होंने दलित वर्गों के लिए सरकारी तथा उच्च संस्थानों में 8.5% नियुक्तियां हासिल कर ली थी।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर हमारे संविधान निमार्ता, दलितों के मसीहा, समस्त सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के प्रति विद्रोह का झंडा उठाने वाले सच्चे देशभक्त थे। वे ख्याति के शिखर पर भाग्य से अथवा संयोगवश नहीं बल्कि अपने प्रखर व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग, निस्वार्थ,विद्वता, समर्पण और वचन बद्धता के बल पर पहुंचे थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था।

भीमराव के पिता 1904 में मुंबई चले आए। भीमराव ने 1907 में एलफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास किया।1912 में बीए किया। कॉलेजी शिक्षा के लिए बड़ौदा के महाराजा ने 25 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति दी थी। अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने करने के लिए भी बड़ौदा के महाराजा ने छात्रवृत्ति दी थी। भीमराव ने 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में नाम लिखाया और अगले वर्ष ही* भारत में राष्ट्रीय लाभांश - एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन* नामक शोध प्रबंध पर उन्हें पी.एच.डी.की डिग्री मिली। बाद में यह शोध प्रबंध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त व्यवस्था नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। अक्टूबर 1916 में वे डी एस सी अर्थशास्त्र तथा बार एट लॉ के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल और साइंस और ग्रेज इन में दाखिल हुए। एक वर्ष बीता ही था कि छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त हो गई। जिनके कारण महाराजा ने उन्हें वापस बुला लिया। कुछ समय तक उन्होंने महाराजा के सैनिक सचिव के रूप में काम किया। परंतु वहां अमानवीय बर्ताव और उच्च वर्गों के लोगों के द्वारा सताये जाने के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया। वे बंबई लौट आए। नवंबर 1918 में वे सिडनहॅम कॉलेज में राजनीति अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। लेकिन उच्च शिक्षा की उनकी ललक ललक बरकरार थी। 1920 में स्वयं वे अपने खर्च पर अध्ययन जारी रखने के लिए लंदन गए और एम. एस.सी. अर्थशास्त्र, बार एट लॉ तथा डी एस सी अर्थशास्त्र की डिग्रियां हासिल की। अप्रैल 1923 में अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटे तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में संघर्ष जोर पकड़ता जा रहा था। जातीय भेदभाव के भयानक यंत्रणाओं के भुक्तभोगी होने के कारण उन्हें लगा कि जब तक यहां सामाजिक भेदभाव दूर नहीं किए जाते तब तक ब्रिटिश राज से मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है।

डॉ अम्बेडकर को अपने प्रखर विचारों के कारण अपने समय के बुद्धिजीवियों का रोष पात्र बनना पड़ा । सवर्ण वर्ग के बुद्धिजीवियों और कांग्रेस नेताओं ने उनके विचारों को राष्ट्र विरोधी कहा और तरह तरह के आरोप लगाये। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड जाने से पूर्व डॉ अम्बेडकर ने कहा मैं वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए न्यायसंगत है और स्वराज्य के मांग का मैं निश्चय ही समर्थन करूंगा। 25 सितंबर 1932 पूना समझौता होने के बाद, जिसके अनुसार दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हुई थी। डॉ अम्बेडकर ने लिखा खोए हुए अधिकार भीख मांगने या हड़पने वाले के अंतःकरण को अपील करने से कभी नहीं मिलते । वे मिलते हैं निरंतर संघर्ष से। पूना समझौते के अवसर पर प्रीतिभोज में शामिल होने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल पीकर अपने को शुद्ध किया वे दलितों को ऊपर उठाने में सच्चे दिल से रूचि नहीं लेंगे । डॉ अम्बेडकर ने इसी कारण पंचायतों को राज्य की मूल इकाई बनाने का विरोध किया क्योंकि वे जानते थे कि यदि गांव में पंचायत सर्वेसर्वा हो गई तो दलित जनों का गांवों में रहना मुश्किल हो जाएगा। डॉ अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तीन व्यवहारिक नारे दिये थे। संगठित हों, शिक्षित हों और आंदोलन करें।

डॉ अम्बेडकर ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ा। डॉ अम्बेडकर अपनी पार्टी के 14 सहयोगियों के साथ बंबई विधानसभा के लिए चुन लिए गए। फरवरी 1938 में मनमाड़ रेल मजदूरों के विराट सम्मेलन में घोषित किया था कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद श्रमजीवी वर्ग के दुश्मन हैं। उन्होंने अछूत कामगार नहीं रखे जाने की श्रम नीति का विरोध किया था और औद्योगिक विवाद बिल जिसमें हड़ताल का अधिकार अस्वीकार किया था, का विरोध किया। वे जुड़वें खतरों पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए किसी का भी साथ देने के लिए तैयार थे। सैनिक बलों में अधिकारी पद पर दलित वर्गों के लोगों को रखने पर लगी रोक को हटवाने के लिए केन्द्रीय विधान सभा में प्रस्ताव पास कराने में उनका हाथ था। नवंबर 1943 में उन्होंने दलित वर्गों के लिए सरकारी तथा उच्च संस्थानों में 8.5% नियुक्तियां हासिल कर ली थी। अप्रैल 1944 में मजदूरों को सवेतन अवकाश दिया जाए इस बिल को पास कराया।

13 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। मुस्लिम लीग तो बहिष्कार कर ही रही थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी सभा में उपस्थित नहीं थे।जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लक्ष्य और उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया तो श्री एम आर जयकर ने संशोधन पेश करते हुए कहा कि प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाए बल्कि लोगों को समझा बुझाकर सभा में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाय। फ्रैंक एन्थोनी ने जयकर का समर्थन किया। इस बीच सभापति डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ अम्बेडकर को बोलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा प्रश्न यह नहीं है कि सभी को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है या नहीं पर प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना बुद्धिमानी का काम होगा ? यदि मुसलमानों के सहयोग और स्वीकृति के बिना संविधान बना तो उसका परिणाम क्या होगा? प्रस्ताव को पारित न करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के इतिहास के निर्माण के समय नेताओं और दलों की प्रतिष्ठा आड़े नहीं आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब मुसलमान भी यह सोचेंगे कि संयुक्त भारत में ही सभी का कल्याण है। उन्होंने व्यक्त की कि विभिन्न धर्मों और जातियों के बावजूद एक संयुक्त भारत बन कर रहेगा। इस भाषण ने डॉ अम्बेडकर को जीवन के एक नये मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।

मसौदा समिति में सात सदस्य थे, पर डॉ अम्बेडकर ने अकेले ही अपने सहयोगियों बीएन राव और एसएन मुखर्जी की सहायता से संविधान बनाने का काम किया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में विचारार्थ रखा गया और 25 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने बौद्ध धर्म के प्रतीक अशोक चक्र के साथ तिरंगा झंडा अंगीकार किया था।

प्रारूप संविधान को डॉ अम्बेडकर ने निम्नलिखित आशय के साथ पूरा किया था, - मैं समझता हूं कि यह व्यवहार्य है, यह नमनीय है और यह इतना सशक्त है कि शांति काल तथा युद्ध काल दोनों में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। असल में मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस संविधान के तहत यदि कुछ गलत हुआ तो कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था। हमें तब यह मानना पड़ेगा कि संविधान लागू करने वाले लोग ही घटिया थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मतदान की अनिवार्यता और लोकतंत्र की दृढ़ता

प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे

मतदान एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है जो हमारे देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मतदान राजनेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाए रखने में मदद करता है और हमारे लोकतंत्र के लिए रूपरेखा तैयार करता है

सबको करना चाहिए, निश्चित ही मतदान।
लोकतंत्र मजबूत हो,बढ़े लोक की शान।।

मतदान नागरिकों को नागरिकता के महत्व का एहसास करने में भी मदद करता है। बहुत से लोग यह सोचते हुए वोट नहीं करते कि एक वोट से कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसा कि यह तथ्य है। एक राष्ट्र की राजनीतिक नींव का उपयोग चुनावों के लिए किया जाता है। मतदान एक बुनियादी प्रक्रिया है जो एक देश की सरकारी प्रणाली को बनाती है। यह नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में सक्षम बनाता है। यह लोगों को सरकार में अपने प्रतिनिधि चुनने की भी अनुमति देता है। प्रत्येक सरकार का उद्देश्य अपने नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना है। यह मुद्दों और स्पष्टीकरण के बारे में सरकार से सवाल करने के अधिकार वाले व्यक्ति को भी सक्षम बनाता है। मतदान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक नागरिक की राय व्यक्त करने का तरीका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतदान नागरिक का अधिकार है, साथ ही यह एक कर्तव्य भी है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार देते हैं। एक मतदान से सरकारें बदल सकती हैं, देश का विकास हो सकता है और समाज में बदलाव आ सकता है। मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि हमारी सरकार बनाते हैं और हमारे देश का शासन करते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने देश के विकास में योगदान दें।

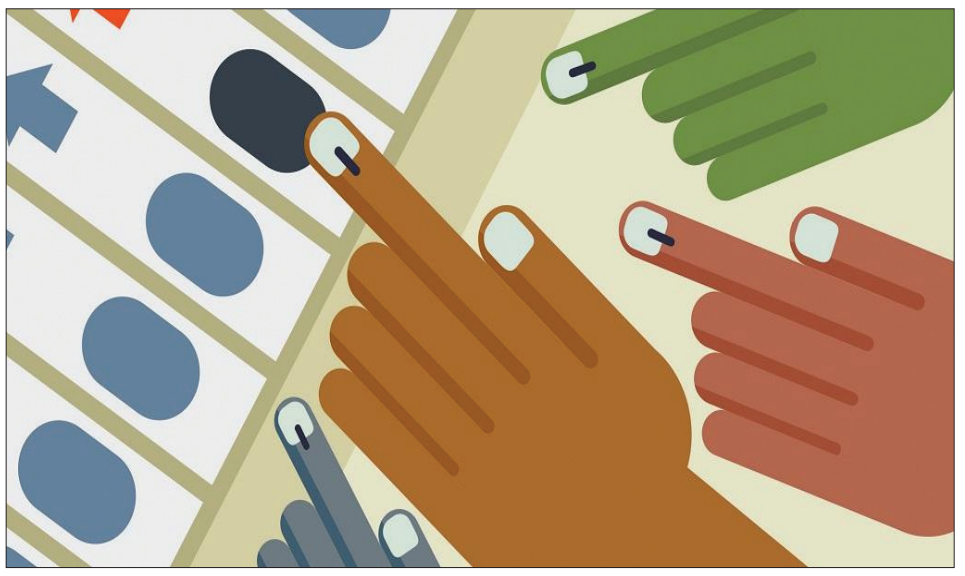

बहुत से लोग मतदान करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता और इसे डालने के तरीके के बारे में जानकारी नहीं होती है। यहीं पर मतदान जागरूकता काम आती है। मतदान जागरूकता का विचार लोगों को मतदान के महत्व को समझने में मदद करना है। मतदाताओं के लिए अपनी सरकार को नियंत्रित करने के लिए मतदान एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह नागरिकों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर यह व्यक्त करने का एक तरीका है कि वे अपने नेताओं से क्या चाहते हैं। इससे बेहतर शासन मिलेगा और हर कोई चाहता है - एक ऐसा लोकतंत्र जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। मतदान से नागरिकों को अपनी सरकार में अधिक शामिल होने और उसे जवाबदेह बनाए रखने में मदद मिलती है। मतदान करने के लिए, आपको विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। मतदान के अलावा, कुछ कानून भी हैं जो दुनिया भर में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं।

मतदान लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और लोगों के लिए अपनी बात रखना जरूरी है। सभी को वोट देने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सभी भारतीय अपनी पसंद के प्रधान मंत्री के लिए वोट कर सकते हैं। मतदान करके, आप बदलाव ला सकते हैं और अपने समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। मतदान करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी कानून को तभी निरस्त कर सकते हैं जब अधिकांश नागरिक उससे सहमत हों। मतदान अपनी सरकार के साथ अधिक नागरिक रूप से जुड़ने का एक तरीका है। अपनी आवाज सुनकर और उन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करके दुनिया में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है जिनके पास कोई आवाज नहीं है। यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं तो मतदान एक बेहतरीन तरीका है। चुनाव में मतदान करने से नागरिकों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि देश को बेहतर अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाती है।

मतदान एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है जो हमारे देश के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मतदान राजनेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाए रखने में मदद करता है और हमारे लोकतंत्र के लिए रूपरेखा तैयार करता है

मतदान के माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा देश किस दिशा में बढ़े। हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह की सरकार हो। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मतदान का सही उपयोग करें। इसी को नैतिक मतदान करना कहा जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य, ज़िला, तहसील व खंड स्तर पर व्यापक रूप में मतदाता जागरुकता (स्वीप)अभियान के माध्यम से जागरुकता लाई जा रही है। मेरे महाविद्यालय में भी प्राचार्य के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी व इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से अनेक गतिविधियों द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाये जाने की सतत कोशिशें हो रही हैं। यह यथार्थ है कि मतदान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, लोकतंत्र उतना ही अधिक मजबूत होगा।

लोकतंत्र हमसे कहे,हो नैतिक मतदान।
अंधकार सब दूर हो,जनता का हो मान।।

संपादकीय

हाईकोर्ट के बेबाक फैसले से सबसे मुश्किल विपक्ष

अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के बेबाक फैसले ने कई भ्रमों को दूर कर दिया है। यही कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना गलत है। इसलिए कि वह झूठे तथ्यों और डराए गए गवाहों से बलात लिए बयानों पर आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली सरकार को जमींदोज के इरादे से रची गई साजिश के तहत है। यह आम चुनाव में भागीदारी के समान अवसर के अधिकार से वंचित करना है। इनके पीछे केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसके इशारे पर ईडी काम कर रहा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 25 मिनट तक पढ़े गए अपने फैसले में केजरीवाल की याचिका के सभी मुद्दों को बिंदुवार स्पष्ट किया है। फैसले के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी नियमतः और साक्ष्य-आधारित है। रिमांड जायज है। ईडी के आठ-आठ समनों के बाद भी पूछताछ में न आना और पर्याप्त सबूत भी हों तो गिरफ्तारी लाजिमी है। इसमें हैसियत के हिसाब से फेरबदल नहीं किया जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री कीआबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के करोड़ों रुपये के मामले में प्रमाणित संलिप्तता रही है। वे इससे व्यक्तिगत रूप से और बतौर आप संयोजक जुड़े रहे हैं। इसकी पुष्टि ईडी के समक्ष नहीं, बल्कि अदालत में धारा 164 के तहत गवाहों के बयानात से भी होती है। हालांकि आप नेता इन्हें ईडी का गढ़ा मान रहे हैं। उनका यह रवैया जनता को तथ्यों से गुमराह करने वाला है, चुनावी मौसम में वह चाहे जितना सही हो।

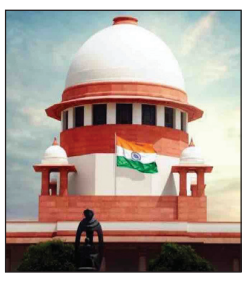

यह अदालत की मान्यता के भी विरुद्ध है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इन गवाहों से आगे मुकदमे की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के बहस के हक को नकारा नहीं है। न्यायालय का यह स्पष्टीकरण महत्त्वपूर्ण है कि यह मामला केंद्र नहीं बल्कि ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल का है। यह कोई राजनीतिक नहीं, सीधे-सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। इसके आरोपित को जांच के तरीके तय करने या इसमें कोई सुविधा मांगने का हक नहीं है। उसे एक आम नागरिक की तरह ही लड़ाई लड ?ी होगी। इस फैसले ने मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया है। उन्हें सहानुभूति पाने के लिए नया तर्क गढ ?ा होगा। केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती न्यायालय के इस आकलन को गलत ठहराने की होगी, जो ईडी से सहमत है कि आप एक पार्टी नहीं, बल्कि कंपनी की तरह है और वे खुद निदेशक की तरह काम करते हैं। उनके लिए फैसले का यह सबसे मुश्किल विपक्ष है। केजरीवाल अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं, जहां इन टिप्पणियों पर भी गौर किया जाएगा।

चिंतन-मनन

वीरत्व की अलंकृति है क्षमा

क्षमा वीरत्व की अलंकृति है। दुर्बल और विवश व्यक्ति द्वारा उद्गीत क्षमा का माहात्म्य उतना प्रखर नहीं हो सकता। ज्ञान की स्फुरणा में मौन की सार्थकता है। शक्ति-संपन्नता में क्षमा की सार्थकता है और त्याग-भावना में आत्मगोपन या अप्रशस्ति की सार्थकता है। शक्ति के अभाव में स्वीकृत का कवच व्यक्ति को कई अवांछनीय परिस्थितियों से त्राण तो दे सकता है, पर उससे क्षमा का वर्चस्व धुंधला हो जाता है। मन के प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर संभावित प्रोध को शांति से प्रतिहत करने वाला व्यक्ति अपनी क्षमा को तेजस्वी बनाता है।

क्षमा के स्वरूप और उसकी क्रियान्विति के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं बन सकता। अपराध करने वलों और क्षमाशील रहने वालों की अनेक भूमिकाएं हैं। एक मुनि, अपराधी व्यक्ति को क्षमा नहीं करता है तो उसका मुनित्व संदिग्ध हो जाता है। भगवान महावीर के साधना काल में कितनी बार प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा की गई, पर महावीर का महावीरत्व उनकी क्षमाशीलता में ही पल्लवित हुआ।

राजधर्म क्षमा को ऐकांतिक महत्व नहीं देता। दुष्ट व्यक्ति को दंडित करना राजधर्म के अनुसार विहित है। दंडनीय को दंड न देना राजधर्म का लोप माना जाता है। इससे अराजकता को प्रोत्साहन मिलता है और अपराधी तत्व निरंकुश हो जाते हैं। दंडसंहिता की सारी धाराएं अपराधों का प्रतिकार करने के लिए हैं।

समाज के साथ अपराध और अपराधों के साथ दंड-पद्धति का सृजन स्वाभाविक माना जाता है। किंतु यह लोक-व्यवस्था या राज्य-व्यवस्था का सिद्धांत है। अध्यात्म की भूमिका इससे भिन्न है। इसमें अपराधी व्यक्ति स्वयं अपराध-शोधन के लिए प्रायश्चित स्वीकार करता है। अपराधी को बलात दंडित करने या उसके प्रति प्रोध प्रदर्शित करने की बात क्षमा-धर्म द्वारा संभव नहीं है। साधना के पथ पर अग्रसर साधकों के लिए क्षमा के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं हैं। क्षमा का प्रभाव अप्रतिहत होता है, पर क्षमा-धर्म की साधना है बहुत कठिन।

आजाद के बाद गुमनाम हुए आजाद

संजय गोस्वामी

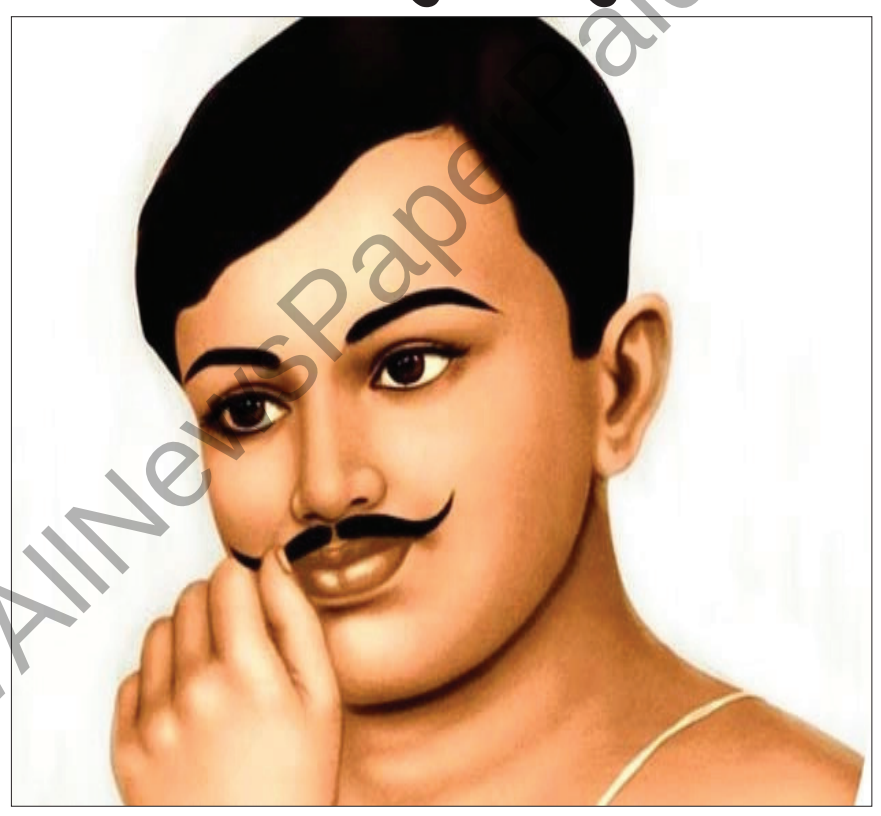

आजादी दिलाने में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें नमन करना जरुरी है क्योंकि वह खुद के लिए नहीं भारत माता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है , भारत को आजादी दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की ऐसी घटना सामने आती है जो गुमनाम हो गए जो देश के आदर्शो पर अपने प्राण कम उम्र में खुद ही लेकर शहीद हो गए । लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर लोग भूल जाते हैं लेकिन देशभक्त जो शहीद हो जाते हैं वो भी खुद गोली अपने सर में चलाकर इतना बड़ा देशप्रेम में कई चेहरे हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया ना ही उसपर किसी राजनेता का ध्यान गया अब गुमनाम-सा हो रहें हैं क्योंकि कोई भी राजनीति पार्टी को देश के शहीदों को भी अपने हिसाब से याद करते हैं ऐ पुरानी राजनीती परंपरा को बदलने की आवश्यकता है आज से करीब 93साल पहले 27 फरवरी 1931 को, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लड़ते हुए वह शहीद हो गए थे। आज भी लोग आजाद का नाम बहुत सम्मान से लिया करते हैं।चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गाँव में हुआ था। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। देश के लिए उनके बलिदान को देखते हुए उनके गाँव का नाम आजादपुरा रख दिया गया है। 1922 में आजाद की मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई जिसके बाद उनका जीवन ही बदल गया और उन्होंने देश को अंग्रजों से आजाद करवाने की कसम खाई। उनके नाम से अंग्रेजी हुकूमत थर-थर कांपा करती थी।ब्रिटिश सरकार ने एक बार उन्हें बचपन में 15 कोड़ों की सजा दी थी, तब आजाद ने कसम खाई थी कि वह दोबारा पुलिस के हाथ कभी नहीं आएंगे। वह अक्सर गुनगुनाया करते थे।।।दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे।।।आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। काकोरी कांड में भी जब सभी क्रांतिकारी पकड़े गए थे, तब भी चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं पकड़ सका था। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि चाहें कुछ भी हो जाए लेकिन वह जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। इसलिए जब 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था तो उन्होंने अकेले ही ब्रिटिश सैनिकों से मुकाबला किया। जब उनकी रिवाल्वर में आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद पर ही गोली चला दी, जिससे वह जिंदा न पकड़े जाएँ। आजाद को डर था कि अगर वह जिंदा पकड़े गए तो अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से मिटाने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। दरअसल आजाद अल्फ्रेड पार्क में भगत सिंह को जेल से निकालने समेत कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे थे लेकिन तभी उन्हें खबर लगी कि अंग्रेजों ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया है। आजाद ने अंग्रेजों से अकेले ही मुकाबला करते हुए अपने साथियों को पार्क से बाहर निकाल दिया, जिससे भारत की आजादी के लिए बनाई उनकी योजनाओं पर कोई प्रभाव न पड़े। जब उनकी रिवाल्वर में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने की वजाय खुद के जीवन को खत्म करना चुना और उस आखिरी गोली से अपना जीवन खत्म कर दिया। आज ऐ आलम है कि कुछ गिने चुने कॉलेज और कुछ ही फोटो गूगल में मिलती है जो चिंता का विषय है एक बार प्रयागराज में किसी सामाजिक संस्थान ने चंद्रशेखर आजाद की याद में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ वहाँ लाचारी से मुझे भी जाने का अवसर मिला जहाँ बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर थे मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे पेपर स्वीकार किए जायेंगे वहाँ ऐ मालूम हुआ कि उनके बारे में जानकारी सोशल मीडिया में बहुत ही कम थी और लगभग सभी को बुलाया गया वहाँ के प्रोफेसर ने बताया की उनके बहुत सारे दस्तावेज जो उनके शहीद होने पर थी वो गायब हो गई या हटा दिया गया मैं तो किसी जमाने में देश की आजादी पर बनी एक फिल्म में उनके साहस और दे देशभक्ति का जज्बा देखकर लिखा और अच्छी लगी लेकिन बहुत सारी सोशल मिडिया ने मौन ब्रत धारण कर लिया और कुछ पाठ्यक्रम में जानकारी का अभाव होना शर्मिंदा की बात है स्व चंद्रशेखर आजाद का प्रयाग राज में एक विश्वविद्यालय है और मप्र में एक संग्रहालय है उसके अलावा कहीं कहीं गली का नाम होगा, आनेवाले समय में ऐसे सच्चे देश भक्त अवश्य याद करना चाहिए एक ऐसे देशभक्त जो देश को आजाद कराने के लिए ना तो डरा ना ही झुका को उनकी शहादत पर शत शत नमन, भारत माँ का वीर सपूत कभी मरता नहीं है देश ही उसके लिए सर्वोपरि है इस पर ध्यान देना जरुरी है।

वैश्विकी : पूर्व से पश्चिम तक संकट में एशिया

डॉ. दिलीप चौबे

जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान एशिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो को प्रकारांतर से खुला न्यौता दिया गया। किशिदा ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के विश्व स्तर पर कायम वर्चस्व को बनाए रखने की वकालत की।

उन्होंने अमेरिका की हिमायत में वे सभी बातें कहीं जो वहां के नेताओं और सांसदों के लिए कर्णप्रिय थीं। किशिदा ने अमेरिका के नेतृत्व और नीतियों की इतनी पुरजोर तारीफ की कि पता लगाना मुश्किल हो गया कि अमेरिका ही वह देश था जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए थे। इस हमले के लिए अमेरिका ने कभी जापान से माफी नहीं मांगी। किशिदा जैसे जापानी नेताओं ने मानो यह स्वीकार कर लिया कि परमाणु हमले के लिए हम खुद जिम्मेदार थे।

किशिदा का संबोधन भारत और एशिया के अन्य देशों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि उन्होंने चीन के साथ ही रूस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दक्षिण चीन सागर और पूर्व एशिया में चीन की आक्रामक गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि यह क्षेत्र नया यूक्रेन बन सकता है। जाहिर है कि वह अमेरिका के नेताओं से गुहार लगा रहे थे कि वे यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देते समय इंडो पेसेफिक देशों को नजरअंदाज न करें। किशिदा ने कहा कि उनका देश रूसी आक्रमण के खिलाफ संघर्षरत यूक्रेन के साथ खड़ा है। किशिदा ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इंडो पेसिफिक में सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। उनके भाषण का यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक ह्यएशियाई नाटोह्ण के पक्ष में है।

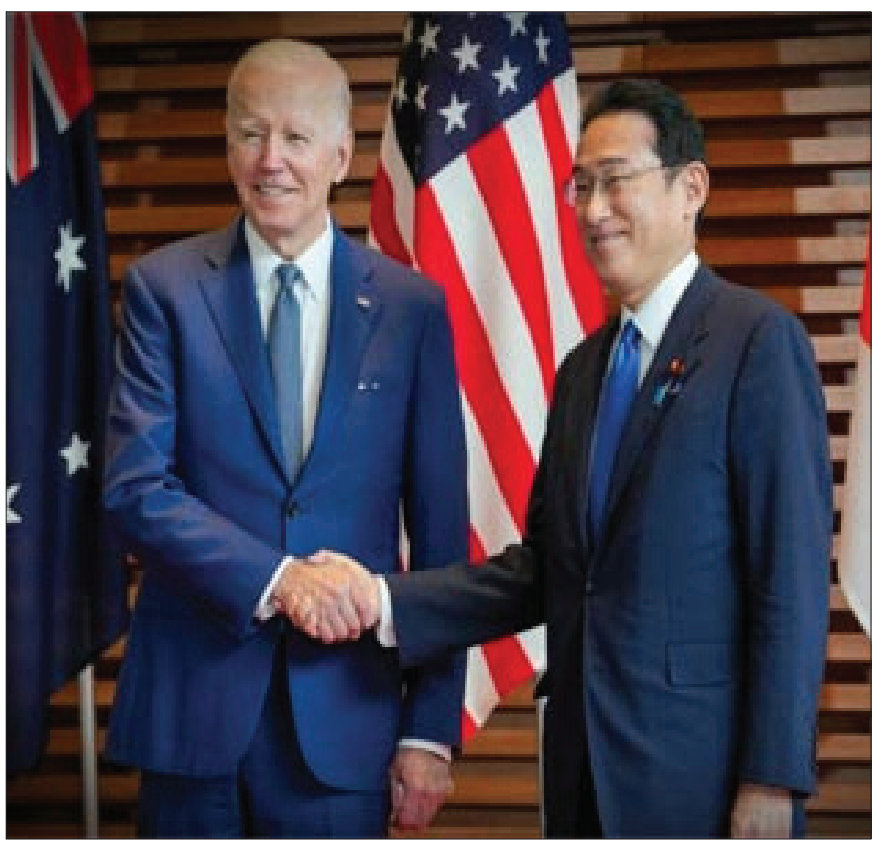

गौर करने वाली बात होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे वर्षो पहले क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक मंच पर लाए थे। क्वाड का कोई सैनिक मंसूबा नहीं था, लेकिन किशिदा जिस एशियाई सुरक्षा ढांचे की बात कर रहे हैं, वह अमेरिका के वर्चस्व वाला सैनिक गठबंधन जैसा है। जाहिर है कि भारत किशिदा के इन विचारों और नीतियों से सहमत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक को दिए गए साक्षात्कार में चीन के साथ संबंधों को पटरी पर लाने के लिए एक पहल की है। मोदी ने कहा है कि सीमा पर लंबे समय से चल रहा तनाव दोनों देशों में से किसी के हित में नहीं है। उनकी यह सोच किशिदा से एकदम अलग है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच किशिदा की यह यात्रा बाइडन को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा सकती है। किशिदा ने कहा कि अमेरिका के नेताओं को अपनी ग्लोबल भूमिका को लेकर कोई संदेह और दुविधा नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने अपने बलबूते दुनिया में स्थायित्व कायम रखा है। उसे अपनी यह भूमिका जारी रखनी चाहिए तथा इस क्रम में जापान पूरी तरह उसके साथ है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद निशस्त्र कर दिया गया था।

तकनीकी रूप से जापान आज भी सेना नहीं रख सकता लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की सैन्य मुहिम को बिना शर्त समर्थन देने का ही नतीजा है कि जापान आज एक सैन्य ताकत बनने की राह पर है। जिस देश से शांति के पैगाम की उम्मीद थी, वह युद्ध का नगाड़ा बजा रहा है। वह भी ऐसे समय जब गाजा में इस्त्राइल का नरसंहार जारी है तथा फारस की खाड़ी के बीच संभावित संघर्ष जापान के लिए मारक सिद्ध हो सकता है। यह संघर्ष यदि व्यापक रूप लेता है तो दुनिया का कच्चे तेल का आधा कारोबार ठप हो जाएगा। रूस से ऊर्जा आयात कम करने वाला जापान इस नये संकट का सामना कैसे करेगा।

वास्तव में भारत के लिए भी पश्चिम एशिया का संकट नई आर्थिक चुनौती पेश कर सकता है। गनीमत यह है कि रूस एक विश्वसनीय ऊर्जा प्रदाता देश है जो आड़े समय में भारत के काम आएगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य कितना ऊपर जाता है, यह विश्व अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए निर्णायक होगा। रूस के खिलाफ यदि प्रतिबंध जारी रहा और पश्चिमी एशिया से तेल आपूर्ति बाधित हुई तो जापान और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है।

प्रधान संपादक : राघवेंद्र, पटना कार्यालय : रामनगरी आशियाना रोड, पटना/रांची कार्यालय: 201 मानस भवन,कांके रोड, रांची। संपर्क : 7488117482...

सम्पादकीय

पैसों की हवस के आगे इंसान

ऋतुपर्ण दवे

पैसों की हवस के आगे इंसान इतना गिर जाए कि जिंदा इंसानों के शरीर के अंग बेचने लग जाए? भला कौन विस करेगा कि यह भी अब उन कुछ वहशियों का कारोबारी हिस्सा है, जो बाकयदा गैंग बनाकर, सुनियोजित तरीके से लगे हुए हैं। हैरानी तब ज्यादा होती है जब इसमें देवालय सदृश्य अस्पतालों के बड़े-बड़े रुतबेदार और ओहदेदार भी हिस्सेदार होते हैं। इस अवैध धंधे ने बहुत गहरी जड़ें कम समय में ऐसी जमा ली हैं कि धंधेबाज सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। भारत में भी सीमा पार तक से गुपचुप तरीके से स्वस्थ लोगों के अंगों को खरीदने-बेचने का सिलसिला तेजी से पनप रहा है। इत्तेफाक से कोई मामला सामने आता है तो उसकी जड़ों तक पहुंचता जांच दल हक्का-बक्का रह जाता है। कैसे, कितनी सफाई से आंखों में धूल झोंक, इतना बड़ा कांड होता रहा और भनक तक नहीं लगी? बीते हफ्ते बांग्लादेश से बुलाकर जयपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले गिरोह का गुरु ग्राम में भांडाफोड़ हुआ। छापेमारी में किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके और कराने वाले डोनर, मरीज सहित 4 लोग हत्थे चढ़े। इनसे खुलासा हुआ कि मरीजों से 10-12 लाख रु पये वसूले जाते, जबकि डोनर को महज दो लाख बांग्लादेशी टका पकड़ाते। पकड़ाए बांग्लादेशी किडनी डोनर शमीम ने हैरान कर देने वाली जानकारी दी। उसने फेसबुक पर किडनी डोनेट करने का विज्ञापन देखकर भारत में मुर्तजा से संपर्क साधा। उसके कई मेडिकल टेस्ट हुए। उसे कोलकाता के मेडिकल वीजा पर गुरु ग्राम में रु कवाया गया। आधार और दूसरे कई फर्जी कागज बने। पता चला कि गुरु ग्राम का बड़ा अस्पताल देख इनके जाल में लोग फंस जाते। बाद में इसी अस्पताल की जयपुर ब्रांच में ट्रांसप्लांटेशन का खेल होता। मुर्तजा झारखंड का है। लंबे समय से इस धंधे में लिप्त है। फरवरी, 2019 में कानपुर पुलिस ने एक बड़े किडनी-लीवर बेचने वाले गिरोह का पदार्फाश किया। गिरोह गरीब को फंसाता और दिल्ली में किडनी बिकवाता। छह लोगों गिरफ्तार हुए जिनके तार न केवल कानपुर से दिल्ली, नोएडा, बल्कि विदेशों से भी जुड़े निकले। गिरोह किडनी बेचने वाले मजबूर को 3-5 लाख रुपये बमुश्किल देता वहीं जरूरतमंद से 30 लाख रु पये से भी ज्यादा वसूलता। जांच में खुलासा हुआ कि गैंग का सरगना टीआरके राव 2016 में अपोलो हॉस्पिटल किडनी कांड में जेल जा चुका है। विडंबना कहें या कानून से बेखौफ निर्लज्जता जेल से बाहर आते ही फिर इसी गोरखधंधे में लग गया।

यह कैसा राम राज?

रघु ठाकुर

22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में, राम लला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्रधानमंत्री जी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वैसे यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस विशाल और व्यापक आयोजन से उनका जनाधार बढ़ा है तथा वे हिंदू मानस के सर्वप्रिय नेता बन गए हैं। यहां तक की हिंदू धर्म गुरु, शंकराचार्य और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के थोक बंद ठेकेदार डॉक्टर मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी की आभा के समक्ष पीछे नजर आ रहे हैं। 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी गुवाहाटी के दौरे पर थे। और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद सत्ता में रहे लोग पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने का चलन स्थापित किया। जबकि विकास और विरासत हमारी नीति है कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा तीर्थ मंदिर सभ्यता की यात्रा की निशानियां है। हमारे तीर्थ मंदिर सिर्फ दर्शन करने की स्थली नहीं है यह हमारी सभ्यता की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे उसको अटल रखा है यह उसकी साक्षी है। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर या मिटाकर विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि पिछले 10 वर्षों में हालात बदल गये है। उनकी आखिरी पंक्ति पर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में जो कुछ अच्छा हुआ है वह उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है और जो कुछ खराब हुआ है वह उनके आने के पूर्व का है, यह कहना उनके प्रारंभिक व स्थाई शगल है। एक प्रकार से वे अपने आपको श्शन भूतों न भविष्यती सिद्ध करते रहते हैं। उनकी आत्म प्रशंसा करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति का स्वभाव होता है। विशेषता जिन सज्जनों में योग्यता कम होती है वे दिखावे ज्यादा करते हैं। हमारी पुरानी कहावत है अध जल भरी गगरिया छलकत जाए्य। पर मूल प्रश्न जिस पर विचार जरूरी है कि संस्कृति पर शर्मिंदगी का चलन देश में कब था। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा को देवरूप मानने वाले थे, वे मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते थे, पर देश में एक ऐसा भी हिंदू समाज या कहें तो हिंदू मानस के विचारकों व धर्म गुरुओं का हिमायती रहा है, जिसने मंदिर व पूजा की परंपरा को स्वीकार नहीं किया। चावार्क ने पाषाण पूजा को स्वीकार नहीं किया तो क्या चावार्क हिंदू नहीं थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि, पत्थर की प्रतिमा में शिव नहीं है तो क्या वे हिंदू नहीं थे? मंदिरों की पुर्नस्थापना तो पहले भी हुई है। क्या स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल प्रथम गृहमंत्री भारत सरकार ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कराया था? हां उसमें स्वर्ण छड़ी से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी कि नही यह में पक्के तौर पर नहीं कह सकता। जहां तक मुझे स्मरण है कि, मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद प्रतिमा स्थापना तो हुई थी परंतु प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल ने तो यह कार्य 1950 के दशक में कराया था तो क्या यह संस्कृति पर शर्मिंदगी का चलना माना जाएगा। स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल ने, यह पुनर्निमाण, सार्वजनिक रूप से तथा उसके लिए जन सहयोग से कराया था। उसमें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सलाह पर सरकारी खजाने के धन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्योंकि, एक धर्मनिरपेक्ष देश में मंदिरों, मस्जिदों, गिरजागरों का निर्माण कराना सरकार का कर्तव्य नहीं है। इनका निर्माण तो उनके मानने वालों के द्वारा ही होना चाहिए। हालांकि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो सब जगह मंदिरों के पुनर्निमाण या विकास के नाम पर या लोक के निर्माण के नाम पर शासन का पैसा लगा रही हैं। क्या किसी मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर के पुनर्निर्माण का काम सरकारी खजाने से हो सका है या होना चाहिए। फिर संस्कृति क्या है? यह भी एक विचार का बिंदु है? संस्कृति का मतलब क्या केवल मंदिर या धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों तक ही सीमित है? आजकल लोग सनातन की बहुत चर्चा कर रहे हैं तो सनातन क्या है? क्या वैदिक काल को सनातन का हिस्सा नहीं माना जाएगा? पर वैदिक काल में यज्ञों व हवन का तो जिक्र मिलता है पर मंदिरों का नहीं मिलता। तो क्या यह माना जाए की वैदिक कालीन लोगों को भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं थी? या फिर उन्हें संस्कृति पर शर्मिंदिगी होती थी?भारत की संरचना में छँटवी शताब्दी के पूर्व की व बाद की स्थिति में फर्क है। इस्लाम के उदय के पूर्व भारत आज के राजनीतिक भूभाग मात्र में सीमित नहीं था वरन कंधार तक फैला था। उस भारत में लगभग एक ही धर्म व परंपराएं प्रचलित थी, पर इस्लाम के उदय के बाद भारत की धार्मिक सीमाएं और फिर कालांतर में राजनीतिक सीमाएं सिकुडने.लगी। लगभग सातवीं शताब्दी से ही मुगल आक्रमण भारतीय सीमाओं में शुरू हो गए, पहले सिंध व पंजाब में और फिर दिल्ली व समूचे भारत में। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बने, वे उसके पूर्व क्या थे? क्या वे बुद्ध नहीं थे? तो बौद्ध मंदिर भी तो भारतीय संस्कृति की धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हुआ। पर संघ के विचार में बौद्ध या सिख या जैन यह क्या भारतीय संस्कृति या धार्मिक इतिहास का हिस्सा माने जाते है। या क्या संघ एक योजना के तहत सभी गैर हिंदू धर्म परंपरा वालों को उनके धार्मिक स्थलों को, मिटाने की योजना रखता है। फिर एक प्रश्न यह भी है, कि संस्कृति क्या है? क्या संस्कृति केवल मंदिरों मठों या धार्मिक स्थलों में है। क्या संस्कृति व इतिहास एक है। इन प्रश्नों पर गहन विचार की आवश्यकता है। फिर संस्कृति व सभ्यता क्या एक है? इस पर भी विचार करना होगा। दरअसल इतिहास संस्कृति और सभ्यता तीनों में समय क्रम एक हो सकता है परंतु भिन्नता भी है। इतिहास उन सारी घटनाओं का संकलन है जो अच्छी या बुरी सही या गलत जब जैसी घटी उनका संग्रह व वर्णन है। संस्कृति वे अच्छे सामयिक जीवन मूल्य है या परंपराएं, जो समाज के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकते हैं, मसलन भारत की जाति प्रथा यह संस्कृति या सभ्यता नहीं कहीं जा सकती। परंतु इतिहास का हिस्सा रहेगी और उसके अच्छे बुरे प्रभावों का विश्लेषण होता रहेगा। सभी जीवों या वस्तुओं में जीवन है और इसलिए उसकी रक्षा की जानी चाहिए। वायु, जल, प्रकृति, मानव यह सभी एक ही रूप के कई हिस्से हैं। यह एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जो शाश्वत जीवन मूल प्रस्तुत करता है। भारत के इतिहास में दो प्रकार के कालखंड है एक राजा भरत का कालखंड है, जहाँ उनके राज्य के भूभाग का फैलाव भी बहुत व्यापक था और आज के अफगानिस्तान तक या कुछ आगे तक वह भूभाग रहा होगा। हालांकि उस समय की आबादी भी शायद हजारों या लाखों में ही रही होगी और वह कालखंड भी राजतंत्र का है।

क्या यह सभी टुकड़े टुकड़े गैंग के राष्ट्र विरोधी व राम द्रोही हैं?

यानी स्थिति कुछ 1977 के चुनाव जैसी दिखाई दे रही है। भाजपा चूंकि अपने संरक्षक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बहुसंख्यकवादी राजनीति करते हुये अपने दूरगामी हिंदूवादी एजेंडे पर काम कर रही है इसलिये वह किसी भी सूरत में सत्ता से हटना नहीं चाहती। इससे निपटने के लिये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ऐसे अनेक हथकंडे अपना रही है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में यहाँ तक कि आपातकाल के उस दौर में भी नहीं देखे गये जिसे कांग्रेस की तानाशाही का दौर कहा जाता था। भाजपा सरकार अपने विपक्षी नेताओं व विरोधी दलों को राजनैतिक प्रतिद्वंदी समझने के बजाय उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अनेक नेताओं को यहाँ तक कि अनेक भ्रष्ट नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय ई डी, सी बी आई या इनकम टैक्स का भय दिखाकर तो किसी को कथित तौर पर धन या पद की लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। जो नेता इनके इस जाल में नहीं फंसता उसे किसी न किसी बहाने जेल भेजा जा रहा है। कई विपक्षी पार्टियों में फूट डलवाई जा रही है। कई विपक्षी पार्टियों में फूट डलवाई जा रही है। और इन सबके बावजूद भी जो इनके पक्ष में नहीं आता उसे तरह तरह की संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है। किसी को राष्ट्रविरोधी बताया जाता है तो किसी को राम विरोधी। कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य तो कोई पाकिस्तान परस्त। कोई भ्रष्ट तो कोई परिवारवादी।

तनवीर जाफरी
लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं

18 वीं लोकसभा के लिये होने जा रहे आम चुनावों में सभी राजनैतिक दल चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को जहाँ अपने दस वर्ष के शासनकाल के दौरान उपजी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है वही विपक्ष भी इस बार एकजुट होकर इंडिया नामक गठबंधन बनाकर भाजपा का मुकाबला करते हुए देश की अधिकांश लोकसभा सीटों पर भाजपा व उसके सहयोगी एन डी ए घटक दलों के एक उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का भी एक ही उम्मीदवार चुनौती दे रहा है। यानी स्थिति कुछ 1977 के चुनाव जैसी दिखाई दे रही है। भाजपा चूंकि अपने संरक्षक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बहुसंख्यकवादी राजनीति करते हुये अपने दूरगामी हिंदूवादी एजेंडे पर काम कर रही है इसलिये वह किसी भी सूरत में सत्ता से हटना नहीं चाहती। इससे निपटने के लिये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ऐसे अनेक हथकंडे अपना रही है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में यहाँ तक कि आपातकाल के उस दौर में भी नहीं देखे गये जिसे कांग्रेस की तानाशाही का दौर कहा जाता था। भाजपा सरकार अपने विपक्षी नेताओं व विरोधी दलों को राजनैतिक प्रतिद्वंदी समझने के बजाय उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मन जैसा बर्ताव कर रही है।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अनेक नेताओं को यहाँ तक कि अनेक भ्रष्ट नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय ई डी, सी बी आई या इनकम टैक्स का भय दिखाकर तो किसी को कथित तौर पर धन या पद की लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। जो नेता इनके इस जाल में नहीं फंसता उसे किसी न किसी बहाने जेल भेजा जा रहा है। कई विपक्षी पार्टियों में फूट डलवाई जा रही है। और इन सबके बावजूद भी जो इनके पक्ष में नहीं आता उसे तरह तरह की संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है। किसी को राष्ट्रविरोधी बताया जाता है तो किसी को राम विरोधी। कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य तो कोई पाकिस्तान परस्त। कोई भ्रष्ट तो कोई परिवारवादी। कोई हिन्दू विरोधी तो कोई अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाला। कोई ह्यखालिस्तानी तो कोई ह्यरेवड़ी बाँटने वाला। यहाँ तक कि भाजपा नेता विशेषकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोकि कभी अपनी छाती 56 इंच की बताते हैं वही मोदी भावनात्मक कार्ड खेलने से भी नहीं चूकते। भाजपा नेता कभी गाँधी-नेहरू का अपमान करते हैं तो कभी गोडसे-सावरकर का महिमामंडन करते हैं और कभी संविधान बदलने की बात करते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि विपक्षी दलों के नेताओं को जिन विशेषणों से प्रधानमंत्री व उनकी पार्टी के तमाम नेता नवाजते रहते हैं और स्वयं को ही भारतीय राजनीति का अब तक का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बताने की कोशिश करते हैं तो क्या उनका विरोध केवल कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के ही नेता करते हैं या करते रहे हैं?

किसी जमाने में वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. राम जेठमलानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। जेठमलानी मोदी के इतने बड़े समर्थक थे कि 2015 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार तक बता डाला था। जेठमलानी को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी काले धन की वापसी करेंगे। वह सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन देंगे। भ्रष्टाचार और विदेश नीति पर अच्छा काम करेंगे। परन्तु जल्द ही जेठमलानी को मोदी की राजनीति की सच्चाई का पता चल गया। आखिरकार उनको कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग का समर्थन करना उनकी सबसे बड़ी नासमझी थी। उन्होंने खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ बताया था। उन्होंने यह कहना भी शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री की बातों का भरोसा ना करें। आखिरकार 9 जून 2015 को राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को ह्यतोड़नेह्व की घोषणा भी कर दी थी। इसके बाद कई मामलों वे खुलकर मोदी व उनकी सरकार के गलत फैसलों के विरुद्ध अदालत में भी पेश हुये।

उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी व शत्रुघ्न सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेताओं व पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी की अनेक गलत नीतियों का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। यशवंत सिन्हा व शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता तो पार्टी छोड़कर भी चले गये परन्तु मोदी हमेशा इसी गलत फहमी का शिकार रहे कि उनसे अच्छी राजनीति की समझ कोई भी नहीं रखता। इस आशय की स्वप्रशंसा वाली कई बातें स्वयं मोदी संसद से लेकर जनसभाओं तक में कहते भी रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो अभी भी भाजपा में ही रहकर मोदी व उनकी सरकार को आईना दिखते रहते हैं। खासकर वित्तीय व विदेश नीति को लेकर और अति विशेष रूप से चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर किये गये हालिया अतिक्रमण को लेकर। उसके बाद भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी और भाजपा नेता व पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के बयानों को सुन लीजिए। किसान विरोधी नीतियों को लेकर इन भाजपा नेताओं ने अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को खरी खोटी सुनाई। वरुण गांधी ने किसानों व बेरोजगारी व मंहगाई के मुद्दे उठाये। जनसमस्याओं से जुड़ी आवाजें बुलंद कीं। तो पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने संघ के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से लेकर पुलवामा में हुये चालीस भारतीय जवानों की शहादत जैसे अति गंभीर विषय पर मोदी को कटघरे में खड़ा किया। परन्तु इसके जवाब में भाजपा ने वरुण गांधी को लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया तो सतपाल मलिक के राज्यपाल का कार्यकाल नहीं बढ़ाया। उल्टे सतपाल मलिक से सम्बंधित 29 ठिकानों पर सी बी आई के छापे जरूर मारे गये।

और अब इन्हीं लोकसभा चुनावों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रसिद्ध अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर के बयानों से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। उन्होंने दावा किया है कि अगर बीजेपी को इस बार भी लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में पैदा हो सकती है। अर्थशास्त्री प्रभाकर के अनुसार 2024 में अगर फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने और यह सरकार वापस आई तो देश में फिर कभी भी चुनाव नहीं होंगे। देश का संविधान बदल जाएगा। मोदी खुद ही लाल किले से नफरती भाषण देंगे और लद्दाख-मणिपुर जैसी स्थिति पूरे देश में बन जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक़्शा है, यह पूरी तरह से बदल जाएगा। आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी आपको पाकिस्तान भेजने, इसे मारने या भगाने की बातें जो धर्म संसद जैसी जगहों से सुनाई दे रही हैं, वो बातें आप लाल किले से सुनेंगे।

कट्टरता की कटार से मानवता की छाती भेदने की तैयारी

दुश्मन के दुश्मनों ने भी दोस्त बनकर कमर कसना शुरू कर दी है। इजराइल के पक्ष में जहां अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य पश्चिमी देश एक जुट हो रहे हैं वहीं ईरान के साथ सीरिया, लेबनान, कतर, जार्डन, तेहरान, ईराक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिल्कान जैसे मुस्लिम देशों के अलावा रूस, चीन तथा उत्तरी कोरिया भी खडे हो सकते हैं। इस संभावित युध्द की तैयारी में यहूदियों और मुसलमानों का अलग-अलग ध्रुवीकरण होने लगा है। इजराइल-लेबनान सीमा पर अनगिनत मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गईं हैं। लेबनान के आतंकवादी गिरोह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर राकेट दागने शुरू कर दिये हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुखिया लेफ्टिनेन्ट जनरल हेरजी हवेली तथा अनेरिका की सेन्टर कमांड के मुखिया माइकल एरिक कुरिला के मध्य महात्वपूर्ण बैठक में भावी रणनीतियां तय कर ली गईं हैं। ऐसे में भारत की अगुवाई तले अनेक देश तटस्थ रहने की शान्तिप्रिय नीतियों का अनुपालन करते भी दिख सकते हैं जो विश्व युध्द को टालने की कोशिश में ही लगे रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, भारत सहित 6 देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह यानी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें इजराइल और ईरान देशों के वर्तमान हालातों की समीक्षा की गई है। अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से सीबीएस न्यूज तथा गुप्त सूत्रों को रेखांकित करते हुए वाल स्ट्रीट जर्नल सहित अनेक संवाद संप्रेषिण माध्यमों ने विगत दिनों संभावित युध्द की घोषणा की थी।

डा. रवीन्द्र अरजरिया
लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

रा तीसरे विश्व युध्द की दस्तक होने लगी है। इजराइल का हमास के साथ हो रहे युध्द का विस्तार अब ईरान तक पहुंच गया है जिसमें दुनिया के देश दो खेमों में बटते जा रहे हैं। दुश्मन के दुश्मनों ने भी दोस्त बनकर कमर कसना शुरू कर दी है। इजराइल के पक्ष में जहां अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य पश्चिमी देश एक जुट हो रहे हैं वहीं ईरान के साथ सीरिया, लेबनान, कतर, जार्डन, तेहरान, ईराक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिल्कान जैसे मुस्लिम देशों के अलावा रूस, चीन तथा उत्तरी कोरिया भी खडे हो सकते हैं। इस संभावित युध्द की तैयारी में यहूदियों और मुसलमानों का अलग-अलग ध्रुवीकरण होने लगा है। इजराइल-लेबनान सीमा पर अनगिनत मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई हैं। लेबनान के आतंकवादी गिरोह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर राकेट दागने शुरू कर दिये हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुखिया लेफ्टिनेन्ट जनरल हेरजी हवेली तथा अनेरिका की सेन्टर कमांड के मुखिया माइकल एरिक कुरिला के मध्य महात्वपूर्ण बैठक में भावी रणनीतियां तय कर ली गईं हैं। ऐसे में भारत की अगुवाई तले अनेक देश तटस्थ रहने की शान्तिप्रिय नीतियों का अनुपालन करते भी दिख सकते हैं जो विश्व युध्द को टालने की कोशिश में ही लगे रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, भारत सहित 6 देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह यानी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें इजराइल और ईरान देशों के वर्तमान हालातों की समीक्षा की गई है। अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से सीबीएस न्यूज तथा गुप्त सूत्रों को रेखांकित करते हुए वाल स्ट्रीट जर्नल सहित अनेक संवाद संप्रेषिण माध्यमों ने विगत दिनों संभावित युध्द की घोषणा की थी। इजराइल पर हुए आतंकी हमले के जबाब में गाजा पर किये गये प्रहार का विस्तार निरंतर होता जा रहा है। आतंकी संगठनों की कट्टरपंथी जमातें एक साथ इजराइल और यहूदियों पर टूट पडना चाहती हैं। गाजा के आम नागरिकों व्दारा मौत की कीमत पर भी हमास को संरक्षण दिया जा रहा है। चिकित्सालयों, मस्जिदों, मदरसों, स्कूलों, आस्था स्थलों सहित विश्व स्वस्थ्य संगठन जैसी संवेदनशील जगहों से आतंक की पाठशालायें निरंतर संचालित होती रहीं हैं। भूमिगत सुरंगों के जाल फैलाने के साथ-साथ हमास ने कट्टरता के क्रूर हथियारों से निरीह आवाम को जेहादी बना दिया है। वहां के आम नागरिकों ने अपनी आंखों के सामने मासूमों की मौत देखना कुबूल किया, भूख की तडफ स्वीकारी और मंजूर किया हमास का आदेश। जमीर की आवाज कहीं दूर दफन हो चुकी थी, ईमान का जज्वा कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गया था और कफन ओढकर ताबूत में लेट गई थी इंसानियत। खुदा के पैगाम का मनमाना तजुर्मा करने वाले खुद के जिस्मानी आराम तलाशने में जुटे है, जीते जी रूह की रुक्सती कर दी है और दुनिया का सुल्लतान बनने की ख्वाइश को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। ऐसे में गाजा का एक बडा भाग इजराइल के प्रतिशोध की भेंट चढने लगा। हमलों पर हमले होते चले गये। हमास के साथ मिलकर लडने वाले देशों ने इस प्रतिशोध पर प्रतिशोध लेने का षडयंत्र करना शुरू कर दिया। समुद्री लुटेरे बनकर आतंक फैलाने वालों ने जहाजों पर आक्रमण तेज कर दिये। इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी करने के सिलसिलों ने तेजी पकड ली। चन्द मुसलमानों ने पूरी कौम को संदेह के दायरे में खडा कर दिया। वर्तमान हालातों के लिए जिस घटना को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है वह 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी के वाणिज्य दूतावास पर घटित हुई थी जिसमें इजराइली हमले में ईरान के टाप कमांडर सहित 13 सैन्य अधिकारियों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से ईरान ने खुली चुनौती देते हुए बदला लेने की घोषणा की थी। इसी मध्य हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे क्रूर आतंकी संगठनों अब अपना कुनवा बढाने की कोशिशों को चरम पर पहुंचे में जुट गये हैं। आतंकवाद को अप्रत्यक्ष में जायज ठहराने वाले देश तो लम्बे समय से अपनी धरती पर उन्हें केवल फलने-फूलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं बल्कि सैन्य साज-ओ-सामान भी मुहैया करा रहे हैं। हैलीकाप्टर, स्पीड वोट, मिनी जहाज, आधुनिकतम अग्नेय शस्त्र, विस्फोटक, भारी-भरकम धनराशि जैसे संसाधनों की भरमार करके षडयंत्रकारी देशों के सत्ताधारी लोग अब अन्य देशों पर कब्जा करने, काबिज होने तथा गुलाम बनाने के लिए अपनी गैर संवैधानिक सैन्य शाखायें स्थापित करने में लगे हैं। तभी तो समुद्री लुटेरे, आतंकी संगठन और उनके रहनुमा अब खुलेआम अपनी गैरइंसानियत वाली क्रूरता को बेझिझक कुबूल करते हैं ताकि उनके नाम से दहशत का डंका बजने लगे। इन घटनाओं को बढावा देने का काम हथियारों के सौदागर, इंसानियत के दुश्मन और जेहाद के नाम पर जुल्म करने वाले मिलकर कर रहे हैं। कट्टरता की कटार से मानवता की छाती भेदने की तैयारी में लगे देशों को एक बार फिर सोचना चाहिए कि लाशों पर चलकर उखडी सांसों को गुलाम बनाने का मंसूबा दीन और दुनिया में कहीं भी कुबूल नहीं होगा फिर भी धमकियों, षडयंत्रों और हमलों की तिपाई पर बैठने वाले षडयंत्रकारी दुनिया भर में अपनी हुकूमत चलाने की ख्वाइश पूरी करने में जुटे हैं। जेहाद के नाम पर जुल्म, जुल्म के साथ बरबरता और बरबरता के आगोश में छुपी मंशा को नकाब में छुपाया जा रहा है। ऐसे में दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देता विश्व युध्द किसी भी हालत में खुशहाली या सुकून नहीं दे सकेगा। इसे टालने के लिए अब जिस्मानी कोशिशों के अलावा रूहानी इबादत भी जरूरी हो गई है। तो आइये हम सब मिलकर अपने-अपने इबादतगाह में अपने-अपने ढंग से दुनिया को इस जंग-ए-दौर से बचाने के लिए दुआयें करें। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।

मतदान की अनिवार्यता और लोकतंत्र की दृढ़ता

प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे

मतदान नागरिकों को नागरिकता के महत्व का एहसास करने में भी मदद करता है। बहुत से लोग यह सोचते हुए वोट नहीं करते कि एक वोट से कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसा कि यह तथ्य है। एक राष्ट्र की राजनीतिक नींव का उपयोग चुनावों के लिए किया जाता है। मतदान एक बुनियादी प्रक्रिया है जो एक देश की सरकारी प्रणाली को बनाती है। यह नागरिकों को अपनी सरकार चुनने में सक्षम बनाता है। यह लोगों को सरकार में अपने प्रतिनिधि चुनने की भी अनुमति देता है। प्रत्येक सरकार का उद्देश्य अपने नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न नीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना है। यह मुद्दों और स्पष्टीकरण के बारे में सरकार से सवाल करने के अधिकार वाले व्यक्ति को भी सक्षम बनाता है। मतदान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक नागरिक की राय व्यक्त करने का तरीका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतदान नागरिक का अधिकार है, साथ ही यह एक कर्तव्य भी है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के भविष्य को आकार देते हैं। एक मतदान से सरकारें बदल सकती हैं, देश का विकास हो सकता है और समाज में बदलाव आ सकता है। मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। मतदान के माध्यम से हम अपने देश के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि हमारी सरकार बनाते हैं और हमारे देश का शासन करते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने देश के विकास में योगदान दें।

बहुत से लोग मतदान करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता और इसे डालने के तरीके के बारे में जानकारी नहीं होती है। यहीं पर मतदान जागरूकता काम आती है। मतदान जागरूकता का विचार लोगों को मतदान के महत्व को समझने में मदद करना है। मतदाताओं के लिए अपनी सरकार को नियंत्रित करने के लिए मतदान एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह नागरिकों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर यह व्यक्त करने का एक तरीका है कि वे अपने नेताओं से क्या चाहते हैं। इससे बेहतर शासन मिलेगा और हर कोई चाहता है - एक ऐसा लोकतंत्र जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। मतदान से नागरिकों को अपनी सरकार में अधिक शामिल होने और उसे जवाबदेह बनाए रखने में मदद मिलती है। मतदान करने के लिए, आपको विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। मतदान के अलावा, कुछ कानून भी हैं जो दुनिया भर में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। मतदान लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और लोगों के लिए अपनी बात रखना जरूरी है। सभी को वोट देने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सभी भारतीय अपनी पसंद के प्रधान मंत्री के लिए वोट कर सकते हैं। मतदान करके, आप बदलाव ला सकते हैं और अपने समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। मतदान करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी कानून को तभी निरस्त कर सकते हैं जब अधिकांश नागरिक उससे सहमत हों। मतदान अपनी सरकार के साथ अधिक नागरिक रूप से जुड़ने का एक तरीका है। अपनी आवाज सुनकर और उन लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करके दुनिया में बदलाव लाना महत्वपूर्ण है जिनके पास कोई आवाज नहीं है। यदि आप बदलाव लाना चाहते हैं तो मतदान एक बेहतरीन तरीका है। चुनाव में मतदान करने से नागरिकों को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि देश को बेहतर अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जाती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

कश्मीर घाटी में बदली हुई फिजा और चुनावी मुकाबला

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों संघ शासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख की छह संसदीय सीटें यहां की राजनीतिक पार्टियों के लिए सेमीफाइनल बन गई हैं। करीब दस साल बाद इस वर्ष सितंबर तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बहरहाल, इन छह संसदीय सीटों में से दो सीटें- उधमपुर-डोडा-कठुआ और अनंतनाग-राजौरी सीट भाजपा के लिए 'हॉट सीट' बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह उधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मत पड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह से उनका मुकाबला है। लाल सिंह भी यहां से पूर्व में दो बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा था, मगर आजाद भाजपा प्रत्याशी डॉ जितेंद्र सिंह से बुरी तरह हार गए थे। इस बार यहां मुकाबला तिकोना है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी पूर्व मंत्री जी एम सरूरी को खड़ा कर दिया है। जितेंद्र सिंह इस दावे के साथ वोट मांग रहे हैं कि देश की यह पहली संसदीय सीट है, जहां सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जिनमें तीन मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार लाल सिंह अपनी गिरफ्तारी और सहानुभूति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वह वोटरों से यह भी कह रहे हैं कि भाजपा बाहरी कारोबारियों को यहां बसाकर आपकी जमीनों का मालिकाना हक उनको दे देगी।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की 2022 की रिपोर्ट के बाद जम्मू संभाग के दो सीमावर्ती जिलों, पूंछ और राजौरी को जम्मू संसदीय सीट से काटकर कश्मीर के अनंतनाग जिले से जोड़ दिया है और इसका नया नाम अनंतनाग-राजौरी-पूंछ संसदीय सीट रखा गया है। पीडीपी प्रमुख व सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्री व गुज्जर धर्मगुरु मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी के जफर मन्हास और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी यहां से मैदान में हैं। भाजपा ने अभी तक यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। चर्चा है कि गुलाम नबी आजाद भाजपा और अपनी पार्टी से वार्ता कर रहे हैं, ताकि उनका रास्ता निरापद हो जाए। ऐसे में, यह भी हॉट सीट बन गई है।

अनंतनाग-राजौरी-पूंछ सीट राष्ट्रपति शासन के दौरान गठित हुई है। यहां सबसे ज्यादा गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी मतदाता हैं। अनंतनाग जिले में अधिकतर मतदाता कश्मीरी हैं। भाजपा ने यहां से इसलिए भी अधिक उम्मीदें बांधी हैं, क्योंकि केंद्र ने गुज्जर-बकरवाल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। जम्मू-रियासी संसदीय सीट से दो बार से भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार मैदान में हैं। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला से है। श्रीनगर संसदीय सीट भी काफी दिलचस्प बनती नजर आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि सेहत ठीक न रहने की वजह से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में, उमर अब्दुल्ला के मैदान में आने की अधिक संभावना है।

अमेठी और रायबरेली के बारे में गांधी परिवार क्या सोच रहा है?

कांग्रेस नेता तर्क देते हैं कि अमेठी-रायबरेली में चुनाव 20 मई को है इसलिए अभी फैसले के लिए काफी समय है। दूसरी ओर कांग्रेस वाराणसी, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है जहां अंतिम चरण में एक जून को मतदान है। ऐसे काफी समय होने का पार्टी का तर्क दमदार नजर नहीं आता।कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह डर भी सता रहा है कि दोनों सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो भाजपा चुनाव में यह मुद्दा बना सकती है वह डर गए हैं। ऐसे में पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और सोच विचार के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा।

अशोक भाटिया

यदि हम पिछले 2019 के चुनाव पर नज़र फेरे तो तब कांग्रेस की 15 उम्मीदवारों की पहली सूची में अमेठी और रायबरेली शामिल थे। इस बार कांग्रेस ने 15 सूची में 244 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए लेकिन इन दोनों सीटों के नाम सामने नहीं आए। रायबरेली से चुनाव लड़ती रही सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन चुकी है। ऐसे में वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम कई बार सामने आया, लेकिन पार्टी ने अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अमेठी में 2019 में राहुल गांधी भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए जबकि वायनाड से जीते थे। वायनाड से राहुल के बतौर उम्मीदवार नाम पहली सूची में आ गया, लेकिन अमेठी की घोषणा रोक दी। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ाने का विकल्प खुला हुआ है।

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ-साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के आला नेता का कहना है कि अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। पहले वायनाड छोड़ू तो अमेठी नाराज और अमेठी छोड़ू तो वायनाड नाराज के चलते राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हाल में जब राहुल पर हार के डर से भागने की तोहमत बीजेपी ने लगाई, तो कांग्रेस नेता ने भी अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है।कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी व्यक्तिगत वजहें थीं, लेकिन डर के भागने जैसी बात की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया।

ये संदेश गलत है, इसको नेस्तनाबूत करना होगा। कांग्रेस के भीतर भी नेता अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। भले ही वे मीडिया के सूत्र बनकर कुछ न कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन वे भी हवा में ही कयास लगा रहे हैं - लेकिन अमेठी पर फैसले में वायनाड फैक्टर की एक खास भूमिका जरूर लगती है। रही बात रायबरेली लोकसभा सीट की तो उसे सोनिया गांधी की चिट्ठी से समझने की थोड़ी कोशिश की जा सकती है। राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम बड़ी ही इमोशनल चिट्ठी लिखी थी - और पुराने रिश्तों को कायम रखते हुए आगे भी परिवार के लिए सपोर्ट सिस्टम बने रहने की सोनिया गांधी ने अपील की थी। अपनी चिट्ठी के जरिये रायबरेली को लेकर जो संकेत सोनिया गांधी ने देने की कोशिश की थी, राहुल गांधी ने कभी ऐसे भाव नहीं व्यक्त किये। हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो अमेठी और रायबरेली गये जरूर थे - लेकिन उस दौरे को लेकर वहां के कांग्रेस नेताओं की नाराजगी ही सामने आई थी। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस नेता के स्वागत के लिए जगह जगह जरूरी इंतजाम किये गये थे, लेकिन राहुल गांधी किसी भी जगह अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। राहुल गांधी की नाराजगी स्वाभाविक लगती है। हैं तो वो भी इंसान ही, नेता और राजनेता होने से क्या होता है? वैसे भी अमेठी के लोगों ने जो सलूक राहुल गांधी के साथ किया है, रायबरेली के लोगों ने तो सोनिया गांधी के साथ नहीं किया। 2019 में भी रायबरेली के लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे, लेकिन अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी समझ से अमेठी की ही तरह रायबरेली में भी तो कभी गांधी परिवार के करीबी रहे कांग्रेस नेता को सोनिया गांधी के खिलाफ उतार दिया था। हां, दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी में बड़ा फर्क तो है ही। बहरहाल, सीनियर कांग्रेस नेता एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर जो संकेत दिया है, वो अपनेआप में काफी महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे वक्त जब दोनों सीटों पर आम लोगों के साथ साथ बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हों। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी अमेठी और रायबरेली में से किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है - वैसे भी अमेठी और रायबरेली में वोटिंग वायनाड के बाद ही होनी है। गांधी परिवार के लिए ये भी बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है।

एक इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों कांग्रेस उम्मीदावार को लेकर सवाल पूछा गया था। एंटनी ने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया लेकिन काफी हद तक तस्वीर साफ भी कर दी - कम से कम ये तो साफ कर ही दिया है कि गांधी परिवार ने यूपी छोड़ देने का फैसला नहीं किया है। वैसे भी यूपी छोड़ देने के मतलब तो उत्तर भारत ही छोड़ देने जैसा समझा जाएगा। एके एंटनी का कहना है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कयास लगाये जाने की जरूरत नहीं है। एके एंटनी कहते हैं, आप अमेठी और रायबरेली लोक सभा सीटों पर फैसले का इंतजार कीजिये। और इंटरव्यू में एके एंटनी ने जो सबसे खास बात कही है, वो है - नेहरू परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में होगा। एके एंटनी का ये जवाब एक चीज तो स्पष्ट कर ही रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से नाता तोड़ लिये जाने की बातें पूरी तरह बकवास हैं - लेकिन दायरा बढ़ा कर एके एंटनी ने नये नये कयासों को दावत दे डाली है। कांग्रेस नेता ने सिर्फ गांधी परिवार का नाम न लेकर नेहरू परिवार की बात कही है, यानी गांधी परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार हो सकता है - हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर एके एंटनी ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली सीटों को लेकर तो सवाल पूछा ही गया, अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाये जाने की संभावनाओं पर भी पूछ लिया गया। जवाब तो एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को लेकर भी दिये, लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट रिस्पॉन्स उनका रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ही लगा। असल में हाल ही में एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने एक साथ कई दावे किये थे। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि चाहते तो वो यही हैं कि पहले प्रियंका गांधी ही संसद पहुंचें, और उसके बाद उनका नंबर आये। अमेठी के लोगों का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वे चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ने का फैसला करूं तो अमेठी से ही - और लगे हाथ, रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी दावा कर डाला था कि कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी दलों से भी उनके पास टिकट के ऑफर हैं। कांग्रेस नेता ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम को तो खारिज कर दिया है लेकिन जो बात कही है, उसमें तो राहुल और प्रियंका के साथ साथ वरुण गांधी भी शामिल हो जाते हैं। अभी तक ऐसे कोई संकेत तो नहीं मिले हैं कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस ने नो-एंट्री वाला बोर्ड हटा लिया है, लेकिन पीलीभीत से बीजेपी ने उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट देकर ऐसी संभावनाओं के द्वार तो खोल ही दिये हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना करीब करीब पक्का है। लेकिन जो स्थिति है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में राहुल गांधी की तुलना में बीजेपी की स्मृति ईरानी को ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती हैं - और जिस तरह से राहुल गांधी को वारिस के तौर पर पेश किया जाता रहा है, रायबरेली का मैदान उनका ज्यादा सूट करता है।अमेठी को लेकर राहुल गांधी के अलावा दो नाम चर्चा में हैं। एक नाम है एमएलसी रह चुके कांग्रेस नेता दीपक सिंह का - और दूसरा नाम है, बीजेपी सांसद वरुण गांधी का। दीपक सिंह को सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी से बड़े ही सख्त लहजे में दो-दो हाथ करते देखा जा सकता है - और वरुण गांधी के बारे में यहां तक बातें हो रही हैं कि वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी सीट तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस के ही पास है। वरुण गांधी को लेकर ऐसी चर्चाओं को एक ही बात कमजोर करती है वो है मेनका गांधी का ताज़ा बयान कि 'हम ऐसे लोग नहीं हैं।'

आज का इतिहास

15 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- फ्रांस ने 1689 में स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- अमेरिका में 1817 में बधिर बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला गया।
- बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया।
- डाईबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए 1923 में इंस्युलिन बाजार में उपलब्ध हुआ।
- तत्कालीन सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड राजनयिक संबंध बनाने पर 1927 में सहमत हुए।
- हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1948 में आज ही के दिन हुई।
- अमेरिका ने 1955 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया।
- भारत सहित 109 देशों द्वारा 1994 में 'गैट' समझौते की स्वीकृति।
- थम्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का 1998 में निधन।
- आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आहवान के साथ जी -77 शिखर सम्मेलन सन 2000 में हवाना में सम्पन्न।
- ब्रिटेन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 2003 में हथियार डाल देने का निर्णय लिया।
- राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े लिट्टे उग्रवादी वी. मुरलीधरन की 2004 में कोलम्बो में हत्या की गयी।
- इंटरपोल ने 2006 के जकार्ता सम्मेलन में एंटी करप्शन एकेडमी के गठन का प्रस्ताव सुझाया।
- पाकिस्तान की एक जेल पर 2012 में हुए हमले के बाद 400 आतंकवादी फरार हुए।
- इराक में 2013 में हुए बम विस्फोट से तक़रीबन 35 लोगों की जान गयी और 160 घायल हुए।

15 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति

- 1452 में इटलीवासी, महान चित्रकार लिओनार्दो दा विंची का जन्म।
- सिख धर्म के संस्थापक गुरू नानक का 1469 में जन्म हुआ।
- 1563 में सिक्खों के पाँचवें गुरु गुरु अर्जन देव का जन्म।
- 1865 में खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्यासिंह उपाध्याय का जन्म।
- 1940 में भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक- सुल्तान ख़ान का जन्म।
- 1960 में मध्य प्रदेश की राजनीति में 'भारतीय जनता पार्टी' के प्रसिद्ध नेता नरोत्तम मिश्रा का जन्म।
- 1972 में बालीवुड अभिनेत्री, क्रिकेट ग्लैमर और फैशन की मूर्ति मंदिरा बेदी का जन्म।

15 अप्रैल को हुए निधन

- चित्रकार नंदलाल बोस का 1966 में निधन।
- हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का 1985 में निधन।
- थम्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का निधन 1998 को हुआ था।

माँ की 'आखिरी सीख' 'बबुआ, माफी मत माँगना चाहे सिर कट जाए'

रामस्वरूप रावतसरे

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आपातकाल में जो कुछ हुआ उसकी चर्चा अब हर जगह है। स्मिता प्रकाश के पॉडकॉस्ट में राजनाथ सिंह ने बताया था कि इमरजेंसी के वक्त जब उन्हें जेल में डाला गया था उस समय उनकी माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया था और 27 दिन बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा था। इतने समय के बीच प्रशासन ने न तो उन्हें माँ से मिलने का मौका दिया था और न ही अंतिम संस्कार के लिए कोई परोल। उनके इस बयान के बाद हर कोई जानना चाहता है कि इतने बड़े दुख के बावजूद कैसे राजनाथ सिंह ने खुद को संभाला और राजनीति से मुँह मोड़ने की बजाय इसमें आगे बढ़े। राजनाथ सिंह के जेल जाने की घटना 12 जुलाई 1975 की है। वह उस समय मिर्जापुर में शिक्षक थे और संघ के दिग्गज नेता थे। जब आपातकाल लगा तो उनकी गिरफ्तारी मीसा के तहत करवा दी गई। इस कानून के तहत वैसे ही किसी परिवार के सदस्य से मिलने की अनुमति नहीं थी और चूँकि राजनाथ सिंह संघ के बड़े नेताओं में से थे तो उनके मामले में तो सख्ती और भी ज्यादा थी। शुरू में राजनाथ सिंह को मिर्जापुर जेल में बंद रखा गया, लेकिन जब बाद में उन्हें इलाहाबाद नैनी जेल में शिफ्ट करने के लिए ट्रेन से लाया गया तो स्टेशन पर उनकी पत्नी सावित्री और माँ गुजराती देवी भागते हुए उन्हें देखने आए। इस दौरान जो बात माँ ने राजनाथ सिंह से कही, उसी के कारण वो एक संघ के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री के पद तक पहुँच पाए। दरअसल, उस दिन स्टेशन पर राजनाथ सिंह के लिए नारे लग रहे थे इसलिए माँ ने जो जो कहा वो उसे सही से नहीं सुन पाए, मगर जो उन्होंने जो सुना उसका जिक्र राजनाथ सिंह की जीवनी पर लिखी गई किताब में पढ़ने को मिलता है। इस किताब को लेखक गौतम चिंतामणि ने लिखा है। इसके अनुसार, नैनी जेल ले जाने के दौरान मिर्जापुर स्टेशन पर पुलिसकर्मी राजनाथ सिंह को जल्दी-जल्दी ट्रेन में बैठाने लगे थे। इस दौरान उनकी माँ ने उनसे कहा था, बबुआ। माफी नहीं माँगना। चाहे उम्र भर काल-कोठरी में क्यों न कट जाए। कभी सिर मत झुकाना। बेटे को जेल जाते हुए जब माँ ने ऐसे शब्द कहे तो राजनाथ सिंह भावुक हो गए। उन्हें तब नहीं पता था कि उनकी माँ से उनकी यह आखिरी मुलाकात है। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि माँ को ब्रेन हैमरेज हो गया है, फिर उनके निधन की खबर आई। राजनाथ सिंह चाहते तो इस घटना के बाद टूट सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ के कहे अंतिम शब्द याद थे और यही शब्द उनके राजनैतिक जीवन के लिए ऐसा टर्निंग प्वाइंट साबित हुए कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेल से निकलने के बाद वह मात्र शिक्षक नहीं रह गए थे।

विशेष आलेख

भाजपा का संकल्प पत्र : 30 मुद्दों पर 'मोदी की गारंटी', यूसीसी भी लागू होगा

रामस्वरूप रावतसरे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भाजपा ने 14 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी किया। इस घोषणा पत्र में भाजपा 'जीवाईएएन'' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी-शक्ति पर फोकस किया है। भाजपा के घोषणा पत्र की थीम है 'भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी'। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने संकल्प पत्र में कई चुनावी वादे किए हैं। इनमें मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर से जीरो बिजली बिल जैसे वादे शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत से पाँच लाख का इलाज मुफ्त मिलता रहा है और यह योजना आगे भी जारी रहेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। संकल्प पत्र को जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। राजनाथजी और उनकी टीम तथा लाखों सुझाव भेजने वालों का भी अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का इंतजार रहता है। बड़ा कारण है कि 10 साल में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, निवेश से नौकरी पर है। संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ ऑपर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ ऑपर्च्यूनिटीज पर फोकस है। स्टार्टअप को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेस पर ध्यान देने जा रहे हैं। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी के जरिए महिला सशक्तिकरण का काम जारी रहेगा। भाजपा ने मोदी की गारंटी में देशवासियों से वादा किया है कि युवाओं के लिए इनवेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, खेल, हाई वेल्यू सर्विस और पर्यटन के लिए नए मार्ग खुलेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कल्याणकारी योजनाओं के साथ महिला सहायता समूहों को मदद देने और सर्वाइकल कैंसल, ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि बीज से बाजार तक किसानों की आय पर फोकस किया जाएगा। श्री अन्न को सुपर फूड में बदला जाएगा। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती के जरिए जमीन की सुरक्षा की जाएगी। मछुआरों के लिए नाव का बीमा, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी को मजबूत किया जाएगा। सी वीड और मोती की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घरों में काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर, ट्रक ड्राइवर और कुली सभी को ई-श्रम से जोड़ने की बात कही है। वहीं, संकल्प पत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम को और सख्ती से लागू करने की बात भी कही गई है। विश्व भर में थिरुवल्लूवर कल्चर सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने और भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था को उच्च शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा और राम की नगरी अयोध्या का और विकास किया जाएगा। संकल्प पत्र में भारतीय न्याय संहिता लागू करने, वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल और देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी बात कही है। भाजपा ने 'मोदी की गारंटी' के तहत हर वंचित वर्ग को वरीयता देने की बात कही है। साल 2025 को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में घोषित करने और एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा ओबीसी, एसी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देने की बात भी कही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएँगे। सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम किया जाएगा। बिजली बिल जीरो करने की दिशा में पीएम सूर्यघर बिलजी योजना लॉन्च होगी। मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। वहीं, दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री के अनुसार आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में रेलवे और हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, वॉटर मेट्रो बनते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तरी-दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। स्पेस, एआई, क्वांटम, ग्रीन हाईड्रोजन, सेमीकंडक्टर और ईवी टेक्नोलॉजी में भारत अग्रणी बनने की दिशा में काम करेगा।भाजपा ने संकल्प पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरण रीजिजू और अर्जुनराम मेघवाल के अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्रभाई पटेल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रविशंकर प्रसाद सहित कुल 27 नेता थे। संकल्प पत्र को 24 समूहों में बाँटा है। 10 सोशल ग्रुप में गरीब, युवा, मध्यम वर्ग, मछुआरे, वंचित वर्ग, सीनियर सिटीजन, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग शामिल हैं। वहीं, गवर्नेंस को 14 सेक्टर में बाँटा गया है। इनमें भारत के अन्य देशों से संबंध, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, समृद्ध भारत, ईज ऑफ लिविंग, विरासत का विकास, गुड गवर्नेंस, सुशासन, स्वस्थ भारत, शिक्षा, खेल, सभी सेक्टर्स का विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को रखा है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

वृष

सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन

किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

कर्क

व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह

आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

कन्या

अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

तुला

आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

वृश्चिक

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

धनु

स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

मकर

दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कुंभ

मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

मीन

आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं बढ़ता राजस्थान नियर शकुन्तला अपार्टमेंट,छावनी मेन रोड, कोटा (राज.) से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। समूह के प्रधान सम्पादक राम बिलास विजयवर्गीय।
मो.नं. 9414242258, 9214048888 प्रधान कार्यालय :185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर (राज.)फोन नं.0141-2796794,2796795,E-Mail-badhatarajasthan@yahoo.com, *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर महानगर होगा)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हाथ की उंगलियों का तात्विक विश्लेषण

शरीर को ब्रम्ह ओर आत्मा को परमात्मा कहा है। मनुष्य शरीर के हाथों की उँगलियों में पंचतत्व, पंचमहाभूत, नवगृह, सभी नक्षत्र सहित सभी राशियो को स्थान प्राप्त है जिसका चिंतन कर इन उंगलीओ का तात्विक विश्लेषण करने का लघु प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही मुझ अल्पज्ञानी की बोद्धिक समझ तत्ववेत्ताओ के अथाह ज्ञानसागर की एक बूंद भर हो सकती है, पर प्रयास करना कोई अपराध नहीं है। मैं अपनी सुगमता के लिए उँगलियो पर जो विचार प्रकट कर रहा हूँ वह अपने दिल दिमाग पर जोर डालने के लिए नहीं है पर अपने स्वंय के दिमाग की कसरत के लिए स्वस्थ समझता हूँ। हाथ ओर उंगलियां स्थूल है, प्रकट है, पर इसमें जो सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म अप्रकट है, दिखाई नहीं देता पर शरीर का अंग होने से प्रतिपल भावनाओं की तरंगों के साथ होता है।

हिन्दू-संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धान्त पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण करना है किन्तु हमारी लापरवाही के कारण इस प्रकार के दुर्लभ ज्ञान का विलोप अंतिम स्थिति में है। ज्योतिषी हाथ देखकर आपका भविष्य बताता है ओर समुद्र शास्त्र का ज्ञान होने पर वह उंगलियों की बनावट, उसमें होने वाले चक्र, नाखून में उभरने वाले स्वेद-रक्त आकार आदि अनेकानेक रेखाओं, चिन्हों व आकृतियों के चित्र देखकर पूरा भविष्य अक्षरशः बखान कर सकता है। प्रत्येक हाथ में पाँच उंगलिया होती है, संयोग से हजारों में किसी एक के छह या ज्यादा हो सकती है। इन पांचों उंगलियों के नाम अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठिका है ओर इन सबकी पहचान पंचतत्व के प्रतीक के रूप में की गई है जिसमें अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का एवं कनिष्ठिका जल की मानी गई है जिनमे 12 राशियो एवं नवग्रह तथा उनके देवताओं का निवास माना है। यही कारण है कि पूजा पाठ या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में, शंख बजाने, तिलक लगाने, आहुति छोड़ने से लेकर वैवाहिक जीवन कि शुरूआत में अंगूठी रस्म के लिए इन उंगलियों का उपयोग इनके मांगलिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका हम सदियों से प्रयोग करते आ रहे है।

जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त मनुष्य जिन-जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है और जो-जो क्रियाएँ करता है, उन सबको हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि- मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंगसे सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है, परंतु इन्हे ठुकुरा कर लोग पाश्चात संस्कृति की दीवानगी में डूबे है। एक भारतवासी हम है जो इन रहस्यमयी अनमोल ज्ञान से परिचित नहीं किन्तु आधुनिकता की दौड़ में चाँद पर पहुँच सारी परंपराओं का गला घोंट पाश्चात संस्कृति की गुलामी में अपने धर्म पर चलने को लकीर का फकीर होना साबित करते है। बावजूद हमारी प्राचीन ऋषि परम्पराओं की कुछ रश्मों रिवाज के बिना पश्चिम भी अधूरा है। जीवन में जो युगल अपने जीवनसाथी के सपने देखते है ओर उन सपनों को साकार करने सदा के लिए प्रणय संबंधों में बंधने को उतावले होते है वे सपने अनामिका उंगली के बिना अधूरे है। अनामिका उंगली सच में सपनों को साकार कर जीवन में रस घोलती है, वह सोने चांदी जवाहरात के बंधन में खुद को बंधना इसलिए स्वीकारती है क्योकि उसके बंधने पर युगल के जीवन में प्यार की शुरूआत होने जा रही है।

सारे धर्म ओर संस्कृति के लोग अपने जीवन की शुरूआत में कितने भी आडंबर रचे पर अंत में अनामिका अंगूठी धारण कर अपनी आहुति देती है। अनामिका पृथ्वी स्वरूप है इसलिए जीवन की शुरूआत पृथ्वी से ही होती है। एक प्रकार से इस पृथ्वी के प्रत्येक युगल के प्यार के बंधन की साक्षी पृथ्वी होती है, पृथ्वी यानी अनामिका। अनामिका का बंधन बहुत ही नाजुक ओर महत्वपूर्ण होता है, जो पृथ्वी के मर्म को समझते है अनामिका उनका जीवनभर साथ देती है ओर जो अनामिका के साथ के बंधन को एक मजाक समझ भावनाओं से खिलवाड़ के शौकीन होते है उनका सब कुछ उल्टा पुलटा कर देती है। जैसे पृथ्वी के तत्व है स्थिरता, जिद्दीपन, हठ, जिम्मेदारी, मध्यस्थता और निष्ठा तथा परंपराओं में यकीन और कई बार लोगों के बीच समन्वय बनाकर चलना, ये सभी गुण जीवनसाथी के रूप में अनामिका से संबंध जोड़ने तोड़ने वालों की नियति के रूप में दिखाई देता है। अतएव जिसप्रकार हाथों की पांचों उंगलिया का अपना अपना महत्व है ओर वे बिना झगड़ा किए एक दूसरे को अन्य उँगलियों से बड़ा साबित करने की कोशिश किए बिना रहती है वैसे है व्यक्ति को रहना चाहिए। जैसे हाथ का पंजा उँगलियों के बिना अधूरा है,प्रत्येक उंगली जब तक संगठित होकर नहीं रहेगी तब तक उनका अस्तित्व नहीं है।

बढ़ती हुई जनसंख्या से समस्याएं

भारत की आबादी 1.4 अरब के लगभग हो चुकी है, और 1 प्रतिशत की दर से लगभग हर वर्ष बढ़ती जा रही है। जो एक गंभीर विषय सोचने पर मजबूर कर रहा है। जनसंख्या में तेज वृद्धि मानव संसाधनों और सेवाओं पर असर डाल रही है। फलस्वरूप पर्यावरणक्षरण और गरीबी असमानता बढ़ रही है। स्वास्थ्य संस्थाओं पर बोझ भी बढ़ रहा है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षा का बुनियादी ढ़ांचा बढ़ती आबादी की जरूरतों से जूझ रहा है। शहरी करण के कारण मूलभूत आवश्यकताओं और आधारभूत संरचना पर दबाव डाल रहा है। पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार अवसरों में भी वृद्धि आई है। देश में बढ़ती हुई जनसंख्याँ पर लगी पाबंदियों के बावजूद जनसंख्यायें कम नही हो रही है। जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ती ही जारही हैं। यह एक गंभीर विषय सोचने पर मजबूर कर रहाहै। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के बहुत सारे विकल्प हैं। मगर हर विकल्पों के पालन करने के बाद भी संख्यायों पर कोई प्रभाव नही पड़ रहा है। वृद्धि पर वृद्धि जनसंख्या हो ही रही है। इसलिए देश में तेजी से बेरोजगारी के मामले बढ़ रहे हैं। और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। देश में बेरोजगारी के कारण ही गरीबी बढ़ रही है। जनता गरीब से गरीब बनती जा रही है। गरीबी के कारण लोंगों में असमानता भी बढ़ने लगी है। दिन प्रतिदिन असमानतायों की दरों में भी वृद्धि होती जारही है। जिससे लोगों में असंतोष पैदा होने लगा है। हर वर्ग के लोंगों के सहयोग के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर अभी और काम करने की जरूरत है। समय की मांग है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अत्यधिक जोर देने की। और लोगों को और भी शिक्षित करने की।

-विक्रम दयाल

भारत का विकास पथ-चुनौतियां और सुधार

वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जिस खराब स्थिति में है, उसे देखते हुए, अगर वह किसी तरह चुनाव जीतने में सफल हो जाती है, तो क्या वह अपने घोषणापत्र के वायदों को पूरा कर पाएगी? न्याय पत्र घोषणापत्र, एक 48 पेज का दस्तावेज है जो युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समानता से संबंधित 5 स्तंभों पर केंद्रित है और इन क्षेत्रों के तहत 25 वायदे शामिल हैं। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि देश भर के लोगों के इनपुट ने घोषणा पत्र को आकार दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इसे अकेले नहीं बनाया है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के प्रभाव का मुकाबला करते हुए भारत के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं सहित विभिन्न समूहों के लिए बेरोजगारी, आर्थिक विकास और न्याय को संबोधित करने और संविधान की रक्षा करने का वायदा किया गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने और फर्जी समाचार जैसे मुद्दों से निपटने का वायदा करता है। कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराने और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वायदा करते हुए सकारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का भी वायदा किया। इसके अतिरिक्त, यह किसानों के लिए एम.एस.पी., स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार और विदेश नीति में बदलाव का वायदा करता है। इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष रूप से कठिन होगा, क्योंकि हाल के वर्षों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमरेंद्र सिंह सहित कई प्रमुख राजनेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा, पार्टी काफी समय से स्पष्ट दिशा की कमी से जूझ रही है। अब, आइए उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर विचार करें जिन्होंने देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लेखक और प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व सी.ई.ओ. गुरचरण दास भारतीय राजनीति की जटिलताओं और आर्थिक सुधारों को लागू करने के महत्व पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करते हुए, दास ने हाल ही में द्द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के साथ अपनी यात्रा सांझा की। बड़े होते हुए, उन्होंने अति-विनियमित अर्थव्यवस्था और कठोर सरकारी नियमों के साथ देश के संघर्ष को देखा, जैसे फ्लू महामारी के दौरान जब उनकी कंपनी को उच्च मांग को पूरा करने के लिए सजा का सामना करना पड़ा। अनुभव ने उन्हें शास्त्रीय उदारवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया।

अमेठी और रायबरेली के बारे में गांधी परिवार क्या सोच रहा है?

अशोक भाटिया

यदि हम पिछले 2019 के चुनाव पर नजर फेरे तो तब कांग्रेस की 15 उम्मीदवारों की पहली सूची में अमेठी और रायबरेली शामिल थे। इस बार कांग्रेस ने 15 सूची में 244 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए लेकिन इन दोनों सीटों के नाम सामने नहीं आए। रायबरेली से चुनाव लड़ती रही सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन चुकी है। ऐसे में वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम कई बार सामने आया, लेकिन पार्टी ने अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अमेठी में 2019 में राहुल गांधी भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए जबकि वायनाड से जीते थे। वायनाड से राहुल के बतौर उम्मीदवार नाम पहली सूची में आ गया, लेकिन अमेठी की घोषणा रोक दी। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ाने का विकल्प खुला हुआ है।

कांग्रेस नेता तर्क देते हैं कि अमेठी-रायबरेली में चुनाव 20 मई को है इसलिए अभी फैसले के लिए काफी समय है। दूसरी ओर कांग्रेस वाराणसी, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है जहां अंतिम चरण में एक जून को मतदान है। ऐसे काफी समय होने का पार्टी का तर्क दमदार नजर नहीं आता।कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह डर भी सता रहा है कि दोनों सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो भाजपा चुनाव में यह मुद्दा बना सकती है वह डर गए हैं। ऐसे में पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और सोच विचार के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा।

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ-साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के आला नेता का कहना है कि अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। पहले वायनाड छोड़ू तो अमेठी नाराज और अमेठी छोड़ू तो वायनाड नाराज के चलते राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हाल में जब राहुल पर हार के डर से भागने की तोहमत बीजेपी ने लगाई, तो कांग्रेस नेता ने भी अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है।कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने कहा, ह्लहम डरने वाले नहीं हैं। मेरी व्यक्तिगत वजहें थीं, लेकिन डर के भागने जैसी बात की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया। ये संदेश गलत है, इसको नेस्तनाबूत करना होगा। कांग्रेस के भीतर भी नेता अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। भले ही वे मीडिया के सूत्र बनकर कुछ न कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन वे भी हवा में ही कयास लगा रहे हैं - लेकिन अमेठी पर फैसले में वायनाड फैक्टर की एक खास भूमिका जरूर लगती है। रही बात रायबरेली लोकसभा सीट की तो उसे सोनिया गांधी की चिट्ठी से समझने की थोड़ी कोशिश की जा सकती है। राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम बड़ी ही इमोशनल चिट्ठी लिखी थी - और पुराने रिश्तों को कायम रखते हुए आगे भी परिवार के लिए सपोर्ट सिस्टम बने रहने की सोनिया गांधी ने अपील की थी।

अपनी चिट्ठी के जरिये रायबरेली को लेकर जो संकेत सोनिया गांधी ने देने की कोशिश की थी, राहुल गांधी ने कभी ऐसे भाव नहीं व्यक्त किये। हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो अमेठी और रायबरेली गये जरूर थे - लेकिन उस दौरे को लेकर वहां के कांग्रेस नेताओं की नाराजगी ही सामने आई थी। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस नेता के स्वागत के लिए जगह जगह जरूरी इंतजाम किये गये थे, लेकिन राहुल गांधी किसी भी जगह अपनी गाड़ी से नहीं उतरे।

राहुल गांधी की नाराजगी स्वाभाविक लगती है। हैं तो वो भी इंसान ही, नेता और राजनेता होने से क्या होता है? वैसे भी अमेठी के लोगों ने जो सलूक राहुल गांधी के साथ किया है, रायबरेली के लोगों ने तो सोनिया गांधी के साथ नहीं किया। 2019 में भी रायबरेली के लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे, लेकिन अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी समझ से अमेठी की ही तरह रायबरेली में भी तो कभी गांधी परिवार के करीबी रहे कांग्रेस नेता को सोनिया गांधी के खिलाफ उतार दिया था। हां, दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी में बड़ा फर्क तो है ही।

बहरहाल, सीनियर कांग्रेस नेता एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर जो संकेत दिया है, वो अपनेआप में काफी महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे वक्त जब दोनों सीटों पर आम लोगों के साथ साथ बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हों। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी अमेठी और रायबरेली में से किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है - वैसे भी अमेठी और रायबरेली में वोटिंग वायनाड के बाद ही होनी है। गांधी परिवार के लिए ये भी बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है।

एक इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों कांग्रेस उम्मीदावार को लेकर सवाल पूछा गया था। एंटनी ने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया लेकिन काफी हद तक तस्वीर साफ भी कर दी - कम से कम ये तो साफ कर ही दिया है कि गांधी परिवार ने यूपी छोड़ देने का फैसला नहीं किया है। वैसे भी यूपी छोड़ देने के मतलब तो उत्तर भारत ही छोड़ देने जैसा समझा जाएगा। एके एंटनी का कहना है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कयास लगाये जाने की जरूरत नहीं है। एके एंटनी कहते हैं, आप अमेठी और रायबरेली लोक सभा सीटों पर फैसले का इंतजार कीजिये। और इंटरव्यू में एके एंटनी ने जो सबसे खास बात कही है, वो है - 'नेहरू परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में होगा।'

एके एंटनी का ये जवाब एक चीज तो स्पष्ट कर ही रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से नाता तोड़ लिये जाने की बातें पूरी तरह बकवास हैं - लेकिन दायरा बढ़ा कर एके एंटनी ने नये नये कयासों को दावत दे डाली है। कांग्रेस नेता ने सिर्फ गांधी परिवार का नाम न लेकर नेहरू परिवार की बात कही है, यानी गांधी परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार हो सकता है - हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर एके एंटनी ने फुल स्टॉप लगा दिया है।

इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली सीटों को लेकर तो सवाल पूछा ही गया, अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाये जाने की संभावनाओं पर भी पूछ लिया गया। जवाब तो एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को लेकर भी दिये, लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट रिस्पॉन्स उनका रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ही लगा। असल में हाल ही में एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने एक साथ कई दावे किये थे। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि चाहते तो वो यही हैं कि पहले प्रियंका गांधी ही संसद पहुंचें, और उसके बाद उनका नंबर आये। अमेठी के लोगों का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वे चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ने का फैसला करूं तो अमेठी से ही - और लगे हाथ, रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी दावा कर डाला था कि कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी दलों से भी उनके पास टिकट के ऑफर हैं। कांग्रेस नेता ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम को तो खारिज कर दिया है लेकिन जो बात कही है, उसमें तो राहुल और प्रियंका के साथ साथ वरुण गांधी भी शामिल हो जाते हैं। अभी तक ऐसे कोई संकेत तो नहीं मिले हैं कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस ने नो-एंट्री वाला बोर्ड हटा लिया है, लेकिन पीलीभीत से बीजेपी ने उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट देकर ऐसी संभावनाओं के द्वार तो खोल ही दिये हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना करीब करीब पक्का है। लेकिन जो स्थिति है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में राहुल गांधी की तुलना में बीजेपी की स्मृति ईरानी को ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती हैं - और जिस तरह से राहुल गांधी को वारिस के तौर पर पेश किया जाता रहा है, रायबरेली का मैदान उनका ज्यादा सूट करता है। अमेठी को लेकर राहुल गांधी के अलावा दो नाम चर्चा में हैं। एक नाम है एमएलसी रह चुके कांग्रेस नेता दीपक सिंह का - और दूसरा नाम है, बीजेपी सांसद वरुण गांधी का। दीपक सिंह को सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी से बड़े ही सख्त लहजे में दो-दो हाथ करते देखा जा सकता है - और वरुण गांधी के बारे में यहां तक बातें हो रही हैं कि वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी सीट तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस के ही पास है। वरुण गांधी को लेकर ऐसी चचाओं को एक ही बात कमजोर करती है वो है मेनका गांधी का ताजा बयान कि 'हम ऐसे लोग नहीं हैं।'

शारदीय नवरात्रि माता का सातवां स्वरूप माँ कालरात्रि

संजीव ठाकुर

मित्रों माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन 'सहस्त्रार' चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है।

देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी- काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यि, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धुमोरना देवी कालात्री के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में हैं। माता ने रक्तबीज राक्षस का वध करने के लिए कालरात्रि का रूप धारण किया था देवी के इस रूप में सभी राक्षस,भूत, प्रेत, पिसाच और नकारात्मक ऊजाओं का नाश होता है, जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। माँ की नासिका के श्वास-प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएँ निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ (गधा) है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभयमुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काँटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग (कटार) है।सिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ, सौधिकागम, देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रा रूप में किया गया है। सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य (सिद्धियों और निधियों विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन) का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों-विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य-लोकों की प्राप्ति होती है।

माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत रौद्ररूप है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम 'शुभंकारी' भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह-बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि-भय, जल-भय, जंतु-भय, शत्रु-भय, रात्रि-भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय-मुक्त हो जाता है।

माँ कालरात्रि के स्वरूप-विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए।

माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए '

नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा-अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में सातवें दिन इसका जाप करना चाहिए।

या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।

अर्थ : हे माँ ! सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार-बार प्रणाम है ' जय माता दी।

राष्ट्र निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ

15 अप्रैल चंद्रगुप्त मौर्य जयंती पर विशेष

चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था, जिसने एक संगठित राज्य की नींव डाली। राष्ट्र निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान भारत के इतिहास में बहुत ऊंचा है। साधारण से परिवार में जन्म लेकर नेपोलियन की ही भांति चंद्रगुप्त भी अपने बाहुबल के पराक्रम से भारत का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य को ठाठबाट तथा सुंदरता से बड़ा प्रेम था। शिकार उसका प्रिय व्यसन था। इस काम के लिये उसने शिकार के वन बनवा रखे थे। उसे पशुओं की लड़ाई देखने का भी बड़ा शौक था। वह एक महान विजेता, कुशल शासक, राजनीतिज्ञ तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यूनानियों को भारत से निकाल कर उत्तरभारत के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके इतना विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त को ही है। दक्षिण विजय का भी प्रमाण उपलब्ध है। अपनी शासन व्यवस्था का सुंदर संगठन करके चंद्रगुप्त ने अपने महान व्यक्तित्व का परिचय दिया। चंद्रगुप्त एक दयालु प्रजापालक तथा न्यायप्रिय शासक था। कृषि, व्यापार, वाणिज्य तथा दण्ड व्यवस्था के विकास में चंद्रगुप्त ने सराहनीय कार्य किया। मेगस्थनीज का कहना है कि उसके शासन ने प्रजासुखी थी। लोग संपन्न थे और अपराध नहीं होते थे।लोगों का जीवन पवित्र एवं शुद्ध था। चंद्रगुप्त का नाम भारतीय सम्राटों में बहुत ऊंचा है।

जिस समय सिकंदर पश्चिमी भारत को विजीत कर रहा था, उस समय पूर्वी भारत में राजनैतिक अराजकता फैली हुई थी। केवल मगध का राज्य ही एकमात्र शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य की सैनिक शक्ति से भयभीत होकर ही सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इंकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर को अपनी विजय अधूरी छोड़कर ही वापस लौटना पड़ा था। मगध राज्य के शासक काफी अलोकप्रिय थे। साथ ही इधर एक व्यक्ति मगध राज्य को पराजित करने की योजना बना रहा था। उस महान व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त की जाति के संबंध में विद्वानों में बहुत मतैक्य है। बहुत से विद्वान उसे किसी नीच जाति का मानते हैं। कुछ विद्वान उसे क्षत्रिय मानते हैं। वहीं कुछ उसे मगध सम्राट नंद का बेटा, जो मुरा नाम की शुद्र स्त्री से उत्पन्न हुआ मानते हैं। कुछ भी हो चंद्रगुप्त एक महान वीर, योग्य तथा पराक्रमी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ई. सन से लगभग तीन सौ पैतालीस वर्ष पूर्व हुआ था। इसका पालन पोषण माता ने किया था। कुछ लोगों का मत है ,चंद्रगुप्त मगध सम्राट के यहां काम करता था। पर कुछ कारणों से राजा से उसकी खटपट हो गई। अतः उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। चाणक्य नाम का एक ब्राम्हण भी नंद राजा का दुश्मन था ,क्योंकि राजा नदं ने उसका अपमान कर दिया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों नंदवंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे। संयोग से चंद्रगुप्त की भेंट चाणक्य से हो गई।

दोनों ने मिलकर नंदवंश के नाश की योजना बनानी शुरू की ।दोनों ने कुछ थोड़ी सेना इकट्ठी की और मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में इनकी पराजय हो गई। फलस्वरूप चाणक्य तथा चंद्रगुप्त दोनों को मगध छोड़ना पड़ा। मगध से भागकर चंद्रगुप्त चाणक्य के साथ पंजाब की ओर चला गया। उन दिनों सिकंदर पंजाब के राज्यों को जीत रहा था चंद्रगुप्त ने सोचा कि यदि सिकंदर नंद राज्य को जीत ले और फिर भारत से वापस चला जाये, तो मैं नंदराज्य पर अधिकार जमा लूं। इस विचारसे चंद्रगुप्त सिकंदर से मिला। पर उसकी बात से सिकंदर चिढ़ गया। और उसने अप्रसन्न होकर चंद्रगुप्त को मार डालने की आज्ञा दे दी, पर चंद्रगुप्त किसी तरह सिकंदर के चंगुल से भाग निकला। सिकंदर के वापिस जाने के बाद पंजाब में ही रहकर चंद्रगुप्त ने सेना इकटठी करनी शुरू कर दी। चाणक्य ने भी उसकी पूरा 'सहायता की दोनों ने मिलकर पंजाब के राजाओं को भी उकसाया। इस प्रकार चंद्रगुप्त के पास काफी विशाल सेना हो गई। और साथ ही वह पंजाब की जनता तथा राजाओं में लोकप्रिय हो गया। सेना - इकट्ठी करके चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उन सेनापतियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जिन्हें सिकंदर लौटते समय उन राज्यों का गवर्नर बना गया था, जो उसने जीते थे। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के बल से उत्तर पश्चिमी भारत से यूनानियों को मार भगाया। इस प्रकार पंजाब पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद चाणक्य ने काश्मीर की पहाड़ियों के राजा पर्वतेश्वर से संधि कर ली, ताकि एक विशाल सेना लेकर मगध के साम्राज्य पर आक्रमण किया जा सके।

इस प्रकार एक विशाल सेना लेकर चंद्रगुप्त मगध के नंद शासक पर आक्रमण करने चला। नंद राज्य का सेनापति भद्रशाल था। वह अपनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गया पर चंद्रगुप्त के सामने वह ठहर नहीं सका। चंद्रगुप्त इस युद्ध में विजयी रहा। इसके बाद नंदवंश के अन्य लोगों का भी वध कर दिया गया। इस प्रकार मगध पर अधिकार हो जाने के बाद संपूर्ण उत्तरी भारत पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। इन युद्धों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बड़ी सहायता की थी। इन युद्धों की विजय में जहां चंद्रगुप्त की वीरता का महत्व है वहां चाणक्य की कूटनीति तथा बुद्धि का भी है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना। चाणक्य को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। मगध के सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का बहुत सुंदर संगठन किया। उसकी सेना में छह लाख पैदल बीस हजार घुडसवार और नौ हजार लडाकू हाथी थे। चंदगुप्त का राज्य मगध और पंजाब तक सीमित नहीं था। जूनागढ़ के शिलालेख से तो यह भी प्रमाण मिलता है कि सौराष्ट्र भी उसके राज्य के अधीन था। कुछ इतिहासविदों का कहना है कि छह लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त दक्षिण विजय को गया एवं वहां भी उसने अधिकार स्थापित किया। चंद्रगुप्त के शासन कार्य में उसका प्रधानमंत्री चाणक्य उसकी बड़ी सहायता करता था। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसके संपूर्ण शासन को आठ अंगों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगर शासन, जनपद ग्रामीण शासन, सैनिक प्रबंध, न्याय व्यवस्था, अर्थ विभाग, गुप्तचर विभाग ।

केंद्रीय शासनः शासन का सारा अधिकार सम्राट को प्राप्त था। वह स्वतंत्र था और उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। देश के लिये वही कानून बनाता और देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश भी वहीं था। अपनी प्रजा के प्रति चंद्रगुप्त कभी उदासीन नही रहा। उसने वहीं कार्य किये, जो प्रजा के लिये हितकारी थे। मौर्य शासन कठोर व निरंकुश था। और समय को देखते हुए ऐसा होना ठीक ही था। शासन के काम में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी। मंत्रियों के अधीन और भी बहुत से कर्मचारी होते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, मंत्री परिषद की एक अंतरंग समिति थी, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज होते थे। युद्ध और शांति के मामले में सम्राट को परापर्श देने के लिये कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की एक समिति होती थी, पर सम्राट मंत्री परिषद या इस समिति की राय मानने के लिये विवश नहीं था। इसके अलावा अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे।

प्रांतीय शासनः संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभाजित व समीप के प्रांतों का शासन स्वयं सम्राट के अधीन होता था और दूर के मुख्य मुख्य प्रांतों का शासन राजकुल के कुमार करते थे। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने राज्यों में विभक्त था वह ज्ञात नहीं है प्रांत के शासको को बारह सौ पण वार्षिक वेतन मिलता था। प्रांत जनपदों में बंटे हुये थे। एक जनपद में कई गण होते थे, गण का अधिकारी स्थानिक कहलाता था। कई गांवों को मिलाकर एक गण बनता था। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता था। इसी प्रकार नगरों में मुख्य अधिकारी नागरिक होता था।

नगर शासनः पाटलीपुत्र के नगर शासन के संबंध में अनुमान है कि सभी बड़े नगरों में भी ऐसी ही व्यवस्था रही होगी। नगर का शासन नागरिकों के हाथ में था। उस समय आजकल की सी नगरपालिकाएं होती थी। नगर के शासन का सारा कार्य समितियों द्वारा होता था। और प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते थे। पहली समिति औद्योगिक शिल्पों की देखभाल करती थी। कारीगरों तथा शिल्पकारों की देखभाल करना तथा उनका परिश्रम के निर्धारित करना इसी समिति का काम था। दूसरी समिति विदेशियों की गतिविधियों तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त के राज्य में विदेशियों की संख्या काफी थी, तीसरी समिति नगर में होने वाले जन्मों तथा मृत्युओं का हिसाब रखती थी, चौथी समिति सामान्य व्यापार तथा वाणिज्य के लिये उत्तरदायी थी। लेनदेन में सही मापों तथा बांटों का प्रयोग किया जाये इस बात की निगरानी वही समिति करती थी। एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करने वालों को अपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता था, कारखानों तथा उत्पादों का निरीक्षण करना पांचवी समिति का काम था। यह समिति ध्यान रखती थी कि नई व पुरानी वस्तुयें एक साथ मिलकर न बेची जाये।

जनपद शासनः गांवों का शासन पहले जैसा ही था गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थे। गांव का प्रबंधकर्ता ग्रामिक कहलाता था, जो ग्राम वृद्धों की सहायता से गांव का प्रबंध करता था। पांच या दस गांवों का अधिकारी गोप कहलाता था। इससे बड़े क्षेत्र का अधिकारी स्थानिक कहलाता था। स्थानिक से बड़ा अधिकारी समाहर्ता होता था।

सैनिक प्रबंधः चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य की काफी सेना मिली थी। बाद में उसने अपनी सेना को और भी बढ़ाया। चंद्रगुप्त की सेना में छह लाख पैदल, तीस हजार घुडसवार,नौ हजार हाथी और आठ हजार रथ थे। इतनी बड़ी विशाल सेना का प्रबंध करने के लिये एक परिषद थी, जिसमें तीस सदस्य होते थे। पांच पांच सदस्यों की छह समितियां बनी हुई थी। सेना के निम्नलिखित विभाग एक एक समिति के अधीन थे। नौ सेना, यातायात तथा युद्ध सामग्री, पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना और गज सेना, नौ सेना समिति का काम नौकाओं व जहाजों की देखभाल करना था, सेना यातायात तथा युद्ध सामग्री समिति का काम सेना के आवागमन का प्रबंध करना, तथा युद्ध सामग्री पहुंचाने का प्रबंध करना था। पैदल सेना समिति का काम पैदल सैनिको का प्रबंध करना था। अश्व सेना समिति का काम घुडसवारों तथा घोड़ों की देखभाल करना था, रथ सेना समिति का काम युद्ध के रथों का प्रबंध करना था। और गज सेना समिति का काम लडाकू हाथियों संबंधी प्रबंध करना था।

न्याय व्यवस्थाः सम्राट देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। नगरों व गांवो में अलग अलग न्यायालय थे, जिनमें मुकदमों के फैसले किए जाते थे। बहुत से मामले साधरण पंचायतों द्वारा तय हो जाते थे, नीचे के न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उपर के न्यायालयों ने अपील करने का नियम था। दण्ड बहुत कठोर था। कठोर दण्ड इसलिये थे कि अपराध बहुत कम हो। अपराधी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जाती थी। छोटे छोटे अपराधों पर भी बहुत सजा दी जाती थी। अंगहानि करने या अपवंचन करने के अपराधों में मृत्युदण्ड दिया जाता था । व्याभिचारी का अंग भंग कर दिया जाता था। दण्डों की कठोरता का प्रभाव यह हुआ कि अपराध बहुत ही कम होते थे।

अर्थ विभाग- साम्राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर या संपूर्ण उपज का चौथाई भाग कर के रूप में लिया जाता था! कुछ अवस्थाओं में यह कर उपज का आठवां भाग भी लिया जाता। भूमिकर की वसूली की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। समाहर्ता नामक अधिकारी इसी काम के लिये होता था। जमींदारी प्रथा नहीं थी। सम्राट तथा किसानों का सीधा संबंध था। राज्य की ओर से भूमि का सिंचाई आदि की व्यवस्था होती थी। नगरों में जन्म मरण कर, जुमार्ने तथा बिक्री कर से भी राज्य को आय होती थी। - इसके अलावा खान, वन, घाट, तथा चुंगी आदि भी राज्य के आय के साधन थे।

गुप्तचर विभागः सम्राट चंद्रगुप्त का गुप्तचर विभाग बहुत अच्छा संगठित था। इसका मुख्य काम अपराधियों तथा विद्रोहियों पर निगरानी रखना तथा उनकी गतिविधियों का पता लगाना था। ये भेष बदलने में बड़े निपुण होते थे। तथा तरह तरह की भाषाएं भी जानते थे। इस तरह वे हर तरह के लोगों में जाकर सब प्रकार की बातें मालूम कर लेते थे। कुछ गुप्तचर एक स्थान पर रहते थे, और कुछ इधर उधर घूमते फिरते थे। राजा के पास ये अपनी क्रियाकलापों का ब्यौरा भेजा करते थे। चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ यह नगर साढ़े नौ मील लंबा और लगभग एक बटे तीन चौथाई मील चौड़ा था। नगर की रक्षा के लिये छह सौ फीट से अधिक चौडी तथा तीस हाथ गहरी खाई चारों तरफ बनाई गई थी। इसके अलावा एक ऊंची प्राचीन भी थी, जिसमें 570 बुर्ज तथा 64 द्वार थे। सारा शहर लकड़ी का बना होता था, जगह जगह पर टूटने वाले पुल तथा फाटक थे। विश्रामगृहों, नाट्यशालाओं, खेलघरों, दौड़ के मैदानों तथा अन्य प्रकार के सार्वजनिक स्थानों से नगर शोभायमान रहता था, बाजार बहुत सुंदर और व्यवस्थित थे। सड़कों पर भी खूब भीडभाड़ रहती थी। सम्राट का महल नगर के बीच में था, जिसके चारों ओर सुंदर बाग थे। सम्राट का महल भी लकड़ी का ही बना हुआ था। सम्राट का महल बड़ा भव्य एवं सुंदरता की मिशाल लिये अप्रतिम था। एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में बहुत जोर का अकाल पड़ा। उसी समय वह जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर चला गया, और उधर ही 298 ई. पू. मे उसकी मृत्यु हो गई।

- सुरेश सिंह बैस ''शाश्वत''

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

दिल्ली शराब घोटाला, पतन की ओर आप

दिल्ली शराबकांड में अब कुछ भी धुंधलापन नहीं रहा। उसका आधे से अधिक सच सामने आ चुका है। सारी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। यह सही है कि हर अपराधी स्वयं को निर्दोष बताता है। यह उसका मौलिक अधिकार तो नहीं मगर एक प्रचलित परम्परा जरुर है जिसे कोर्ट में साबित करने के लिए उसके पास वकील होते हैं। केजरीवाल के पास तो वकीलों की फ़ौज मौजूद है। विडम्बना है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस करने वाली यह पार्टी यदि इंडी गठबंधन के माध्यम से कभी सत्ता में आ जाए तो क्या इसके खिलाफ निर्णय देने वाले जजों को सबक सिखाया जाएगा जैसे कि इंदिरा गांधी ने उन जजों और वकीलों को सबक सिखाया था जिन्होंने उनके चुनाव को अवैध करार दिया था। भारत के राजनैतिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए जेल भेजा गया है। केजरीवाल ने जमानत की आशा में अभी तक सीएम पद से त्यागपत्र नहीं दिया है जबकि उन्होंने जेल जाने पर मनीष सिसौदिया और सत्येंद्र जैन से त्यागपत्र ले लिया था। निश्चित रूप से यह इन दोनों के प्रति अन्याय भी है और डर भी। व्यावहारिक रूप से केजरीवाल जेल से सरकार चला भी नहीं सकते। जब ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ़्तारी को अवैध कहने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और साफ़ कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी सबूतों और जांच के बाद की गई है जो गैर कानूनी नहीं है तो सारे प्रकरण की कढ़ी फ़ैल गयी। गिरफ़्तारी को पुनः चुनौती देकर उस पर बहस करते हुए फिर वही पुराना राग अलापा गया कि कोई पैसा नहीं मिला और बिना जांच और सबूतों के केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वह भी चुनाव के समय जिससे उसे बदनाम किया जा सके और पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसी बातें भला कानून की नज़र में कैसे सही मानी जा सकती हैं क्योंकि उनका गिरफ़्तारी से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

केजरीवाल को जब पहला सम्मन अक्टूबर, 2023 में दिया गया था तब तो लोकसभा चुनाव की हवा तक नहीं थी। नवंबर में तीन राज्यों के चुनाव थे लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे जिन्हे देख कर जजों को कहना पड़ा कि इन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर रोक न लगा कर एक तरह से अनुमति दे दी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। शराब घोटाला काण्ड में ईडी ने केजरीवाल पर पीएमएलए की धारा 70 (जिसके अंतर्गत राजनैतिक दल एक कंपनी के समान हैं) के तहत जो आरोप लगाया है, उसने केजरीवाल की गर्दन बहुत सही से फंसा दी है। पार्टी की अधिकाधिक शक्तियां अपने पास रख कर पार्टी पर वर्चस्व बनाये रखने के मामले मे खुद को खुदाई फौजदार समझना ही उन पर भारी पड़ रहा है। दिए गये सबूतों के आधार पर सुप्रीमकोर्ट भी यह नहीं कह पायेगा कि पीएमएलए की धारा 70 इस मामले में लागू नहीं होती।

बंगाल में रक्तरंजित चुनाव की आहट

– बाल मुकुन्द ओझा

बंगाल की राजनीति और हिंसा का गहरा सम्बन्ध है। यह गहन शोध का विषय है की आखिर बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं तब यहाँ क्यों खून बहता है। कम्युनिष्ट नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने बंगाल में वर्ष 1967 में नक्सलबाड़ी से हिंसक राजनीतिक विरोध की शुरुआत की थी। तत्कालीन सरकार ने हिंसक हो चुके नक्सलबाड़ी आंदोलन पर पुलिस बल का प्रयोग करके उसे कुचलने का प्रयास किया और उसके बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच शुरू हुई राजनीतिक हिंसा की बेहद खराब परंपरा बंगाल में आज और ज्यादा वीभत्स रूप में बनी हुई है। एक लम्बे वामपंथी शासन से यह रक्तरंजित शुरुआत हुई जो ममता बनर्जी शासन में लगातार जारी है। यहाँ पिछले पचास वर्षों में शासन सत्ता जरूर बदली मगर हिंसा कभी नहीं थमी जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और यह खूनी खेल आज भी बदस्तूर जारी है। वर्तमान लोकसभा चुनाव की बात करें तो बात बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली प बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे है बंगाल में लोकसभा चुनाव का। पिछले विधानसभा और फिर पंचायत चुनाव में इस प्रदेश में खून की होली खेली गई थी। इस बार भी कमोवेश फिर यही स्थिति बनने का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जाँच एजेंसियों पर खुलेआम हमले हो रहे है। बंगाल हाई कोर्ट ने भी कई बार राज्य सरकार को चेतावनी दी है। अब लोकसभा के सियासी संग्राम के रक्तरंजित होने के खतरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चुनौतीपूर्ण हो गए है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही शुरू हुई हिंसा और इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज हो रही है। भाजपा प्रत्यासियों पर लगातार हमले हो रहे है। सरकारी आंकड़ों के दौरान नामांकन-पत्र दाखिल करने के दौरान राज्य के अलग-अलग इलाको में हुई हिंसा में कई दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इससे पूर्व विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान भी भारी हिंसा हुई जिसमें अनेक लोग मारे गए हुए सैंकड़ों लोग घायल हो गए थे। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बल तैनाती का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने प्रदेश के अनेक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्यपाल ने दौरे के बाद कहा, राज्य में राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर हुई झड़पों के बाद पिछले कई दिनों से भारी हिंसा की मार झेल रहा है। इससे पूर्व संदेशखाली में महिलाओं से हुए अत्याचार की घटनाएं सामने आ चुकी है। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव में जीत वोटों की गिनती पर आधारित होनी चाहिए न कि हिंसा पर। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें इसे रोकना होगा। पश्चिम बंगाल में फैली हिंसा में राजनीतिक दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिष्ट और कांग्रेस पार्टियों के बीच दावों-प्रतिदावों समेत आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। नेताओं की जबान फिसलने की भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। प बंगाल की चुनावी लड़ाई लोकसभा चुनाव के इतिहास में बहुत अधिक दिलचस्प और रोमांचक होने जा रही है। तृणमूल का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों ने यहाँ अपनी सारी शक्ति झोंक दी है। भाजपा के लिए यह चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। प बंगाल में वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ है। तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी ने इस राज्य में वामपंथियों के लम्बे शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की थी। भाजपा ममता की पार्टी को नेस्तनाबूद कर सत्ता प्राप्त करना चाहती है और उसने यहाँ अपने सारे संसाधन लगा दिए है। प बंगाल में लोकसभा के चुनाव बहुकोणीय है।

यहाँ कांग्रेस और वामपंथियों ने अपना गठजोड़ किया है। सियासी दलों के बीच बयानों के प्रहार तीखे होते जा रहे हैं। ये तीखे प्रहार कटु नारों और व्यंग्य के रूप में वायरल भी हो रहे हैं। इस भांति यहाँ स्पष्ट रूप से त्रिकोणात्मक संघर्ष की सम्भावना अधिक है। बंगाल में सत्ता की राह ग्रामीण इलाकों से ही निकलती है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों के चुनावों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में होने वाले लोकसभा चुनावों को ज्यादा सुर्खियां और अहमियत मिलती रही हैं। बंगाल में ग्रामीण इलाके शुरू से ही सत्ता की चाभी हैं। बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। यहाँ रक्तरंजित चुनाव से इंकार नहीं किया जा सकता। दलों ने बड़ी बड़ी रैलियों का आगाज कर प्रचार शरू कर दिया है। पार्टियों में रोज ही मारकाट होती है। एक दूसरे पर हमले हो रहे है। बम बाजी आम बात हो गई है। हत्या के आरोप भी लगाए जा रहे है। भाजपा का कहना है उसकी पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे है। दूसरी तरफ राज्यपाल भी बहुत मुखर होकर बोल रहे है। राज्यपाल खुले आम कह रहे है सरकारी कर्मचारी सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता की भांति काम कर रहे है। राज्यपाल कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगा रह है। उन्होंने केंद्र को भेजी अपनी रिपोर्ट में बंगाल की स्थिति की चर्चा करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपनी शंका व्यक्त की है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

चुनाव में व्यक्ति नहीं, मूल्यों की स्थापना का दौर चले

भाजपा जो हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करती रही,उसकी शुचिता कहां है? कितने दागी एवं अपराधी नेताओं को उसने अपने दल में जगह ही नहीं दी,टिकट तक दे दिया। हो सकता है 400 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिये भाजपा की कुछ मजबूरियां हो। कमल तो खिलेगा ही,लेकिन उस खिलाहट में मजबूरियों के नाम पर मूल्यों के साथ समझौता नहीं होता तो यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने का एक अनूठा उदाहरण होता।

– ललित गर्ग –

लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां उग्र से उग्रतर होती जा रही है, पहली बार भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बन रहा है, कुछ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं तो कुछ भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं। मुसलमान वोटों की राजनीति करने वाले दल अपने घोषणा पत्रों में उनके कल्याण की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का सशक्तीकरण करने की बचाय उनके तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ दल देश-विकास की बात कर रहे हैं तो कुछ दल विकास योजनाओं की छिछालेदार कर रहे हैं। किसी भी दल के चुनावी मुद्दे में पर्यावरण विकास की बात नहीं हैं। व्यक्ति नहीं, मूल्यों की स्थापना के स्वर कहीं भी सुनाई नहीं दे रहे हैं। सत्ता और स्वार्थ ने अपनी आकांक्षी योजनाओं को पूर्णता देने में नैतिक कायरता दिखाई है। केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात करके नैतिक एवं राजनीतिक मूल्यों के आन्दोलन से सरकार बनाने के सच को ही बदनुमा बना दिया है। इसकी वजह से लोगों में विश्वास इस कदर उठ गया कि चौराहे पर खड़े आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला भी झूठा-सा लगता है। आंखें उस चेहरे पर सचाई की साक्षी ढूंढती हैं। समस्याओं से लड़ने के लिये हमारी तैयारी पूरे मन से होनी चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व पर समझना चाहिए कि हमने जीने का सही अर्थ ही खो दिया है। यद्यपि बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है। कितने ही नए रास्ते बने हैं। फिर भी किन्हीं दृष्टियों से हम भटक रहे हैं। भौतिक समृद्धि बटोरकर भी न जाने कितनी रिक्तताओं की पीड़ा सही है। गरीब अभाव से तड़पा है, अमीर अतृप्ति से। कहीं अतिभाव, कहीं अभाव। जीवन-वैषम्य कहां बांट पाया अपनों के बीच अपनापन। अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं, बस्तियां बस रही हैं मगर आदमी उजड़ता जा रहा है। पूरे देश में मानवीय मूल्यों का ह्रास, राजनीति अपराध, भ्रष्टाचार, कालेधन की गर्मी, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन, अन्याय, शोषण, संग्रह, झूठ, चोरी जैसे-अनैतिक अपराध पनपे हैं। धर्म, जाति, राजनीति-सत्ता और प्रांत के नाम पर नए संदर्भों में समस्याओं ने पंख फैलाये हैं। हर बार के चुनावों की तरह इस बार भी आप, हम सभी अपने आपको जीवन से जुड़ी अंतहीन समस्याओं के कटघरे में खड़ा पा रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि जनता की अदालत में कहां, कौन दोषी है? पर यह चिंतनीय प्रश्न अवश्य है हम इतने उदासीन एवं लापरवाह कैसे हो गये कि राजनीति को इतना आपराधिक होने दिया? जब आपके द्वार की सीढ़ियां मैली हैं तो अपने पड़ौसी की छत पर गन्दगी का उलाहना मत दीजिए। कोई भी अच्छी शुरूआत सबसे पहले स्वयं की की जानी जरूरी है। देश के लोकतंत्र को हांकने वाले लोग इतने बदहवास होकर निर्लज्जतापूर्ण कारनामे करेंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चौराहे पर खड़ा आदमी सब कुछ देख रहा है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा कि वह कौन सी राह पकड़े। आम आदमी सरकार ने शराब-शिक्षा में घोटाले किए, दागी चिन्हित भी हुए लेकिन आप सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड अपना लिए। अपनों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार नहीं, राबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ नजर नहीं आता और वे चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बात केवल कांग्रेस की ही नहीं है, बात राजनीतिक आदर्शों की हैं। जिसकी वकालत करते हुए कभी अन्ना हजारे तो कभी बाबा रामदेव, कभी केजरीवाल तो कभी श्री रविशंकरजी जन-आन्दोलन की अगवाई करते देते थे, अब ना तो ऐसे आन्दोलन होते हैं न ही उन पर विश्वास रहा। हमारे भीतर नीति और निष्ठा के साथ गहरी जागृति की जरूरत है। नीतियां सिर्फ शब्दों में हो और निष्ठा पर संदेह की परतें पड़ने लगें तो भला उपलब्धियों का आंकड़ा वजनदार कैसे होगा? बिना जागती आंखों के सुरक्षा की साक्षी भी कैसी! एक वफादार चौकीदार अच्छा सपना देखने पर भी इसलिए मालिक द्वारा तत्काल हटा दिया जाता है कि पहरेदारी में सपनों का खयाल चोरी को खुला आमंत्रण है।

भाजपा जो हमेशा राजनीतिक शुचिता की बात करती रही, उसकी शुचिता कहां है? कितने दागी एवं अपराधी नेताओं को उसने अपने दल में जगह ही नहीं दी, टिकट तक दे दिया। हो सकता है 400 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिये भाजपा की कुछ मजबूरियां हो। कमल तो खिलेगा ही, लेकिन उस खिलाहट में मजबूरियों के नाम पर मूल्यों के साथ समझौता नहीं होता तो यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने का एक अनूठा उदाहरण होता। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कभी कहा था कि व्यक्ति को अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से पहचाना जाना चाहिए, यह वाक्य उनके पोते राहुल गांधी पर भी लागू हो रहा है। वे तमाम सुखों एवं सुविधाओं में पले-बढ़े और उन्होंने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया या ये कहें कि जीवन के लिए संघर्ष करने की उनके सामने कोई नौबत नहीं आई। कहते हैं - 'जा के पैर न परी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'। जब आप लोगों की पीड़ा को उसी भाव से महसूस नहीं कर पाते तो दूसरों को आपकी बात पर भरोसा नहीं हो पाता। इस भरोसे को पाने के लिए उस पीड़ा को पहले खुद भुगतना होता है। यही वजह है कि राहुल गांधी सच्ची और ठीक बात कहते हैं तब भी लोग उसे उस सच्चाई के साथ, उस भाव में अंगीकार नहीं कर पाते। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मौजूदा यह आचरण स्वीकार्य नहीं। पूरा राजनीतिक वातावरण ही हास्यास्पद हो चुका है। यदि हालात नहीं सुधरे तो राजनीतिक दलों की दुर्गति तय है। बदलती राजनीतिक सोच एवं व्यवस्था के मंच पर बिखरते मानवीय मूल्यों के बीच अपने आदर्शों को, उद्देश्यों को, सिद्धांतों को, परम्पराओं को और जीवनशैली को हम कोई ऐसा रंग न दे दें कि उससे उभरने वाली आकृतियां हमारी भावी पीढ़ी को सही रास्ता न दिखा सकें। राजनीति का वह युग बीत चुका जब राजनीतिज्ञ आदर्शों पर चलते थे। आज हम राजनीतिक दलों की विभीषिका और उसकी अतियों से ग्रस्त होकर राष्ट्र के मूल्यों को भूल गए हैं। भारतीय राजनीति उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। चारों ओर भ्रम और मायाजाल का वातावरण है। भ्रष्टाचार और घोटालों के शोर और किस्म-किस्म के आरोपों के बीच देश ने अपनी नैतिक एवं चारित्रिक गरिमा को खोया है। मुद्दों की जगह अभद्र टिप्पणियों ने ली है। व्यक्तिगत रूप से छींटाकशी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाठशाला के प्रधानाचार्य की तरह अपने दल के कार्यकर्ताओं को पाठ पढ़ाया कि वह झूठे एवं बेबुनियाद आरोपों की परवाह किए बिना तेजी से काम करें। जबकि विपक्षी दलों की सारी की सारी कवायद में एक अनर्थ सच्चाई के ही दर्शन हुए क्योंकि जैसे केवल चेहरे बदलने से दामन के दाग नहीं धुल जाते, वैसे ही कुछ युवा चेहरों को सामने खड़ा करने से क्रांतिकारी सोच पैदा नहीं की जा सकती। भ्रष्टाचार के मुद्दे को व्यक्तिगत आरोपों की झड़ी लगाकर पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश की जा रही है। कई राजनीतिक दल तो पारिवारिक उत्थान और उन्नयन के लिये व्यावसायिक संगठन बन चुके हैं। सामाजिक एकता की बात कौन करता है। आज देश में भारतीय कोई नहीं नजर आ रहा क्योंकि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, तमिल की पहचान भारतीयता पर हावी हो चुकी है। वोट बैंक की राजनीति ने सामाजिक व्यवस्था को क्षत-विक्षत करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि सब चोर एक साथ शोर मचा रहे हैं और देश की जनता बोर हो चुकी हैं। हमें अतीत की भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हुई हैं। हो सकता है कि हम परिस्थितियों को न बदल सकें पर उनके प्रति अपना रूख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। आने वाले नये राजनीतिक नेतृत्व का सबसे बड़ा संकल्प यही हो कि राष्ट्रहित में स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। व्यक्ति का क्या मूल और क्या विसात। विरोध नीतिगत होना चाहिए व्यक्तिगत नहीं। एक उन्नत एवं विकासशील भारत का निर्माण करने के लिये हमें व्यक्ति नहीं, मूल्यों एवं सिद्धान्तों को शक्तिशाली बनाना होगा।

आदर्श आचार संहिता

– पंकज शर्मा तरुण

आजकल देश में लोकसभा के चुनाव का मौसम चल रहा है।आचार संहिता लागू होने के बाद से देश में अनुशासन जैसा लगने लगा है। सारे सरकारी विभाग खासकर पुलिस, आबकारी व परिवहन विभाग सड़कों पर गश्त करते दिखाई देने लगे हैं। आम जनता असहज सा महसूस करने लगती है। जब उसे नियमों का पालन सख्ती से करने के लिए बाध्य किया जाता है, बेतरतीब ट्रेफिक में मनमाने तरीकों से वाहन चलाना हमारी आजादी की जैसे खास शर्त है। शराब पीकर वाहन चलाना जन्म सिद्ध अधिकार है। पुलिस के साथ गलती करने पर भी उलझना और फिर करीबी सत्ताधारी नेता से फोन पर धमकी दिलवाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है। संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले कथित पढ़े लिखे सभ्य नागरिक अपने कर्तव्यों को निभाने की नौबत आती है तो बगलें झांकने लग जाते है।यदि कोई पुलिस वाला किसी एक्सीडेंट स्थल का मौका पंचनामा बनाकर हस्ताक्षर करने को कहता है तो हम बचने का पूरा प्रयास करते हैं। यह कहते हुए कि साहब कहां कोर्ट कचहरी के पचड़े में डाल रहे हैं। जबकि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी कामों में पूरी सहायता करेगा। अब जब आचार संहिता लग जाती है तो प्रशासनिक सख्ती तो बुरी लगती ही है। प्रशासन का यह बदला स्वरूप अजीब लगने लगाता है, क्योंकि इसकी तो हमें आदत थी ही नहीं । नगर प्रशासन जब अवैध अतिक्रमण हटाने को आता है, तो लोग काले नाग की तरह फुफकारने लगते हैं। जैसे उसकी मणि छीनने का प्रयास किया जा रहा है। जब कि इसने सरकारी जमीन पर अपना घर/ दुकान लगाया होता है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से यह प्रमुख समस्या है। जिसको कोई भी सुलझाने में प्रशासन की मदद नहीं करना चाहता। जबकि यह काम जन हित का ही काम है। आचार संहिता में नेता जी की हालत मरे हुए सांप की भांति हो जाती है। जिससे डर भी लगता है कि कहीं बेहोश हुआ तो डस लेगा। देश के लगभग सभी शहरों में जुआ/ सट्टा धड़ल्ले से जारी रहता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आचार संहिता लगने के पश्चात पुलिस द्वारा इनकी धर पकड़ में अचानक हुई वृद्धि से साबित होता है। लगता है कि भारत में हमेशा कोई न कोई चुनाव होते रहना चाहिए, ताकि देश में अनुशासन बना रहे और मरे हुए सांप जीवित न हो सकें। अंत में आप से मेरा एक कर बद्ध निवेदन है कि यदि आप वयस्क नागरिक हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुनें जो आपके दुख दर्द में हमेशा सहयोगी बनता रहे। समाज की बुराइयों को मिटाने की पुरजोर कोशिश करे। विकास के पहिए को थमने न दें। (विनायक फीचर्स)

हस्त बंधने मोबाइलाया !

– रामविलास जांगिड़

सभी सरकारी ऑफिसर अपना ऑफिस व्हाट्सएप पर सजाते हैं। तरह-तरह के सरकारी ग्रुप व्हाट्सएप पर सरक-कार का झुनझुना बजाते हैं। ग्रुप के भीतर ग्रुप! ग्रुप के बाहर ग्रुप! ग्रुप के अंदर ग्रुप! ग्रुप ही ग्रुप! सरकारी आज्ञा, आदेश, नियम, निर्देश, योजना, क्रियान्विति, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन आदि का पचड़ा व्हाट्सएप ग्रुप का सच्चा अखाड़ा है। मैसेज, ऑडियो, वीडियो, फोटो बखेड़ा है! कट-पेस्ट फॉरवर्ड! कटिंग पेस्टिंग फॉरवर्डिंग! सरकारी खेल चालू है! टीचर व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ा रहा है और विद्यार्थी ग्रुप में कहीं ओर पार्टी मना रहा है। अफसर व्हाट्सएप पर कुरकुरी रिश्वत खा रहा है और नेता व्हाट्सएप से कुर्सी पर नजरें जमा रहा है। सभी सरकारी कार्यालय व्हाट्सएप पर जारी है और प्रेमी-प्रेमिका को व्हाट्सएप की बीमारी है। दुनिया में व्हाट्सएप ही भारी है। पीर-पंडित गण गला फाड़ रहे हैं- कराग्रे वसति व्हाट्सएपा, कर मध्ये भी व्हाट्सएपा। कर मूले व्हाट्सएपा, हस्त बंधने मोबाइलाया। शेर और बकरी एक ही तालाब पर पानी पीते हैं; तालाब का नाम है व्हाट्सएप! नेता और डाकू अपना सम्मेलन एक साथ करते हैं, जगह का नाम है व्हाट्सएप! चोर और साहूकार एक जगह मंडी लगाए बैठे हैं, मंडी सजी है व्हाट्सएप! अगर कोई सरकार व्हाट्सएप बंद कर दे तो सरकार उसी क्षण गिर जाएगी। अगर कोई प्रेमी व्हाट्सएप बंद कर दे तो प्रेमिका उसी क्षण मर जाएगी। हलवाई व्हाट्सएप न खोले तो उसके पकोड़े हवा हो जाएंगे। व्हाट्सएप टचिंग बिन हॉस्पिटल के सारे पत्थर दवा हो जाएंगे। काकी व्हाट्सएप पर चूड़ियां खनका रही है और भैंस लिपस्टिक की नई शेड व्हाट्सएप पर चिपका रही है। सारे देवता व्हाट्सएप पर फूलों की बरसात कर रहे हैं और सारे पीर-पैगंबर व्हाट्सएप पर प्रेम गीत गा रहे हैं। हे व्हाट्सएप देव! प्लीज! ऐसे धोखा मत देना! सकल पदारथ है जग माहीं, बिन व्हाट्सएप कछु पावत नाहीं! व्हाट्सएप बिना चैन कहां रे! सोना नहीं, चांदी नहीं, व्हाट्सएप तो मिला! अरे व्हाट्सएप कर दे! कब्रिस्तान में भूतों को व्हाट्सएप न मिले तो वे खफा हो जाएंगे। व्हाट्सएप बिना कवि सारी कविताएं भूलकर मूंगफली बेचने के धंधे में उतर जाएंगे। व्हाट्सएप बिना सारे बादल बिन बरसात किए यूं ही छितर जाएंगे। गुड्डू को नाश्ते में, अफसर को लंच में और बीवी को डिनर में सिर्फ व्हाट्सएप चाहिए! जरिए व्हाट्सएप खनखनाती गर्मी में सावन की बरसात लाइए। चादर ओढ़ रात ढाई बजे जापानी कन्या संग प्रेम गीत गाइए! मुझे बहुत डर लग रहा है। हे व्हाट्सएप देव! अगर किसी रात आप बंद हो गए तो हमारी सरकार का क्या होगा? हमारे अफसरों का क्या होगा? सरकारी कार्यालय तो बंद ही हो जाएंगे। हमारे कामकाज का क्या होगा? हमारी प्रेमिकाओं को क्या होगा?

(उत्तम नगर, घूघरा, अजमेर)

कह सकते हैं कि हरेक लोकसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले कुछ न कुछ विजयी रहे हैं। बेशक,ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जुझारू प्रतिबद्धता के साथ कुछ काम तो करते होंगे। वर्ना ये सब लोकसभा में कभी नहीं पहुंच पाते। खासतौर पर तब जबकि चुनावों में धन का इस्तेमाल तो बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप में बहुत बुलंद शख्सियत के मालिक होते हैं।

क्यों घट रही लोकसभा में आजाद उम्मीदवारों की संख्या ?

- आर.के. सिन्हा

बुजुर्ग हिन्दुस्तानियों को याद होगा ही कि एक दौर में वी.के.कृष्ण मेनन, आचार्य कृपलानी, एस.एम.बैनर्जी, मीनू मसानी, लक्ष्मीमल सिंघवी, इंद्रजीत सिंह नामधारी, करणी सिंह, जी. जी. स्वैल जैसे बहुत सारे नेता आजाद उम्मीदवार होते हुए भी लोकसभा का कठिन चुनाव जीत जाते थे। पर अब इन आजाद उम्मीदवारों का आंकड़ा लगातार सिकुड़ता ही चला जा रहा है। अगर 1952 के पहले लोकसभा चुनावों के नतीजों को देखें तो हमें इन विजयी आजाद उम्मीदवारों की संख्या 36 मिलेगी। तब इनका समूह कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा था। यानि किसी भी गैर-कांग्रेसी दल से बड़ा था। निवर्तमान लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ तीन रह गई थी। अभी तक मात्र 202 निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे हैं। बेशक, लोकसभा का चुनाव अपन बलबूते पर लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की दरकरार रहती है। इसके बावजूद भी अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो इतना तो माना ही जा सकता है कि उसकाआम जनता में गहरा प्रभाव है। पहले लोकसभा चुनावों के बाद 1967 के लोकसभा चुनावों में 34 आजाद उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे थे। देश में इमरजेंसी लगने के बाद 1977 में चुनाव हुआ। तब सिर्फ सात आजाद उम्मीदवार सफल रहे। यह संख्या 1980 में मात्र चार रह गई। 1984 और 1989 के लोकसभा चुनावों में क्रमशः 9 और 8 आजाद उम्मीदवार ही निर्दलीय रूप से लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कह सकते हैं कि हरेक लोकसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले कुछ न कुछ विजयी रहे हैं। बेशक, ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जुझारू प्रतिबद्धता के साथ कुछ काम तो करते होंगे। वर्ना ये सब लोकसभा में कभी नहीं पहुंच पाते। खासतौर पर तब जबकि चुनावों में धन का इस्तेमाल तो बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप में बहुत बुलंद शख्सियत के मालिक होते हैं। इनमें से कुछ मनीषी भी रहे हैं। कृपलानी जी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे गांधी जी के सबसे उत्साही और विश्वासपात्र शिष्यों में से एक थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में भी कार्य किया था। लक्ष्मीमल सिंघवी जैसे सरस्वती पुत्र भी सदियों में पैदा होते हैं। वे ख्यातिलब्ध न्यायविद, संविधान विशेषज्ञ, कवि, भाषाविद एवं लेखक थे। वे 'धर्मयुग' में विधि संबंधी मामलों में खूब लिखते थे। जब मैं 'धर्मयुग' में आवरण कथाएं लिखा करता था। उनका जन्म जोधपुर में हुआ था। वे 1952 से 1967 तक तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। चाहे सांसद रहे हों या किसी और संस्था से जुड़ गए हों, लेकिन उन्होंने वेतन के रूप में हमेशा एक रुपया ही लिया था। आप कानपुर में जाकर अब भी एस.एम. बैनर्जी के बारे में पूछ लें। आपको लोग उनके तमाम किस्से सुनाएँगे। वे एक विख्यात मजदूर नेता थे। वे पश्चिम बंगाल से कानपुर में नौकरी करने के लिए आए थे। कानपुर को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना लिया था। कोलकाता से आये मजदूर नेता एस.एम. बैनर्जी ने 1957 में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की तो 1962, 1967 और 1971 तक जीत का सेहरा वही पहनते रहे। शायद कानपुर अकेला शहर होगा, जहां चार बार लगातार कोई निर्दलीय सांसद चुना गया हो।

आपको विजयी हुए निर्दलीय उम्मीदवारों में इस तरह के कई नाम मिल जाएंगे जो उस लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए, जहाँ से उनका उस क्षेत्र से कोई सीधा संबंध नहीं था। वहां पर जनता से जुड़कर और उनके सुख-दुःख का हिस्सा बनकर वे वहां के हो गए। कृपलानी जी सिंध (अब पाकिस्तान) से आए थे। वे बिहार से सांसद बने। इंदरजीत सिंह नामधारी का परिवार देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान से बिहार आकर बस गया था। वे बरसों बिहार के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रहे। बिहार के विभाजन के बाद वे झारखंड में सक्रिय हो गए। इंदर सिंह नामधारी झारखंड के पहले विधान सभा अध्यक्ष बने। वे वनांचल राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता थे जिसने दक्षिण बिहार के लिए अलग राज्य की मांग की थी। अब डॉ. करणी सिंह की भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि नई पीढ़ी को उनके संबंध में कम जानकारी हो। वे देश के चोटी के निशानेबाज थे। डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज किसी खिलाडी के नाम पर रखा गया राजधानी का पहला स्टेडियम माना जा सकता है। आमतौर पर यह नहीं होता। डॉ. करणी सिंह रेंज का निर्माण 9 वें एशियाई खेलों के निशानेबाजी के मुकाबलों के लिए 1982 में हुआ था। डॉ. करणी सिंह बीकानेर के राज परिवार से थे। वे देश के पहले निशानेबाज थे जिन्हें 1961 में 'अर्जुन पुरस्कार' देकर सम्मानित किया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे राज परिवार से आने के बावजूद आम जनता के सुख-दुख में शामिल होते रहते थे। वे 1952 से 1977 तक लगातार पांच बार सांसद रहे। उन्होंने दो चुनाव में 70 से 71 फीसदी मत प्राप्त किए थे। उनके बाद इस मत प्रतिशत को प्राप्त करने में कोई भी पार्टी प्रत्याशी सफल नहीं हो पाया। बीकानेर लोकसभा

क्षेत्र से लगातार पांच बार सांसद रहने का रिकॉर्ड करणी सिंह के नाम है। अब लोकसभा चुनाव का उत्सव देश देख रहा है। सारा देश जानता है कि अब चुनाव लड़ना कितना खर्चीला हो गया है। कैंपेन इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी इंसान आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से पहले कई बार जरूर सोचता होगा। इसके बावजूद तमाम जनता के बीच में काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावी रणभूमि में कूदने से पीछे नहीं रहते। उम्मीद करनी चाहिए कि देश आगामी लोकसभा में पहले से अधिक आजाद उम्मीदवारों को देखेगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आवश्यक कार्रवाई

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने एप और वेबसाइट से 'स्वास्थ्य पेय' (हेल्थ ड्रिंक्स) श्रेणी से सभी पेय उत्पादों को हटाने को कहा है. उल्लेखनीय है कि इसी महीने के शुरू में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे खाद्य उत्पादों का समुचित श्रेणीकरण सुनिश्चित करें. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपनी जांच में पाया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में 'स्वास्थ्य पेय' (हेल्थ ड्रिंक्स) जैसी किसी श्रेणी को परिभाषित नहीं किया गया है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार, 'एनर्जी ड्रिंक्स' बस ऐसे पेय पदार्थ भर हैं, जिनमें कुछ अतिरिक्त सुगंध और स्वाद मिला दिया जाता है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस जांच को अपने निदेश में उल्लिखित किया है. कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने अपने एक पोस्ट में बताया था कि एक उत्पाद विशेष में चीनी की मात्रा इतनी है कि उसे स्वास्थ्य पेय नहीं माना जा सकता. उस उत्पाद को बनाने वाली कंपनी ने उक्त इंफ्लुएंसर को कानूनी नोटिस भेजकर वीडियो हटाने का दबाव बनाया, लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जांच के बाद मांग की सभी भ्रामक विज्ञापनों को हटाया जाना चाहिए. यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि कथित स्वास्थ्य पेय की श्रेणी निर्धारित नहीं होने के बावजूद कंपनियां अपने उत्पादों को इस आधार पर लंबे समय से बेच रही हैं. यह केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि छलावा देकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का अपराध भी है. हाल के समय में ऐसे भी कुछ मसले आये हैं कि नुकसानदेह मैदा, चीनी और रिफाइंड तेल में बने बिस्किट उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक कह कर बेचा जा रहा है. हमारे देश में हालिया दशकों में बच्चों में मोटापा की समस्या तेजी से बढ़ी है. साल 2003 से 2023 की अवधि के तथ्यों एवं आंकड़ों के आधार पर हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि बच्चों में मोटापा 8.4 प्रतिशत है, जबकि अधिक वजन का आंकड़ा 12.4 प्रतिशत है. विभिन्न आकलनों में कहा गया है कि अगर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगामी वर्षों एवं दशकों में इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जायेगी. भारत एक साथ कम पोषण और अत्यधिक पोषण की समस्या का सामना कर रहा है. इसकी सबसे वजह यह है कि लोगों में पोषण को लेकर समुचित जानकारी का अभाव है. ऊपर से अगर बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के नाम पर गलत उत्पाद बेचे जायेंगे, तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है.

कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने या खाने से पहले उसमें इस्तेमाल चीजों, कैलोरी आदि के बारे में पड़ताल करनी चाहिए.

भयावह खतरा है लू की तीव्रता

ज्ञानेंद्र रावत
पर्यावरणविद
rawat.gyanendra@rediffmail.com

बीते सालों की प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने में वैश्विक समुदाय उतना सजग नहीं दिखता. मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच की अवधि में वैश्विक तापमान ने 1.5 डिग्री की सीमा को लांघ दिया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि आज धरती एक बडे.संकट के मुहाने पर खड़ी है.

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम में आ रहे बदलाव से आगामी महीनों में तापमान में बढ़ोतरी, हीटवेव और उससे उपजे खतरों से निपटने से संबंधित समीक्षा बैठक को संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया. उन्होंने तैयारियों की जानकारी ली और सतर्कता, सजगता एवं आपसी तालमेल से उपाय करने का निर्देश दिया. यह कवायद देश में लू की तीव्रता और घातकता बढ़ने से जुड़ी है, जिसकी जद में देश की 80 फीसदी आबादी और 90 फीसदी क्षेत्रफल के आने की आशंका है. यदि हीटवेव से निपटने की दिशा में त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो भारत को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने में मुश्किल हो सकती है. भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है. हीटवेव अत्याधिक गर्म मौसम की स्थिति है, जिसमें किसी क्षेत्र का तापमान ऐतिहासिक औसत से अधिक हो जाता है. मैदानी, तटीय तथा पर्वतीय इलाकों में अधिकतम तापमान क्रमशः 30, 37 और 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर हीटवेव की स्थिति पैदा होती है. ये तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री अधिक होते हैं और जब ये पांच से छह डिग्री अधिक होते हैं, तब उसे हीटवेव कहते हैं. अगर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वह स्थिति बेहद खतरनाक मानी जाती है.

हीटवेव से डीहाईड्रेशन, हीटस्ट्रोक और मौत भी हो सकती है. इसकी चपेट में बच्चे, ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, महिलाएं, फेफड़ों की पुरानी बीमारी वाले, निर्माण और श्रम से जुडे. लोग ज्यादा आते हैं. बीते बरसों में हर महाद्वीप को हीटवेव ने प्रभावित किया है. इससे जंगलों में आग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है. आने वाले 26 सालों में 60 करोड़ लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे. इससे घर के बाहर लोगों की कार्यक्षमता में 15 फीसदी की गिरावट होगी और 31 से 48 करोड़ लोगों के जीवन की गुणवत्ता घटेगी. बीते सालों की प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए यह कम आश्चर्यजनक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने में वैश्विक समुदाय उतना सजग नहीं दिखता. मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच की अवधि में वैश्विक तापमान ने 1.5 डिग्री की सीमा को लांघ दिया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि आज धरती एक बडे.संकट के मुहाने पर खड़ी है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट की मानें, तो न केवल बीता वर्ष बल्कि पूरा बीता दशक धरती पर अभी तक का सबसे गर्म दशक रहा है. यह वर्ष भी गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ देगा. चिंता की बात यह है कि यदि तापमान वृद्धि पर अंकुश नहीं लगा, तो सदी के अंत तक गर्मी से 1.5 करोड़ लोग मौत के मुहाने तक पहुंच जायेंगे. अमेरिका की पर्यावरण संस्था ग्लोबल विटनेस और कोलंबिया यूनीवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उत्सर्जन स्तर यदि 2050 तक यही रहा, तो 2100 तक गर्मी अपने घातक स्तर तक पहुंच जायेगी. यह भी कि प्रत्येक मिलियन टन कार्बन में बढ़ोतरी से दुनियाभर में 226 अतिरिक्त हीटवेव की घटनाएं होंगी.

क्लाइमेट चेंज जर्नल के एक अध्ययन की मानें, तो यदि तापमान में तीन डिग्री की वृद्धि होती है, तो हिमालय में सूखा पड़ने की प्रबल संभावना है. इससे सबसे ज्यादा नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पडेग़ा. इससे भारत और ब्राजील का 50 फीसदी से अधिक कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा. इन देशों में एक से तीस वर्ष तक सूखे का खतरा बना रह सकता है. अत्याधिक तापमान से समय पूर्व जन्म दर में बढ़ोतरी का खतरा 60 फीसदी तक बढ़ जायेगा. यह खतरा कई हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा. गर्मी के बढ़ते प्रभाव से खाद्यान्न आपूर्ति पर संकट बढ़ जायेगा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की मानें, तो बढ़ते तापमान से अमेरिका से चीन तक खेत तबाह हो रहे हैं. इससे फसलों की कटाई, फलों का उत्पादन और डेयरी उत्पादन सभी दबाव में हैं. बाढ़, सूखा और तूफान की बढ़ती आवृत्ति ने इसमें और इजाफा किया है. वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के खाद्य विशेषज्ञ कैटलिन वैल्श कहते हैं कि इन मौसमी घटनाओं की वजह से खाद्य सुरक्षा और कीमतों के बारे में चिंता लगातार बढ़ रही है. इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बडे.हिस्से के किसान मुश्किल में हैं. दक्षिणी यूरोप में गर्मी के कारण गायें दूध कम दे रही हैं. समुद्र का बढ़ता तापमान मछलियों को अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर कर रहा है. इससे बहुत सी प्रजातियों के खत्म होने का अंदेशा बढ़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति के अनुसार यदि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है, तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 43 फीसदी तक घटाना होगा. आज धरती 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुकी है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानक तापमान के अनुमान से आधा डिग्री अधिक है.

वैश्विक तापमान वृद्धि ने समूची दुनिया को अपनी जद में ले लिया है. इसके चलते पेरिस में दुनिया के तमाम देशों ने वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया था. यहां यह विचार करना बेहद जरूरी है कि क्या हम ईमानदारी से उस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. मौजूदा हालात तो इसकी गवाही कतई नहीं देते क्योंकि धरती के गर्म होने की गति तेजी से बढ़ ही रही है और हम तापमान बढ़ोतरी के मामले में पेरिस सम्मेलन में लिये गये निर्णय के बावजूद 3-4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. यदि हमने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया, तो सदी के आखिर तक धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जायेगा. क्या उस दशा में धरती रहने के लायक बची रह पायेगी? संयुक्त राष्ट्र जलवायु एजेंसी के प्रमुख साइमन स्टील ने चेतावनी दी है कि धरती को बचाने के लिए अब केवल दो साल का समय ही बचा है. कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और इसके लिए बनायी जाने वाली योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए भी समय कम बचा है. जरूरी है कि गैस उत्सर्जन में गिरावट लाने के लिए ग्रीनहाउस बनाये जायें और सशक्त अर्थव्यवस्था हेतु जी-20 द्वारा अधिक धन प्रदान किया जाये क्योंकि तापमान बढ़ाने वाले उत्सर्जन में इन देशों का 80 फीसदी योगदान है. धरती पर यदि कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन इसी तरह बढ़ता रहा, तो हालात और भयावह होंगे. उस दशा में करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

जैव विविधता का संरक्षण भी है मधुमक्खी पालन

पद्मश्री अशोक भगत
सचिव, विकास भारती बिशुनपुर
vikasbharti1983@gmail.com

मधुमक्खी पालन ग्रामीण गरीब, भूमिहीन मजदूर एवं ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय का प्रमुख साधन बन सकता है. सरल होने के कारण अशिक्षित व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सकता है. इस व्यवसाय को 5-10 बक्सों से कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है.

भारत जैव विविधता वाला देश है. दक्षिण से लेकर उत्तर तक यहां की जलवायु कई भागों में विभाजित दिखती है. पश्चिमी भारत में यदि भीषण गर्मी और शुष्कता है, तो पूर्वी भारत दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्र में शुमार है. वैसे तो वर्तमान विश्व जैव विविधता के संरक्षण को लेकर कोई खास संवेदनशील नहीं दिख रहा है, लेकिन हाल में ब्राजील में संपन्न आम चुनाव में जैव विविधता महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल था. वहां उसी पार्टी की जीत हुई, जिसने जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करने की बात कही. जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रकृति संरक्षण के साथ ही साथ जैव विविधता के संरक्षण को लेकर लोगों में जागृति देखने को मिल रही है. भारत में भी इसकी सुगबुगाहट है. ऐसे में जैव विविधता के संरक्षण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत है. हमें अपने कृषि विकास नीति में भी इसे जोड़ना होगा. यदि उस दिशा में प्रयास करना है, तो प्रथम कदम के तौर पर किसानों को खेती के साथ मधुमक्खी पालन के आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण जरूरी हो जाता है. यह हमारे लिए मात्र रोजगार का साधन भर नहीं होगा, अपितु इसके माध्यम से हम अपनी जैव विविधता का संरक्षण भी कर सकते हैं. झारखंड जैसे राज्य के लिए तो यह बेहतर वैकल्पिक रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकता है. झारखंड में विभिन्न प्रकार के पौधों के अतिरिक्त औषधीय पौधे भी बहुतायत में पाये जाते हैं, जिसके फूलों के माध्यम से आसानी से मधुमक्खी पालन हो सकता है. इससे अतिरिक्त आमदनी तो होगी ही, जैव संरक्षण को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा.

मधुमक्खियों द्वारा जहां शहद एकत्र किया जाता है, वहीं विभिन्न पौधों में परागण के आदान–प्रदान से बीजों की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के पौधे जंगलों में अपनी संख्या बनाये रखने में सक्षम होते हैं. विशेषज्ञों की मानें, तो यदि मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो जीवन की संभावना की कल्पना नहीं की जा सकती. मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है क्योंकि इसके परिवार में रानी, श्रमिक एवं नर मधुमक्खी पाये जाते हैं. मधुमक्खी से शहद निकालने एवं पालन करने की प्रथा काफी पुरानी है क्योंकि मधुमक्खियों का वर्णन सभी धार्मिक ग्रंथों, जैसे वेदों, महाभारत, बाइबल एवं कुरान, में मिलता है. शहद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मीठा पदार्थ है, जो निर्दोष एवं हानिरहित है. इसलिए इसे हम पृथ्वी का अमृत भी कह सकते हैं. प्राचीन काल से इसका उपयोग खाने, धार्मिक कार्यक्रमों एवं औषधीय कार्यों में किया जाता रहा है. इसका महत्व बढ़ने के कारण इसे पालने के लिए सर्वप्रथम 1789 में स्विट्जरलैंड के निवासी फ्रांसिस ह्यूबर ने बॉक्स बनाकर मधुमक्खी पालन की शुरुआत की. धीरे-धीरे इसमें कई परिवर्तन हुए, जो आज कृषि आधारित कुटीर उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया है.

भारत की बड़ी ग्रामीण आबादी में छोटे एवं मझोले किसानों की संख्या ज्यादा है. मधुमक्खी पालन ग्रामीण गरीब, भूमिहीन मजदूर एवं ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं अतिरिक्त आय का प्रमुख साधन बन सकता है. सरल होने के कारण अशिक्षित व्यक्ति भी इसे आसानी से कर सकता है. इस व्यवसाय को 5-10 बक्सों से कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है. यह व्यवसाय इतना प्रभावशाली है कि तीन से पांच वर्षों में कोई भी व्यक्ति 100 से 150 बक्सों का मालिक बन सकता है तथा प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आमदनी कर सकता है. इस व्यवसाय में बिजली, इमारत या जमीन की आवश्यकता न के बराबर पड़ती है. इसके लिए कच्चे माल की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है. इस व्यवसाय के खड़े होने से गांव के कुछ लोग मधुमक्खी पालन में काम आने वाले औजार, बक्सा, मधु निष्कासन यंत्र इत्यादि बनाकर कुटीर उद्योग खड़ा कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में नये प्रकार की रोजगार क्रांति आ सकती है. मधुमक्खी अपना भोजन, जिसमें मधु एवं पराग प्रमुख हैं, तीन किलोमीटर क्षेत्र से एकत्र करती हैं. इसका लाभ परोक्ष तौर पर फसलों को होता है.

विश्व भर में लगभग पांच करोड़ मधुमक्खी कॉलोनियां हैं. ऐसा अनुमान है कि विश्व में लगभग 14 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है. कुल 15 देश इस वैश्विक उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत का योगदान करते हैं. चीन शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत शहद होता है. अमेरिका, अर्जेंटीना, यूक्रेन आदि भी शहद उत्पादन में योगदान देते हैं. भारत में मुख्यतः चार प्रकार की मधुमक्खियां पायी जाती हैं. यहां लगभग 20 लाख कॉलोनियां हैं तथा वन्य मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद को शामिल करते हुए अनुमानतः प्रति वर्ष लगभग 80,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है. भारत में लगभग 13,809 मधुमक्खी पालक एवं 1,84,769 कालोनियां पंजीकृत हैं. भारत के पास चीन से बड़ी जैव संपदा है. यहां शहद उत्पादन की अपार संभावना है. यदि उन संपूर्ण संभावनाओं का दोहन किया जाए, तो हमारी बड़ी आबादी को अतिरिक्त आमदनी का साधन भी उपलब्ध हो जायेगा और हम बिना किसी बड़े प्रयास के अपने जैव विविधता का संरक्षण करने में भी सफल हो पायेंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

मध्य-पूर्व संघर्ष की आंच पड़ोस तक पहुंचने की संभावना

एक अप्रैल को ईरानी दूतावास पर इस्राइली हमले के बाद ईरान द्वारा प्रतिशोध लेने का खतरा बढ़ रहा है, इस कारण मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण हो गयी है. इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता अब खतरे में है. यह सच है कि युद्ध के समय किसी भी देश के अधिकारियों और राजनयिकों को आम तौर पर निशाना नहीं बनाया जाता है, पर इस्राइल ने इस मूलभूत अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का उल्लंघन किया है. ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर हमला करने के लिए इस्राइल को दंडित किया जाना चाहिए. हालांकि अधिक संभावना इस बात की है कि ईरान सीधे इजरायली क्षेत्र पर हमला न करके, अपने संबद्ध नेटवर्क के माध्यम से यह काम करेगा. अब यक्ष प्रश्न यह है कि इस तनाव का क्षेत्रीय और पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. पाकिस्तान और ईरान पहले से ही विवादों में हैं, दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध छद्म युद्ध का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान, जो पहले से ही एक अस्थिर देश है, सुरक्षा चुनौतियों और आतंकवाद से जूझ रहा है. इतिहास में झांकने से पता चलता है कि ईरानियों ने विपरीत परिस्थिति में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है. यह स्पष्ट है कि किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में निसंदेह दुनिया को नुकसान होगा, परंतु इस क्षेत्र को उसके परिणामों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में ईरान की ओर से बड़ी जवाबी कार्रवाई की आशंका बनी हुई है. यदि ईरान-इस्राइल के बीच सीधा संघर्ष छिड़ गया, तो युद्ध की लपटें मध्य एशियाई मोर्चों से दक्षिण एशियाई मोर्चों, जैसे पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, तक फैल जायेंगी. पाकिस्तान-ईरान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है. चूंकि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, सो स्थिति के और भी खराब होने की संभावना है, विशेष रूप से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर.

-मुहम्मद शरीफ

बोधि वृक्ष

दूसरों को समझें

संबंधों में आपसी समझ की कमी के कारण आज परिवार बिखर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा रहे हैं. ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या किसी को समझना इतना कठिन है? बरसों से चली आ रही हमारी संयुक्त परिवार की परंपरा आपसी समझ के ऊपर ही तो टिकी रही हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतनी मजबूत नींव कमजोर पड़ गयी. यदि सोचने बैठें, तो कारण हजार निकल आयेंगे, परंतु सौ बात की एक बात यह है कि दूसरों को समझने का कौशल बहुत कम लोगों के पास है. समझना दोतरफा प्रक्रिया है, किंतु दुर्भाग्यवश हम सभी केवल एकतरफा प्रक्रिया के आदी हैं. इसका अर्थ है कि हममें से अधिकांश लोग वही बात समझते हैं जिसे सुनना वे पसंद करते हैं. हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए की संबंधों में आपसी समझ की कमी का मूल कारण यदि कुछ है, तो वह हमारा पूर्वाग्रही एवं पक्षपाती स्वभाव और हमारी सोच की शैली, जो हमें दूसरों के दृष्टिकोण को यथार्थ रीति से समझने से रोकती है और हमारे संबंधों में टकराव पैदा करती है. समझ और गलतफहमी के बीच बहुत महीन रेखा होती है, जिसे मापने के लिए तेज बुद्धि की जरूरत होती है. जिस व्यक्ति के पास समझ नहीं होती, वह नासमझी और जिसके पास विपरीत समझ होती है, वह गलतफहमी का शिकार हो जाता है.

अतः हमें सदैव याद रखना है कि नासमझी से अधिक गलतफहमी हानिकारक होती है. विद्वानों का मानना है कि यदि किसी के जीवन में स्वास्थ्य नहीं है, वह मन से प्रसन्न नहीं है, तो उसका मूल कारण गलतफहमी है, न कि नासमझी. गलतफहमी का कोई उपचार नहीं है. जिस व्यक्ति के अंदर इसका विकास होता जाता है, वह समाज में अलग-थलग पड़ जाता है. एक छोटी सी गलतफहमी बरसों के बने हुए संबंध को एक झटके में तबाह कर देती है. इस प्रकार, गलतफहमी हमारे जीवन में आने वाली अनगिनत समस्याओं की श्रृंखला का एक संकेत है जिसे समय पर समझना अति आवश्यक है. बेहतर जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम बेहतर समझ धारण करें.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

कुछ अलग

नमक का दारोगा-पार्ट टू

आलोक पुराणिक
व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

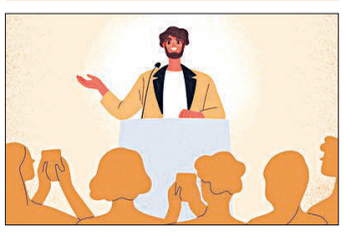

प्रेमचंद की एक क्लासिक कहानी है- नमक का दारोगा. इसमें एक ईमानदार दारोगा वंशीधर की कहानी है, जो ईमानदारी से नौकरी करते हुए नौकरी से हाथ धो बैठता है. फिर उसे उस कारोबारी अलोपीदीन से नौकरी का ऑफर मिलता है, जिसके खिलाफ वह कड़े कदम उठा रहा था. कहानी का अंत इसी बिंदु पर होता है कि ईमानदार दारोगा को उस भ्रष्ट कारोबारी के यहां नौकरी मिल जाती है, जिसके खिलाफ कदम उठाने के लिए उसकी नौकरी गयी थी. आगे की कहानी अब के टाइम के हिसाब से कुछ यूं हो सकती है.

वंशीधर की आत्मा एक दिन जागकर उनसे बोली- रे वंशीधर, तू इसी करप्ट कारोबारी के खिलाफ एक्शन लेने के चक्कर में, ईमानदारी दिखाने के चक्कर में नौकरी से गया. अब उसी की नौकरी कर रहा है तू! वंशीधर की आत्मा जग गयी. आत्मा बहुत डेंजरस होती है, एक बार जग जाये, तो भौत परेशान करती है. वंशीधर एक सभा में बैठे हुए थे कि एक कंपनी के एक अफसर ने उनसे संपर्क किया और पूछा कि आप वही वंशीधर हैं, जिनकी ईमानदारी की चर्चा एक वक्त बहुत हुआ करती थी. वंशीधर ने कहा- हां, पर अब उसी भ्रष्ट कारोबारी का नौकर का हूं, जिसके खिलाफ एक्शन लिया था. अफसर बोला- आप एक एनजीओ खोल लें- ईमान की दुकान- यानी यह एनजीओ ईमान का प्रचार-प्रसार करेगा. हम आपको अच्छी खासी रकम देंगे. वंशीधर ने नौकरी के साथ ईमान की दुकान शुरू कर दी. लेक्चर का काम मिलता, तो लेक्चर का काम देनेवाला कहता है कि हमारा पच्चीस परसेंट कमीशन आप दे दीजिये, पहले. वंशीधर ने कहा कि यह क्या बात है, ईमान के काम में पहले ही बेईमानी हो रही है. उन्होंने आगे जांच की, तो पता चला कि किसी कंपनी की रुचि ईमान को चलाने में नहीं है. वो तो सरकार का रुल है कि हर कंपनी को अपने मुनाफे का एक हिस्सा कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी वाले कामों में खर्च करने होंगे. एक दिन एक वरिष्ठ ईमानदार टकराया, तो वंशीधर ने पूछा- हम इतने लेक्चर दे रहे हैं ईमानदारी के. एक पैसे का ईमान भी किसी में ना आ रहा है. देखो, उस नेता ने मुझसे लेक्चर करवाया था, और आज वह उस रैली में झूठ पर झूठ बोले जा रहा था.

वरिष्ठ ईमानदार ने बताया- बेट्टे, हमारा काम सिर्फ लेक्चर देना है, ईमान वगैरह सच में आ गया, तो हमारी दुकान बंद हो लेगी. वैसे तुम्हारे ईमान ने तुम्हें दिया क्या, एक भ्रष्ट कारोबारी के यहां नौकरी. इससे तो बेहतर यही है कि तुम यहां प्रवचन खेंच कर कमा लो. वंशीधर को बात समझ में आ गयी, ईमान सत्य सिर्फ प्रवचन में सही लगते हैं. सच में इनकी कोई डिमांड ना है.

आपके पत्र

वायु प्रदूषण से बीमार हो रहे लोग

दिन पर दिन हवा जहरीली होती जा रही है, जिससे लोग गंभीर बीमारी के शिकार हो रहे हैं. विकास के नाम पर हर दिन जंगल व पेड़ की कटाई होने से स्थिति खराब हो गयी है. प्रदूषण के कारण लोगों को सांस से संबंधित बीमारी हो रही है. वाहनों की बढ़ती संख्या, सड़क जाम, औद्योगिक इकाइयों से निकलनेवाले धुएं से हवा दूषित हो रही है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देना होगा. प्रदूषण की विभीषिका से बचने के लिए सरकार और जनता को मिल कर प्रयास करना होगा.

संजीत कुमार, बांका

सार्वजनिक जगहों पर हो स्तनपान कक्ष

सार्वजनिक जगहों पर माताओं को आज भी संघर्ष करना पड़ता है. बच्चों को दूध पिलाना जितना प्राकृतिक है, सार्वजनिक जगहों पर इस काम को उतना ही शर्मनाक हो जाता है. इसमें परेशानी और तब बढ़ जाती है जब वह यात्रा कर रही होती है. इस दौरान शर्म की वजह से बच्चे को स्तनपान नहीं कराती हैं, जिससे बच्चा भूखा रह जाता है. यह अमानवीय है. इसलिए सार्वजनिक जगहों पर स्तनपान कक्ष का निर्माण कराया जाना चाहिए, जहां मां अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सके.

संदीप कुमार, इमेल से

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | मुंबई | सोमवार, 15 अप्रैल 2024

युद्ध फैलने का खतरा

ईरान की ओर से शनिवार देर रात इस्राइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने छह महीने से गाजा में जारी इस्राइल-हमास युद्ध के और फैलने का गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। पहले ही दो युद्धों के प्रभावों से बेहाल दुनिया के लिए अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस्राइल इस हमले के जवाब में क्या और कैसा कदम उठाता है।

ईरान का बदला | हालांकि ईरान ने अपने कदम को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यह दमिश्क में उसके दूतावास पर हुए हमले का जवाब है। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि इस कार्रवाई के बाद उसकी तरफ से मामले को खत्म माना जा सकता है, पर इस्राइल ने फिर कोई गलती की तो नतीजे इससे भी गंभीर होंगे।

ईरानी कार्रवाई से तनाव

इस्राइली रुख | हमले से ठीक पहले इस्राइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपना यह सिद्धांत घोषित किया था कि 'जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे।' वैसे भी ईरान की प्रतिक्रिया को अपेक्षा से ज्यादा सख्त माना जा रहा है। ऐसे में इस्राइल अपनी जमीन पर सीधे हमले की ईरानी कार्रवाई को चुपचाप स्वीकार कर लेगा, इसके आसार नहीं दिखते।

अमेरिका की प्रतिक्रिया | लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए जरा सी असावधानी दुनिया को बड़े संकट में धकेल सकती है। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस्राइल की आत्मरक्षा के सवाल पर हर तरह के सहयोग का वादा करते हुए भी यह साफ कर दिया है कि उसकी ओर से की जाने वाली किसी आक्रामक कार्रवाई में वह साथ नहीं देंगे।

भारत की दुविधा | भारत के लिए यह स्थिति खास तौर पर असमंजस पैदा करने वाली है। इस्राइल और ईरान दोनों से ही उसके बहुत अच्छे और करीबी रिश्ते रहे हैं। मिसाइल हमले से एक दिन पहले ईरान ने होरमुज जलडमरूमध्य में इस्राइल से जुड़े जिस कार्गो शिप पर कब्जा किया, उसमें 17 भारतीय नागरिक भी हैं। इसलिए, भारत की पहली चुनौती इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें छुड़ाने की बन गई है।

साइड इफेक्ट | मगर जिस तरह के तनावपूर्ण हालात इस्राइल और ईरान के बीच बन गए हैं, उसके साइड इफेक्ट भी कम गंभीर नहीं होने वाले। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले ही 90 डॉलर पार कर चुकी है। यह 100 डॉलर से ऊपर पहुंच सकती है। इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर दिखेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन भी इससे प्रभावित होगी। लाल सागर रूट पहले ही हूती विद्रोहियों की कार्रवाई के चलते बाधित है। अब होरमुज जलडमरूमध्य में भी हालात प्रतिकूल हो रहे हैं। यही नहीं यूरोप आने जाने का हवाई किराया भी बढ़ने के आसार हैं क्योंकि फ्लाइट आवर्स बढ़ जाएंगे। साफ है कि हालात समेत तमाम देशों के हक में जरूरी है कि हालात को बेकाबू न होने दिया जाए।

चक्र-व्यू

माया मिसकॉल की

राहुल पाण्डेय

डेली का डेढ़ GB डेटा फ्री है। कॉल पर बात भी अब अनलिमिटेड होती है। मगर मैं अपने गांव वालों का क्या करूं कि मिसकॉल न तो उनके मोबाइल से निकल पा रही है, ना लाइफ से। क्या मजाल कि कभी सीधे फोन कर लें। मारेंगे तो मिसकॉल ही मारेंगे। सुबह सोकर उठा तो देखा कि अनजान नंबर से पंद्रह मिसकॉल थी। इतना तो समझ में आ गया कि गांव से ही कोई था। लगता है कि गांववालों ने ऐसी टेलीपैथी साध रखी है कि उन्हें परली ओर वाले का भी हाल दिखाई देता है। उन्हें दिख जाता है कि परली ओर वाला बस फोन उठाने ही वाला है। फिर वे तुरंत फोन काट देते हैं। परली ओर मौजूद मैं या मेरे जैसा कोई शख्स इतनी ही देर में जाने क्या-क्या सोच डालता है! गांव से मिसकॉल! सब सही तो है? या फिर अब किसकी गैया पगहा तुड़ा ली? किसका खेत चर लिया गया? किसका मेड़ टूट गई? मुकदमा क्या है आखिर? या कोई और बड़ी अनहोनी तो नहीं हो गई।

मुसीबत महज मिसकॉल की ही नहीं है। नए सिम के साथ नई-नई स्कीमें भी मिलती हैं। हमारे बड़े भाई साहब पिंटू ने तो महीनों फोन रीचार्ज ही नहीं कराया। एक पर डेटा और कॉलिंग पैक खत्म हो तो सीधे दूसरा सिम खरीद लें। हर बार नए-नए नंबर से मिसकॉल आए। एक बार मैंने पूछा कि इतने ढेर सारे नंबर क्यों? बताने लगे, दो सौ का रीचार्ज या नब्बे का सिम। बताओ सस्ता क्या? सिम और रीचार्ज में आए इस फर्क का असर यह पड़ा कि अब हर बार नए-नए नंबर से मिसकॉल आती है। कोई सोचे तो सोचता ही रहे कि आखिर ये नंबर किसका है? पलटकर फोन करें या ना करें? जाने कौन हो? वो तो भला हो स्पैम कॉलिंग वालों का कि बेचारे मिसकॉल नहीं मारते, बल्कि तब तक घंटी बजाते रहते हैं, जब तक कि हम फोन ना उठा लें या काट ना दें। अगर वे भी मिसकॉल मारना शुरू कर देते तो न जाने क्या हाल होता।

डेढ़ GB डेटा फ्री होने के बाद मिसकॉल तो नहीं बदली, अलबत्ता कॉलिंग की विधि जरूर बदल गई। अब मिसकॉल सिर्फ फोन पर ही नहीं आती। अब वह विडियो कॉल की भी आती है और वट्सऐप जैसे कॉलिंग ऐप्स पर वॉइस कॉल की भी आती है। कल सुबह जब अनजान नंबर से सोलहवीं मिसकॉल आई, मैं समझ गया कि यह जरूर हमारे परम पूज्य रामस्वरूप काका होंगे। काका जी को तो जैसे मिसकॉल से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भी फोन करते हैं, एक रिंग पूरी होने से पहले ही काट देते हैं। मैंने वापस फोन मिलाया। अंदाजा सही था। परली ओर से काका कह रहे थे, कुछ पता चला तुमको? मैंने कहा, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कहने लगे, फर्जी पत्रकार हो तुम! तुमको पता ही नहीं चला कि लालमुनि की पतोहू भाग गई? मुझे याद आया कि लालमुनि का फोन तो परसों ही आया था। बड़ी देर तक बचपन की बातें हुई थीं। अब समझ में आया कि उन्होंने सीधे फोन क्यों किया था और आदत के मुताबिक मिसकॉल क्यों नहीं दी।

एकदा

लाइब्रेरियन की उदारता

डॉ. भीमराव आंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश स्थित उनके गांव महु के विद्यालय में हुई थी। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन की। हायर एजुकेशन के लिए वह इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उतने पैसे ही नहीं थे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। लगने लगा कि आगे की पढ़ाई की इच्छा अब अधूरी रह जाएगी। लेकिन इसी बीच वह बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के संपर्क में आए। उन्होंने आंबेडकर को इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए मदद देनी मंजूर कर ली, और यूनिवर्सिटी ऑफ

Shital Verma

लंदन में उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। भीमराव को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इस शौक के चलते उनकी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी बन गई। उसमें 50 हजार से अधिक पुस्तकें थीं। लंदन में भी वह रोज अपना अधिक से अधिक वक्त लाइब्रेरी में बिताते थे। एक बार वह लंच टाइम में लाइब्रेरी में अकेले बैठे पढ़ते हुए कुछ चबा रहे थे। लाइब्रेरियन ने इस पर आपत्ति की, 'लाइब्रेरी में खाना-पीना मना है। फिर भी आप छिप कर खा रहे हैं।' वह उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने पर आमादा था। भीमराव ने विनम्रता से माफी मांगी और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि कैफेटेरिया जाकर लंच करना उनके लिए संभव नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते। लाइब्रेरियन ने और भी सवाल किए, उनकी पूरी स्थिति समझी। वह उनसे बातचीत कर इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, 'आज से तुम लंच के समय मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा।' लाइब्रेरियन की यह उदारता आंबेडकर को चकित कर गई। उन्हें महसूस हुआ कि किसी व्यक्ति को जन्म के बजाय सोच और गुण के आधार पर आंकना कितनी बड़ी बात होती है। इसके बाद देश के अंदर जातिगत भेदभावों के खिलाफ संघर्ष का उनका संकल्प और मजबूत हो गया।

संकलन : दीपक कुमार

ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP की इकाइयां मोदी की तीसरी पारी के लिए कमर कस चुकी हैं

BJP की कैसे मदद करते हैं NRI समर्थक

अलका धुपकर

जहां BJP ने आगामी चुनावों में सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें पार करने का बड़ा लक्ष्य तय किया है, वहीं 25 देशों में फैली पार्टी की अंतरराष्ट्रीय इकाइयां भी इसमें मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (OFBJP) कहलाने वाली ये इकाइयां न केवल अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी सक्रिय मौजूदगी भी बनाए हुए हैं। इन इकाइयों ने प्रचार अभियान की रणनीति के तहत भारत के अपने मित्रों-परिजनों से संपर्क बनाए रखने के लिए वट्सऐप ग्रुप भी बनाए हैं।

इंडियन डायसपोरा | फिलहाल 3.21 करोड़ भारतीय विदेश में बसे हुए हैं। इनमें से 1.34 करोड़ NRI हैं और 1.86 करोड़ PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। NRI को भारत में मतदान का अधिकार है। NRI की संख्या सबसे ज्यादा (34 लाख) संयुक्त अरब अमीरात में है। उसके बाद है सऊदी अरब (26 लाख) में और फिर अमेरिका (12.8 लाख) का नंबर आता है।

भारत की छवि | पिछले 10 वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। 15 फरवरी को, पीएम ने अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित किया। 2023 CSDS-लोकनीति सर्वेक्षण से पता चला कि 49.1% लोगों को लगता है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुनिया में भारत की छवि को सुधारने का काम किया है। इससे अंदाजा मिलता है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के बीच BJP का ऐसा व्यापक समर्थन क्यों है।

स्वयंसेवकों की बढ़ती संख्या | OFBJP का गठन 1991 में हुआ था। शुरू में इसके चैप्टर मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में उभरे, लेकिन अब संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में भी इसकी प्रभावशाली मौजूदगी है। 2004 में अमेरिका से भारतीय मूल के 20 लोग BJP के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रचार करने भारत आए थे। हालांकि, BJP के नेतृत्व वाला NDA चुनाव हार गया और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UPA सत्ता में आया।

बना रहता है तालमेल
- माहौल बनाने को चलाते हैं अभियान
- विदेश से फंड जुटाने में भूमिका
- पार्टी के नियमित संपर्क में होते है

NRI से मदद | इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों के भारत आने की संभावना बताई जा रही है। 31.8 लाख के साथ अमेरिका PIO की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद मलेशिया और म्यांमार है, जहां क्रमशः 27.6 लाख और 20 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं।

मंदिर में हवन | OFFBJP के योगदान को सही ढंग से समझना है तो याद करना बेहतर होगा कि 2014 से पहले मोदी को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित आरोपों के कारण अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद BJP के विदेश में रहने

वाले समर्थकों ने उनकी वैश्विक छवि बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। हाल में 'ग्लोबल भारत' ब्रैंड एंबेसडर और OFBJP के पूर्व संयोजक विजय जॉली ने दक्षिण अमेरिकी देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न वैश्विक नेताओं को राम मंदिर की प्रतिकृतियां भेंट कीं और भारतीय प्रवासियों से जुड़े। इसी 18 मार्च को, सिलिकॉन वैली में भारतीय-अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों ने पीएम मोदी की जीत के लिए एक मंदिर में हवन का आयोजन किया। जो लोग भारत नहीं जा सकते वे वहीं से अपने परिजनों और दोस्तों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट BJP को ही दें।

जागरूकता अभियान | अन्य देशों में भी इसी तरह के अभियान चल रहे हैं। 16 मार्च को, ब्रिटेन के नॉर्थोल्ट में कच्छ लेवा पाटीदार समाज परिसर से पीएम मोदी के प्रति एकजुटता और समर्थन दिखाने के लिए एक कार रैली शुरू हुई। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच यह रैली नीसडेन के स्वामीनारायण मंदिर में समाप्त हुई। इसी तरह, OFBJP के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया चैप्टर ने 16 मार्च को स्वयंसेवकों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत के विकास के बारे में तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में शामिल स्वयंसेवकों से कहा गया कि ये तथ्य लोगों से साझा करें।

ऑस्ट्रेलिया में भी सक्रिय | उसी दिन, OFBJP ऑस्ट्रेलिया के पंजाब चैप्टर ने राज्य में मोदी सरकार की विकास पहलों पर BJP नेता सुभाष शर्मा के साथ एक वर्चुअल सेशन आयोजित किया। BJP महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर OFBJP ऑस्ट्रेलिया कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तीकरण अभियानों की जानकारी साझा की।

दुष्प्रचार की काट | BJP के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, 'OFBJP पश्चिमी दुनिया में भारत और BJP की पॉजिटिव और सही छवि पेश करने और विरोधियों के दुष्प्रचार से उपजे भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहा है। OFBJP दुनिया भर में भारत और NRI के हितों को बढ़ावा देने का काम करता है।' पार्टी की वैश्विक छवि को बेहतर बनाने के लिए BJP का विदेशी नेटवर्क अपने कार्यक्रम तो चलाता ही है, अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें दूर करने की भी कोशिश करता रहता है। इस सिलसिले में संबंधित लोगों और अधिकारियों की वर्चुअल बैठकें भी समय-समय पर कराई जाती रहती हैं।

फंडिंग और अजेंडा सेटिंग | OFBJP इकाइयां जिन देशों में भी हैं, वहां के नियमों और कानूनों के दायरे में ही काम करती हैं। कुछ देशों में OFBJP के कई चैप्टर हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर देशों में ये केंद्रीकृत संगठन के रूप मे काम करते हैं। OFBJP के दिन-प्रतिदिन के कार्य करने वाले पदाधिकारी फंड जुटाने और अजेंडा तय करने के लिए भारत में पार्टी नेतृत्व से नियमित संपर्क में रहते हैं।

भाषा बदलने से दुनिया बदल जाएगी, क्यों कहते हैं ऐसा

AI Image

जीवन आनंद

लाइबेरिया में जन्में जियाद यूसुफ फजाह को इस वक्त का सबसे महान Polyglot बताया जाता है। Polyglot यानी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञानी। दावा है कि उनके नाम सबसे अधिक भाषाएं जानने का विश्व रेकॉर्ड है। हालांकि यह दावा ऐसा है, जिसकी पुष्टि करने में बड़े से बड़े एक्सपर्ट की बोलती बंद हो जाए। वजह कि किसी को किसी भाषा का जानकार कब माना जाए, इसका कोई तयशुदा मानक नहीं। क्या दूसरी भाषा को समझना भर पर्याप्त है, या थोड़ा-बहुत बोल लेना या फिर धड़ल्ले से फटाफट जवाब देना? खैर, यूसुफ को लगभग 50 भाषाएं आती हैं, कुछ पर उनका जबरदस्त होल्ड है और कुछ में वह थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। 10वीं सदी में एक मुस्लिम विद्वान हुए अल-फराबी, उन्हें 70 भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन, सर जॉन बॉरिंग के आगे शायद कोई न टिके, जिन्हें दावे के मुताबिक 100 भाषाएं बोलने में महारत थी।

पूरे जीवन में हमारा काम दो-तीन भाषाओं से चल जाता है। ज्यादातर का तो बस एक से। ऐसे में क्या चीज किसी को Polyglot बनने के लिए प्रेरित करती है? सूफी संत रूमी का कहना था कि, 'एक नई भाषा बोलें ताकि यह दुनिया एक नई दुनिया बन जाए।' संसार के भीतर एक नया संसार रचना, यह ताकत तो भाषा को ही हासिल है। केवल भाषा ऐसा कारनामा कर सकती है कि नजरों के लिए सब कुछ पुराना ही रहे, लेकिन कहने का अंदाज बदल जाए। और यह अंदाज-ए-बयां ही काफी है पुरानी चीजों में नए रंग भरने के लिए। अगर कोई बिना कुछ बदले सब बदलना चाहता है, तो उसका रास्ता है भाषा बदलना।

सीखने के लिए कुछ सीखना, हमारी इसी आदत ने आगे बढ़ाया इंसानी सभ्यता को। किसी नए हुनर को पाना, उस पर महारत हासिल करना संतुष्ट और खुशी की भावना भर देता है। इसमें भी अगर वह नया हुनर कोई नई भाषा हो, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व के साथ नया आयाम जुड़ गया।

भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं। यह बोलने और सुनने वालों को एक-दूसरे से जोड़ती है। नेल्सन मंडेला का मानना था कि अगर आप किसी से किसी भाषा में बात करते हैं, तो बात उसके दिमाग में जाती है, लेकिन अगर आप उससे उसकी अपनी भाषा में बात करें, तो बात सीधे उसके दिल में उतर जाएगी। भावनाओं को गहराइयों से छूना भाषा को ही आता है। यह झिझक तोड़ देती है, अपनापन बढ़ाती है।

ऐसी कुंजी है भाषा, जिससे दूसरी सभ्यता-संस्कृति के खजाने के ताले खोले जा सकते हैं। फिर कोई इतिहास अनजाना नहीं रहता और कोई कहानी अजनबी नहीं लगती। किसी को जानने का सबसे बेहतर तरीका है उसकी भाषा को जानना। यह विस्तार करना सिखाती है। तुर्किये में कहावत है कि केवल एक भाषा बोलने वाला एक शख्स है, लेकिन दो भाषाएं बोलने वाला दो शख्स होता है। फ्रांस के समाज में इस कहावत को कुछ इस तरह कहा जाता है कि, 'एक आदमी जो दो भाषाएं जानता है, वह दो इंसानों के बराबर है।' भाषा को सीमित करना यानी खुद को सीमित कर लेना।

हर भाषा हमारे दिमाग के एक नए हिस्से को खोलती है। बदलती है हमारे सोचने और समझने के तरीके को। एक नई भाषा के सफर पर निकलना खुद की खोज में जाने जैसा है। बेहद रोमांचकारी अनुभव होता है अपने को अलग-अलग जुबानों से अभिव्यक्त करना। ऐसा लगता है कि हर बार एक नई बात कही जा रही हो। नई भाषा सीखने का अनुभव अपनी अंतरात्मा को भी समझने का मौका देता है। भाषा जरूरी है, लेकिन जटिल भी। इसका अंदाजा होता है जब पहली बार किसी दूसरी भाषा में बात करने की कोशिश की जाए। लगता है कि दिमाग की सारी नसें बस उसी नई भाषा के शब्दों को पकड़ने में लगी हैं। लेकिन जब इतना मुश्किल काम हो जाता है, तो संतुष्टि मिलती है जीत की।

कोई भी भाषा बस शब्दों और ध्वनियों का एक बेजान समूह नहीं होती। वह तो जान डालती है अपने समाज में। उसकी ताकत को अपने भीतर समाना रोमांचकारी है और उसके साथ चलना बहुत ही आनंदभरा अनुभव। इस अनुभव को किसी एक भाषा में जाहिर नहीं किया जा सकता, तो एक बार आनंद के इस रास्ते पर निकल कर देखिए।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesgroup.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- **'जीवन आनंद'**

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

जीवन ऊर्जा का अक्षय स्रोत हैं देवी के नौ स्वरूप

स्वामी अवधेशानंद गिरि

महाशक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्र। मां अपने भक्तों के मन में लगे मैल, दुर्गुण और सारे दोषों का नाश कर देती हैं। साधक के दिल में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की संस्थापना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ स्थिरता मां की आराधना के नियम हैं। मां की कृपा से ही नवरात्र में उपासना की चरम सिद्धि यानी चेतना का विकास होता है। नवरात्र काल में खुद के शाश्वत स्वरूप का बोध अभ्यास करके चित्त की पवित्रता को महसूस किया जा सकता है। मां परांबा आध्यात्मिक प्रकाश का ज्ञान, शक्ति, शांति और समृद्धि का स्रोत हैं। ज्ञान और क्रियाशक्ति के रूप में जो परम चेतना इस जगत में व्याप्त है, ऐसी समर्थ कल्याणी जगत जननी परांबा की आराधना का पवित्र पर्व है नवरात्र।

नवरात्र प्रतीक है नारी में छिपी उस दैवीय शक्ति के सम्मान का, जिसे मां के रूप में पूजा जाता है। दो ऋतुओं के संधिकाल में नौ दिनों का दिव्य पर्व अपने-आप में बेहद विलक्षण और अद्भुत है। इसकी हरेक रात हमारी सोई हुई आंतरिक क्षमता और ऊर्जा के अलग-अलग पहलू दिखाती है। इन पहलुओं को सभी नौ शक्तियां मान्यता देती हैं। शैलपुत्री हों या ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी हों या सिद्धिदात्री, ये किसी अन्य लोक में रहने वाली देवियां नहीं हैं। यह तो हमारी अपनी ही ऊर्जा के नौ विलक्षण स्वरूप हैं।

मां शैलपुत्री के त्रिशूल की तरह हमारे त्रिलक्ष्य हैं- धर्म, अर्थ और मोक्ष। इसके साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर सक्रिय बल है। वहीं ब्रह्मचारिणी मां हमारे प्रारब्ध और नवीन कर्म के साथ कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली महाशक्ति हैं। हमारे मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र की ऊर्जा से मां चंद्रघंटा ब्रह्मांड की ध्वनियों और सुगंधों से हमारा परिचय कराती हैं। वहीं मां कूष्मांडा के हाथ के शस्त्र, कमंडल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा समस्त सिद्धियों और निधियों को समेट कर एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का संकेत देते हैं। कंठ चक्र पर क्रियाशील स्कंदमाता कमल के रूप में चेतना का विस्तार दिखाती हैं। आज्ञा चक्र ऊर्जा की स्वामिनी मां कात्यायनी हैं। वह जीवात्मा को परम चेतना सद्गुरु यानी प्रभु में समाहित होने की प्रेरणा देती हैं। इन देवियों से ही हमें वह ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने विकारों और कमजोरियों का सामना करते हैं, और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं।

अध्यात्म में नवरात्र का पर्व हमारी नौ गुनी क्षमता से हमारा परिचय कराता है। हम सब एक अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति की खोज में भटक रहे हैं, जिसे देवी कहा गया है। देवी या देवी मां इस संपूर्ण सृष्टि का गर्भ स्थान हैं। वह गतिशीलता, ओज, सुंदरता, धैर्य, शांति और पोषण का बीज हैं। वह जीवन की ऊर्जा शक्ति हैं। एक मां को अपने बच्चे के लिए पूरा प्रेम होता है। देवी मां को भी अपने बच्चों के लिए हर हाल में असीम प्रेम है, जिसमें इस जगत के सभी जीव शामिल हैं।

बाहरी स्थूल जगत से ऊर्जा के सूक्ष्म जगत की ओर की यात्रा ही नवरात्र है। जब हम बाहरी सुंदरता से भीतर की ओर जाते हैं और दिव्य गुणों में भीगते हैं, तब हमारी चेतना भी खिल जाती है। हम अपनी पूर्ण खिली हुई चेतना को मां को अर्पित कर देते हैं। एक खिली चेतना से की गई उनकी पूजा ही सर्वश्रेष्ठ चढ़ावा है।

प्रस्तुति : सुभाष चन्द्र शर्मा

लंबी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी होगी?

मृत्युंजय राय

मृत्यु तय है, यह सभी जानते हैं। फिर भी शायद ही कोई चाहता है कि उसकी मौत आए। मौत आनी ही आनी है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह देर से आए और जीवन को अधिक से अधिक लंबा किया जा सके? **'Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality'** नाम की किताब में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के बायलॉजिस्ट वेंकी रामकृष्णन ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया है।

वह लिखते हैं कि मृत्यु इंसानों को इतनी डरावनी लगती है कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर वक्त उसे नामंजूर करते हुए गुजारते हैं। शायद, इसी वजह से इंसानों ने पुनर्जन्म की कल्पना की होगी। लेकिन एक और सच भी है। सच यह कि पिछले 150 वर्षों में इंसानों की औसत उम्र दोगुनी हो गई है। इसमें दूसरी चीजों के साथ मेडिकल साइंस की बेहतरी का बड़ा योगदान रहा है। वेंकी सवाल करते हैं कि क्या साइंस निरोग जीवन का जरिया बन सकता है, ताकि इंसान आज के मुकाबले कई गुना लंबी जिंदगी जी सके? केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वेंकी इन सवालों का जवाब देने के लिए हालिया रिसर्च का जिक्र करते हैं। वह इस बात की पड़ताल करते हैं कि लंबी जिंदगी के लिए physiology में बदलाव की खातिर जो अत्याधुनिक शोध हो रहे हैं, उनसे क्या हासिल होगा। क्या मौत से कोई जरूरी जैविक मकसद पूरा होता है? वह यह भी बताते हैं कि उनकी नजर में उम्रदराजी या उम्र का बढ़ना क्या है?

वेंकी लिखते हैं, 'मैं मानता हूं कि हमारे शरीर में जो केमिकल बदलाव होते हैं, उन्हीं की वजह से इंसान की उम्र बढ़ती है।' वेंकी बताते हैं कि हमारे शरीर में कोशिकाओं के मरने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और मरी हुए कोशिकाएं बदली जाती हैं। यह बात और है कि हम इससे अनजान हैं। कोशिकाओं के मरने को हम मौत नहीं मानते, जबकि करोड़ों की संख्या में इनकी मृत्यु हो रही होती है और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती रहती हैं।

AI Image

विचार विंडो

जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमारे शरीर में ज्यादातर कोशिकाएं जीवित होती हैं। हमारे अंग जिंदा होते हैं। तभी तो अंगों का दान संभव हो पाता है। लेकिन शरीर में जब खास कोशिकाओं का समूह मर जाता है तब इंसान की मृत्यु हो जाती है। वेंकी के शब्दों में, 'उम्र का बढ़ना शरीर के अंदर छोटी गड़बड़ियों के होने से जारी रहता है और जब शरीर के अंदर कोई क्रिटिकल सिस्टम फेल हो जाता है तो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।'

वेंकी किताब में लिखते हैं कि रानी मधुमक्खी आमतौर पर एक या दो साल तक जीवित रहती है, जबकि उसी छत्ते में रहने वालीं आम मधुमक्खियां सिर्फ 6 हफ्ते जीवित रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों का जीनोम करीब-करीब समान होता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि अलग-अलग जीन सक्रिय होते हैं। इंसानी शरीर की एक और पहेली के बारे में बताते हुए वह लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति युवा होता है तो उस वक्त जो चीजें कोशिकाओं के जिंदा रहने में मदद करती हैं, वही उसकी उम्र बढ़ने पर परेशानी खड़ी करती हैं। इस संदर्भ में वह Yamanaka factors नाम के प्रोटीन्स का जिक्र करते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन्स उम्र बढ़ने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। किताब में वेंकी सवाल करते हैं कि क्या Yamanaka factors में से कैंसर का कारण बनने वाले खतरनाक प्रोटीन्स को हटाया जा सकता है? चूहों पर हुई रिसर्च का जिक्र करते हुए वेंकी लिखते हैं कि साइंस ने इस मामले में कमाल का काम किया है। हालांकि, अभी इस प्रॉसेस की सुरक्षा और दूसरे पहलुओं पर और काम करने की जरूरत है। वेंकी के पास लंबी उम्र के लिए ऐसे सुझाव भी हैं, जिन पर आप अभी से अमल कर सकते हैं और उसकी खातिर मेडिकल साइंस की शरण लेने की भी जरूरत नहीं है। यूं भी ब्लू जोन में रहने वाले लोगों के लिए 100-110 साल जीना आम बात है। इनमें ओकिनावा (Okinawa), सार्डिनिया (Sardinia) और लोमा लिंडा (Loma Linda) जैसी जगहें शामिल हैं। इस पर हुई रिसर्च से यह बात सामने आई है कि इनकी लंबी उम्र का कारण बेहतर खान-पान और अधिक चलना-फिरना है।

अपना रास्ता खुद चुनें

प्रणव प्रियदर्शी

अमेरिकी मल्टिनैशनल फाइनैंशल सर्विसेज कंपनी वेल्स फारगो में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (टेक्नॉलजी फॉर इंडिया एंड फिलिपींस) हैं हेमा शर्मा। दो दशक पहले कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान एक टेक्नॉलजी कंपनी ने उन्हें दो टूक कह दिया था कि उनके यहां इंजीनियरिंग रोल्स में लड़कियों को नहीं लिया जाता। उस कंपनी को उस वक्त शायद नहीं पता था कि जिस कैंडिडेट को लड़की होने के कारण रिजेक्ट कर रही है, वह उनमें से है जो इस रिजेक्शन के बावजूद इस फील्ड में घुसेंगी, यहां टिकेंगी और यहां का पूरा सीन बदल देंगी। पिछले दो दशक उनकी और उन जैसी दृढ़ संकल्प लड़कियों की कामयाबी के गवाह रहे हैं। लेकिन ऐसी हर यात्रा की तरह हेमा शर्मा की भी यात्रा आसान नहीं रही। यह अलग बात है कि कि मुश्किलों को उन्होंने जीवन के एक खास दौर के रूप में लिया। उस दौर को पार करने और फिर मंजिल की ओर आगे बढ़ने का संकल्प कमजोर नहीं होने दिया। वह कहती हैं कि सबके लिए सबकुछ बनने की न सोचें, बस यह देखें कि किसी खास समय पर आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। इसी फॉर्म्यूले के मुताबिक जब वह मां बनीं तो पाया कि उस वक्त उनके लिए बेटी की परवरिश और उसकी निकटता सबसे ज्यादा जरूरी थी। स्वाभाविक ही करियर प्राथमिकता में पीछे चला गया। उन्होंने फ्लेक्सिबल टाइमिंग, वर्क फ्रॉम होम आदि सारे तरीके अपनाए। फिर भी करियर की रफ्तार सुस्त पड़नी ही थी, सो पड़ी। बाद में जब वह इस फेज से निकलीं और लगा कि अब बेटी को मां की वैसी और उतनी जरूरत नहीं रही तो फिर करियर प्राथमिकता में ऊपर आ गया और सुस्त पड़ी रफ्तार तेज हो गई। उनका कहना है कि आप अपनी चॉइस का सम्मान करें, उस पर शर्मिंदा न हों। दूसरी बात यह कि करीबी लोगों से मदद मांगने, उनका सहयोग लेने में हिचक न महसूस करें। जब वह बिटिया के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रही थीं, तब पति ने फैमिली के लिए अर्निंग की पतवार थाम रखी थी और जब दोबारा करियर को आगे बढ़ाने में लगीं, तब पति बेटी के देखरेख में हाथ बंटाने लगे। मगर ऐसा कोई मंत्र देने में उनका यकीन नहीं। नई लड़कियों से वह कहती हैं कि एक फॉर्म्यूला जो मेरी जिंदगी में काम आया, जरूरी नहीं कि आपके हालात में भी काम करे। इसलिए खुद अपने रास्ते खोजें, आजमाएं और आगे बढ़ें।

हेमा शर्मा

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ धूर्तता की पराकाष्ठा
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक भी विभाग का कार्य अपने पास नहीं रखा। उन्होंने तो मूलभूत सिध्दांत बना रखा है कि किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने ही नहीं हैं, फिर भी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका के विरुध्द उन्हें मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है। उन्हें जब ऐसा लगा कि अब वह घोटाले में फंस जाएंगे, तब उन्होंने अपने दो मंत्रियों का नाम लेते हुए कह दिया कि मुल्जिम मुझे नहीं, आतिशी और भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। संभवतः उनकी इसी धूर्तता के कारण ही आप के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, आशुतोष, आशीष खेतान, कुमार विश्वास ने भी किनारा कर लिया था।

-धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी (डोंबिवली), ईमेल से

■ समाज व देश के लिए घातक
जीनत अमान ने युवाओं को शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सलाह दी है। मैडम शायद यह भूल गई कि यह देश श्री राम जैसे ऋषि मुनियों व योगियों का देश है। जीनत जी, आप एक तरफ बुर्का प्रथा को स्वीकार करती हो, तो दूसरी तरफ आप ऐसे खुले नाजायज संबंधों को कैसे बढ़ावा दे सकती हो? ये प्रथा तो समाज में भोग विलास को, उच्छृंखलता को ही बढ़ाएगी। यदि तीन-चार महीने ऐसे रिलेशन में रहकर भी दोनों के दिल, स्वभाव नहीं मिले, तो क्या वे उसे छोड़कर फिर दूसरे, तीसरे और कई संबंध बनाकर टेस्ट करते रहेंगे। क्या गारंटी है कि इसके बावजूद उनके वैवाहिक जीवन में फिर कभी कोई भी मतभेद व अन्य समस्याएं नहीं आएंगी, कभी झगड़े व तलाक की नौबत नहीं आएगी। समाज में तो लव मैरिज के बाद भी तलाक की कई खबरें सामने आ रही हैं। लिव इन रिलेशन समाज व देश के लिए घातक सिद्ध होगा।

-संदीप आर्य, ईमेल से

■ दल बदलू नेताओं पर अंकुश
चुनाव आयोग भी लगता है कि सरकार का पोपट बन गया है। चुनाव के वक्त हर वो नेता, जिसे उसकी पार्टी से टिकट नहीं मिलता, वो दल बदल लेता है। चुनाव आयोग क्यों नहीं लगाम कस पाता। काश प्रधानमंत्री तीन तलाक़ और अनुच्छेद 370 जैसे कानून की बजाय दल-बदलू नेताओं को 7 साल तक चुनाव न लड़ सकने वाला कानून बनाते, तो ज्यादा बेहतर होता। ये राम मंदिर निर्माण से भी बड़ा फैसला होता।

-शकील खिलजी, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

खबर: उद्धव ठाकरे ने कहा- अबकी बार 400 पार नहीं, तड़ीपार।
टिप्पणी: जिसने आपके हाथ से 'तीर-कमान' को छीनकर 'मशाल' थमा दी है, तो क्या उन्हें आप तड़ीपार करोगे।

-आर. डी. प्रेमी, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

हिन्दुस्तान 1936 सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

काली खांसी

काली खांसी के प्रकोप ने दुनिया के अनेक देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। चीन में हुई कई मौतों के अलावा, अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस, चेक गणराज्य और नीदरलैंड में भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। बच्चों और शिशुओं में विशेष रूप से काली खांसी का खतरा ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति चीन में है। चीन में 2024 के पहले दो महीनों में 32,380 मामलों के साथ कम से कम 13 मौतें हुई हैं। वहां एक साल पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि, चीन में काली खांसी से हालात कुछ ज्यादा खराब होने की आशंका है। यह ध्यान रखने की बात है कि चीन अपनी बीमारियों को छिपाने की कोशिश करता है, यह हम अतीत में देख चुके हैं। काली खांसी एक अत्यधिक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है, जो बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और छोटे बच्चों में ज्यादा आसानी से फैलता है। संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है।

काली खांसी में बुखार, छींक आने, आंखों और नाक से पानी निकलने व सूखी खांसी की शिकायतें होती हैं। वैसे तो काली खांसी के उपचार का एक माध्यम टीकाकरण है। तीन खुराक लेने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि जब काली खांसी की दवा मौजूद है, तब चीन में इससे लोगों की मौत क्यों हुई है? जिनकी मौत हुई है, उनके इतिहास को देखने की जरूरत है। क्या पहले से बीमार लोगों को काली खांसी की वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है? मरने वालों में क्या केवल बच्चे हैं या बड़ी उम्र के लोगों की भी जान गई है? यथोचित दवा के बावजूद अगर मौत हो रही है, तो यह बड़े पैमाने पर सोचने वाली बात है। आखिर चीन में संक्रमण वाली बीमारियां क्यों घातक रूप अख्तियार कर ले रही हैं? क्या चीन में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो गई है? क्या काली खांसी का पूरी तरह अंत किया जा सकता है? इस खांसी ने ऐसे अनेक सवाल पैदा कर दिए हैं। जब कोई खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है, तो विशेष रूप से सावधान हो जाना समय की मांग है। चिकित्सकों को इसके सभी आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिए। जिनकी मौत हुई है, क्या उनको यथोचित टीके लगे थे? चीन के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन, जैसे ज्यादा पारदर्शी देशों को इस बीमारी के प्रति ज्यादा सचेत रहना होगा।

दुनिया में बढ़ती काली खांसी के प्रति सावधानी आवश्यक है। हाथ व शरीर की स्वच्छता और यदि कोई छींक या खांस रहा है, तो मुंह ढकना जरूरी हो गया है।

इधर, भारत में गरमियों की शुरुआत हो चुकी है और साफ-सफाई रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही जगह-जगह वातानुकूलित व्यवस्था होने की वजह से भी ऐसी बीमारियों के संक्रमण को बल मिलेगा। कोरोना वायरस जब फैला था, तब भी चिकित्सक खुले में ज्यादा रहने और भीड़ भरे बंद कमरे में न रहने की सलाह देते थे। वही सावधानी अब काली खांसी में बरतने की सलाह देनी चाहिए। हाथ व शरीर की स्वच्छता और यदि बच्चा छींक या खांस रहा है, तो उसके व अपने मुंह पर मास्का लगाना चाहिए। वातानुकूलित कमरों में रहना चूंकि मजबूरी है, इसलिए हमें स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देना होगा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के पर्याप्त उपाय रखने पड़ेंगे। सांस के मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण (निमोनिया), दिल और दिमाग पर असर हो सकता है। सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को जरूरी टीकों के साथ अपने मोरचे पर पूरी तैयारी रखनी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
15 अप्रैल, 1949

काश्मीर का मोर्चा

काश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कमीशन बराबर प्रयत्न कर रहा है। मतसंग्रह व्यवस्थापक के लिए एडमिरल निमित्ज की नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है और वह भारत के लिए रवाना होने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के ही प्रधानमंत्रियों ने इस पसन्दगी का स्वागत किया है और उन्हें अपने कठिन कार्य में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। काश्मीर की समस्या के हल के लिए सबसे पहले जनमत-संग्रह का प्रस्ताव भारत की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था। भारत ने काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था और जब काश्मीर में युद्ध बन्द करने का अवसर आया, तब भी भारत ने पहल की थी, जिसके फलस्वरूप काश्मीर में इस वर्ष के प्रथम दिन युद्ध बन्द हुआ था। पाकिस्तान ने शुरू में ताकत पर भरोसा किया, किन्तु जब उसे पता चल गया कि ताकत से इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकेगा, तो उसने भी जनमत-संग्रह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। काश्मीर के मोर्चे पर शान्ति स्थापित हुई और उसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी काफी सुधार हुआ। अब काश्मीर कमीशन भारत और पाकिस्तान में अस्थायी समझौते के लिए प्रयत्न कर रहा है, जिसके अनुसार काश्मीर के मोर्चे पर दोनों ओर की सीमा-रेखाएं निर्धारित की जायेंगी। समझौते की शर्तें तय होने में आवश्यकता से अधिक समय लग गया है।

इस बीच काश्मीर के मोर्चे से अनेक चिन्ताजनक समाचार आये हैं। कहा जाता है कि युद्धबन्दी के बाद पिछले तीन महीनों में पाकिस्तानी फौजों ने मोर्चे के अनेक क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा लिया है। ऐसा उन्होंने उरी, गुरेज और तिथवाल क्षेत्र में किया बताया जाता है। सर्दी के मौसम में भारतीय सेना ने कुछ स्थानों से अपनी चौकियां हटा ली थीं। वहां पाकिस्तान की सेना ने अपनी चौकियां बना ली हैं। स्पष्टतः यह युद्धबन्दी की शर्तों का खुला भंग है। भारत ने इस बारे में काश्मीर कमीशन का ध्यान आकर्षित किया है। ईमानदारी का यह तकाजा है कि दोनों पक्ष उन शर्तों का पालन करें जो शर्तें उन्होंने स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की हैं। भारत ने कोई सीधा प्रतिकारात्मक कदम नहीं उठाया, यह उसकी शान्तिप्रियता का सूचक है। वह काश्मीर कमीशन के आमने कोई नई अड़चन नहीं खड़ी करना चाहता।

जब जंग में सीधे उतर आया ईरान

यहां स्कैन करें

अश्विनी महापात्र | प्रोफेसर, जेएनयू

वास्तव में, कोई देश नहीं चाहता कि एशिया में बड़े पैमाने पर कोई युद्ध छिड़े, क्योंकि अगर बड़ा युद्ध छिड़ता है, तो फिर दुनिया के कई देश उसमें कूदने को मजबूर हो जाएंगे।

ईरान ने आखिर इजरायल पर हमला कर ही दिया। इसकी आशंका विगत सप्ताह से जताई जा रही थी और इसके साथ ही पहले से जारी युद्धों से दुखी लोगों की दुनिया में चिंता की एक नई लहर दौड़ गई है। छह महीने से जारी हमास-इजरायल की घातक जंग में हजारों लोग मारे गए हैं और अब अगर ईरान के मोर्चे पर भी जंग छिड़ती है, तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे?

आखिर ईरान को युद्ध में सीधे कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? ईरान और इजरायल के बीच वैसे भी भौगोलिक दूरी ज्यादा है। दरअसल, दोनों देशों के बीच तनातनी को समझने के लिए 1979 में हुई ईरान की क्रांति को समझना पड़ेगा। ईरान में तब इस्लाम के नाम पर क्रांति हुई थी। ईरान की बुनियाद वैचारिक है, इस्लाम आधारित है। वह पूरी मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है, पर शिया-सुन्नी का भेद बाधा है। सुन्नी मत की प्रधानता वाले मुस्लिम देश शिया ईरान को नेतृत्व के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ईरान में इस्लाम के नाम पर हुई क्रांति के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने जब सत्ता संभाली थी, तब उन्होंने सऊदी अरब के साथ विवाद शुरू कर दिया था। मक्का-मदीना पर कब्जे का मनसूबा था, मगर कामयाब नहीं हो पाए। ईरान जब सऊदी अरब को झुका या मना नहीं सका, तब उसने अपने प्लान-बी को आजमाया। ईरान के लिए यह आसान था कि वह इजरायल का विरोध करे और फलस्तीन का समर्थन। ध्यान रहे, ईरान इस पूरे क्षेत्र में अकेला देश है, जो येरुशलम दिवस मनाता है। फलस्तीन का समर्थन करने के लिए इजरायल का विरोध करना ईरान की उस इस्लामी रणनीति का हिस्सा है, जिस पर वह विगत चार दशक से चल रहा है।

मतलब, ईरान के लिए इजरायल कोई भू-रणनीतिक आधार या नजरिया नहीं है, उसका विरोध सिर्फ संप्रदाय आधारित है। विडंबना देखिए, साल 1979 से पहले जब ईरान में शाह शासन था, तब ईरान-इजरायल की दोस्ती थी। दोनों देश अमेरिका के करीबी थे, मगर जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, तो सब कुछ बदल गया। अरब दुनिया की कूटनीति और राजनीति भी बदल गई। इजरायल का विरोध करना ईरान के लिए मानो बाध्यता हो गई है, अब वह इजरायल के विरोध में अपने लिए वैधता या मान्यता तलाशता है।

खैर, अब जब ईरान ने हमला कर दिया है, तब भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग वहां होंगे, जो नहीं चाहेंगे कि संघर्ष या युद्ध बढ़े। सच है कि इजरायल के खिलाफ लड़ने वाले आतंकी संगठनों को ईरान से मदद मिलती रही है। वह आतंकियों को हथियार भी देता रहा है और प्रशिक्षण भी। हमास और हिज्बुल्लाह को ईरान के जरिये करीब 25 साल से मदद मिलती रही है। हिंसा बढ़ते-बढ़ते, हालात बिगड़ते-बिगड़ते और खासतौर पर 7 अक्तूबर के बाद अब ऐसी नौबत आ गई है कि ईरान को सीधे हमला करना पड़ा है। जब हमास ने इजरायल पर खूंखार ढंग से हमला किया था, तभी इजरायल ने साफ कर दिया था कि आतंकी संगठनों को ईरान का संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में, इजरायल भला क्यों नहीं चाहेगा कि वह ईरान को कमजोर करे? यह भी एक कारण है कि इजरायल शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहता है। खासकर साल 2002 में जब ईरानी परमाणु कार्यक्रम सबके सामने आ गया, तब से इजरायल और अमेरिका, दोनों ईरान का विरोध करते आ रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच कोई भौगोलिक दुश्मनी नहीं है, पर एक-दूसरे का विरोध करते नौबत जंग तक पहुंच गई है।

अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? शायद ईरान भी नहीं चाहेगा कि पूरे क्षेत्र में संघर्ष फैले। अमेरिका भी यह नहीं चाहेगा, इसलिए अमेरिका ने इजरायल से कहा है कि वह उसे अपनी जवाबी रणनीति के बारे में बताए। जरूरी नहीं कि इजरायल बात मान जाए, पर अमेरिका में ऐसे लोग हैं, जो कह रहे हैं कि हम इजरायल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। फिर भी मुझे लगता है कि इजरायल आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करेगा। हो सकता है, आगे बड़ा हमला नहीं हो। वास्तव में, अभी कोई देश नहीं चाहता कि एशिया के व्यापक हिस्से में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर बड़ा युद्ध छिड़ता है, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, रूस जैसे देश भी उसमें कूद पड़ेंगे।

ज्यादा संभावना यही है कि दोनों देशों के बीच भले समझौता न हो, मगर दोनों को युद्ध विराम के लिए तैयार कर लिया जाएगा। गौर करने की बात है कि जितनी मिसाइलें ईरान के पास हैं, उनसे ज्यादा उन्नत इजरायल के पास हैं। ईरान के लिए भी युद्ध आसान नहीं है। अभी बताया जा रहा है कि ताजा हमले में उसने करीब 300 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 99 फीसदी को इजरायल ने अपनी बेहतर तकनीक से नाकाम कर दिया है। ईरान भी किसी बड़ी जंग के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि वहां जो सरकार है, उसकी लोकप्रियता काफी घट गई है। युवा पीढ़ी मुल्ला-सियासत का विरोध कर रही है।

ताजा घटनाक्रम का एक पहलू यह भी है कि ईरान ने एक ऐसे कार्गो जहाज को रोक लिया है, जिस पर भारतीयों के साथ-साथ रूसी भी सवार हैं। अगर ईरान अपने नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग पर पाबंदियां जारी रखता है, तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ओमान और फारस की खाड़ियों को जोड़ने वाले इस होर्मूज जलडमरूमध्य या समुद्री मार्ग से संसार का करीब 33 प्रतिशत तेल गुजरता है, वहीं से संसार का करीब 25 प्रतिशत प्राकृतिक गैस भी जाता है। ईरान चाहे, तो इस मार्ग को बंद रख सकता है, पर इससे उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान को यहां समझदारी का परिचय देना होगा। जरूरत से ज्यादा दुश्मनी ठीक नहीं।

ध्यान रहे, अमेरिका में यह चुनावी वर्ष है। रूस पहले ही एक युद्ध में लगा है। अरब देशों के लिए भी फैसला आसान नहीं है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी होंगे और चीन भी आर्थिक नुकसान नहीं चाहेगा, अतः किसी बड़े युद्ध की आशंका कम ही है।

जहां तक भारत का सवाल है। ईरान के साथ हमारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंध रहा है, पर इधर के दस वर्षों में इजरायल हमारा बेहतर रणनीतिक सहयोगी बनकर उभरा है। ऐसे में, युद्ध का विरोध ही भारत के हित में है। किसी भी एक पक्ष में झुकने से हमें बचना होगा। ईरान की घनिष्ठता चीन से बढ़ गई है। चीन अब ईरान का बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। ऐसे में, चीन सहित तमाम विकसित व प्रभावशाली देशों को यह कोशिश करनी चाहिए कि नया युद्ध न भड़के। ईरान और इजरायल, दोनों को ही इंसानियत और ज्यादा समझदारी का परिचय देना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेज बढ़ता भारत

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क भारत आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इंतजार है। चर्चा गरम है कि मस्क भारत में टेस्ला का कारखाना लगाने का एलान करेंगे, जिसमें दो से तीन अरब डॉलर का निवेश होगा। कारखाना लगने में तो वक्त लगेगा, लेकिन भारत में जो लोग टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तुरंत खुशखबरी आ सकती है। अभी टेस्ला के वाहन खरीदने के लिए कम से कम 70-75 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कुछ ही समय पहले मुंबई में पुरानी कारों के एक डीलर ने 1.3 करोड़ रुपये में सेकेंड हैंड टेस्ला बेची है। मतलब, दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें अभी बहुत महंगी हैं।

मगर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ई-वाहनों की नीति में जो बदलाव किया है, उसके बाद तस्वीर बदल सकती है। अभी तक विदेश से आने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यानी, कार का दाम दोगुना होना तय है। मगर अब भारत सरकार पूरी तरह विदेश में बनी कारों के आयात पर सिर्फ 15 फीसदी ड्यूटी लेने को तैयार है। शर्त है कि वह कार कंपनी भारत में कम से कम 4,150 करोड़ रुपये या लगभग 50 करोड़ डॉलर लगाकर कारखाना लगाने का काम शुरू करे। शर्त यह भी है कि तीसरे साल तक कम से कम 25 फीसदी इसके पुर्जे यहीं बनने लगें। एक शर्त यह भी है कि बाहर से बनकर आने वाली कार का दाम 35,000 डॉलर, यानी करीब 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मस्क ने ऐसे संकेत दिए भी हैं कि भारत में वह कार का दाम 20 लाख रुपये से शुरू करना चाहते हैं।

एलन मस्क भारत में टेस्ला का कारखाना लगाने का एलान कर सकते हैं। ई-वाहनों के किफायती होने की चर्चा लोगों को ललचा रही है।

पिछले साल जून में एलन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से कई विभागों को संदेश गए और अब जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, उसने काम आसान कर दिया। अब बिजली की कारों का बाजार गरम होने वाला है। कोरोना महामारी के पहले तक देश में तीन कंपनियों ने कुल चार इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में उतारी थीं। पिछले साल तक ही सात कंपनियों की 12 ऐसी गाड़ियां बाजार में आ चुकी थीं। आंकड़ों के हिसाब से अभी टाटा मोटर्स, एमजी मोटर और महिंद्रा इस बाजार में आगे चल रहे हैं।

आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहती है। भारतीय शहरों में हवा का हाल देखते हुए हमारे लिए भी यह बेहद जरूरी है। आश्चर्य नहीं, ऑटो बिक्री के आंकड़े दिखाते भी हैं कि 2023-24 में सभी तरह के ई-वाहनों की बिक्री में तेजी दिखी है। सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बिके हैं, जिनकी गिनती लगभग 9.5 लाख रही और सालाना बढ़त 30 फीसदी के ऊपर। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बिक्री में तो 56 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया और गिनती रही 6,32,636। ई-पैसेंजर व्हीकल या कारों की गिनती 91 फीसदी बढ़कर 90,996 और व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में 175.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, हालांकि, यहां गिनती 8,571 ही रही।

ध्यान रहे, केंद्र सरकार साल 2023 तक सारे तीन पहिए वाले वाहनों और 2025 तक सारे दोपहिया वाहनों को बैटरी से चलते देखना चाहती थी। अभी तक 54 प्रतिशत तिपहिए और दोपहिया वाहन ही बैटरी वाले हो पाए हैं। व्यावसायिक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों में तो यह आंकड़ा एक फीसदी पर भी नहीं पहुंच पाया है, जबकि स्कैंडेनेविया के कुछ देश तो करीब-करीब सारी गाड़ियों को बिजली से चलाने के नजदीक हैं। भारत में केंद्र व राज्य सरकारें अपनी तरफ से रियायतें दे रही हैं और बिजली की गाड़ी पर चलाने का खर्च भी लोगों को लगातार ललचा रहा है। कुछ समय पहले हुए एक अध्ययन में आया कि जहां पेट्रोल पर 50 किलोमीटर का एवरेज देने वाली बाइक पर 50 हजार किलोमीटर चलने का खर्च एक लाख रुपये आएगा, वहीं लगभग वैसी ही ई-बाइक पर सिर्फ पांच हजार रुपये खर्च होंगे।

दूसरी तरफ, जहां टेस्ला की ऊंची कीमत सुनकर ही ग्राहक सोच में पड़ जाते हैं, तो वहीं चीन से आने वाली सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने अलग तहलका मचा रखा है। शायद यही वजह है कि जितनी जरूरत भारत को टेस्ला जैसी कंपनियों की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत टेस्ला को भारत जैसे बड़े बाजार की है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आनंद उठाना भी एक कला

यह यात्रा का समय है। लोग छुट्टियों में देश-विदेश में घूमने की योजना बना रहे होंगे। यात्राएं मन के लिए रोमांचक, शिक्षाप्रद और उसे तरोताजा करने वाली होती हैं, लेकिन शरीर के लिए? शरीर थक जाता है, हालांकि उसके बारे में कोई सोचता नहीं। अमेरिकन एक्सप्रेस 'एमेक्स ट्रेंडेक्स' ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि 76 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत हैं कि जब वे यात्रा का टिकट बुक करते हैं, तब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वास्तव में यात्रा करते हैं, तब उतने अधिक खुश नहीं होते। यात्रा की कल्पना मन में उमंग भरती है, रोमांच पैदा करती है, पर जब यथार्थ का सामना होता है, तब सारी कल्पनाएं ढह जाती हैं। यात्रा में जो असुविधाएं होती हैं, जो आकस्मिक स्थितियां आ खड़ी होती हैं, उनके बारे में पहले से नहीं सोचा जा सकता। फिर जब हम वापस आते हैं और काम पर जाते हैं, तब एक तरह की उदासी हमें घेर लेती है। हमारे जाने के बाद जो काम का ढेर पड़ा रहा या इकट्ठा हुआ, उनको निपटाने में छुट्टियों की सारी खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है।

ऐसे में, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जाने से पहले और आने के बाद जो होगा, उसकी तैयारी कर ली जाए। अगर आपका सामान्य जीवन बहुत नीरस और उबाऊ है, तो यात्रा से लौटकर आप उदास हो ही जाएंगे। यात्रा की उत्तेजना और रोज की नीरसता इनके बीच तालमेल नहीं बिठा पाएंगी। जरा सोचें, आप हर पल अह्लादित क्यों नहीं रह सकते? अगर मन को खुश रहने की आदत न हो, तो वह हर कहीं दुख ढूंढ़ लेगा। इसलिए पहले से ही हरेक बात की अच्छाई देखने की कोशिश करें। सबसे पहले, यात्रा में आपके शरीर पर जो बोझ पड़ने वाला है, उसके लिए उसे तैयार करें।

शरीर की थकान आसानी से दूर की जा सकती है। जब भी आप किसी वाहन में सैर करते हैं, तो बाद में आप थकान अनुभव करते हैं, क्योंकि आप प्रतिरोध कर रहे होते हैं। वाहन बायीं ओर घूमता है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए आप दायीं ओर झुकते हैं; आप लगातार विरोध कर रहे होते हैं। इसीलिए रेलगाड़ी में बैठे-बैठे भी थक जाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर इतने क्यों थक जाते हैं? क्योंकि आप लगातार ट्रेन से लड़ रहे थे। अपने भीतर एक लय बनाएं। अपनी सामान्य गतिविधियों में भी एक लय बनाएं।

जरा सोचें, आप हर पल अह्लादित क्यों नहीं रह सकते? अगर मन को खुश रहने की आदत न हो, तो वह हर कहीं दुख ढूंढ़ लेगा। इसलिए हरेक बात में अच्छाई देखने की कोशिश करें।

कार से जा रहे हैं, तो सड़क और सरकार को मत कोसिए, उनको भूल जाएं। अपनी आंखें बंद करके लयबद्ध तरीके से वहीं बैठे-बैठे गोल-गोल झूलने लगें। शरीर हल्का बना रहेगा। आप जहां होते हैं, वहां की तुलना दूसरी जगहों से न करें, इससे आपकी ऊर्जा रिसती है। ऐसे में, आप कहीं भी आनंद नहीं ले पाएंगे। आनंद लेने के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

स्वच्छ महासागर हमारे ग्रह और इस पर बसने वाले तमाम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपनी भावी संततियों के लिए इनको स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सबको अपनी-अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

निवेशकों पर भारी पड़ रहा निगरानी का अभाव

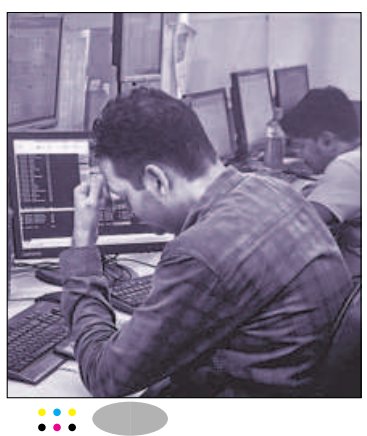

यह सच है कि विगत पांच वर्षों में सेंसेक्स दोगुना हो गया है, जिससे कई सारे लोगों ने अच्छा-खासा पैसा बनाया। इस सुखद पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर इसके पीछे छिपा एक काला सच भी है, जो प्रायः दबकर रह जाता है। दरअसल, हर वर्ष कई नए आईपीओ जारी किए जाते हैं। आईपीओ, यानी शेयर बाजार में पहली बार उतरने पर की जाने वाली आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसमें किसी कंपनी के शेयर पहली बार जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। आईपीओ शुरुआत में तो अच्छा दम भरते हैं, मगर उनमें से करीब 25-30 प्रतिशत की वैल्यू घटकर 10 फीसदी तक आ जाती है, बल्कि कुछ तो शून्य के करीब भी पहुंच जाते हैं। इससे निवेशकों, विशेष तौर पर छोटे निवेशकों का अच्छा-खासा पैसा डूब जाता है।

मैं यह किसी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर नहीं कह रहा। पिछले 10 वर्षों से मैंने खुद ऐसे कई शेयर संभालकर रखे हैं, जिनकी वैल्यू अब चार से पांच फीसदी पर आ चुकी है। ऐसे में, सवाल यह है कि इनको जारी करने वाली कंपनियों पर वित्त मंत्रालय या संबंधित नियामक एजेंसियां सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करतीं, ताकि जनता का कम से कम मूलधन तो वापस लौट सके?

एक दिक्कत यह भी है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों विशेषज्ञों की बाढ़ आ गई है। वे कई आर्थिक विश्लेषकों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके रातोंरात मालामाल होने के दावे करते हैं। ऐसे विज्ञापन नए निवेशकों को भ्रमित करते हैं। इसमें फंसने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, मानसिक कष्ट भी होता है, क्योंकि इनमें उनकी जीवन भर की जमा-पूंजी डूब जाती है। चूंकि इन सब पर सेबी या वित्त मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं दिखता, इसलिए नए निवेशक इनके चक्रव्यूह में आसानी से फंस जाते हैं और आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं।

भारत फिलहाल एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और जल्द ही यह अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर काबिज होने वाली है। मुनादी तो यह भी हो रही है कि जल्द ही हम विकसित देशों की कतार में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में, वित्त मंत्रालय या नियामक एजेंसियों को गंभीरता दिखानी चाहिए और सोशल मीडिया पर निवेशकों को ठगने वाले ऐसे गिरोहों या लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी निगरानी आवश्यक है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती घरेलू निवेशकों की सुरक्षा के बिना संभव नहीं।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
शेयर बाजार

नियामक संस्थाएं रखने लगीं पैनी निगाह

पिछली फरवरी की बात है। सेबी ने छोटे और मिड-कैप सेगमेंट में उछाल और इन योजनाओं में फंड के प्रवाह को देखते हुए सभी निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाली नीति की जरूरत पर बल दिया था। सेबी ने जिस निवेशक संरक्षण नीति का प्रस्ताव दिया था, उसके दो प्रमुख पहलू हैं- पहला, म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजरों को निवेशकों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे उचित और सक्रिय उपायों को रेखांकित करना चाहिए। इसमें इनफ्लो को नियंत्रित करना और निवेश पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करना शामिल है। दूसरा, फंड हाउस को यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्याख्या करनी चाहिए कि शेयर के जल्दी गोता लगाने से निवेशकों को नुकसान न हो। यहां कोई पूछ सकता है कि सेबी को यह सब करने की क्या जरूरत थी? दरअसल, छोटी और मिड-कैप योजनाओं में निवेशकों की भलाई को लेकर सेबी चिंतित थी, क्योंकि छोटे इलिक्विड शेयरों में फंड का प्रवाह बढ़ा है। इन शेयरों ने पिछले चंद सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सेबी की चिंता यही है कि इनका उछाल ज्यादा हो सकता है। इन सबसे समझा जा सकता है कि सरकार निवेशकों के हितों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है।

वास्तव में, निवेशकों की सुरक्षा को लेकर सरकार विभिन्न कोणों से नजर रखती है। वह इक्विटी के निवेशक, बड़े संस्थागत निवेशक, विदेशी निवेशक, डिबेंचर निवेशक, छोटे निवेशक, जमाधारक आदि सभी निवेशकों पर अलग-अलग तरीके से ध्यान देती है और उनकी सुरक्षा को लेकर कई प्रावधान बनाती है। निवेशकों को शिक्षित करने के लिए उनमें जागरूकता फैलाने को लेकर भी तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने तो कानून के जरिये जमाधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। ऐसे में, यह कहना कि सरकार निवेशकों के हितों की नहीं सोचती, उचित नहीं है। हकीकत यह है कि जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार बढ़ रहा है, निवेशकों की सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है और सरकार विभिन्न तरीकों से निवेशकों को सुरक्षा देने को तत्पर दिखती रहती है।

हां, अगर कुछ निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ा है, तो यह विदित है कि बाजार हमेशा से जोखिम के अधीन होता है। बाजार का अपना चरित्र है, जिसमें यह तय नहीं कि वह हमेशा आगे ही बढ़ेगा। कभी-कभी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसमें गिरावट भी होती है, जिसका नुकसान आखिरकार निवेशकों को ही उठाना पड़ता है, जो अस्वाभाविक नहीं।

मनोज कुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AIINewsPaperPaid

दैनिक जागरण

विनम्रता मानवीय गुणों की आधारशिला है

भाजपा का संकल्प

भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से जो घोषणा पत्र जारी किया, उस पर अन्य दलों के घोषणा पत्रों के मुकाबले अधिक ध्यान दिया जाना और चर्चा होना इसलिए स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो वह सत्ता में है और दूसरे, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त दिख रही है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से न केवल विकसित भारत का खाका पेश किया है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा भी दिलाया है। अपने इन वादों को महत्व देने के लिए उसने उन्हें मोदी की गारंटी के रूप में इसीलिए पेश किया है, क्योंकि वह इस समय सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा उनकी छवि और लोकप्रियता के सहारे ही चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इस सबके साथ यह भी एक तथ्य है कि अन्य दलों की तरह से भाजपा ने भी कुछ लोकलुभावन वादे किए हैं। वर्तमान राजनीतिक माहौल में कोई भी दल ऐसा नहीं जो खुद को लोकलुभावन वादों से अलग कर सके। वास्तव में ऐसे वादे करना राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है और इसीलिए वे अपने घोषणा पत्रों को संकल्प पत्र, न्याय पत्र, वचन पत्र, परिवर्तन पत्र आदि नाम देने लगे हैं।

भाजपा के संकल्प पत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिन पर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। एक तो इस घोषणा पत्र के जरिये यह स्पष्ट किया गया कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लाने जा रही है और दूसरे, वह एक साथ चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी। चूंकि भाजपा अपने प्रमुख मुद्दों में से दो मुद्दे अर्थात जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को पहले ही पूरा कर चुकी है इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने तीसरे प्रमुख मुद्दे यानी समान नागरिक संहिता को अपने अगले कार्यकाल में लागू करके दिखाए। जहां तक एक साथ चुनाव की बात है, भले ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विचार का विरोध किया हो, लेकिन समय की मांग है कि एक साथ चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इससे न केवल राजनीतिक दलों, बल्कि देश की जनता को भी लाभ मिलेगा और रह-रहकर होने वाले चुनावों के कारण शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो तब्दीली आती है, उससे भी बचकर विकास और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। भाजपा ने कुछ अन्य उल्लेखनीय वादे भी किए हैं, जैसे कि 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाना, मुद्रा लोन की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करना, नए सेटेलाइट टाउन बनाना, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि स्मार्ट सिटी बनाने का उसका वादा सही ढंग से पूरा नहीं हो सका। भाजपा ने कृषि और किसानों की समस्याओं को दूर करने का भी वादा किया है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिए बिना बात बनने वाली नहीं है।

अच्छी खबर

खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में पहली बार खदानों से रिकार्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह आंकड़ा 10 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है। सरकार के खजाने की सेहत के लिए यह अच्छी खबर है। महत्वपूर्ण बात यह कि जिन क्षेत्रों से राजस्व की वसूली अपेक्षाकृत अधिक हुई है, वहां ईडी लगातार कैंप करती रही है और पैसों से संबद्ध लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखती रही है। और तो और जिन जिलों से पहले नाम मात्र का राजस्व प्राप्त होता था, उन जिलों में लक्ष्य की तुलना में डेढ़ से दो गुना तक राजस्व प्राप्त हुए हैं। इससे इतर राज्य के वैसे जिले जहां खनन प्रक्रिया और खनिजों के परिवहन की निगरानी में कोताही बरती गई, वहां राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसा उन जिलों में भी हुआ है, जहां पूर्व के वर्षों में रिकार्ड राजस्व की प्राप्ति हुई है। कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अव्वल रामगढ़ इसकी बानगी है, जहां इस वर्ष राजस्व वसूली की उपलब्धि महज 68 प्रतिशत रही है। स्पष्ट है कि ईडी की पैनी नजर के बीच सरकार के राजस्व पर डाका डालने वालों की इस बार नहीं चली। सवाल यह कि इस मद में हर वर्ष अरबों रुपये के वारे-न्यारे कर सरकार की झोली में सेंधमारी करने वालों पर शासन-प्रशासन की नजर अब तक क्यों नहीं गई? आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में हाथ धोने वालों की पहचान करने की ताकि रत्नगर्भा धरती को खोखली कर राजस्व चोरी करने वाले बेनकाब हो सकें। राज्य हित में यह भी आवश्यक है कि सरकार प्राप्त राजस्व का सही ढंग से इस्तेमाल कर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर खर्च करे, ताकि खनन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके।

सवाल यह है कि सरकार की झोली में सेंधमारी करने वालों पर शासन-प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई?

मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र

राहुल वर्मा

भाजपा के संकल्प पत्र में पीएम मोदी पार्टी, सरकार या संगठन से अधिक प्रभावी पात्र के रूप में उपस्थित हैं

चुनावी घोषणा पत्र वास्तविकता के धरातल पर तो किसी बड़े परिवर्तन की वजह नहीं बनते, लेकिन हर चुनाव से पहले उनके जारी होने की उत्सुकता अवश्य बनी रहती है। असल में इन घोषणा पत्रों की भूमिका भोजन में अचार या पापड़ की तरह होती है, जो अगर थाली में न भी हों तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कुछ जायका जरूर बन जाता है। चुनावी घोषणा पत्र की इसी रस्म अदायगी को पूरा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी रविवार को संसदीय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है। चूंकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों एवं पहचान की राजनीति में काफी विश्वास रखते हैं तो संकल्प पत्र को अपेक्षित समय से कुछ दिन पहले आंबेडकर जयंती के दिन जारी कर एक अंतर्निहित राजनीतिक संदेश देने का भी काम किया गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है।

यह बहुत ही स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्र लुभावने वादों पर केंद्रित होते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल के ऐसे घोषणा पत्र में वादों के साथ अपनी उपलब्धियों का भी कुछ बखान होता है। भाजपा के संकल्प पत्र पर इसी संकल्पना की छाप दिखती है। चूंकि भाजपा पिछले दस वर्षों से केंद्र की सत्ता में है तो उसने अपनी उपलब्धियों के साथ ही उनमें निरंतरता के भाव को प्रदर्शित करने के साथ ही सुखद भविष्य की तस्वीर दिखाई है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इसे समझा जा सकता है। पहला अपनी वैचारिकी की कसौटी पर खरा उतरना। दूसरा, सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर समीकरणों को साधना। तीसरा, बेहतर भविष्य की रूपरेखा के आधार बिंदु पेश करना। चौथा, विकसित भारत की आधारभूमि तैयार करना एवं लोककल्याण के दायरे को बढ़ाते हुए उसे बेहतर करना और प्रधानमंत्री मोदी की इस पर गहरी छाप।

भाजपा की अपनी एक बहुत स्पष्ट विचारधारा रही है। अपनी स्थापना के बाद से ही वह अपनी वैचारिकी पर अडिग रही है। गठबंधन सरकारों के दौरान जरूर विचारधारा से जुड़े कुछ मुद्दों पर वैसी सक्रियता न दिखी हो, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पार्टी के तीन प्रमुख वैचारिक वादों को पूरा करने का काम किया है। सबसे पहले तो जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को समाप्त किया गया जो एक समय असंभव सा काम लगता था। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर खासे मुखर भी हैं। अदालती आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राह खुली और सरकार ने भव्य मंदिर के निर्माण की राह सुगम करते हुए हरसंभव सहयोग प्रदान किया। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भी सरकार ने अपनी विचारधारा से जुड़े एक वादे की पूर्ति की। समान नागरिक संहिता जैसे एक मूल वैचारिक मुद्दे की दिशा में भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने कदम आगे बढ़ाए हैं और इस संकल्प पत्र के माध्यम से भी भाजपा ने अखिल भारतीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन के संकेत देकर इस नीतिगत मोर्चे पर निरंतरता का वादा किया है।

अवधेश राजपूत

आर्थिक-सामाजिक मोर्चे पर भाजपा ने अपनी विशिष्ट सोशल इंजीनियरिंग को मूर्त रूप दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की आड़ में ओबीसी को लुभाने के मकसद से भाजपा को घेरने की व्यूह रचना बना रहे हैं, उसी ओबीसी से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग को भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुंचाया है। नए संस्थान-संगठन सृजित करने का संदेश भी दिया है। जैसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। इसी प्रकार पुराने संसद भवन की जगह नया बनाकर यही संदेश दिया गया कि बदलते समय के अनुसार बदलाव बहुत आवश्यक है। आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिहाज से भाजपा ने 'एक देश-एक चुनाव' की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठित भी की, जिसने बीते दिनों अपनी संस्तुतियां पेश की हैं। इसके माध्यम से भाजपा यही संदेश देना चाहती है कि बार-बार होने वाले चुनाव के चलते जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसका प्रभाव विकास गतिविधियों पर तो पड़ता ही है और यह संसाधनों के लिहाज से भी खर्चीला होता है। इसलिए समय, ऊर्जा, संसाधन व विकास के मोर्चे पर यह परिवर्तन बहुत आवश्यक है।

पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का आह्वान किया है और तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनाने की बात कही है। इस संकल्प की पूर्ति में वह चार वर्गों-युवा शक्ति, किसानों, महिलाओं और गरीबों को साधने की बात करते हैं। वह इन वर्गों को ही देश की सबसे बड़ी और प्रमुख 'जातियां' भी बताते हैं। उनके लिए कार्ययोजना से लेकर संकल्प पत्र में भाजपा के प्रयासों की छाप दिखती है। युवा शक्ति के लिए कौशल विकास और मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाने की बात है। वहीं किसानों के लिए यही बात सम्मान निधि और एमएसपी के लिए कही जा सकती है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला, ड्रोन दीदी जैसे कई बिंदु हैं। वहीं, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना के साथ ही 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए उपचार और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं हैं। यहां देश को विकसित बनाने के साथ ही जनकल्याण के दायरे को विस्तृत बनाने की मंशा है।

संकल्प पत्र पर पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी की छाप दिखती है। इसमें वह पार्टी, सरकार या संगठन से भी अधिक प्रभावी पात्र के रूप में उपस्थित हैं। उसमें जगह-जगह 'मोदी की गारंटी' का ही उल्लेख है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार का संकल्प भी दोहराया। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को इस बात की भी गारंटी देनी होगी कि भाजपा में शामिल होने वाले भ्रष्ट नेताओं पर भी कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ऐसा होने पर ही उनकी यह गारंटी प्रभावी दिखेगी। अन्यथा शायद यह जनता को उतनी आश्वस्त करने में सफल नहीं हो सकेगी। कुछ ही दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के संकल्प पत्र पर जनता क्या विकल्प अपनाती है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)

response@jagran.com

भारत के विकसित बनने की राह

रमेश कुमार दुबे

विकसित भारत का सपना हवा-हवाई नहीं है। इसके साकार रूप लेने के कुछ ठोस आधार भी हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सामान्यतः लोकसभा चुनाव से पहले सरकारें जनादेश को लेकर आशंकित रहती हैं, लेकिन मोदी सरकार इन सबसे अलग नजर आ रही है। तभी तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिन और पांच साल के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विकसित भारत-2047 के विजन दस्तावेज पर विचार-विमर्श किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं न छोटा सोचता हूं, न मामूली सपने देखता हूं और न ही मामूली संकल्प करता हूं, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 वर्ष का रोडमैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके केंद्र में है छोटे शहरों का विकास।

इसका आभास संकल्प पत्र के नाम से जारी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र से भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विकसित देश बनाने का यह संकल्प हवा-हवाई नहीं है। इसकी सफलता के ठोस जमीनी आधार हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार में चार करोड़ गरीबों को घर बनाकर दिए गए हैं। सरकार 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। नल जल योजना के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीणों तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। देश के हर घर में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो रहा है।

गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार की जनधन-आधार-मोबाइल त्रयी के जरिये विकसित हुए बिचौलिया मुक्त धन हस्तांतरण नेटवर्क की मुख्य भूमिका रही है। आज जनधन बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा सहायता जैसी अनगिनत योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के 7.16 लाख करोड़ रुपये

समग्रता में आकार लेती विकास की धारा। प्रतीकात्मक

लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए, जो 2013-14 में हस्तांतरित राशि (7,367 करोड़ रुपये) की तुलना में 100 गुना ज्यादा है जब प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू किया गया था। आज 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 320 योजनाओं के लाभ डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। इसी तरह महंगे इलाज के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों तक नहीं जा पाता था। लाखों परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता था जिससे उनकी जमीन-जायदाद तक बिक जाती थी। इस संकट को आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे मुफ्त इलाज ने खत्म कर दिया।

भारत विकसित देश बने, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति भी जरूरी है। इसी के तहत पहले चरण में देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के साथ-साथ आपूर्ति में सुधार किया गया। इसी का परिणाम है कि आज शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20.5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब सरकार देश के हर घर को सातों दिन-चौबीसों घंटे रोशन करने की कवायद में जुटी है। इसके लिए मार्च 2025 की समयसीमा तय की गई है। बिजली क्षेत्र की भांति ही सरकार रेलवे और सड़क क्षेत्र का भी कायाकल्प कर रही है, ताकि देश में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बने। विकास में बाधा बने सैकड़ों कानूनों को पहले ही निरस्त किया जा चुका है।

मोदी सरकार की योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का नतीजा गरीबी उन्मूलन के रूप में सामने आया है। वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी 29.17 प्रतिशत से घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई। इस दौरान 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। शहरों की तुलना में ग्रामीण आबादी का अधिक हिस्सा गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मुख्य राज्य रहे हैं। गरीबी घटने की इस रफ्तार को देखें तो जल्दी ही वह एक अंक में रह जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) गरीबी की एक परिभाषा का उपयोग करता है जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के 10 संकेतकों को शामिल करता है। भारत में नीति आयोग ने इसके अलावा मातृत्व स्वास्थ्य और बैंक खाते को भी शामिल कर लिया है। इस प्रकार भारत में 12 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जाता है। इसमें बहुआयामी गरीबी को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की कसौटी पर मापा जाता है। एक व्यक्ति जो इन सभी मोर्चों पर मजबूत हुआ हो उसे ही बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के तौर पर गिना गया है। अब तक देश में गरीबी आकलन के आंकड़े प्रति व्यक्ति आय तक सिमटे रहे हैं। इससे गरीबी उन्मूलन की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसका कारण है कि आय के अनुमान हासिल करना कठिन है।

कुल मिलाकर मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत दुनिया की 10वीं से पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गारंटी दे रहे हैं कि उनकी तीसरी पारी में भारत दुनिया की तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

(लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दुर्गा की महिमा

देवताओं के भी देव महादेव यानी भगवान शंकर भी जिस शक्ति से अनुप्राणित होते हैं और जिसके बिना स्पंदनहीन होते हैं, वह परम शक्ति भगवती दुर्गा हैं, जो सबसे ऊपर हैं। उनके बिना शिव भी निःशक्त हैं। 'सौंदर्य लहरी' के प्रथम श्लोक में ही आदि शंकराचार्य भी ऐसा ही कहते हैं। यही नहीं, उनके अति घोर काली रूप की उग्रता शांत करने के लिए तो भगवान शिव को उनके कदमों के नीचे आना पड़ा था। धोखे से पति पर पड़े पैर से मां काली एकदम ठिठक गईं, दांतों तले जीभ दबा लीं, उनकी उग्रता शांत हो गई और तब देवताओं और विश्व ने चैन की सांस ली, अन्यथा वह असुरों पर हुए क्रोध के कारण प्रलयंकारी रूप में आ गई थीं।

भगवान विष्णु से एक संवाद के दौरान जब देवर्षि नारद ने उन्हें त्रिलोक में सर्वोपरि बताया, तो वह बोले, 'नहीं नारद! मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। मैं तो उन आद्या शक्ति देवी के अधीन कार्य करता हूं, जो भुवनेश्वरी हैं और त्रिभुवन संचालन करती हैं। श्रीराम जब रावण से युद्ध के लिए तत्पर हुए तो नारद जी ने उन्हें नवरात्र व्रत रखने और देवी दुर्गा को पूजने की सलाह दी। श्रीराम ने वैसा ही किया।

उन मां के नाना रूप, भेद, वर्गीकरण और ध्यान मुद्राएं हैं, जिनका सम्यक वर्णन करने की क्षमता शेष और शारदा में भी नहीं है। माता के नौ रूप वाला वर्गीकरण ज्यादा लोक प्रचलित है और नवरात्र में प्रतिदिन इन्हीं में से हर एक रूप की पूजा होती है। ये श्रीविग्रह हैं-शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री। शुंभ दैत्य ने युद्धकाल में जब देवी के अनेक रूपों पर आपत्ति जताई, तब वह बोलीं, 'अरे दुष्ट! मैं सृष्टि में अकेली ही हूं, मेरे समान भला कौन है? देख! ये सब मेरी ही विभूतियां हैं और मुझमें प्रविष्ट हो रही हैं।' फिर सभी विग्रह उन अंबिका में प्रवेश कर गए। उन अनेक रूपा एक भगवती दुर्गा की महिमा अपरंपार है।

रघोत्तम शुक्ल

जंगलों में आग का बढ़ता खतरा

रंजना मिश्रा

तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी से इन दिनों जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है

पिछले दिनों तमिलनाडु के नीलगिरी में कुन्नूर वन क्षेत्र में लगी आग अब काबू में है। भारत में जंगलों में आग लगने की घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी है। यह चिंताजनक स्थिति कई कारणों से पैदा होती है। जंगलों में आग लगने का सबसे आम कारण मानवीय लापरवाही है, जिसमें जलती हुई माचिस की तीली या सिगरेट के अवशेष को फेंकना, जंगलों में खाना पकाना तथा अवैध शिकार के लिए जानवरों को भगाने के लिए आग लगाना आदि मुख्य कारण हैं। वनाग्नि के प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत बिजली गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट तथा पत्तियों एवं लकड़ी का सूख जाना आदि होते हैं।

तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी से जंगलों में आग लगने का खतरा इन दिनों बढ़ गया है। वनों की समुचित देखभाल न होने से भी यह खतरा बढ़ रहा है। फारेस्ट सर्वे आफ इंडिया बताता है कि भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में भीषण आग लगने की सबसे अधिक आशंका रहती है, जबकि सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार एवं पर्वतीय समशीतोष्ण वनों में तुलनात्मक रूप से आग का कम जोखिम रहता है।

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार देश में नवंबर 2020 से जून 2021 तक जंगलों की आग लगने की 3.45 लाख घटनाएं हुईं। देश में 71.35 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है जिसमें 25.93 करोड़ हेक्टेयर वनाग्नि के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। वहीं, 10.03 करोड़ हेक्टेयर वनाग्नि के प्रति कम संवेदनशील है। जबकि 35.39 करोड़ हेक्टेयर वनाग्नि के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील है। देश के लगभग चार प्रतिशत वन क्षेत्र में आग लगने का सर्वाधिक खतरा है। इन क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल शामिल हैं। दरअसल इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है, जिससे वनस्पतियां सूख जाती हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इन क्षेत्रों में ढलान अधिक होता है, जिससे आग तेजी से फैलती है। इन क्षेत्रों में कृषि, खनन और पर्यटन जैसी गतिविधियां होती हैं, जिनसे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। आग लगने से वन संपदा को नुकसान होता है, वन्यजीवों की जान जाती है और जलवायु परिवर्तन होता है।

स्पष्ट है कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। जंगलों की देखभाल करने वाले कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। आग लगने की घटनाओं की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना जरूरी है। सभी का दायित्व है कि वे जंगलों की रक्षा करें। हमें जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खुद को मजबूत करे कांग्रेस

'लोकतंत्र-संविधान के खात्मे का हौवा' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने कांग्रेस को यह आईना दिखाने की कोशिश की है कि उसे अपनी कमियों को दूर करने पर मंथन करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध करना चाहिए, जो उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए हैं। कांग्रेस को ईडी, सीबीआइ आदि जांच एजेंसियों के काम को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। यह माना जा सकता है कि गैर-भाजपा नेताओं और मंत्रियों की ही जांच ईडी और सीबीआइ कर रही हैं और विपक्षी दलों द्वारा इसे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि कांग्रेस जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया उसके राज में भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे काम क्यों नहीं हुए? भाजपा के नेताओं की जांच उसने ईडी या सीबीआइ से क्यों नहीं करवाई? या फिर यह समझा जाए कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था ही नहीं? अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो फिर कैसे घोटाले हुए? दूसरी बात, अगर देश में लोकतंत्र खतरे में होता तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी तथा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें न बनतीं? कांग्रेस को पहले अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, अपने नेतृत्व को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा कोई चेहरा पेश करना चाहिए, जिस पर देश भरोसा कर सके, न कि मात्र मोदी सरकार पर ही बेवजह सवाल खड़े करने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

दुर्घटनाओं पर रोक के लिए सख्ती

शनिवार के संपादकीय में दैनिक जागरण ने सटीक टिप्पणी की है कि स्कूली बस हादसे रोकने के तमाम प्रयासों को सिरे चढ़ाने के लिए निचले स्तर तक के अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। महेंद्रगढ़ (हरियाणा) के कनीना उपमंडल के अंतर्गत उन्हाणी गांव के पास स्कूल बस पलटने की घटना न केवल शिक्षा विभाग के लिए, बल्कि स्कूलों के सभी परिवहन सेवा प्रदाताओं के लिए भी आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। निजी स्कूल वैन संचालक और आटो रिक्शा चालक भी सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। स्कूल संचालक अधिक पैसा कमाने के लिए स्कूली बच्चों को वाहनों में क्षमता से अधिक बैठने की अनुमति देते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। सड़कों पर तेज गति और यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस, बस के फिटनेस प्रमाणपत्र का समयबद्ध निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार को स्कूल परिवहन सेवाओं में सुरक्षित ड्राइविंग पहलुओं और खामियों को दूर करने की रणनीति बनानी चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

सुरक्षित संविधान, सुरक्षित राष्ट्र

दैनिक जागरण के 14 अप्रैल के अंक में प्रकाशित लेख ''लोकतंत्र-संविधान के खात्मे का हौवा'' काफी सटीक है। लोकसभा चुनावों के दौर में विपक्षी दलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर संविधान को खत्म करने का डर दिखाने की राजनीति को जनमानस में कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के छह दशकों के शासन में संविधान में अनेक संशोधन हुए। सबसे खतरनाक 42वां संशोधन और 19 महीने के आपातकाल के दौरान प्रेस पर पाबंदी, विरोधी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद रखना और यातनाएं देना, वर्तमान में उनके द्वारा संविधान के खात्मे के डर को झुठलाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिछले दस वर्षों के कार्यकाल में कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ और किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य सरकार को भंग नहीं किया। किसी विधानसभा के चुनाव को संवैधानिक अवधि में चुनावों से वंचित नहीं किया, जबकि कांग्रेस की सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया। संविधान के प्रति इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इस बारे में विचार किया जाना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

विनम्रता मानवीय गुणों की आधारशिला है

भाजपा का संकल्प

भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से जो घोषणा पत्र जारी किया, उस पर अन्य दलों के घोषणा पत्रों के मुकाबले अधिक ध्यान दिया जाना और चर्चा होना इसलिए स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो वह सत्ता में है और दूसरे, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त दिख रही है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से न केवल विकसित भारत का खाका पेश किया है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा भी दिलाया है। अपने इन वादों को महत्व देने के लिए उसने उन्हें मोदी की गारंटी के रूप में इसीलिए पेश किया है, क्योंकि वह इस समय सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा उनकी छवि और लोकप्रियता के सहारे ही चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इस सबके साथ यह भी एक तथ्य है कि अन्य दलों की तरह से भाजपा ने भी कुछ लोकलुभावन वादे किए हैं। वर्तमान राजनीतिक माहौल में कोई भी दल ऐसा नहीं जो खुद को लोकलुभावन वादों से अलग कर सके। वास्तव में ऐसे वादे करना राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है और इसीलिए वे अपने घोषणा पत्रों को संकल्प पत्र, न्याय पत्र, वचन पत्र, परिवर्तन पत्र आदि नाम देने लगे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिन पर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। एक तो इस घोषणा पत्र के जरिये यह स्पष्ट किया गया कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लाने जा रही है और दूसरे, वह एक साथ चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी। चूंकि भाजपा अपने प्रमख मुद्दों में से दो मुद्दे अर्थात जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को पहले ही पूरा कर चुकी है इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने तीसरे प्रमुख मुद्दे यानी समान नागरिक संहिता को अपने अगले कार्यकाल में लागू करके दिखाए। जहां तक एक साथ चुनाव की बात है, भले ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विचार का विरोध किया हो, लेकिन समय की मांग है कि एक साथ चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इससे न केवल राजनीतिक दलों, बल्कि देश की जनता को भी लाभ मिलेगा और रह-रहकर होने वाले चुनावों के कारण शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो तब्दीली आती है, उससे भी बचकर विकास और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। भाजपा ने कुछ अन्य उल्लेखनीय वादे भी किए हैं, जैसे कि 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाना, मुद्रा लोन की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करना, नए सेटेलाइट टाउन बनाना, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि स्मार्ट सिटी बनाने का उसका वादा सही ढंग से पूरा नहीं हो सका। भाजपा ने कृषि और किसानों की समस्याओं को दूर करने का भी वादा किया है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिए बिना बात बनने वाली नहीं है।

बेटियों पर संकट

यूं तो मानव तस्करी की समस्या देशव्यापी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में यह धंधा वर्षों से बदस्तूर चल रहा है। गाहे-बगाहे कुछ तस्कर पकड़े जाते हैं और उनके चंगुल से बच्चों को मुक्त कराया जाता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों को नेस्तनाबूत करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। बिहार के साथ पड़ोसी राज्य झारखंड से भी से भी मानव तस्करी का रैकेट चलता है। इसका पर्दाफाश भी होता रहता है। पुलिस की सख्ती के बाद जिस तरह से अपराधी तकनीक और अपने तरीके बदल रहे हैं, उसी तरह मानव तस्कर अब अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब महिलाओं, विशेष रूप से कम उम्र की लड़कियों को बहला-फुसलाकर उसका सौदा करने वाले तस्कर घूम रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ताकि कोई शक नहीं करे। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां लड़कियों की खरीद-बिक्री का खेल चलता है। सासाराम में ऐसे कई मामले सामने आए थे, पर यह नेटवर्क फैलता जा रहा है। एक छात्रा को अगवा कर उसे कोलकाता में बेचने का प्रयास भी इसी की एक कड़ी है, हालांकि समय रहते आरोपित दबोच लिए गए। नाबालिगों को बहुत सुनियोजित तरीके से उठाया जाता है। तस्करों के निशाने पर गरीब और निम्न मध्यम परिवारों की लड़कियां होती हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जो आंकड़े पिछले वर्ष जारी किए थे, उसके अनुसार 5117 बच्चियां गुम हुई थीं, जिसमें 2416 को बरामद कर लिया गया था। बच्चियों की तस्करी का मामला गंभीर है। इसपर शिकंजे के लिए तंत्र को और सक्रिय होना होगा और तस्कर जो नए हथकंडे अपना रहे हैं, उनका तोड़ निकालना होगा।

बच्चियों को अगवा कर बेचने वाले तस्कर नए हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस को भी अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए?

आज का सवाल

क्या आप इजरायल पर ईरान के हमले के फलस्वरूप पश्चिम एशिया को बड़ी अशांति की ओर बढ़ते देख रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

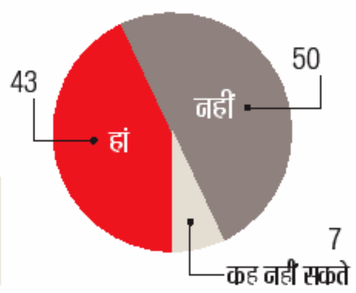

मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र

राहुल वर्मा

भाजपा के संकल्प पत्र में पीएम मोदी पार्टी, सरकार या संगठन से अधिक प्रभावी पात्र के रूप में उपस्थित हैं

चुनावी घोषणा पत्र वास्तविकता के धरातल पर तो किसी बड़े परिवर्तन की वजह नहीं बनते, लेकिन हर चुनाव से पहले उनके जारी होने की उत्सुकता अवश्य बनी रहती है। असल में इन घोषणा पत्रों की भूमिका भोजन में अचार या पापड़ की तरह होती है, जो अगर थाली में न भी हों तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कुछ जायका जरूर बन जाता है। चुनावी घोषणा पत्र की इसी रस्म अदायगी को पूरा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी रविवार को संसदीय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है। चूंकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों एवं पहचान की राजनीति में काफी विश्वास रखते हैं तो संकल्प पत्र को अपेक्षित समय से कुछ दिन पहले आंबेडकर जयंती के दिन जारी कर एक अंतर्निहित राजनीतिक संदेश देने का भी काम किया गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है।

यह बहुत ही स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्र लुभावने वादों पर केंद्रित होते हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल के ऐसे घोषणा पत्र में वादों के साथ अपनी उपलब्धियों का भी कुछ बखान होता है। भाजपा के संकल्प पत्र पर इसी संकल्पना की छाप दिखती है। चूंकि भाजपा पिछले दस वर्षों से केंद्र की सत्ता में है तो उसने अपनी उपलब्धियों के साथ ही उनमें निरंतरता के भाव को प्रदर्शित करने के साथ ही सुखद भविष्य की तस्वीर दिखाई है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इसे समझा जा सकता है। पहला अपनी वैचारिकी की कसौटी पर खरा उतरना। दूसरा, सामाजिक-आर्थिक मोर्चे पर समीकरणों को साधना। तीसरा, बेहतर भविष्य की रूपरेखा के आधार बिंदु पेश करना। चौथा, विकसित भारत की आधारभूमि तैयार करना एवं लोककल्याण के दायरे को बढ़ाते हुए उसे बेहतर करना और प्रधानमंत्री मोदी की इस पर गहरी छाप।

भाजपा की अपनी एक बहुत स्पष्ट विचारधारा रही है। अपनी स्थापना के बाद से ही वह अपनी वैचारिकी पर अडिग रही है। गठबंधन सरकारों के दौरान जरूर विचारधारा से जुड़े कुछ मुद्दों पर वैसी सक्रियता न दिखी हो, लेकिन मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पार्टी के तीन प्रमुख वैचारिक वादों को पूरा करने का काम किया है। सबसे पहले तो जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को समाप्त किया गया जो एक समय असंभव सा काम लगता था। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर खासे मुखर भी हैं। अदालती आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राह खुली और सरकार ने भव्य मंदिर के निर्माण की राह सुगम करते हुए हरसंभव सहयोग प्रदान किया। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भी सरकार ने अपनी विचारधारा से जुड़े एक वादे की पूर्ति की। समान नागरिक संहिता जैसे एक मूल वैचारिक मुद्दे की दिशा में भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने कदम आगे बढ़ाए हैं और इस संकल्प पत्र के माध्यम से भी भाजपा ने अखिल भारतीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन के संकेत देकर इस नीतिगत मोर्चे पर निरंतरता का वादा किया है।

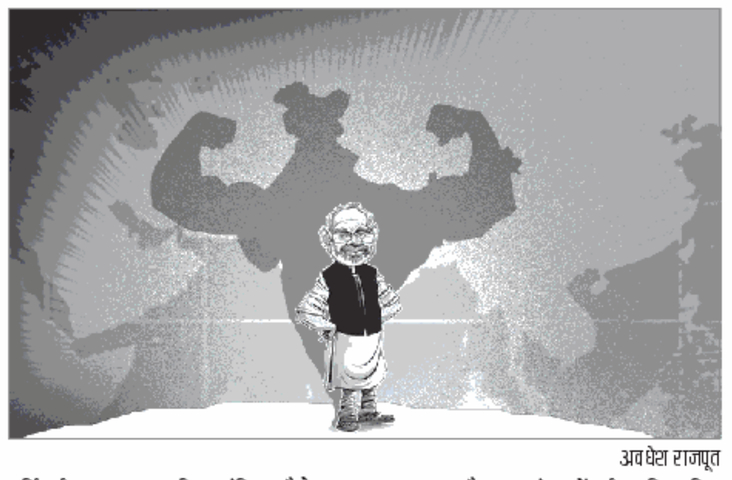

अवधेश राजपूत

आर्थिक-सामाजिक मोर्चे पर भाजपा ने अपनी विशिष्ट सोशल इंजीनियरिंग को मूर्त रूप दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की आड़ में ओबीसी को लुभाने के मकसद से भाजपा को घेरने की व्यूह रचना बना रहे हैं, उसी ओबीसी से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग को भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फाइबर पहुंचाया है। नए संस्थान-संगठन सृजित करने का संदेश भी दिया है। जैसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। इसी प्रकार पुराने संसद भवन की जगह नया बनाकर यही संदेश दिया गया कि बदलते समय के अनुसार बदलाव बहुत आवश्यक है। आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिहाज से भाजपा ने 'एक देश-एक चुनाव' की दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठित भी की, जिसने बीते दिनों अपनी संस्तुतियां पेश की हैं। इसके माध्यम से भाजपा यही संदेश देना चाहती है कि बार-बार होने वाले चुनाव के चलते जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसका प्रभाव विकास गतिविधियों पर तो पड़ता ही है और यह संसाधनों के लिहाज से भी खर्चीला होता है। इसलिए समय, ऊर्जा, संसाधन और विकास के मोर्चे पर निरंतरता के लिए यह परिवर्तन बहुत आवश्यक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का आह्वान किया है और तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनाने की बात कही है। इस संकल्प की पूर्ति में वह चार वर्गों-युवा शक्ति, किसानों, महिलाओं और गरीबों को साधने की बात करते हैं। वह इन वर्गों को ही देश की सबसे बड़ी और प्रमुख 'जातियां' भी बताते हैं। उनके लिए कार्ययोजना से लेकर संकल्प पत्र में भाजपा के प्रयासों की छाप दिखती है। युवा शक्ति के लिए कौशल विकास और मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाने की बात है। वहीं किसानों के लिए यही बात सम्मान निधि और एमएसपी के लिए कही जा सकती है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला, ड्रोन दीदी और विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे बिंदु हैं। वहीं, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना के साथ ही 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए उपचार और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं हैं। कुल मिलाकर यहां देश को विकसित बनाने के साथ ही जनकल्याण के दायरे को विस्तृत बनाने की मंशा है।

संकल्प पत्र पर पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी की छाप दिखती है। इसमें वह पार्टी, सरकार या संगठन से भी अधिक प्रभावी पात्र के रूप में उपस्थित हैं। उसमें जगह-जगह 'मोदी की गारंटी' का ही उल्लेख है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार का संकल्प भी दोहराया। निःसंदेह भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को इस बात की भी गारंटी देनी होगी कि भाजपा में शामिल होने वाले भ्रष्ट नेताओं पर भी कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ऐसा होने पर ही उनकी यह गारंटी प्रभावी दिखेगी। अन्यथा शायद यह जनता को उतनी आश्वस्त करने में सफल नहीं हो सकेगी। कुछ ही दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के संकल्प पत्र पर जनता क्या विकल्प अपनाती है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो हैं)

response@jagran.com

भारत के विकसित बनने की राह

रमेश कुमार दुबे

विकसित भारत का सपना हवा-हवाई नहीं है। इसके साकार रूप लेने के कुछ ठोस आधार भी हैं

सामान्यतः लोकसभा चुनाव से पहले सरकारें जनादेश को लेकर आशंकित रहती हैं, लेकिन मोदी सरकार इन सबसे अलग नजर आ रही है। तभी तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिन और पांच साल के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विकसित भारत-2047 के विजन दस्तावेज पर विचार-विमर्श किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं न छोटा सोचता हूं, न मामूली सपने देखता हूं और न ही मामूली संकल्प करता हूं, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 वर्ष का रोडमैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके केंद्र में है छोटे शहरों का विकास।

इसका आभास संकल्प पत्र के नाम से जारी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र से भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विकसित देश बनाने का यह संकल्प हवा-हवाई नहीं है। इसकी सफलता के ठोस जमीनी आधार हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार में चार करोड़ गरीबों को घर बनाकर दिए गए हैं। सरकार 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। नल जल योजना के तहत 75 प्रतिशत ग्रामीणों तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। देश के हर घर में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो रहा है।

गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार की जनधन-आधार-मोबाइल त्रयी के जरिये विकसित हुए बिचौलिया मुक्त धन हस्तांतरण नेटवर्क की मुख्य भूमिका रही है। आज जनधन बैंक खातों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन, आपदा सहायता जैसी अनगिनत योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने विभिन्न योजनाओं के 7.16 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए, जो 2013-14 में हस्तांतरित राशि (7,367 करोड़ रुपये) की तुलना में 100 गुना ज्यादा है जब प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू किया गया था। आज 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 320 योजनाओं के लाभ डीबीटी के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। इसी तरह महंगे इलाज के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों तक नहीं जा पाता था। लाखों परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता था जिससे उनकी जमीन-जायदाद तक बिक जाती थी। इस संकट को आयुष्मान भारत योजना के तहत मिल रहे मुफ्त इलाज ने खत्म कर दिया।

समग्रता में आकार लेती विकास की धारा • प्रतीकात्मक

भारत विकसित देश बने, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति भी जरूरी है। इसी के तहत पहले चरण में देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने के साथ-साथ आपूर्ति में सुधार किया गया। इसी का परिणाम है कि आज शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20.5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। अब सरकार देश के हर घर को सातों दिन-चौबीसों घंटे रोशन करने की कवायद में जुटी है। इसके लिए मार्च 2025 की समयसीमा तय की गई है। बिजली क्षेत्र की भांति ही सरकार रेलवे और सड़क क्षेत्र का भी कायाकल्प कर रही है, ताकि देश में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बने। विकास में बाधा बने सैकड़ों कानूनों को पहले ही निरस्त किया जा चुका है।

मोदी सरकार की योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन का नतीजा गरीबी उन्मूलन के रूप में सामने आया है। वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी 29.17 प्रतिशत से घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई। इस दौरान 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। शहरों की तुलना में ग्रामीण आबादी का अधिक हिस्सा गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मुख्य राज्य रहे हैं। गरीबी घटने की इस रफ्तार को देखें तो जल्दी ही वह एक अंक में रह जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) गरीबी की एक परिभाषा का उपयोग करता है जिसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहा जाता है। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के 10 संकेतकों को शामिल करता है। भारत में नीति आयोग ने इसके अलावा मातृत्व स्वास्थ्य और बैंक खाते को भी शामिल कर लिया है। इस प्रकार भारत में 12 संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी का आकलन किया जाता है। इसमें बहुआयामी गरीबी को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की कसौटी पर मापा जाता है। सरलता से देखें तो एक व्यक्ति जो इन सभी मोर्चों पर मजबूत हुआ हो उसे ही बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के तौर पर गिना गया है। अब तक देश में गरीबी आकलन के आंकड़े प्रति व्यक्ति आय तक सिमटे रहे हैं। इससे गरीबी उन्मूलन की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसका कारण है कि आय के अनुमान हासिल करना कठिन है।

कुल मिलाकर मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत दुनिया की 10वीं से पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गारंटी दे रहे हैं कि उनकी तीसरी पारी में भारत दुनिया की तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

(लेखक एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दुर्गा की महिमा

देवताओं के भी देव महादेव यानी भगवान शंकर भी जिस शक्ति से अनुप्राणित होते हैं और जिसके बिना स्पंदनहीन होते हैं, वह परम शक्ति भगवती दुर्गा हैं, जो सबसे ऊपर हैं। उनके बिना शिव भी निःशक्त हैं। 'सौंदर्य लहरी' के प्रथम श्लोक में ही आदि शंकराचार्य भी ऐसा ही कहते हैं। यही नहीं, उनके अति घोर काली रूप की उग्रता शांत करने के लिए तो भगवान शिव को उनके कदमों के नीचे आना पड़ा था। धोखे से पति पर पड़े पैर से मां काली एकदम ठिठक गईं, दांतों तले जीभ दबा लीं, उनकी उग्रता शांत हो गई और तब देवताओं और विश्व ने चैन की सांस ली, अन्यथा वह असुरों पर हुए क्रोध के कारण प्रलयंकारी रूप में आ गई थीं।

भगवान विष्णु से एक संवाद के दौरान जब देवर्षि नारद ने उन्हें त्रिलोक में सर्वोपरि बताया, तो वह बोले, 'नहीं नारद! मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। मैं तो उन आद्या शक्ति देवी के अधीन कार्य करता हूं, जो भुवनेश्वरी हैं और त्रिभुवन संचालन करती हैं।' श्रीराम जब रावण से युद्ध के लिए तत्पर हुए तो नारद जी ने उन्हें नवरात्र व्रत रखने और देवी दुर्गा को पूजने की सलाह दी। श्रीराम ने वैसा ही किया और अंततः उन्हें सफलता हासिल हुई।

उन मां के नाना रूप, भेद, वर्गीकरण और ध्यान मुद्राएं हैं, जिनका सम्यक वर्णन करने की क्षमता शेष और शारदा में भी नहीं है। माता के नौ रूप वाला वर्गीकरण ज्यादा लोक प्रचलित है और नवरात्र में प्रतिदिन इन्हीं में से हर एक रूप की पूजा होती है। ये श्रीविग्रह हैं-शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री। शुंभ दैत्य ने युद्धकाल में जब देवी के अनेक रूपों पर आपत्ति जताई, तब वह बोलीं, 'अरे दुष्ट! मैं सृष्टि में अकेली ही हूं, मेरे समान भला कौन है? देख! ये सब मेरी ही विभूतियां हैं और मुझमें प्रविष्ट हो रही हैं।' फिर सभी विग्रह उन अंबिका में प्रवेश कर गए। उन अनेक रूपा एक भगवती दुर्गा की महिमा अपरंपार है।

रघोत्तम शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

खुद को मजबूत करे कांग्रेस

'लोकतंत्र-संविधान के खात्मे का हौवा' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने कांग्रेस को यह आईना दिखाने की कोशिश की है कि उसे अपनी कमियों को दूर करने पर मंथन करना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के उन फैसलों का विरोध करना चाहिए, जो उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए हैं। कांग्रेस को ईडी, सीबीआइ आदि जांच एजेंसियों के काम को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। यह माना जा सकता है कि गैर-भाजपा नेताओं और मंत्रियों की ही जांच ईडी और सीबीआइ कर रही हैं और विपक्षी दलों द्वारा इसे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि कांग्रेस जिसने लंबे समय तक देश पर शासन किया उसके राज में भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे काम क्यों नहीं हुए? भाजपा के नेताओं की जांच उसने ईडी या सीबीआइ से क्यों नहीं करवाई? या फिर यह समझा जाए कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था ही नहीं? अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो फिर कैसे घोटाले हुए? दूसरी बात, अगर देश में लोकतंत्र खतरे में होता तो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी तथा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें न बनतीं? कांग्रेस को पहले अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, अपने नेतृत्व को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा कोई चेहरा पेश करना चाहिए, जिस पर देश भरोसा कर सके, न कि मात्र मोदी सरकार पर ही बेवजह सवाल खड़े करने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

असमंजस में अमेरिका

रूस-यूक्रेन युद्ध को प्रारंभ हुए गत 24 फरवरी को दो वर्ष हो गए। इजरायल हमास युद्ध को भी जारी रहते गत सात अप्रैल को छह माह हो गए। अब मध्य पूर्व में युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। ईरान ने 331 ड्रोन की सहायता से इजरायल पर बारूदी बौछार कर दी है। इससे पहले इजरायल पर आरोप लगा कि उसने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हवाई हमला किया था, जिसमें दो ईरानी कमांडर के अलावा 12 लोगों की मौत हो गई। उस हमले के लिए अमेरिका ने भी इजरायल की निंदा की थी। इसे लेकर अमेरिका असमंजस में फंस गया है। ईरान ने अपने वर्तमान हमले को उसी का प्रतिकार बताया है और यह भी कहा है कि अब वह और हमले नहीं करेगा। अमेरिका ने यद्यपि इजरायल की सहायता के लिए अपना युद्ध पोत लाल सागर में भेज दिया है, परंतु उसको आगे हमले नहीं करने की सलाह दी है। इजरायल ने ईरान की 103 मिसाइलें नष्ट करने का दावा किया है। अगर इजरायल ने बदले में ईरान पर बड़ा हमला कर दिया तो युद्ध और भड़क जाएगा। ईरान के पास एक सप्ताह में परमाणु बम बनाने की क्षमता है। वहीं रूस ईरान के साथ है। ईरान ने अपने यहां रूसी ऐब्टोराजा रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। उधर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एवं यूरोपियन देश इजरायल के पक्ष में एकजुट हैं। ईरान के निकट में 35 अमेरिकन बेस हैं। युद्ध बढ़ने पर ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व का यह युद्ध थम जाए। यह अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होगा। वैसे अभी दुनिया किसी भी एक और युद्ध को झेलने की स्थिति नहीं है। ईरान-इजरायल के बीच जल्द शांति बहाल हो।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं

संजय गुप्त द्वारा लिखित आलेख 'मोदी के मुकाबले कौन' पढ़ा। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देश को नई सरकार मिलेगी। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला दो गठबंधन के बीच है। एक गठबंधन एनडीए है, तो दूसरा गठबंधन आइएनडीआइए है। एनडीए की ओर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी हैं, लेकिन आइएनडीआइए गठबंधन की ओर से अभी तक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चयन नहीं हो सका है। अभी मोदी की लोकप्रियता चरम सीमा पर है, उनकी लोकप्रियता के आगे विपक्षी दल का कोई भी नेता नहीं टिक पाता है। एनडीए ने विकसित भारत को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है, संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन आइएनडीआइए गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका है। कांग्रेस ने अलग घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस व उनके सहयोगी दल लोकतंत्र एवं संविधान को खतरे में बता कर जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। संविधान किस तरह खतरे में हैं, इसे आम जन को बता नहीं पा रहे। देश का संविधान एवं लोकतंत्र दोनों सुरक्षित हाथों में है। आज भी देश के कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है। विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता रही है, लेकिन अदालत भी उन भ्रष्टाचारियों को कोई राहत नहीं प्रदान कर रहा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

ईरान ने आखिर क्या सोचकर इजरायल पर हमला किया? यह लड़ाई बढ़ी तो पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप का मौका मिल जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि ईरान भी इराक की तरह शिकार बन जाए। प्रमोद जोशी@pjoshi23

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस भारत की नई 'लेफ्ट पार्टी' है और भारतीय जनता पार्टी-नई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

राहुल दुबे@Therahul_dubey

इंदिरा गांधी के बाद नरेन्द्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'न्यूजवीक' के आवरण पर स्थान मिला। अंततः, मुख्यधारा के किसी पश्चिमी मीडिया संस्थान ने यह तो माना कि 'भारत और मोदी अजेय हैं, उनकी राह रोकना आसान नहीं।'

राहुल शिवशंकर@RShivshankar

कांग्रेस ने भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र को बगैर ठीक से पढ़े और समझे, वही पुराने घिसे-पिटे अंदाज में उसकी आलोचना की है। इसलिए आम जनता पर इस आलोचना का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसा लगा कि भाजपा की घोषणा से पहले ही कांग्रेस की आलोचना वाला बयान टाइप हो गया था।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

जनपथ

चर्चा में हैं आजकल राजनीति के 'नूब',
पत्थर पर बोलो कहां उगी आज तक दूब!
उगी आज तक दूब रहे कच्चे के कच्चे,
कब होंगे वे प्रौढ़ रहेंगे कब तक बच्चे?
हो जाओ परिपक्व 'नूब' का छोड़ो दर्जा,
वरना तो सब लोग रहेंगे करते चर्चा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 4

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

कोई आपको प्यार करे, तो वह ताकत देता है और जब आप किसी को प्यार करते हैं, तो उससे साहस मिलता है।
-लाओत्से

इस्राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच ईरान के प्रत्यक्ष प्रवेश से पश्चिम एशिया में गहराते तनाव में एक नया मोड़ तो आया ही है, यह स्थितियों के गंभीर होने का संकेत भी देता है।

खतरनाक संकेत

पश्चिम एशिया में गहराते तनाव के बीच ईरान द्वारा इस्राइली अरबपति के भारत की ओर बढ़ते मालवाहक जहाज पर कब्जे और फिर कुछ ही घंटों बाद इस्राइल पर किए गए ड्रोन व मिसाइल हमले से इस्राइल और हमास के बीच पहले से चले आ रहे युद्ध में नया मोड़ तो आया ही है, इससे युद्ध के एकाधिक मोर्चे खुलने की भी आशंका है। दरअसल, पहली अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के लिए तेहरान ने इस्राइल को जिम्मेवार ठहराया था, तब से ही ऐसी आशंका थी कि वह इस्राइल पर जल्द ही हमला करेगा। उल्लेखनीय है कि ईरान और इस्राइल लंबे समय से एक-दूसरे के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं, पर यह इस मायने में ऐतिहासिक है कि पहली बार दोनों देश खुलकर एक-दूसरे के सामने आए हैं। ईरान जहां हिजबुल्ला व हमास जैसे आतंकी संगठनों का उपयोग कर इस्राइली हितों पर चोट कर रहा है, वहीं, ईरान के सैन्य नेताओं व परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं इस्राइली रणनीति का प्रमुख हिस्सा रही हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं। 1948 में जब नव यहूदी राष्ट्र इस्राइल की स्थापना हुई, उस वक्त तब तुर्किये के अलावा ईरान ही दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था, जिसने इसे बतौर देश मान्यता दी। अमेरिका की शह पर जब ईरान में चुनी हुई सरकार को गिराकर शाह रजा पहलवी के नेतृत्व में कठपुतली सरकार का गठन हुआ, तब तो इस्राइल के साथ इसकी निकटता और भी बढ़ गई। इतना ही नहीं, 1980 में जब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोला, तब अमेरिकी इच्छा के खिलाफ इस्राइल ने ईरान की मदद की। दरअसल, सद्दाम के नेतृत्व में इराक परमाणु हथियार पाने की कोशिश कर रहा था, जिसे लेकर अमेरिका और इस्राइल, दोनों विरोध में थे। लेकिन जंग खत्म होने के बाद 2002 में जब यह खबर आई कि ईरान भी परमाणु हथियारों की होड़ में शामिल है, तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने की शुरुआत

हुई, जो आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि ईरान ने समुद्री लुटेरों वाले आपराधिक अंदाज में इस्राइली जहाज पर कब्जा किया है। जाहिर है, इसके संकेत ठीक नहीं हैं। चालक दल में शामिल भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए केंद्र सरकार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और उसके हालिया ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी भारतीय जल्द से जल्द सुरक्षित लौटेंगे। दूसरी ओर, दो बड़े युद्धों को झेल रही और तीसरे विश्वयुद्ध की आशंकाओं से घिरी विश्व व्यवस्था के लिए युद्ध का यह नया मोर्चा गंभीर होती स्थितियों को ही दर्शाता है।

यह तो बस शुरुआत है

पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सशस्त्र बल होने के बावजूद वायु सेना हमेशा से ही ईरान का कमजोर पक्ष रही है, जिसका प्रमाण इस्राइल पर इसके ताजा हमले में भी दिखता है। उसकी तकरीबन सभी मिसाइलों का कामयाबीपूर्वक सामना करने वाले इस्राइल ने इस पर प्रतिक्रिया को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

ईरान और इस्राइल के बीच सीधे सैन्य टकराव की शुरुआत ने ईरान के सशस्त्र बलों की तरफ एक बार फिर लोगों को ध्यान खींचा है। इस महीने की शुरुआत में, इस्राइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के राजनयिक परिसर में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें ईरान के सात वरिष्ठ कमांडरों और सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी। उसी समय ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई थी। और लगभग दो सप्ताह बाद उसने बीते शनिवार को इस्राइल पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें शामिल थीं। इन हमलों का लक्ष्य इस्राइल के भीतरी और नियंत्रण वाले क्षेत्र को निशाना बनाना था। ऐसे में ईरान की सैन्य क्षमता का विश्लेषण प्रासंगिक है।

फरनाज फासिही
द न्यूयॉर्क टाइम्स

इस्राइली अधिकारियों ने कहा है कि ईरान के किसी भी हमले का हम पलटवार करेंगे। ईरान ने जिन मिसाइलों से इस्राइल पर हमला बोला, उनको तो इस्राइल ने कामयाबीपूर्वक झेल लिया। लेकिन, इसमें संदेह नहीं कि ईरान फिर हमला कर सकता है और यह अंततः एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है। ऐसी भी आशंका है कि इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल हो जाए, हालांकि वाशिंगटन ने स्पष्ट कहा है कि उसका दमिश्क हमले से कोई लेना-देना नहीं है।

विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के विरोधी (मुख्यतः अमेरिका और इस्राइल) तेहरान के जटिल सैन्य तंत्र से उलझना नहीं चाहते हैं, इसलिए दशकों से वे ईरान पर सीधे हमला करने से बचते रहे हैं। हालांकि ईरान और इस्राइल लंबे समय से हवाई, समुद्री, जमीनी और साइबर हमलों के माध्यम से छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। इस्राइल ने ईरान के भीतर सैन्य एवं परमाणु ठिकानों को गुप्त रूप से निशाना बनाया है और कमांडरों एवं वैज्ञानिकों को मारा है। नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के एसोसिएट प्रोफेसर और ईरानी सेना के विशेषज्ञ अफशोन ओस्तोवर ने बताया कि ईरान पर हमला नहीं करने का कारण यह नहीं है कि उसके

विरोधी उससे डरते हैं, बल्कि उन्हें पता है कि ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध बेहद गंभीर होगा।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज द्वारा पिछले साल किए गए आकलन के मुताबिक, ईरानी सशस्त्र बल पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा है, जिसमें 5,80,000 सक्रिय जवान हैं और पारंपरिक एवं इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर में विभाजित करीब दो लाख प्रशिक्षित जवान सुरक्षित रखे गए हैं। सेना और गार्ड दोनों अलग हैं तथा जमीन, वायु एवं समुद्र में सक्रिय हैं। गार्ड ईरान की सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वे कुद्स बल का भी संचालन करते हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया में छद्म लड़ाकू गुटों के नेटवर्क को हथियार, प्रशिक्षण एवं समर्थन देने वाली विशिष्ट इकाई है। इन लड़ाकू गुटों में लेबनान के हिजबुल्ला, यमन का हूती, सीरिया, इराक के विद्रोही, हमास और गाजा के फलस्तीन इस्लामी जिहाद शामिल हैं। भले ही छद्म लड़ाकू गुटों को ईरान की सेना में नहीं गिना जाता, पर विश्लेषक कहते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय सहयोगी बल माना जाता है, जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, भारी हथियारों से लैस और वैचारिक रूप से ईरान के प्रति वफादार हैं, जो उसकी तरफ से लड़ने के लिए आ सकते हैं। खासकर हिजबुल्ला को ईरान की सैन्य क्षमता का हिस्सा माना जाता है, जिसका ईरान के साथ करीबी रणनीतिक रिश्ता है।

सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन एवं हवा रक्षा के विकास पर जोर देते हुए दशकों से ईरान की रणनीति अवरोध पर आधारित रही है। इसने स्पीडबोट और कुछ छोटी पनडुब्बियों का बेड़ा तैयार किया है, जो फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक पोतों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने में सक्षम है। ओस्तोवर कहते हैं कि ईरान के पास पश्चिम एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का विशाल भंडार है। इसमें 2,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही क्रूज मिसाइलें एवं एंटी-शिप मिसाइलें भी हैं। वह इस्राइल सहित पश्चिम एशिया के किसी भी देश को निशाना बना सकता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, हाल के वर्षों में तेहरान ने लगभग 1,200 से 1,550 मील की दूरी तक मार करने और रडार से बचने में सक्षम ड्रोन का बेड़ा किया तैयार है। ईरान ने अपनी मिसाइलों एवं ड्रोन को छिपाया नहीं है, बल्कि सैन्य परेडों में प्रदर्शित किया है, क्योंकि वह ड्रोन का बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में कर रहा है और सूडानी संघर्ष में भी इसे देखा गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान के हथियार ठिकाने और भंडारण सुविधाएं व्यापक रूप से फैली हुई हैं और उन्हें हवाई हमलों से नष्ट करना मुश्किल है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान टैंक और लड़ाकू जेट जैसे उच्च तकनीक वाले हथियारों और विदेशी सैन्य उपकरणों का आयात नहीं कर सकता है। 1980 के दशक में इराक के साथ आठ साल चले युद्ध के दौरान कुछ ही देशों ने ईरान को हथियार बेचने की इच्छा जताई थी। युद्ध खत्म होने के एक साल बाद 1989 में जब अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने, उन्होंने घरेलू हथियारों का उद्योग खड़ा करने के लिए काफी संसाधन खर्च किया। वह ईरान को आश्वस्त करना चाहते थे कि उसे अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज ईरान घरेलू स्तर पर बड़ी मात्रा में मिसाइलों और ड्रोनों का निर्माण करता है और उसने रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि उपकरणों, सामंजस्य, अनुभव एवं सैन्यकर्मियों की गुणवत्ता के मामले में ईरान की सेना को क्षेत्र में मजबूत माना जाता है, पर अमेरिका, इस्राइल और यूरोपीय देशों की सेना से वह काफी पीछे है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वायु सेना है। ईरान के ज्यादातर विमान पुराने हैं और उनमें से कई जरूरी कल-पुर्जों के अभाव में निष्क्रिय हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि 1990 के दशक में उसने रूस से एक छोटा बेड़ा भी खरीदा था। ईरान के टैंक और बख्तरबंद वाहन पुराने हैं, और देश में केवल कुछ बड़े नौसैनिक जहाज हैं।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की हत्याओं से ईरान के क्षेत्रीय अभियानों पर असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि उन्हें वर्षों का अनुभव था और सहयोगी लड़ाकू गुटों के प्रमुखों से उनके रिश्ते थे। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, ईरान के सशस्त्र बलों को कमांड करने की शृंखला बरकरार है।

©The New York Times 2024

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

ओशो

समस्याओं से भागने पर आप कभी किसी चीज को उसकी संपूर्णता में अनुभव नहीं कर पाते। आप कभी उससे कुछ हासिल नहीं कर पाते। बुद्धि कष्ट और स्वीकृति से आती है। इसलिए जो भी हो, सहज रहें।

दुख से भागिए मत उसे स्वीकार कीजिए

यदि आपके पास डर है, तो इसे समस्या क्यों बना रहे हैं! डर है, तो इसे स्वीकार कीजिए। इसकी चिंता मत कीजिए कि क्या हो जाएगा। स्वीकार करने पर अचानक आपको लगने लगेगा कि डर गायब हो गया है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, तो समस्या गायब हो जाती है। और यदि आप इसके साथ संघर्ष करते हैं, तो समस्या और जटिल हो जाती है। दुख और भय अचानक आ जाता है, इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। यह नहीं सोचिए कि मैं निराशावाद के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको इसे हल करने की कुंजी दे रहा हूं।

दुख तो जीवन का हिस्सा है। और ऐसा होने में कुछ भी बुरा नहीं है। दुख तभी बुरा होता है, जब वह केवल विनाशकारी होता है। कष्ट तभी बुरा होता है, जब आप इसे चुपचाप सहते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दुख के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है और तब यह दुख रचनात्मक हो जाता है। अंधेरा खूबसूरत है, अगर जल्द ही सुबह होने वाली हो। आपके साथ यही हो रहा है। एक दुख से बचने के लिए ही आप दूसरा दुख खड़ा कर लेते हैं, और फिर दूसरे दुख से बचने के लिए तीसरा, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसे में वे सभी कष्ट आपका इंतजार करते रहते हैं, जिन्हें आपने भोगा नहीं है। आप बच गए हैं, और एक दुख से दूसरे दुख की ओर भाग रहे हैं। जो मन दुख पैदा कर रहा था, वह अब और दुख पैदा करेगा। आप इस पीड़ा से उस पीड़ा तक बच तो सकते हैं, लेकिन पीड़ा रहेगी। इसलिए दुख को स्वीकार करें और उससे गुजरें, उसका सामना करें, उससे भागिए मत। कष्ट सबको होता है, डर सबको लगता है। जिन लोगों को आप बहादुर कहते हैं, निडर समझते हैं, वह केवल उनका ऊपरी मुखौटा है। भीतर से तो वे भी अन्य लोगों की तरह डरते ही हैं। बल्कि यह भी हो सकता है कि वे कहीं ज्यादा कायर, ज्यादा भयभीत हों। बस, उस कायरता को छिपाने के लिए उन्होंने अपने चारों ओर बहादुरी की भावना पैदा कर ली है। सच तो यह है कि उनकी बहादुरी सिर्फ एक दिखावा है।

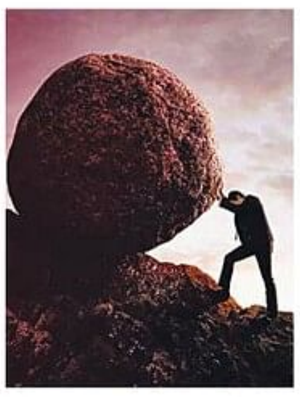

मनुष्य बहादुर कैसे हो सकता है? आखिरकार मृत्यु तो है उसके पीछे। आदमी तो बस पेड़ के एक पत्ते की तरह है, जो हवा चलते ही कांप उठता है। लेकिन आप पत्ते से कभी नहीं कहते कि तुम कायर हो। इसलिए जब आप पर भय हावी होता है, तो आप हवा में उड़ते पत्ते की तरह होते हैं। इसमें समस्या क्या और कहां है? लेकिन समाज ने हर चीज में समस्याएं पैदा कर दी हैं। समस्याओं से भागने पर आप कभी किसी चीज को उसकी संपूर्णता में अनुभव नहीं कर पाते। आप कभी उससे कुछ हासिल नहीं कर पाते। कष्ट और स्वीकृति से ही बुद्धि आती है। इसलिए जो भी हो, सहज रहें। यदि आपके पास कोई समस्या है, तो उससे दूसरी समस्या को जन्म न दें।

दुख तो जीवन का हिस्सा है...

सूत्र

जीवन में दुख और संकट आते रहते हैं। ये जीवन का ही हिस्सा हैं। इनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि सहजता के साथ ही इनका सामना करना चाहिए। जब तक आप दुख या कष्ट का सामना नहीं करेंगे, आपको जीवन की पूर्णता का अहसास नहीं होगा। ऐसे में आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।

दूसरा पहलू

आंगनबाड़ी केंद्र सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है।

ग्रामीण इलाकों के लिए सौगात हैं आंगनबाड़ी केंद्र

एक अप्रैल से राजस्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है, जिससे आंगनबाड़ी कर्मियों को काफी लाभ होगा। अक्सर इनके वेतन रुके होने की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। इस वक्त पूरे राज्य में 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनके माध्यम से लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त किया जा रहा है। कम वेतन और विषम परिस्थितियों के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों एवं महिलाओं की सेहत और मानसिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है।

बेबी कंवर

बीकानेर के कालू गांव के अधिकतर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो दैनिक मजदूरी करने शहर जाते हैं, जहां से लौटने में उन्हें देर हो जाती है। इसलिए वे अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं।

आंगनबाड़ी केंद्र सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाना है। दो अक्तूबर, 1975 को शुरू की गई इस योजना ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त बनाया है। हालांकि कई बार आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकरण से बहुत कम बच्चे आते हैं। मसलन, बीकानेर के कालू गांव में कई वर्षों से छह आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन सभी छह केंद्रों में शून्य से छह साल की उम्र के करीब 400 बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें पूरक आहार दिया जाता है। लेकिन अक्सर काफी कम बच्चे केंद्र पर आते हैं। बच्चों की कम उपस्थिति के बारे में पार्वती देवी बताती हैं कि 'दरअसल इस गांव का अधिकतर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ज्यादातर माता-पिता दैनिक मजदूरी करने शहर जाते हैं, जहां से लौटने में उन्हें देर हो जाती है। इतनी देर तक आंगनबाड़ी केंद्र खुला नहीं रह सकता, इसलिए वे अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं।' इन केंद्रों में बच्चों को पूरक पोषक आहार के अतिरिक्त किताबें और खिलौने दिए जाते हैं। महिलाओं और किशोरियों को सेनेटरी पैड, आयरन व कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। उन्हें साफ-सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है।

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण इलाके के न केवल लाखों बच्चे, बल्कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं भी कुपोषण से मुक्त हुई हैं।

हालांकि कुछ ग्रामीण इनमें उपलब्ध सुविधाओं की कमी की भी शिकायत करते हैं। लेकिन सुशीला देवी कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र किसी सौगात से कम नहीं हैं। अक्सर कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दे पाते, जिससे वे कुपोषित हो जाते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से न केवल लाखों गरीब बच्चे, बल्कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं भी कुपोषण से मुक्त हुई हैं। *(चरखा फीचर)*

आंकड़े

वैश्विक सीमेंट उत्पादन

सीमेंट आधारभूत संरचना एवं आवास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कुल वैश्विक उत्पादन का आधे से ज्यादा चीन में होता है।

चीन	51.2%
भारत	9.02%
वियतनाम	2.9%
अमेरिका	2.3%
तुर्किये	2.0%

(आंकड़े 2022 के) | स्रोत : USGS.

कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा, जो दोनों तरफ शोषण करेंगे और दूसरों का धन हड़पने में लगे रहेंगे।

कलियुग के लक्षण

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार पांडवों ने श्रीकृष्ण से पूछा कि कलियुग में मनुष्य कैसा होगा? श्रीकृष्ण ने कहा, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी दिखाई पड़े, उसके बारे में बताओ। पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर ने देखा कि हाथी की दो सूंड़ हैं। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद मंत्र लिखे हैं, पर वह मुर्दे का मांस खा रहा है! भीम ने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वह लहूलुहान हो रहा है। सहदेव ने चारों तरफ भरे हुए कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। नकुल ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से लुढ़कती हुई शिला कई वृक्षों से टकराई, पर कोई उसे रोक न सका, मगर एक छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। शाम को सबने अपने दृश्यों का वर्णन किया, तो श्रीकृष्ण ने कहा, कलियुग में ऐसे लोगों का राज होगा, जो दोनों तरफ शोषण करेंगे। विद्वान कहलाने वाले तो बहुत होंगे, पर वे दूसरों का धन हड़पने में लगे रहेंगे। आदमी अपनी संतानों को इतना लाड़ करेगा कि उनका विकास रुक जाएगा। लोग अपने छोटे-बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु भूखे-प्यासे की मदद नहीं करेंगे। पहाड़ से लुढ़कती शिला मन की उस गिरावट का संकेत है, जो भगवन्नाम जप के छोटे पौधे के स्पर्श से ही रुक सकेगा।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 1 जनवरी, 1950

नेहरू मंत्रिमंडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा

नेहरू मंत्रीमंडल में कोई परिवर्तन न होगा

26 जनवरी को नेहरू मंत्रिमंडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और डॉ राजेंद्र प्रसाद को ही देश का प्रथम अस्थायी राष्ट्रपति चुना जाएगा। वह 28 जनवरी को संसद में भाषण देंगे, जिसमें सरकारी नीति व कार्यक्रम की घोषणा होगी।

गांवों से मिल रही अर्थव्यवस्था को दिशा

एडीबी, स्काइमेट एवं रिजर्व बैंक, सभी की रिपोर्टों का सार यही है कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए जीडीपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है।

जयंतीलाल भंडारी

अर्थव्यवस्था

इन दिनों भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित हो रही विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का नया परिदृश्य उभरता दिखाई दे रहा है। 10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए जीडीपी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और प्रमुख मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि अनुकूल मानसूनी मौसम के कारण इस वर्ष 2024 में भारत में अच्छी वर्षा के संकेत दिख रहे हैं। इसी प्रकार हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि गतिविधियों में और तेजी आएगी।

गौरतलब है कि भारत के गांवों में न केवल कृषि संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, बल्कि फ्रिज, दो पहिया वाहन और टीवी की खरीदारी उच्च स्तर पर है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी

योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय, ग्रामीणों के रोजगार की मनरेगा योजना तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति और मांग में भारी इजाफा हुआ है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। विश्व में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। गेहूं तथा फलों के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर तथा सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। विश्व स्तर पर, भारत केला, आम, अमरूद, पपीता, अदरक, भिंडी, चावल, चाय, गन्ना, काजू, नारियल, इलायची और काली मिर्च आदि का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

निश्चित रूप से पिछले दस वर्षों में कृषि एवं ग्रामीण विकास का नया आधार तैयार हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 15 फीसदी है। कृषि बजट में दस वर्षों में पांच गुना वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब तीन लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित होने जैसे प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि रसायन, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण, जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं के अधिक उपयोग से किसानों को लाभ हुआ है। कृषि ऋण समितियों, किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने के लिए सरकार की क्रेडिट गारंटी और ब्याज में रियायत कृषि में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने जैसे जो रणनीतिक प्रयास किए हैं, उनसे भी काफी किसान लाभान्वित हुए हैं। देश में प्राकृतिक यानी जैविक खेती को विशेष प्राथमिकता दिए जाने से प्राकृतिक खेती ग्रामीण भारत के विकास का एक और नया माध्यम बनते हुए दिखाई दे रही है।

जहां कोविड-19 की आपदा से लेकर अब तक भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया के जरूरतमंद देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं दुनिया भर में भारत अपने कृषि उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा, विश्व बाजार में भारत के मसालों की खुशबू की धमक बहुत अधिक बढ़ी है।

इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब 50 हजार डॉलर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है। इस समय भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 लाख टन से बढ़कर दो सौ लाख टन हो गई है। पिछले नौ वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण निर्यातों में 15 गुना वृद्धि हुई है। निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13 फीसदी से बढ़कर 23 प्रतिशत हो गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी, 2024 को सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए प्रायोगिक परियोजना के तहत जिन 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को लक्षित किया गया है, उनके माध्यम से पैक्स की किसानों के हित में बहुआयामी भूमिका होगी।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी और इससे किसानों व ग्रामीण भारत के चेहरे पर मुस्कराहट बढ़ती दिखाई दे सकेगी।

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

किसी भी देश की समृद्धि उसके धन की प्रचुरता, उसके किलों की मजबूती या उसकी भव्य इमारतों पर निर्भर नहीं करती। यह तो उस देश की शिक्षा, संस्कृति, चरित्र और मानसिक खुलेपन के पैमाने पर मापी जा सकती है।

– मार्टिन लूथर किंग

महंगाई का रुख

मार्च महीने में खुदरा महंगाई का रुख कुछ नरमी लिए दर्ज हुआ। निस्संदेह यह राहत की बात है। फरवरी में खुदरा महंगाई की दर 5.09 फीसद थी, जो मार्च में घट कर 4.85 फीसद पर आ गई। यह पिछले दस महीनों का सबसे निचला स्तर है। हालांकि रिजर्व बैंक लगातार दावा करता रहा है कि वह महंगाई पर बहुत जल्दी काबू पा लेगा और इसे चार फीसद पर स्थिर कर सकेगा। स्वाभाविक ही ताजा आंकड़े से रिजर्व बैंक ने कुछ राहत की सांस ली होगी। मगर दावा करना मुश्किल है कि आगे भी महंगाई का रुख नीचे की तरफ ही बना रहेगा। खुदरा महंगाई की दर में आई ताजा कमी की बड़ी वजह तेल, गैस और बिजली की कीमतों का घटना है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस तरह कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आ रहा है, उसमें महंगाई को लेकर कोई अंतिम दावा करना कठिन है। खुदरा महंगाई में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कोई खास अंतर दर्ज नहीं हुआ है। फरवरी में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 7.8 फीसद दर्ज हुई थी, जो मार्च में घट कर 7.7 हो गई। सबसे चिंता की बात है कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मोटे अनाज, दूध, अंडे वगैरह की कीमतों में कोई कमी दर्ज नहीं हुई है। आखिर आम लोगों का वास्ता तो इन्हीं चीजों से होता है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई का अंतर भी चिंता की एक बड़ी वजह है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 5.45 फीसद है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 4.14 फीसद है। यह 1.31 फीसद का अंतर पिछले तेईस महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी ग्रामीण लोगों पर महंगाई की मार शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक पड़ रही है, जबकि क्रयशक्ति की दृष्टि से ग्रामीण लोगों की क्षमता शहरी लोगों की अपेक्षा कम होती है। उत्पादन के मामले में तेईस प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में से दस का उत्पादन घटा है। रिजर्व बैंक अपनी रेपो दर को यथावत बनाए रख कर महंगाई के मोर्चे पर कामयाबी हासिल करने का प्रयास कर रहा है, मगर जिस तरह अनेक स्तरों पर विसंगतियां और असंतुलन नजर आ रहा है, उसमें महंगाई पर काबू पाना उसके लिए चुनौती बना हुआ है। एक तरफ बड़ी कारों और भवनों की बिक्री में तेजी दर्ज हो रही है, तो दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में कमी देखी जा रही है। जिस मौसम में अनाज, फल और सब्जियों की बाजार में आवक तेज होती है, उसमें भी उनकी कीमतें ऊपर बनी रहती हैं।

महंगाई दरअसल, अर्थव्यवस्था में असंतुलन का संकेतक होती है। भले विकास दर के सात फीसद पर रहने के अनुमान और भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के आंकड़ों से देश में समृद्धि के संकेत मिलते हों, पर हकीकत यह है कि खुद सरकार के मुताबिक करीब बयासी करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं। रोजगार के मामले में स्थिति निरंतर भयावह होती जा रही है। सामान्य बोध यही है कि रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं तो लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है और उससे बाजार में पूंजी का प्रवाह तेज होता है। मगर इस दिशा में कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर ईंधन की कीमतों में कमी करने से महंगाई का रुख जरूर कुछ नीचे की तरफ हो गया है, पर यह स्थायी और व्यावहारिक समाधान नहीं है। बुनियादी कमजोरियों को दूर किए बिना शायद ही जमीन पर बेहतरी नजर आए।

समय रहते

पिछले दो विश्व युद्धों के इतिहास से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। दो देशों के बीच शुरू हुआ टकराव कब एक युद्ध में बदल जाए, कब वह दोनों पक्षों के सहयोगी देशों के बीच फैल जाए और विश्व युद्ध की शक्ल ले ले, कहा नहीं जा सकता। विडंबना है कि अतीत के अनुभवों से सबक लेना जरूरी नहीं समझा जाता। अमूमन हर युद्ध में इसी गलती को दोहराया जाता है। अब इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष की आग अन्य देशों की ओर भी फैलती दिखने लगी है। गौरतलब है कि हाल ही में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल की ओर से हमला करने की खबर आई थी। उसमें ईरान के दो जनरलों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ईरान ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। मगर अब मामला धमकियों से आगे बढ़ गया लगता है और ईरान ने जिस तेवर में जवाबी कार्रवाई की बात की है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने भी ईरान के हमले की तैयारी को लेकर चेतावनी दी है।

भारत और अमेरिका सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इस समय इजराइल और ईरान जाने से बचें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग अभी ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वे वहां के भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। ईरान में फिलहाल लगभग चार हजार और इजराइल में साढ़े अठारह हजार भारतीय रहते हैं। मगर ईरान के तेवर तीखे होने के बाद जिस तरह युद्ध का दायरा फैलने की आशंका मंडराने लगी है, उसके मद्देनजर भारत सरकार इन दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की संभावित निकासी के साथ-साथ अचानक पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। जाहिर है, अगर किन्हीं वजहों से बातचीत के जरिए स्थिति को संभाला नहीं गया, युद्ध को टाला नहीं जा सका तो फिलहाल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे जंग का दायरा चिंताजनक स्तर तक फैल जा सकता है। इसलिए भारत या अन्य देशों का अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है।

जानलेवा बनती बिगड़ती हवा

शरीर ही नहीं, मन-मस्तिष्क से जुड़ी अनेक व्याधियां भी हवा में घुलते जहर का परिणाम हैं। वर्ष के कुछ विशेष दिनों में तो वायु प्रदूषण के कारण एलर्जी और श्वसन से जुड़ी बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं।

मोनिका शर्मा

कुछ वर्ष पहले तक महानगरों की समस्या समझा जाने वाला वायु प्रदूषण अब गांवों-कस्बों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। यातायात के बढ़ते साधनों और अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण धूल और धुएं का प्रकोप दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंच जाना वाकई चिंताजनक है। हाल ही में 'सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर' संस्था ने खुलासा किया कि देश के सर्वाधिक पचास प्रदूषित शहरों में बिहार के उन्नीस शहर शामिल हैं। इनमें बेगूसराय, छपरा और पटना देश के सर्वाधिक दस प्रदूषित शहरों में से हैं। प्रदूषण का स्तर बेगूसराय में 265, छपरा में 212 और पटना में 212 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रहा। स्वच्छ हवा के मामले में राज्य के अन्य सोलह शहरों की हालत भी खराब है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में भी बिहार के करीब सोलह शहर ऐसे थे, जहां लगभग नब्बे फीसद दिनों की वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में खराब थी। इस वर्ष के शुरुआती दिनों में दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों को पीछे छोड़ सहरसा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 378 पर पहुंच गया था। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी 71 अंकों के उछाल के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़कर 331 दर्ज किया गया। गौरतलब है कि उन दिनों अगरतला, अररिया, आसनसोल, बद्दी, भागलपुर, बीकानेर, गुवाहाटी, हनुमानगढ़, करौली, मुजफ्फरनगर, रूपनगर और सोनीपत जैसे छोटे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर था। कुछ समय पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रपट में सामने आया था कि देश के 243 में से केवल चौदह शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहतर, यानी 0-50 के बीच रही। 59 शहरों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक (51-100) थी, जबकि सौ शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम (101-200) रही। दूर-दराज के कस्बों में हवा की गुणवत्ता का स्तर 300 पार कर जाना चिंताजनक है।

शरीर ही नहीं, मन-मस्तिष्क से जुड़ी अनेक व्याधियां भी हवा में घुलते जहर का परिणाम हैं। वर्ष के कुछ विशेष दिनों में तो वायु प्रदूषण के कारण एलर्जी और श्वसन से जुड़ी बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। हर आयुवर्ग के लोग दूषित हवा के कारण सेहत से जुड़ी परेशानियों की चपेट में आ रहे हैं। गर्भवती महिलाओं में सिरदर्द, चिंता और चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। एक ओर प्रजनन क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरी ओर अजन्मे शिशु मां के गर्भ में ही दूषित हवा से जुड़ी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। असल में, फेफड़ों के कैंसर और हृदयाघात जैसी समस्याओं के बढ़ते मामलों के साथ ही शारीरिक-मानसिक सेहत से जुड़ा ऐसा कोई पहलू नहीं है, जो वायु प्रदूषण से प्रभावित न होता हो। बढ़ते प्रदूषण के चलते मौसम चक्र भी बदल रहा है। मौसम की अनियमितता शारीरिक व्याधियों को न्योता देती है। 2023 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार घरों, वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषण भारत में हर साल 21.8 लाख नागरिकों का जीवन छीन रहा है। चीन

के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है, जहां दूषित हवा बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी लील रही है। भारत में पीएम 2.5 हर साल दो लाख से ज्यादा अजन्मे बच्चों की जान ले रहा है।

विचारणीय है कि बढ़ती तपिश के साथ भी वायु प्रदूषण और बढ़ता है। हवा में नमी की मात्रा कम होने से वाहनों द्वारा उड़ने वाले सूक्ष्म धूल कण वायु की गुणवत्ता कम करते और श्वसन संक्रमण से जुड़ी परेशानियां बढ़ाते हैं। तकलीफदेह है कि हाल के बरसों में भारत के छोटे शहरों में भी न केवल तापमान में बढ़ोतरी, बल्कि वायु की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में खराब हो रही है। दमघोंटू हवा के ये आंकड़े आने वाले कल की भी भयावह तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। शुद्ध वायु, कम आबादी और खुले परिवेश वाली छोटी जगहों पर छाता प्रदूषण का स्याह घेरा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को न्योता देने वाला साबित होगा। छोटे कस्बों में बढ़ते वाहन, बिजली के उपकरण और आसपास के क्षेत्रों से निकलता औद्योगिक धुआं और पेड़-पौधों की लगातार घटती संख्या के कारण गांव-घर का परिवेश भी बदल गया है। जबकि कोरोना के बाद बहुत से लोगों ने अपने गांव-कस्बे में लौटने का मानस बनाया था। तकनीकी सहूलियत से देश के किसी भी हिस्से में बैठकर काम करने की स्थितियों में 'रिवर्स माइग्रेशन' भी देखने को मिला। इसकी एक बड़ी वजह छोटे शहरों और गांवों-कस्बों का स्वच्छ परिवेश था।

> **हाल के बरसों में भारत के छोटे शहरों में भी न केवल तापमान में बढ़ोतरी, बल्कि वायु की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की तुलना में खराब हो रही है। दमघोंटू हवा के ये आंकड़े आने वाले कल की भी भयावह तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। शुद्ध वायु, कम आबादी और खुले परिवेश वाली छोटी जगहों पर छाता प्रदूषण का स्याह घेरा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को न्योता देने वाला साबित होगा। छोटे कस्बों में बढ़ते वाहन, बिजली के उपकरण और आसपास के क्षेत्रों से निकलता औद्योगिक धुआं और पेड़-पौधों की लगातार घटती संख्या के कारण गांव-घर का परिवेश भी बदल गया है।**

एक ओर सुविधासंपन्न जीवन-शैली प्रदूषण बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर जहां-तहां लगे कचरे के ढेर जहरीली गैस उगल रहे हैं। ज्ञात हो कि 2019 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी लागू किया गया था। इसके तहत चौबीस राज्यों के चुनिंदा 131 शहरों में 2025-26 तक पीएम 2.5 की सघनता में 40 फीसद की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पीएम 2.5 छोटे आकार के होने की वजह से सांस लेने पर फेफड़ों में गहराई तक पहुंच कर स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होते हैं। मोनाश विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुए नए अध्ययन में सामने आया है कि प्रदूषण के इन महीन कणों के संपर्क में आने से हर साल औसतन 10,18,688 लोगों को असमय जीवन गंवाना पड़ता है। हर साल वैश्विक स्तर पर प्रति लाख आबादी पर सत्रह लोगों की मौत के पीछे वायु प्रदूषण के ये महीन कण ही हैं।

अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'द लैंसेट' में छपी यह रपट बताती है कि पीएम 2.5 के थोड़े समय के संपर्क से ही वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों में से करीब 65.2 फीसद एशिया में दर्ज की गई हैं। बावजूद इसके, हमारे यहां जहरीली हवा से बढ़ते रोग, घटती जीवन प्रत्याशा और प्रकृति के रंग छिनने तक, प्रदूषण का दुष्प्रभाव साफ दिख रहा है। दुखद यह भी है कि लागू करने के बाद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे प्रयासों के असर का आकलन तक नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप, स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा के पांच वर्ष पूरे होने पर 'सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर' की ही विश्लेषणात्मक रपट बताती है कि सरकार द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने में कमी रहने पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। इसके चलते काफी लापरवाहियां हुई हैं। आवश्यक है कि जीवन बचाने वाले ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े लक्ष्य हासिल करने को गंभीरता से लिया जाए। राष्ट्रीय स्तर की सधी रणनीति के साथ ही सामाजिक, प्रशासनिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर जीवन सहेजने से जुड़े प्रयास किए जाएं।

दुनिया मेरे आगे

ज्ञान की यात्रा

एकता कानूनगो बक्षी

हमारे सामने सीखने-समझने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मौजूद होता है। जिन तथ्यों की जानकारी हमें आज है, भविष्य में उससे जुड़े ऐसे पक्षों के बारे में सुनेंगे, जिनका आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अनभिज्ञता के साथ पूर्णता प्राप्त करने की यही आकांक्षा जीवन को इतना रोचक और गतिवान बना देती है। जिज्ञासाओं की एक असीम राह सफल जीवन के लक्ष्य और ज्ञान के प्रति सदैव उत्सुक बनाए रखती है। ज्ञान जहां हमें वैचारिक रूप से मजबूत बनाता है, वहीं इससे उपजा दंभ हमें शून्यता की ओर अग्रसर कर देता है। ज्ञान को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसका उद्देश्य व्यापक रखते हैं, तब हम सम्मानीय हो जाते हैं। यही ज्ञान जब सिर चढ़कर अहंकार में बदलने लगे तो हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए।

विद्वान शब्द सुनते ही व्यक्ति की एक अलग ही छवि मन मे अंकित होने लगती है। किसी ताल या तलैया में ज्ञान का शांत जल ठहरा हुआ हो, जिज्ञासा की कंकरी डालते ही उसमें विचारों की लहरें सौंदर्य पैदा करने लगती हैं। जैसे कोई गहन चिंतन-मनन के साथ धैर्यपूर्वक अपनी बात रख रहा हो। विद्वान केवल विषय विशेष में सीमित न होकर जीवन के ऐसे पुस्तकालय की तरह होता है, जिसकी विविधतापूर्ण क्षमता से हम चकित हो जाते हैं, जिसके भीतर पूर्वाग्रह, मान, अभिमान से परे विनम्रता और लगातार सीखने, समझने और सुनने का धैर्य मौजूद होता है।

ज्ञानी व्यक्ति के साथ केवल एकतरफा संवाद नहीं होता, वहां सुनने और समझने का धैर्य मौजूद होने से सार्थक बातचीत का अवसर उपलब्ध होता है। किसी सुलझे हुए व्यक्ति से मिलकर हम खुद को भी अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। निराशा और कमियों से परे हमारे भीतर की क्षमता और संभावनाएं भी नजर आने लगती है। जिसकी उपस्थिति और आचरण से परेशानियों के बादल छटने लगें, शिथिल मन मजबूत होने लगे, वह सम्मान के योग्य निश्चित ही है। वही सच्चा विद्वान, ज्ञानी या महापुरुष कहलाने योग्य है। ऐसे व्यक्ति विनम्रतापूर्वक अक्सर आग्रह करते हुए नजर आते हैं कि उनके साथ किसी तरह का विशेष व्यवहार न किया जाए। अपनी गलती को स्वीकार करना और अपने कहे और किए हुए कामों को बिना हिचक संशोधित कर लेना। यह भी विद्वान व्यक्ति के कई गुणों में से एक गुण होता है।

हमारे समय में ऐसी कई महान विभूतियां रही हैं, जो लगातार अपनी किताबों, विचारों के जरिए हमसे आग्रह करते हुए नजर आती हैं कि उनका लिखे, किए पर आंख बंद करके विश्वास न करें। उसे परखें, समझें और सही लगे तभी आत्मसात करें। ऐसी व्यापक और खुली सोच के जरिए स्वस्थ और नए विचारों को गति मिलती है। संकीर्ण विचारों को विचार-विमर्श के जरिए समाप्त किया जा सकता है। इससे हमारा समाज परिष्कृत होता चला जाता है। सच्चा विद्वान ऐसी उपजाऊ जमीन तैयार करता है, जिसमें गुणवान लोगों के पल्लवित होने की असीमित संभावनाएं निहित होती हैं।

हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, जब हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने और उसका प्रसार करने के कई जरिया मौजूद हैं। यह सच है कि हम लगातार सीख रहे हैं, विशेषज्ञ बन रहे हैं और बेबाक, धाराप्रवाह अपने आप को अभिव्यक्त कर रहें हैं। अपने ज्ञान को दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत करना तर्कसंगत है, पर अगर हम यह केवल खुद को महत्त्वपूर्ण साबित करने के लिए कर रहे हैं और उस घमंड में खुद को डुबो रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर नया ज्ञान और विशेषज्ञता की एक समाप्ति तिथि अवश्य होती है, जिसके बाद कोई न कोई नया तथ्य और महत्त्वपूर्ण विषय उसे प्रतिस्थापित कर देता है। ज्ञान निरंतर अपने को अद्यतन करता रहता है। यही विकास क्रम है।

तात्कालिक तौर पर हमें यह समझना होगा कि उपलब्ध ज्ञान या किसी बात को याद कर लेने या उसे सीख लेने से बेहतर होगा कि हम यह जानें कि सीखे हुए का किस तरह और किस उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि जब हम अपने आप को सर्वज्ञाता मानने लगते हैं, हम अपने ही विकास का रास्ता बंद कर रहे होते हैं। इसे एक तरह से आत्मघात ही कहा जाएगा। संभव है कि आत्मप्रशंसा में लिप्त ज्ञानियों की हरकतों ने ही मूर्ख शब्द को प्रचलित किया होगा। विद्वान की विवेकशीलता किसी की अनभिज्ञता को मूर्खता नहीं कह सकती। सब कुछ जान लेने का भ्रम पाल लेना जरूर एक तरह की भूल कही जा सकती है।

> **उपलब्ध ज्ञान या किसी बात को याद कर लेने या उसे सीख लेने से बेहतर होगा कि हम यह जानें कि सीखे हुए का किस तरह और किस उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि जब हम अपने आप को सर्वज्ञाता मानने लगते हैं, हम अपने ही विकास का रास्ता बंद कर रहे होते हैं।**

हर चीज जान और सीख लेना किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य में कभी नहीं रहा। 'यह मुझे नहीं आता' यह एक स्वाभाविक वाक्य है। इसमें किसी तरह की हीनभावना या शर्म गैरजरूरी है। ज्ञानी दिखने की होड़ में बिना विचारे की गई प्रतिक्रिया से बेहतर है किसी भी विषय को थोड़ा समय देकर ठीक तरह से उसका अध्ययन कर अपनी बात रखना, जो हमारी विवेकशीलता दर्शाता है। दूसरों द्वारा अनजाने में हुई छोटी-बड़ी त्रुटियों का मखौल बनाना भी एक छोटी समझ है। गलतियां होना, सीखने-समझने की प्रवृत्ति और असफलता का होना दरअसल, जीवंतता का प्रमाण है। यह हमारी सफलता व प्रगति भी सुनिश्चित करता है।

दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी समझ और दृष्टि से अभी भी ओझल हैं। बीता कल जी चुके, इसका मतलब यह नहीं है कि आज को हम पूरी तरह जानते हैं। आज बिल्कुल नया है, जो हमें बदल देने की क्षमता रखता है। ज्ञानी बनकर वाहवाही बटोरने की जगह हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सच्चे विद्वान व्यक्ति की तरह विनम्रता खुद में ला सकें। सर्वज्ञाता बनकर खुद को महत्त्वपूर्ण मान लेने की जगह उत्सुक मुसाफिर की तरह इस दुनिया मे रहें।

जीवन की जगह

वर्तमान में इलेट्रानिक दुनिया की भागदौड़ भरी व्यस्ततम जिंदगी में बच्चों के लिए साथ बिताने का समय लोग नहीं निकाल पाते। इसके अलावा रिश्तेदारी का व्यवहारिक ज्ञान भी पीछे छूट-सा गया है। कहानी से कल्पना की उत्पत्ति होती और मातृत्व दुलार भी सही तरीके से प्राप्त होता। इसमें इंसान होने के लिए जो सबसे जरूरी पक्ष है, संवेदना, उसकी क्या जगह होगी? आधुनिक तकनीकी के युग में मोबाइल और इंटरनेट ही सहारा बन गए है। बच्चों को तो जैसे मोबाइल की लत पड़ गई है। अगर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया तो रोने लगेगा। उससे बड़े बच्चे यूट्यूब के वीडियो में गुम हो रहे हैं। अब ऐसा लगने बच्चे खिलौने की दुनिया ही भूल गए। कुल मिला कर शारीरिक-बौद्धिक गतिविधि कमजोर हो गई। मोबाइल की आभासी दुनिया ने बच्चों को चश्मे चढ़वा दिए। घर पर मेहमान कुछ कह रहे होंगे, मगर लोगों का ध्यान बस फेसबुक, वाट्सएप में लगा रहता है। घर के काम तो पिछड़ ही रहे। ऐसे में अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चों के लिए अपनी भाग-दौड़ भरी व्यस्ततम जिंदगी से कुछ समय बच्चों को घर पर कहानियां सुनाने के लिए भी निकालें।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

नकारात्मकता से आगे

देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल में हर तरफ केवल एक दूसरे की बुराई और आरोप-प्रत्यारोप का घटनाक्रम जारी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव प्रचार में जनता के वास्तविक मुद्दों और सरोकारों की बात नहीं करती। शायद हमारे राजनेताओं के पास आज ऐसा कोई सकारात्मक विचार या जनता के हित की योजना या कार्यक्रम नहीं है जिसके बल पर देश की जनता को प्रभावित किया जा सके। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र की यह स्थिति वाकई बहुत दुखदायी है। आज विकास और सर्वधर्म सद्भाव अथवा सामाजिक समरसता और भाईचारे की बात लगभग समाप्त हो चुकी है। चहुंओर केवल नकारात्मक प्रचार का बोलबाला दिखाई देता है। काश राजनीतिक दल देश और समाज के व्यापक हित में, रचनात्मक विचारों और लोकोपकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। हमारा देश आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में शुमार होता है। वास्तविक प्रगति, विकास और खुशहाली के बिना सब कुछ अधूरा ही रहेगा।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

सबकी जिम्मेदारी

'अपराध का मानस' (संपादकीय, 9 अप्रैल) पढ़ा। बड़े अफसोस की बात है कि एक माचिस की तीली न देने पर दो नाबालिगों ने ने अपने परिचित नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी। दुख इस बात का है मामूली बात पर झगड़ने वाले दोनों ही नाबालिग थे। इससे यह भी पता चलता है कि इन बच्चों के माता-पिता उनके प्रति कितनी लापरवाही रखते हैं। अगर पुलिस प्रशासन दोषी है जो ऐसे अपराधियों को समय पर पकड़ नहीं पाती है, तब माता पिता की जिम्मेदारी भी बनती है। उनका नाबालिग बच्चा अपराधियों की संगत में न जाए। अगर ऐसा हो तो उसकी गतिविधियों पर निगाह रखने और उसे वापस लाने की जरूरत है। साधारण-सी बातों पर अपना आपा खोकर हत्या को अंजाम देने वाले नाबालिगों के माता-पिता भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

– बीरसैन सरल, गाजियाबाद

शुचिता जरूरी

हाल ही में आई एक खबर स्तब्ध करने वाली थी कि रीवा में तीन हजार अभ्यर्थियों को उत्तर रटाए गए थे। इतने ढेर सारे सुरक्षात्मक उपायों और चाक-चौबंद व्यवस्था के बावजूद अगर प्रश्नपत्र बाहर आ जाने जैसी बड़ी चूक हो जा रही है तो निश्चित रूप से यह प्रतियोगी अभ्यर्थियों और विशेषकर सरकार के लिए चिंता का विषय है। वर्षों तक कोई प्रतियोगी छात्र किसी एक परीक्षा की पूरी तन्मयता से तैयारी करता है, परीक्षा भी दे आता है और सफलता के प्रति आश्वस्त भी रहता है। मगर बाद में जब उसे मालूम होता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र तो पहले ही बाहर आ चुका था, तो समझा जा सकता है कि उस छात्र और उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। परीक्षा की शुचिता के प्रति लोगों में विश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ ही सरकार और आयोगों के प्रति भी विश्वसनीयता बढ़ेगी।

– रतन कुमार श्रीवास्तव 'रतन', लखनऊ

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid
www.readwhere.com

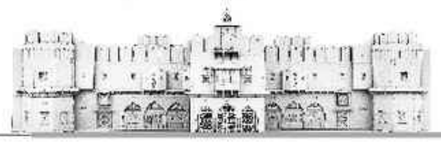

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

इजरायल पर हमले से संघर्ष के नए मोर्चे का खतरा

इजरायल पर ईरान के हमले ने रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास के युद्ध से पहले से ही त्रस्त दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मामले को खत्म करने की बात कही है, लेकिन उसकी इस चेतावनी से संकट बरकरार है कि अगर इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जाहिर है, अगर इजरायल जवाबी हमले करता है तो मध्य-पूर्व में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने की आशंका है। संकट टालने की कोशिशों की बजाय अमरीका के साथ ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश जिस तरह इजरायल को समर्थन दे रहे हैं, उससे भी हालात विकट मोड़ लेते दिख रहे हैं।

ईरान ने दो दिन पहले ही इजरायल पर हमले की खुली चेतावनी दी थी। अफसोस की बात यह है कि उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने में इस वैश्विक संगठन की शिथिलता लगातार उजागर हो रही है। ईरान और इजरायल पुराने दुश्मन हैं। इजरायल का अस्तित्व ईरान को मंजूर नहीं है। उसका कहना है कि इजरायल ने मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सीरिया के हालात ने दोनों देशों के बीच आग में घी डालने का काम किया। सीरिया वर्ष 2011 से इस संघर्ष से जूझ रहा है। ईरान वहां की सरकार का समर्थन करता है, जबकि इजरायल को लगता है कि इसकी आड़ में ईरान वहां अपने सैनिक अड्डे बना रहा है। सीरिया के आतंकी अड्डों से इजरायल पर कई हमले हो चुके हैं। ताजा विवाद की भूमिका एक अप्रेल को सीरिया पर इजरायल के हमले ने तैयार की, जिसमें ईरान समर्थित इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ब्रिगेडियर जनरल समेत आठ अफसर मारे गए थे। ईरान रविवार के हमले को इसी का जवाब बताते हुए 'हिसाब बराबर' होने का दम भर रहा है। मध्य-पूर्व के घटनाक्रम ने भारत की भी चिंता बढ़ा रखी है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इजरायल में करीब 20 हजार और ईरान में करीब चार हजार भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। ईरान ने इजरायल जा रहे जिस मालवाहक जहाज पर शनिवार को कब्जा किया था, उसके चालक दल में शामिल सत्रह भारतीयों की रिहाई को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में है।

दरअसल, भारत हमेशा युद्ध और युद्ध क्षेत्र से दूर रहने को प्राथमिकता देता है। रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाते हुए वह सभी पक्षों से युद्ध खत्म करने की अपील करता रहा है। युद्ध कहीं भी हो, समूची मानव सभ्यता को प्रभावित करता है। दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र को हर युद्ध खत्म करने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए।

उत्तरप्रदेश : 819 नहीं बचा पाए जमानत

लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 819 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। दमन दीव में सबसे कम एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। पूरे देश में कुल 6897 प्रत्याशी जमानत बचाने में विफल रहे थे।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

लोकसभा चुनाव 2024

भाजपा को 9.63 % मत मिले

लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को सबसे ज्यादा मत हिमाचल प्रदेश में 69.11 प्रतिशत मिले थे। साथ ही सबसे कम 9.63 प्रतिशत मत पंजाब में मिले थे।

उत्तराखंड भाजपा की हैट्रिक की राह में निर्दलीय रोड़ा, कांग्रेस वजूद बचाने की कोशिश में

पहाड़ सी है पहाड़ की सियासत

हरिद्वार से
अभिषेक श्रीवास्तव

आंदोलनों की पृष्ठभूमि से बने उत्तराखंड में राजनीतिक पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। इस पहाड़ी राज्य में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पांच लोकसभा क्षेत्रों में दो पर निर्दलियों ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। पहली बार टिहरी में 'रानी' को निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी चुनौती दे रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ती दिख रही है। हरिद्वार में पुत्र की जीत सुनिश्चित करने के लिए हरीश रावत को कैम्प करना पड़ रहा है।

उत्तराखंड का सियासी मिजाज भांपने के लिए जब उदयपुर से ट्रेन में बैठा तो वहां मिले बिष्ट दंपती ने उत्सुकता अचानक बढ़ा दी। ट्रेन की गति के साथ सियासी बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह काफी देर तक चला। देहरादून के पास डोईवाला के रहने वाले बिष्ट दंपती ने शुरुआत ही एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के नाम के साथ की और साथ ही उनकी तुलना राजस्थान के रविंद्र सिंह भाटी से कर दी। पेशे से पत्रकार उमेश कुमार वहीं हैं जो काफी समय तक जेल में रहे और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जीत दर्ज की थी।

खैर, ट्रेन के धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचने पर जनता का मूड भांपने के लिए पहले हर की पौड़ी और फिर वहां से रुड़की निकल गया। रास्ते में पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की में ही हैं और वहां कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे अपने बेटे वीरेंद्र रावत का प्रचार कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर मिले हरीश रावत ने कहा कि इस बार उत्तराखंड की पांचों सीटें कांग्रेस जीतने वाली हैं। पार्टी से खरपतवार निकल कर भाजपा में जा रहा है। बीजेपी ने बेरोजगारों को छला है।

यहां की राजनीति दो ध्रुवों में बंटी है, एक का नियंत्रण कुमाऊं से होता है तो दूसरे का गढ़वाल से। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गढ़वाल से। राजनीतिक दलों को दोनों मंडलों के बीच सामंजस्य बनाकर चलना होता है। प्रदेश की पांच सीटों में हरिद्वार, टिहरी पूरी तरह से गढ़वाल मंडल का हिस्सा हैं, जबकि गढ़वाल सीट का कुछ हिस्सा कुमाऊं में आता है। हरिद्वार सीट की बात करें तो इसमें हरिद्वार जिले के 11 और देहरादून के तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मैदानी क्षेत्रों में लड़ाई त्रिकोणीय नजर आती है। यहां से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। उनको चुनौती निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और कांग्रेस के वीरेंद्र रावत से मिल रही है। रुड़की में ही प्रचार कर रहे उमेश कुमार ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। दोनों पार्टियों के पास विजन नहीं है। ऑटो चलाने वाले हैप्पी ने बताया कि हरिद्वार में मुकाबला टफ है। बीजेपी के पास मोदी का चेहरा है। कांग्रेस रावत परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसके लोग उसे छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। हरिद्वार के मोती बाजार में जैन चाट भंडार के संचालक नीरज जैन ने बताया कि भाजपा आश्वस्त है। पहाड़ों में बीजेपी अधिक मजबूत है।

हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी।

टिहरी में त्रिकोणीय मुकाबला

हरिद्वार सीट का जायजा लेने के बाद टिहरी-गढ़वाल सीट का मूड परखने पहुंचा। यहां 1991 से ही पूर्व राजपरिवार का कब्जा रहा है। 2007 के उपचुनाव और 2009 के चुनाव में कांग्रेस के विजय बहुगुणा जरूर सांसद चुने गए थे। 2012 में विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव से टिहरी पूर्व राज परिवार की सदस्य माला राज्यलक्ष्मी शाह यहां से लगातार सांसद हैं। कांग्रेस ने मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को मैदान में उतारा है। दिलचस्प यह कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। बेरोजगारों के आंदोलन से चर्चा में आए बॉबी पंवार को युवाओं ने मैदान में उतार दिया है। देहरादून में मिले भुवन कांडपाल ने बताया कि 'रानी' के लिए राह आसान नहीं है। इस परिवार का सीट पर लगातार कब्जा रहा है। दरअसल, टिहरी अपने बांध के लिए भी जाना जाता है। कुछ गांवों के लिए विस्थापन अब भी मुद्दा है।

बड़े मुद्दे

गढ़वाल मंडल की सीटों पर रोजगार बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। पहाड़ी जिलों में बादल फटने की घटनाओं से लोग परेशान रहते हैं। आपदा प्रबंधन उनके लिए मुद्दा है। दुर्गम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हालांकि भाजपा यूसीसी (समान नागरिक संहिता) को बड़ी उपलब्धि मानकर चल रही है।

स्ट्राइक रेट

वर्ष	
2019	बीजेपी 5 vs कांग्रेस 0
2014	बीजेपी 5 vs कांग्रेस 0
2009	बीजेपी 0 vs कांग्रेस 5

चुनावी चटकारा

होने लगी तीनों लोक की चर्चा...

लोकसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल एक-दूसरे पर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की होड़ मची हुई है। मध्यप्रदेश में भाजपा की एक सभा हुई, इसमें आए कार्यकर्ताओं में यह चर्चा थी कि कांग्रेस चंदे पर भाजपा को घेर रही है। अब भाजपा क्या जवाब देगी। सभा शुरू होते ही भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस ने तीनों लोकों में भ्रष्टाचार किया है। इस आरोप के बाद कार्यकर्ता देखते ही रहे गए, वे इतना ही कह पाए वाह क्या दमदार बात कही है। इसके आगे कांग्रेस का कोई आरोप टिकने वाला नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी भाजपा के आरोपों पर टिप्पणी करने से नहीं चूके, उन्होंने भी कह दिया कि काल्पनिक आरोप ऐसे ही लगाए जाते हैं। जुमले वाली पार्टी के नेता हवाई आरोपों की तरह ही हवाई वादे करते हैं।

राग सियासी

सियासत गरमा रही,
है वादों का शोर।
सियासी सूरमा लगा रहे,
एड़ी चोटी का जोर।।
एडी चोटी का जोर,
दौरे पर दौरे।
मतदाताओं को लुभा रहे,
डाले उन पर डोरे।।
देहरी देहरी धोक रहे हैं,
दिन देखे ना रात।
बुझे सितारा या चमकेगा,
यह किस्मत की बात।।

\- सुरेंद्र पगारिया

यूपी : फायदा उठाने की कोशिश में बसपा

कुंवर से मुकाबला तो नाम में जोड़ दिया कुंवरानी

मुरादाबाद
डॉ.संजीव मिश्र

पीतलनगरी मुरादाबाद में चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। उत्तरप्रदेश राज्य की इस लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी की सीट बनाए रखने में प्रत्याशी बनी रुचि वीरा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह से मुकाबले के लिए उन्होंने अपने नाम में कुंवरानी लिखना शुरू कर दिया है। यही नहीं वैश्य वोटों के लिए नाम के साथ गुप्ता जोड़ने की चर्चा भी मुरादाबाद में आम हो गई है।

मुरादाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सांसद बनने वाले और 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन से हारने वाले कुंवर सर्वेश सिंह को टिकट दिया है। उनके मुकाबले में सपा ने बिजनौर की विधायक रुचि वीरा को टिकट दिया है।

राजघरानों में संघर्ष: भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह अफजलगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वे अपने नाम के साथ कुंवर लगाते हैं, तो सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने भी कुंवरानी लगाना शुरू कर दिया है। वे राजा ज्वाला प्रसाद के वीरा राजघराने की कुलवधू हैं। रुचि वीरा ने अपने नाम के आगे कोष्ठक में गुप्ता लिखना भी शुरू किया है। कहा जा रहा है कि भाजपा का स्थायी वोट बैंक माने जाने वाले वैश्य वोटों के लिए यह बदलाव किया गया है।

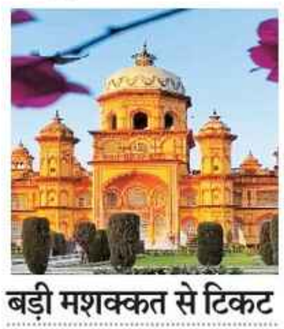

बड़ी मशक्कत से टिकट

मुरादाबाद के मौजूदा सांसद एसटी हसन लोकसभा में सपा संसदीय दल के नेता भी थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खां की पैरवी पर रुचि वीरा को दे दिया। रुचि वीरा के नामांकन करा चुकने के बाद अखिलेश का मन बदला और उन्होंने एसटी हसन को ही प्रत्याशी बनाने की चिट्ठी निर्वाचन अधिकारी को लिख दी, लेकिन समय पर चिट्ठी ही पहुंची ही नहीं।

बसपा की मुस्लिम मतदाताओं पर नजर

बसपा यहां मौके का फायदा उठाना चाहती है। बसपा संघर्ष को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। यहां 45 फीसदी के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। यहां भाजपा व सपा द्वारा हिंदू प्रत्याशी उतारे जाने के बाद बसपा प्रत्याशी मोहम्मद इरफान की नजर इन मुस्लिम वोटों पर है। बसपा अपना मूल वोट बैंक भी जोड़ कर लड़ाई में रहने की उम्मीद लगाए है।

पश्चिम बंगाल: कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चे का खोई हुई जमीन हासिल करने पर जोर

अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रही है तृणमूल कांग्रेस

मनोज कुमार सिंह

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में पिछली बार से अधिक लोकसभा सीटें जीतने की कोशिश तेज हो गई है। भाजपा राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 30 से अधिक सीटें जीतने का निर्धारित लक्ष्य भेदने और तृणमूल अपनी सीटें बचाने के साथ भाजपा की सीटें झटकने के लिए मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की जुगत भिड़ा रही हैं। कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चा मिलकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए दमखम लगा रहे हैं।

कश्मीर और असम के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 32 प्रतिशत है। राज्य के 32 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं में सबसे अधिक बांग्ला भाषी हैं। इनके एक बड़े धड़े में ममता सरकार से खासा नाराजगी है, जो तृणमूल का अटूट वोट बैंक रहा हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में यह सवाल उठ रहा है कि ममता से नाराज मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पाले में वोट डालेंगे। हालांकि मुस्लिम समुदाय के नेताओं का मानना है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए तृणमूल को वोट देना आवश्यक है, लेकिन मुस्लिम मतदाता अब भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं।

इस तरह बन रहा है समीकरण

सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद, मालदह और उत्तर दिनाजपुर जिले के आधा दर्जन से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में किसकी जीत होगी, जहां अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यक हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट, हुगली जिले के आरामबाग लोकसभा सीट सहित हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जिले की उन लोकसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ममता के अल्पसंख्यक वोट बैंक बिखरने से तृणमूल की सीटें घटने के साथ उन लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं।

तृणमूल के वोट बैंक में विपक्ष की सेंधमारी की कोशिश

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जैसे मुद्दों पर मुखर है। उन्होंने इनका विरोध कर अपनी पार्टी और मुस्लिम समाज के बीच बढ़ती दूरी को पाटने की कोशिश तेज की हैं। दूसरी ओर वाम मोर्चा-कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष गठबंधन खुद को तृणमूल के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। इसके अलावा ऑल इंडिया सेक्युलर फंट (एआईएसएफ) भी पहली बार लोकसभा में जाने के लिए बांग्ला भाषी मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डाल रहा है।भाजपा राष्ट्रवाद, राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे मुद्दे उठाकर तृणमूल के हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में हैं।

पोलीटून

महाराष्ट्र बारामती बन गई है राज्य की हॉट सीट

ननद और भौजाई में शुरू हुई चुनावी लड़ाई

राम दिनेश यादव

महाराष्ट्र की इस लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बारामती है। यह वरिष्ठ नेता शरद पवार परिवार का गढ़ है। शरद पवार राजनीति में हमेशा शतरंज की बिसात बिछाते रहे हैं। इस बार भाजपा ने उन्हें मात दे दिया है। उनके परिवार में फूट पड़ गई है। हालात यह है कि उनकी बेटी और उनकी बहू आपने सामने हैं। उनके भतीजे और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा सीट से उनकी बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में हैं। प्रदेश की राजनीति में शायद पहली बार पवार खानदान की दो महिलाएं चुनावी रण में आमने सामने हैं।

सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल इस लोकसभा सीट पर भले ननद भौजाई आमने सामने हैं लेकिन वास्तव में यह लड़ाई पवार चाचा भतीजे की है। पिछले साल अपने चाचा से अलग होकर अजित पवार ने भाजपा के साथ सत्ता में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार के नेतृत्व वाली टीम ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा के इशारे पर अजित पवार ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है।

अजित पवार को अब भी चाचा का सहारा!

सुप्रिया सुले अपनी बारामती की सीट बचाने के लिए 'भाभी' सुनेत्रा पवार से इस बार प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ेंगी।पवार खानदान की ननद भौजाई को आमने सामने होने की वजह से पवार खानदान के समर्थक असमंजस में नजर आ रहे हैं। उनके लिए कभी शरद पवार और अजित पवार में कोई भेद नहीं था। वे आज समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे वोट दें, ननद को या भौजाई सुनेत्रा को। इसके अलावा अजित पवार भले ही अपने चाचा से अलग हो गए हैं लेकिन आज भी वे मतदाताओं के बीच अपने चाचा का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के लिए पांच चरणों में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच मतदान होगा। बारामती में 7 मई को मतदान होगा।

'नेताजी के तारे-सितारे'

भाषण का प्रभाव पड़ेगा, प्रतिद्वंद्वी के हौसले पस्त होंगे

लोकसभा चुनाव के रण में कई नेता ताल ठोक रहे हैं। इनमें ऐसे भी नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। यानी वे बागी होकर मैदान में हैं। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। नेता शुभ-अशुभ का ध्यान रख कदम उठा रहे हैं तो जानिए आज नेताजी के तारे-सितारे क्या कह रहे हैं।

\-अज़हर हाशमी

मेष- आज आपकी राशि में चंद्रमा मिथुन का यानी तीसरा है जो बहुत शुभ है। सूर्य भी उच्च का हो गया है। प्रचार में आपका जलवा रहेगा।

वृषभ- आज आपकी राशि में गोचर में दूसरा चंद्रमा अनुकूल है। आपके भाषण का प्रभाव श्रोताओं पर पड़ेगा। प्रतिद्वंद्वी के हौसले पस्त होंगे।

मिथुन- आज तो आपकी राशि में ही चंद्रमा गोचर में है जो बहुत ही शुभ स्थिति है। आज आप 'दाल-बाटी' खा सकते हैं। ज्यादा मत खाना!

कर्क- आज आपकी राशि में बारहवां चंद्रमा बहुत अशुभ है। प्रचार में वाणी में संयम रखें। आप कैमरे की नजर में हैं। सावधान!

सिंह- आज आपकी राशि में गोचर में ग्यारहवां चंद्रमा बहुत शुभ है। आज आप प्रतिद्वंद्वी का मुगालता दूर कर देंगे। बधाई!

कन्या- आज आप गोचर के दसवें चंद्रमा के कारण लाभ में तो रहेंगे किंतु मंगल के अशुभ प्रभाव से आपका स्वास्थ्य मंच पर बिगड़ सकता है।

तुला- आज आपकी राशि में गोचर में चंद्रमा नौवां है जो अनुकूल है। आज प्रतिद्वंद्वी आपको नौ बार सलाम बजाएगा। इतराना मत।

वृश्चिक- आज आपकी राशि में गोचर का आठवां चन्द्र बहुत अशुभ है। अशुभता दूर करने के लिए प्रतिद्वंद्वी को मूंग का हलवा खिलाएं।

धनु- आज आपकी राशि में गोचर में सातवां चंद्र इतना शुभ है कि आप सातवें आसमान तक उड़ सकते हैं। पैराशूट साथ रखें।

मकर- आज आपकी राशि में छठा चंद्रमा गोचर में प्रतिकूल है। आज प्रतिद्वंद्वी आप पर भारी पड़ेगा। आज प्रचार से परहेज करें।

कुंभ-आज आपकी राशि में गोचर में पांचवां चंद्र आपके लिए अनुकूल है। आज आप प्रचार में प्रतिद्वंद्वी के छक्के छुड़ा देंगे। बधाई!

मीन- आज गोचर में चौथा चंद्रमा आपकी राशि में अशुभ है। अशुभता दूर करने के लिए प्रतिद्वंद्वी के सामने चार बार अपना सिर खुजाएं। फायदा होगा।

अगला राशिफल गुरुवार के अंक में

आज का सवाल

ईरान-इजरायल के बीच तनाव का भारत पर क्या असर होगा?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

फल-सब्जियों का सेवन करें

निरोगी व स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन संतुलित आहार के साथ ताजे फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पीना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर व्यायाम अवश्य करनी चाहिए।

\- **उमराव सिंह वर्मा,** बेमेतरा, छत्तीसगढ़

नियमित दिनचर्या जरूरी

स्वस्थ बने रहने के नियमित दिनचर्या जरूरी है। साथ ही स्वच्छ आहार, पर्याप्त नींद, योग, व्यायाम, पर्याप्त पानी का सेवन, धूम्रपान का त्याग, जंक फूड से बचाव जैसी बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है।

\-**राहुल कुमार पालीवाल,** राजसमंद

आहार पर खास ध्यान जरूरी

हमें निरोगी रहने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में से कम से कम एक घंटा व्यायाम करना चाहिए। हमें अपने खान-पान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम आहार लेते हैं।

\-**ज्योत प्रकाश गुलाटी,** रोहतक, हरियाणा

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'निरोगी रहने के लिए क्या करना चाहिए ?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/mrtOP

चिंतन

न्याय बनाम संकल्प पत्र पर जन भरोसे की परीक्षा

आम चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी करने की परंपरा रही है। घोषणा पत्र के जरिये लोकलुभावन वादों से वोटरों को लुभाने की कोशिश होती है। हालांकि 1952 से हो रहे आम चुनाव में घोषणा पत्रों में किए गए वादे पार्टियों ने शायद ही पूरे किए हैं। केंद्र में चाहे सरकार कांग्रेस या उसके गठबंधन की रही हो या फिर भाजपा नीत गठबंधन की, किसी ने भी चुनाव से पहले किए वादों को पूर्णतः पूरा नहीं किया। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पूर्व मिशन 2024 के लिए कांग्रेस और भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने 76 पन्नों के मेनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है, कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है। गत पांच अप्रैल को कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी के वादे के साथ अपना 48 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था और आज भाजपा ने डा. भीम राव आंबेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल को अपना संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें 24 गारंटी के वादे हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए आंबेडकर जयंती का दिन चुनकर एक बड़े वर्ग को सामाजिक न्याय का भरोसा दिया है। उसने अपने संकल्प पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने, उनका दायरा बढ़ाने, 2047 तक विकसित भारत बनाने समेत कई बड़े वादे किए हैं। ये बातें पीएम मोदी पहले से ही करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने 'न्याय पत्र' में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केन्द्र में रखकर कई बड़े वादे किए हैं। बारीकी से देखें तो, दोनों घोषणा पत्र गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के ईर्द-गिर्द हैं। कांग्रेस का जोर स्थाई सरकारी नौकरी व महिलाओं को नकद देने पर ज्यादा है। भाजपा की गारंटियों में सभी को स्वास्थ्य बीमा, सभी के लिए बीमा योजना और सभी को पक्का घर देने का वादा प्रमुख हैं। इसमें मूलभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ कृषि और रोजगार क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया गया है। भाजपा के घोषणा पत्र को मोदी सरकार 3.0 के अगले पांच सालों के बजट का संकेत पत्र माना जा सकता है। भाजपा के घोषणा-पत्र में समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, अगले पांच साल तक 5 किलो मुफ्त राशन, पेपर-लीक पर लगाम लगाने के लिए कानून लाने, मैन्युफैक्चरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार, हाई-वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर्स, किसान निधि जारी रखने, 3 करोड़ लखपति दीदी, उत्तर भारत में भी बुलेट ट्रेन, 70 से अधिक उम्र के सभी लोगों व ट्रांसजेंडरों को भी आयुष्मान योजना का लाभ, गरीबों को 3 करोड़ नए घर, रसोई गैस की पाइप से आपूर्ति, 20 लाख तक मुद्रा ऋण जैसे सर्व समावेशी वादे किए गए हैं। 2019 के घोषणा-पत्र में भी भाजपा ने यूसीसी, एक राष्ट्र एक चुनाव, 60 साल की उम्र के बाद देश के किसानों व छोटे दुकानदारों को पेंशन देने आदि जैसे बड़े वादे किए गए थे, जो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में पांच न्याय- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय के साथ जाति जनगणना कराने, गरीब महिलाओं को प्रति वर्ष एक लाख रुपये नकद देने, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने, 30 लाख सरकारी नौकरी देने, एमएसपी को कानूनी दर्जा, जीएसटी मुक्त खेती, एक वर्ष के भीतर एससी/एसटी के बैकलॉग भरने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, योजना आयोग की बहाली, बुल्डोजर न्याय को खत्म करने, संविधान की रक्षा करने जैसे बड़े वादे किए हैं। अब गेंद जनता के पाले में है कि वह भाजपा या कांग्रेस में से किसकी गारंटी पर भरोसा करती है। यह चुनाव न्याय बनाम संकल्प पत्र पर जन भरोसे की परीक्षा है। चूंकि इस बार का चुनाव पूर्ण बहुमत बनाम गठबंधन सरकार के बीच है, जिसमें भाजपा पूर्ण बहुमत की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस इंडी गठबंधन की विजय के लिए कोशिश में है, ऐसे में मेनिफेस्टो में गारंटियों की परीक्षा भी है।

सारा संसार

महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 14 किलोमीटर दूर पुणे-बेंगलुरू राजमार्ग पर चिन्मय गणेशधाम मंदिर पूरी दुनिया में गणेश की सबसे ऊंची मूर्ति के लिए जाना जाता है। यह प्रतिमा 61 फीट की ऊंचाई पर खड़ी है। इसका उद्घाटन 2001 में किया गया।

आम चुनाव
सोनम लववंशी

भाषा का गिरता स्तर चिंताजनक

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर है। पक्ष विपक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कब सिद्धांतों को धत्ता बता दें यह पता ही नहीं चलता। अभिव्यक्ति के नाम पर अनर्गल बयानबाजी ने राजनीति की शुचिता को तार-तार कर दिया है। 'बोल के लब आजाद हैं तेरे' पंक्ति का शोर आजकल राजनीतिक आबोहवा में गुंजित हो रहा है। ऐसे में मालूम तो यही पड़ता कि जब मशहूर शायर फैज अहमद फैज ने इन पंक्तियों को लिखा होगा तो शायद ही कभी ये सोचा होगा कि देश के राजनेता उनकी इस पंक्ति के सहारे शब्दों की सारी मर्यादा लांघ जाएंगे! यूं तो महिलाओं के प्रति की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों के लिए भारतीय लोकतंत्र सदियों से बदनाम रहा है, लेकिन चुनाव आते-आते विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को अमर्यादित भाषा के वायरस से कलंकित करने में हमारे राजनेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब महिला नेत्री भी इस मुकाबले में पीछे नहीं रही है। बीते दिनों ही कंगना रनौत और ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इसकी ताजा मिसाल हैं, लेकिन महिलाओं पर ऐसे हमले क्यों होते हैं और यह स्थिति कैसे बदलगी? ये कोई नहीं कह सकता। वैसे जब महिला ही महिला को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे तो स्थिति और असहज हो जाती है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी की। यूं तो चुनाव आयोग ने ऐसे बयानों पर चेतावनी देकर इतिश्री कर ली, पर इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा तभी तो अभी हाल के दिनों में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब जरा कोई रणदीप सुरजेवाला को यह बताएगा कि कांग्रेस में भी महिलाएं सांसद-विधायक क्यों बनती हैं? एक पार्टी का जिम्मेदार नेता कैसे अशोभनीय भाषा पर उतारू हो जाता है। यह समझ नहीं आता। विडंबना देखिए कि चुनाव आते ही देश में महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन महिलाओं के साथ छींटाकशी आधुनिक समाज में भी चरम पर हैं। माना कि चुनाव का दौर चल रहा है और जीतने के लिए मुद्दे गढ़े जाते हैं, लेकिन यह कौन सा तरीका हुआ कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाए। किसी भी महिला के खिलाफ किसी राजनेता को अभद्र टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिला के साथ शाब्दिक छींटाकशी क्यों? दुःखद तथ्य यह है कि अब तो महिलाएं स्वयं महिलाओं पर अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। आज जिस दौर में भारतीय राजनीति में भाषा की गिरावट अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। राजनेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। उन्हें दूसरे राजनीतिक दल के नेताओ को बुरा बोलने में कोई बुराई नजर नही आती है। फिर सवालों की एक लंबी फेहरिस्त उत्पन्न होती है। क्या उसके उत्तर हमारे लोकतांत्रिक पहरुओं के पास है? पहला सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी ये तो नहीं कहती कि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान को भंग करें? फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीति निजी दुश्मनी अदा करने का कोई अखाड़ा भी नहीं। फिर अमर्यादित होने का क्या निहितार्थ? जब संवैधानिक व्यवस्था में राजनीति का जन्म देश को सुचारू रूप से आगे ले जाने के लिए हुआ। फिर मूल उद्देश्य को क्यों बिसार रहे राजनीति के सिपहसालार?

(लेखक सामाजिक विश्लेषक व वूमन एक्टिविस्ट हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

दो टूक
अवधेश कुमार

अपराधियों को नायक न बनाएं

माफियाओं, बाहुबलियों, अपराधियों को मृत्यु के बाद उसे गरीबों का मसीहा और नायक बनाया जाना भय पैदा करता है। सजाप्राप्त अपराधी को मुसलमानों का नायक, गरीबों का मसीहा बताया जाए तथा राजनीतिक पार्टियां और नेता उसके पक्ष में बयान दें इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाया गया खतरनाक झूठ कि मुसलमानों की चुन-चुन कर हत्याएं हो रही हैं- देश में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा कर रहा है। ऐसी राजनीति और एक्टिविज्म भयभीत करने वाली है। मुख्तार जैसे लोग नायक नहीं खलनायक हैं। खलनायक को नायक बनाने की प्रवृत्ति के विरुद्ध डटकर खड़ा होने की आवश्यकता है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर जाकर उसे महान और मसीहा साबित करने की उस अभियान को आगे बढ़ाया जो उसकी मौत के समय से ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने जेल में रहते हुए मुख्तार को पांच बार विधायक बनाया तो इसका मतलब है कि वह जनता के दुख दर्द में शामिल रहे और उसी का परिणाम है कि जनाजे में इतनी अधिक भीड़ उमड़ी। उन्होंने बांदा जेल में मुख्तार की मृत्यु पर सरकार को घेरा तथा उसकी तुलना रूस में बिना नाम लिए विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी की जेल में हुई मृत्यु से कर दी। जेल में कैदी की मृत्यु की कानून के अनुसार न्यायिक दंडाधिकारी से जांच आवश्यक है और जांच रिपोर्ट आना बाकी है। मुख्तार अंसारी पिछले लंबे समय से जब भी वीडियो में आया काफी कमजोर दिखता था। व्हील चेयर पर ही उसके बाहर निकलने या अंदर जाने की तस्वीरें आईं थीं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में अनेक बीमारियां लिखी हुई हैं। इतनी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की कभी भी किसी कारण से मृत्यु हो सकती है। वैसे भी बाहुबल और धनबल की बदौलत बादशाहत कायम करने की मानसिकता में जीने वाले व्यक्ति को जेल में आम अपराधी की तरह व्यवहार से मानसिक आघात लगना बिलकुल स्वाभाविक है। मानसिक तनाव, दबाव व हताशा में मनुष्य अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कारण बांदा जेल में वह आम सजाप्राप्त कैदी की तरह ही था। कुछ बुद्धिजीवियों, संगठनों, नेताओं, राजनीतिक पार्टियों आदि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कोई मायने नहीं हैं। प्रचार यही हो रहा है कि उसे मारा गया है। कुछ दिनों से उसके परिवार और वकील धीमा जहर देने का आरोप एक रणनीति के तहत लग रहे थे, जिसका उद्देश्य जमानत दिलाना या मन मुताबिक किसी जेल में शिफ्ट कराना था। मृत्यु से कुछ दिनों पहले बेटे से बातचीत के ऑडियो से उसके काफी अस्वस्थ व कमजोर होने के साथ गहरी निराशा में डूबे होने का पता भी चलता है।

उसकी मृत्यु पर सपा, बसपा या कुछ अन्य पार्टियों, मजहबी नेताओं आदि ने जिस ढंग का माहौल बनाया है उसने आम व्यक्ति को उद्वेलित किया है। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, जिससे प्रशासन या जेल या सरकार उसे तत्काल गैर कानूनी तरीके से मारने का कदम उठाए। इस समय उसकी मृत्यु से किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला था। लगातार उसे सजा मिल रही थी और अंतिम समय तक वह जेल में छटपटाते रहता तो इसका संदेश अन्य माफियाओं, बाहुबलियों, अपराधियों के बीच जाता कि ऐसे लोगों के साथ यही होना है। योगी सरकार की दृष्टि से यह स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। मृत्यु के बाद उसे गरीबों का मसीहा और नायक बनाया जाना भय पैदा करता है। जितनी संख्या में उसके नमाज ए जनाजा में लोग शामिल हुए वह सामान्य अवस्था का द्योतक नहीं है। ऐसे लोगों के जनाजे में इतने बड़े जन समूह का उभरना मुस्लिम समाज के अंदर बढ़ती ऐसी प्रवृत्ति है जिससे डरने और जिसको हर हाल में रोके जाने की आवश्यकता है। मुख्तार अंसारी न्यायालय द्वारा सिद्ध माफिया, हत्यारा, अपहरणकर्ता , सांप्रदायिक दंगा करने

वाला बाहुबली था। 65 से ज्यादा मुकदमे उसके नाम पर थे जिनमें आठ में उसे सजा दी जा चुकी थी। इनमें दो में उम्र कैद की सजा थी। न्यायालय द्वारा घोषित सजाप्राप्त अपराधी को मुसलमानों का नायक, गरीबों का मसीहा बताया जाए तथा राजनीतिक पार्टियां और नेता उसके पक्ष में बयान दें इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता। वे सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ न्यायपालिका पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। 2013 में मुंबई बम विस्फोटों के अपराधी टाइगर मेनन के जनाजे में मुंबई में उमड़ी भीड़ ने पहली बार देश को हैरत में डाला था। उस समय से यह एक स्थापित प्रवृत्ति है। अतीक अहमद की हत्या पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न था, लेकिन उसकी मृत्यु पर विशेष नमाज जगह-जगह अदा कर जन्नत की दुआ करना किस बात का द्योतक था? डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु पर इस तरह का दृश्य नहीं था। वस्तुतः उनके जनाजे में हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक थी। कांग्रेस के शासनकाल से उत्पन्न राजनीति के अपराधीकरण के भयावह दौर में ऐसे अपराधी और बाहुबली, जिन्हें जेल में होना चाहिए वो विधायक और सांसद बनकर नीति-नियंता बन गए। अतीक, अंसारी या शहाबुद्दीन जैसों की एकमात्र योग्यता यही थी कि वो अपने अपराध के बल पर साम्राज्य कायम कर चुके थे। सैयद शहाबुद्दीन को भी अपराधी होने के बाद ही राजद ने सांसद बना दिया। इनके कारण इन पार्टियों को कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों के बड़े वर्ग का वोट भी मिलता था। सांसद और विधायक बनने के बाद इनका अपराध तंत्र ज्यादा फैला और प्रशासन के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई हमेशा कठिन रही। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार ने जेल में रहते हुए कराई। अतीक जेल से भी पूरा तंत्र चलाता था और पुलिस की तरह ही उसके पास इंटेरोगेशन से लेकर कैद रखने के ढांचे बने हुए थे। शहाबुद्दीन की भी ऐसी ही स्थिति थी।

अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं होती तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बाबू बजरंगी जैसों का कानून की गिरफ्त में इस तरह आना, मारा जाना या सजा देना कतई संभव ही नहीं होता। जरा सोचिए, मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की सरेआम हत्या करवाई और आज कांग्रेस उसे अपराधी तक कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने उसे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कराया तथा उसे वापस न लाया जा सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयां लड़ी। ऐसी पार्टियों के होते क्या उसे सजा मिल सकती थी? ये पार्टियां भूल रही हैं कि देश ने राजनीति के अपराधीकरण और अल्पसंख्यकवाद के दौर को पीछे छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 में भाजपा सरकार की वापसी का सबसे बड़ा कारण यही था कि अपराधी और माफिया के विरुद्ध अविश्वसनीय स्तर तक कार्रवाई हुई। योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि देश में आम लोगों के बीच अपराधियों व माफियाओं के विरुद्ध किसी भी दबाव से परे अडिग रहते हुए कठोरता से कार्रवाई करने वाले नायक के रूप में खड़े हुए हैं तो इसी कारण। उप्र में सभी समुदायों के आम आदमी की प्रक्रिया होती है कि हम अब निर्भय होकर सड़कों पर चल सकते हैं, इसलिए बसपा, सपा या कांग्रेस या अन्य पार्टियां अगर मानती है कि ऐसे अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर वे मुस्लिम वोटों से फिर विजय प्राप्त कर सत्ता पा लेंगे तो यह सपना पूरा नहीं होने वाला, पर इस व्यवहार के कारण सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाया गया खतरनाक झूठ कि मुसलमानों की चुन-चुन कर हत्याएं हो रही हैं- देश में सांप्रदायिक तनाव का वातावरण पैदा कर रहा है। ऐसी राजनीति और एक्टिविज्म भयभीत करने वाली है। मुख्तार जैसे लोग समाज के नायक नहीं खलनायक हैं। खलनायक को नायक बनाने की सांप्रदायिक और विभाजनकारी प्रवृत्ति के विरुद्ध डटकर खड़ा होने की आवश्यकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

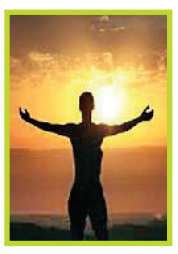

जीवन में सफलता पाने मन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है?

संकलित
दर्शन

मन अधिक चंचल है, क्योंकि वह माया में रमा हुआ है। उसे जीवन सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए बड़े अंकुश की आवश्यकता होती है। परमात्मा के भय से बड़ा कोई नियंत्रक नहीं है। वह दृष्टिगोचर नहीं है। फिर भी सर्वव्यापी है। उसके कोई अधिकारी नहीं हैं। फिर भी उसका राज्य अनंत एवं व्यवस्था अति सुचारु है। उसने कोई संविधान नहीं बनाया। फिर भी वह गुण-दोष परखकर फल देता जा रहा है। परमात्मा अंतर्यामी है। कुछ भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है। उसका न्याय होकर रहता है। सांसारिक विधानों से बचा जा सकता है, किंतु परमात्मा की परम शक्ति से नहीं। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना ही दंड से बचने का एकमेव उपाय है। परमात्मा निराकार है, किंतु उसका कौतुक जीवन को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। परमात्मा का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य का तन है, जो पांच तत्वों जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश के संयोग से बना है। ये पांचों तत्व परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं। वे एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा की ही महिमा है कि एक साथ जीव के तन में बस रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार कोई और नहीं हो सकता। परमात्मा ने अगण्य जीव रचे हैं और नित्य रचता जा रहा है। वह जीवों को रचता ही नहीं, उनका प्रतिपालन भी करता है। उसकी कृपा एवं उसका दंड पल-पल संसार में प्रकट होते हैं। वह राजा से रंक, रंक से राजा, ज्ञानी से अज्ञानी एवं अज्ञानी से ज्ञानी बना रहा है। उसकी लीला वही जानता है।

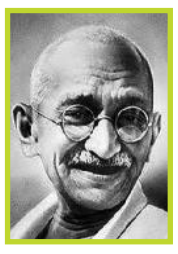

जब हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें

संकलित
प्रेरणा

महात्मा गांधी के बचपन का चर्चित किस्सा है। जब गांधी जी छोटे थे, तब एक दिन उन्होंने अपने ही घर में चोरी कर ली थी। इस बारे में गांधी जी ने भी खुद जिक्र किया था। बालक मोहनदास ने बड़े भाई के सोने के कड़े में से कुछ सोना निकाल लिया था। मोहनदास अपनी कुछ जरूरतें पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें धन की जरूरत थी। उन्होंने चोरी कर ली, लेकिन बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि अब इस गलती को किसके सामने स्वीकार किया जाए? मोहनदास ने पिता के सामने गलती स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्हें डर भी लग रहा था कि अगर चोरी के बारे में बताऊंगा तो सजा भी मिलेगी। मोहनदास ने डरते-डरते अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में उन्होंने अपनी गलती के बारे में लिखा था। जब मोहनदास के पिता को चिट्ठी मिली तो उन्होंने उसे पढ़ा। चिट्ठी में पूरी बात लिखने के साथ ही लिखा था कि मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैं इसकी सजा मानने के लिए भी तैयार हूं। जैसे ही मोहनदास के पिता ने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसु आ गए और वे मौन हो गए। जबकि मोहनदास ने सोचा था कि पिता से डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिता के मौन ने गांधी जी की सोच बदल दी, इस घटना के बाद से ही संसार को महात्मा गांधी के रूप में सबसे ईमानदार व्यक्ति मिल गया।

अंतर्मन

आज की पाती

बैसाखी का इतिहास और संदेश

बैसाखी का पर्व हिंदुओं और सिक्खों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। 13 अप्रैल 1699 को सिक्खों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह दिन जहां किसानों के लिए अपनी फसल के पकने और काटने की खुशी का दिन होता है, वहीं इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों की नापाक हरकत को भी याद करवाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में जिस नापाक हरकत को अंजाम देते हुए कई भारतीयों पर गोलियां चलाकर निहत्थे लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उसको याद कर अब भी हर किसी की रुह तक कांप जाती है।

- संतोष मेहता, जगदलपुर

करंट अफेयर

बाइडन ने ईरान के हमले की निंदा की

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की और स्थिति पर विचार विमर्श तथा आगे की कार्रवाई के लिए रविवार को जी-7 नेताओं की बैठक बुलाई है। बाइडन की इस प्रतिक्रिया के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने के प्रयासों में मदद की। इजराइल ने कहा कि उसने और उसके सहयोगी देशों ने ईरान की ओर से दागी गईं 200 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों में से अधिकतर को बीच में ही रोक दिया है। बाइडन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, 'आज तड़के ईरान और यमन, सीरिया तथा इराक के उसके हमदर्दों ने इजराइल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया। मैं इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।' बाइडन ने कहा कि इजराइल की मदद करने के उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह क्षेत्र में विमान और बैलेस्टिक मिसाइल रक्षा विध्वंसक भेजे थे। उन्होंने कहा, 'इन तैनाती और हमारे सैनिकों की दक्षता के कारण हम लगभग सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में इजराइल की मदद कर पाए।' बाइडन ने कहा, 'मैंने अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इजराइल को अमेरिका के मजबूत समर्थन को दोहराया।'

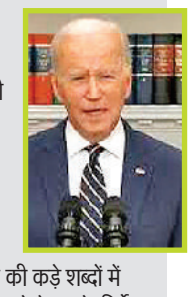

ऑफ बीट

मानसिक स्वास्थ्य के लिए कला थेरेपी है लाभदायक

उपचार के उद्देश्यों के लिए कला का उपयोग दुनिया भर में प्रथम राष्ट्र के लोगों की प्रथाओं से हजारों साल पुराना है। कला चिकित्सा शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई में सुधार लाने के लिए रचनात्मक प्रक्रियाओं, मुख्य रूप से दृश्य कला जैसे पेंटिंग, ड्राइंग या मूर्तिकला का उपयोग करती है। जब लोग शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता का सामना करते हैं, तो उनके अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कला चिकित्सक एक चिंतनशील कला-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को जबरदस्त विचारों, भावनाओं और अनुभवों का पता लगाने और संसाधित करने में सहायता करते हैं। यह कला कक्षाओं से अलग है, जो अक्सर कलाकृति के तकनीकी पहलुओं, या अंतिम उत्पाद के सौंदर्यशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कला चिकित्सा का उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार में सहायता के लिए किया जा सकता है। इसे बेहतर आत्म-जागरूकता, सामाजिक संबंध और भावनात्मक विनियमन सहित लाभों से जोड़ा गया है और इसकी मदद से संकट, चिंता और यहां तक कि दर्द के स्तर को भी कम किया गया है।

ट्रेंड

गरीब को समर्पित संकल्प पत्र

भाजपा का संकल्प पत्र युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब को समर्पित है। इन्हीं संकल्पों को लेकर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अपनों के बीच आकर गर्व महसूस कर रहा हूं। भाजपा का संकल्प पत्र, देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जीवन को खोज लेंगे

एक बार जब आप दुख के डर से आगे निकल जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से जीवन को पूरी तरह से खोज लेंगे। दुनिया में प्रभावी कामकाज के लिए ज्ञान मुख्य कारक नहीं है, बल्कि धारणा की स्पष्टता है।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

दो शब्द गायब

भाजपा के मेनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से दो शब्द गायब हैं-महंगाई और बेरोज़गारी। जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडी गठबंधन का प्लान बिलकुल स्पष्ट है। 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी।

-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

मात देता है

व्यायाम चिकित्सा बिलों को मात देता है। सूरज की रोशनी अवसाद को मात देती है। स्वस्थ भोजन मोटापे को, पैसा बचाना कर्ज से मुक्ति दिलाता है। ज्ञान अज्ञान को हराता है। कृतज्ञता ईर्ष्या को मात देती है।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।